राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 191

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 19 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रोहित के शतक और कुलदीप की हैट्रिक से दूसरे वनडे में जीती टीम इंडिया

>> 14

सरोकार

'यूएस' को कलाम ने दिया था 'जल ग्राम' का आइडिया...

बांदा : जिस बुंदेलखंड में पानी को लेकर हाहाकार रहता है, वहीं गांव जखनी समस्त संकटों को धता बताकर अचरज का विषय बन गया है। यह संभव हुआ उमाशंकर पांडेय के बूते, जिन्हें जल ग्राम का आइडिया किसी और ने नहीं वरन अग्निपुरुष डॉ. कलाम ने दिया था। (पेज-10)

जागरण विशेष

हिमालयी उथल-पुथल की पहेली सुलझाएगा 'मोडिस'

लखनऊ : अब बर्फ से ढके हिमालय में होने वाली मौसमी उथल-पुथल अबूझ पहेली नहीं रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखना हो, बर्फ पिघलने की दर आंकनी हो या पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना हो..., 'मोडिस' से यह सब कुछ आसान होगा। (पेज-10)

नागरिकता संशोधन कानून पर फिलहाल रोक नहीं

सीधी बात ▶ कानून की वैधानिकता को परखेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक मांगा जवाब

59 याचिकाएं दाखिल कर कानून को दी गई है चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि कोर्ट कानून की वैधानिकता परखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते हुए कानून को चुनौती देने वाली कुल 59 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को 22 जनवरी तक अपना जवाब देना है। कोर्ट मामले पर 22 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा।

यह आदेश प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने जारी किए। कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश, सांसद असदुद्दीन ओवैसी और महुआ मोइत्रा शामिल हैं। बुधवार को मामले पर सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और बराबरी के मौलिक अधिकार का भी हनन करता है। उन्होंने कुछ दलीलें रखीं ही थीं कि कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर विचार का मन बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया। तभी कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अंतरिम रोक का विरोध करते हुए कहा कि कानून अधिसूचित होने के बाद कोर्ट इस तरह अंतरिम रोक नहीं लगा सकता। इस बारे में चार पूर्व फैसले हैं और वह उन्हें पेश कर सकते हैं। तभी एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि अभी कानून पर रोक लगाने की मांग की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कानून लागू नहीं हुआ है। कानून के तहत नियम आदि अभी तय नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि वे अभी सिर्फ याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं। वे अभी कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि कानून पर रोक की मांग पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को पक्ष रखा जा सकता है।

पिछले सप्ताह नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैरमुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

जयराम रमेश की याचिका में कहा गया है कि यह कानून 1985 के असम समझौते के खिलाफ भी है। उनका यह भी कहना है, कोर्ट घोषित करे कि नागरिकता संशोधन कानून अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। इस कानून को तैयार करने में संयुक्त संसदीय समिति की सात जनवरी, 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी की गई है। कानून में संशोधन करके अवैध रूप से देश में घुसे लोगों (घुसपैठिये) की परिभाषा बदल दी गई है। यह कानून भेदभाव करता है क्योंकि इसमें मनमाने तरीके से सिर्फ तीन देशों के छह धर्मावलंबियों को शामिल किया गया है और विशेष तौर पर एक धर्म और भाग को छोड़ दिया गया है।

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू), पीस पार्टी, गैरसरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन अगेंस्ट हेट, एहतशाम हाशमी और सिंब्योसिस के लॉ स्टूडेंट, जन अधिकार पार्टी, असम में नेता विपक्ष देबब्रत्रा और वकील एमएल शर्मा, केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि ने याचिका की है।

हिंसक प्रदर्शनों के पीछे उग्रवादी व कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका पेज>>5

हिंसा के पीछे शामिल तत्वों पर सख्त हुई असम सरकार पेज>>5

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

'सीएए के उद्देश्य और तथ्यों का सरकार करें व्यापक प्रचार'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सीएए के उद्देश्य और तथ्यों का व्यापक प्रचार करने के सुझाव पर विचार करे ताकि लोगों में फैला भ्रम दूर हो। दरअसल, सुनवाई के दौरान वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा, वह जामिया और सीलमपुर गए और पाया कि 95 फीसद प्रदर्शनकारियों को इस कानून के बारे में मालूम ही नहीं है। वे समझते हैं कि इस कानून से उनकी नागरिकता चली जाएगी। शरारती तत्व झूठी खबरें फैला रहे हैं। सरकार कानून के बारे में प्रचार करे ताकि भ्रम दूर हो। इन दलीलों पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि मांग विचार करने योग्य है। आप इस पर विचार करेंगे या फिर कोर्ट इस बारे में कोई आदेश दे। वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट को इस बारे में आदेश देने की जरूरत नहीं है। वह सरकार को इस बात से अवगत कराएंगे और सरकार ऐसा करेगी। कोर्ट की इजाजत लेकर उपाध्याय ने अपनी याचिका केके वेणुगोपाल को दे दी।

कानून के विरोध में पुणे, ठाणे और सोलापुर में भी प्रदर्शन

नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध दिल्ली और असम के बाद अब महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी पहुंच गया है। बुधवार को पुणे में असम मूल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि ठाणे और सोलापुर में स्थानीय लोगों ने कानून के विरोध में मार्च निकाला। इसके अलावा मद्रास में भी प्रदर्शन किए जाने का समाचार है। (पेज-5)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

स्कूली बच्चों को मिड डे मील ही नहीं, नाश्ता भी मिलेगा

नई दिल्ली : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब दोपहर के भोजन के साथ सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बजट में प्रस्ताव के साथ-साथ इसे नई शिक्षा नीति के फाइनल ड्राफ्ट में भी प्रमुखता से रखा गया है। दूसरी तरफ, स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाने का काम शिक्षकों की जगह पूरी तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी की जा रही है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, ठिठुरन बढ़ी

नई दिल्ली : सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दो दिनों में रिकार्ड तोड़ सर्दी के बीच बुधवार को शीतलहर ने समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। अलबत्ता, कुछ राज्यों में हल्की धूप जरूरत निकली, मगर हवाओं के चलते लोगों को राहत नहीं मिली।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

नए सामाजिक सुरक्षा कोड से बहुरेंगे कर्मचारियों के दिन

नई दिल्ली : कर्मचारियों के दिन बहुरने वाले हैं। संशोधित सामाजिक सुरक्षा कोड में पांच वर्ष से कम अवधि के फिक्स टर्म रोजगार में भी ग्रेच्युटी देने का प्रावधान किया गया है। कर्मियों के घर-दफ्तर के बीच दुर्घटना की स्थिति में नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

मुशर्रफ की मौत की सजा को चुनौती देगी पाकिस्तान सरकार

इस्लामाबाद : देशद्रोह के लिए मौत की सजा पाए पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के समर्थन में सेना के आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। मंगलवार को सैन्य तानाशाह मुशर्रफ को छह साल चले मुकदमे उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। मुशर्रफ इलाज के लिए अनुमति लेकर 2016 में विदेश गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे। इस समय वह दुबई में रह रहे हैं।

अक्षय की फांसी पर फिर मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी अक्षय कुमार सिंह की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी मुहर लगा दी है। बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पिछले वर्ष ही खारिज हो चुकी हैं। हालांकि इन दोषियों के पास अभी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका देने का विकल्प बचा हुआ है।

जस्टिस आर.भानुमति, अशोक भूषण व एएस बोपन्ना की पीठ ने बुधवार को अक्षय के वकील एपी सिंह की सारी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अक्षय को मृत्युदंड सुनाने के 5 मई 2017 के फैसले में कोई खामी नजर नहीं आती। न ही उन्हें पुनर्विचार याचिका में ऐसा कोई आधार दिखा है जिससे कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अक्षय ने अपनी पुनर्विचार याचिका में वही आधार दिए हैं जिनपर पहले ही कोर्ट विचार कर चुका है। ऐसे ही आधार तीन अन्य सहअभियुक्तों की ओर से भी दिए गए जिन पर विचार करने के बाद कोर्ट ने 9 जुलाई 2018 को उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका में दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति की गंभीरता का मुद्दा उठाए जाने और प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी घटने की दलील तथा कलयुग में व्यक्ति को जिंदा लाश के समान बताते हुए मृत्युदंड देना बेकार कहे जाने की दलीलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

कोर्ट ने कहा, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने गंभीर मामले में इस तरह के तर्क दिए गए हैं। बहस के दौरान अक्षय के वकील ने तिहाड़ जेल के पूर्व विधि अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद लिखी गई किताब 'ब्लैक वारंट' का जिक्र किया और कहा कि उसमें विधि अधिकारी ने इस मामले में एक आरोपित रामसिंह की जेल में हत्या होने की आशंका जताई है। कोर्ट ने दलीलें खारिज करते हुए कहा कि किताब में कही गई बातें मात्र राय हैं। उसके साथ कोई भी सहयोगी साक्ष्य नहीं पेश किए गए। ऐसे में उसके आधार पर फैसले पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर उस विधि अधिकारी को रामसिंह की मौत के बारे में कोई शंका थी तो उसे अदालत में आकर गवाही देनी चाहिए थी। या फिर वह इस बारे में कोर्ट में हलफनामा देता। शीर्ष अदालत ने मामले की जांच में खामी और पीड़िता के मृत्युपूर्व दिए बयानों पर उठाए गए सवालों को भी खारिज कर दिया। तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस सब बातों पर विस्तृत विचार करने के बाद 5 मई 2017 का फैसला सुनाया था।

दुष्कर्म केस की धीमी चाल से कोर्ट चिंतित पेज>>2

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड

- सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका खारिज, क्यूरेटिव और दया याचिका का विकल्प बाकी
- कोर्ट ने प्रदूषण से लोगों की जिंदगी घटने जैसी दलीलों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
- जांच में खामी व पीड़िता के बयानों पर उठाए गए सवालों को भी नकारा

प्रतीकात्मक फोटो

...भगवान का भी सिर शर्म से झुका होगा

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह किसी भी तरह के रहम का हकदार नहीं है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनसे मानवता रोती है। निर्भया (पीड़िता का बदला हुआ नाम) पर हुआ अपराध भी वैसा ही था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे देख कर भगवान का भी सिर शर्म से झुक गया होगा। उसके दो कारण होंगे पहला तो यह कि वे एक निर्दोष असहाय पीड़िता को बचा नहीं पाए और दूसरा इन पांच राक्षसों को उत्पन्न करने के कारण। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक इसे सजा सुनाई जा चुकी है। अब फैसले पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है।

तय समय में याचिका दाखिल करने की छूट : कोर्ट

पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अक्षय के वकील ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट से तीन सप्ताह का समय मांगा लेकिन तुषार मेहता ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि कानून में इसके लिए सात दिन की अवधि तय है। कोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया सिर्फ इतना कहा कि कानून में तय समय के भीतर उसे याचिका दाखिल करने की छूट होगी। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को पैरामेडिकल की छात्रा से रात में चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस दौरान छात्रा को गंभीर चोटें पहुंचाई गईं जिससे बाद में इलाज के दौरान 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में कुल छह अभियुक्त थे जिनमें से एक अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी और एक अन्य दोषी नाबालिग था जिसका मामला जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में चला। बाकी के चार दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुनाई थी।

दोषियों से दया याचिका के बारे में पूछे जेल प्रशासन

नई दिल्ली : दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया कि चारों दोषियों को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर उनकी तरफ से दायर होने वाली दया याचिका की स्थिति के बारे में पूछा जाए। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि दोषियों को डेथ वारंट जारी किया जाए, क्योंकि अक्षय की अर्जी खारिज हो गई है। अरोड़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद इस पर विचार किया जा सकता है। अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।

जज ने बोला, कानून का भी है एक दायरा : सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने कहा, हम जहां भी जाते हैं तो यही सुनते हैं कि उनके (दोषियों) पास अभी कानूनी उपाय हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? इस पर जज ने कहा, आपने बेटी को खोया है, लेकिन उनके अधिकार भी हैं। हम आपको सुनने के लिए यहां मौजूद हैं, लेकिन कानून का भी दायरा है।

एनक्लैट का फरमान, सायरस मिस्त्री को फिर बनाया जाए टाटा संस का चेयरमैन

नई दिल्ली, प्रेट्र : टाटा समूह के साथ कानूनी लड़ाई में सायरस मिस्त्री को बड़ी जीत मिली है। बुधवार को एनक्लैट ने मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि बहाली फौरन नहीं होगी। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए टाटा ग्रुप को चार सप्ताह की मोहलत मिली है।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने अपने फैसले में नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली विभिन्न कंपनियों की होल्डिंग फर्म टाटा संस के चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को गैरकानूनी करार दिया है। इसके अलावा टाटा संस को पब्लिक फर्म से प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने के फैसले को भी रद कर दिया है।

सायरस मिस्त्री सपूरजी पलोनजी कारोबारी घराने से हैं। रतन टाटा के रिटायर होने के बाद साल 2012 में उन्हें टाटा संस की कमान सौंपी गई थी। वह इस कंपनी के छठे चेयरमैन बने थे। अक्टूबर, 2016 में उन्हें जबरन टाटा संस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था और कंपनी के बोर्ड से भी बाहर कर दिया गया था।

देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप का संचालन करने वाली कंपनी टाटा संस में 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले मिस्त्री परिवार ने सायरस की बर्खास्तगी के फैसले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में चुनौती दी। तब से अब तक इस मामले में कई मोड़ आए और अंततः फैसला मिस्त्री के पक्ष में आया।

संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे रतन टाटा : एनक्लैट ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को टाटा संस के निदेशक मंडल (बोर्ड) के रोजमर्रा के काम से दूरी बनाए रखने का आदेश दिया है। सायरस मिस्त्री को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने में टाटा की बड़ी भूमिका रही थी।

कब क्या हुआ? पेज>>3

- कंपनी के चेयरमैन पद पर एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति गैर-कानूनी करार
- टाटा संस को पब्लिक फर्म से प्राइवेट कंपनी में तब्दील करने का फैसला भी हुआ रद
- एनक्लैट के फैसले के विरुद्ध याचिका के लिए टाटा संस के पास चार सप्ताह का वक्त

सायरस पी. मिस्त्री की फाइल फोटो। प्रेट्र

यह गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों और छोटे शेयरधारकों के हितों की जीत है। – **सायरस मिस्त्री**

मिस्त्री की बहाली के आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। – **टाटा संस**

जयपुर बम धमाकों में चार दोषी करार, 71 की ली थी जान

मनीष गोधा, जयपुर

- एक आरोपित को कोर्ट ने किया बरी, सजा का एलान कल संभव
- 2008 में श्रृंखलाबद्ध आठ धमाकों में 185 लोग हुए थे घायल
- 10 आरोपित थे, दो बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए, तीन फरार

राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 11 साल पहले हुए श्रृंखलाबद्ध आठ बम धमाकों के मामले में बुधवार को विशेष अदालत ने पांच आरोपितों में से चार को दोषी करार दिया। ये चारों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। एक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। धमाकों के 10 आरोपित थे, जिनमें से दो सितंबर 2008 में दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे और तीन अब भी फरार हैं। चारों दोषियों की सजा पर गुरुवार को बहस होगी और संभवतः शुक्रवार को सजा का एलान किया जाएगा। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हो गए थे।

गौरतलब है कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र में 13 मई, 2008 को शाम सवा सात से साढ़े सात बजे के बीच 15 मिनट में आठ बम धमाकों से गुलाबी नगरी दहल उठी थी। शहर के व्यस्त इलाकों व बाजारों में हुए इन धमाकों से गुलाबी नगर रक्तरंजित हो गई थी। शहर के माणक चौक और कोतवाली थाने में इस मामले में चार-चार एफआइआर दर्ज की गई थीं। इनकी सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई थी।

विशेष अदालत ने इन चारों को ठहराया दोषी

मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन।

मुहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, निवासी सरायमीर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। दिसंबर 2008 में गिरफ्तारी हुई। **आरोप**–गुलाबी नगरी में पहला बम धमाका इसी ने किया था। माणक चौक खंदा क्षेत्र में बम रखा।

मुहम्मद सरवर आजमी।

मुहम्मद सरवर आजमी, निवासी–चांद पट्टी, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। जनवरी 2009 में गिरफ्तारी। **आरोप**–चांदपोल हनुमान मंदिर के सामने बम रखा। धमाके में श्रद्धालुओं समेत कई लोगों की मौत

सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी।

सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी, निवासी–आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। अप्रैल 2009 में गिरफ्तारी। **आरोप**–फूल वालों का खंदा क्षेत्र में बम रखा। इस धमाके में कई बेगुनाहों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा।

मुहम्मद सलमान। सभी फाइल फोटो

मुहम्मद सलमान, निवासी–निजामाबाद, सरायमीर आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)। दिसंबर 2010 में गिरफ्तारी। **आरोप**–षड्यंत्र में शामिल, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास बम रखा।

ईमेल कर जिम्मेदारी लेने वाला दोषमुक्त

धमाकों के अगले दिन इंडियन मुजाहिदीन के नाम से ईमेल कर इन विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने वाले मुहम्मद शहबाज अहमद, निवासी–लखनऊ को विशेष कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। उसे सितंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन उसके खिलाफ सुबूत पेश नहीं कर सका।

11 वर्ष सात माह बाद आया सीरियल धमाकों के मामले में फैसला पेज>>7

नियंत्रण रेखा पर किसी भी समय खराब हो सकते हैं हालात : सेना प्रमुख

बिपिन रावत फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर हालात कभी भी खराब हो सकते हैं और सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल रावत ने यह टिप्पणी ऐसे समय की है जब अगस्त में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन काफी बढ़ गया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने पिछले महीने लोकसभा में बताया भी था कि अगस्त, 2019 से अक्टूबर, 2019 के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की 950 घटनाएं दर्ज की गईं।

सूत्रों का भी कहना है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीमें (बैट) लगातार नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने की कोशिशें कर रही हैं। पाक हर तीसरे-चौथे दिन बैट के अभियानों को अंजाम दे रहा है। बैट में सामान्यतः पाकिस्तानी सेना के विशेष बलों के कर्मी और आतंकी शामिल होते हैं। पूर्व में बैट द्वारा भारतीय सैनिकों के शवों को क्षतविक्षत करने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। बताते चलें कि 31 दिसंबर, 2016 को सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद से जनरल रावत ने घाटी में सीमा पार से आतंकवाद से निपटने में आक्रामक नीति अपनाने में अहम भूमिका निभाई है। वह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। इस बीच, सुरक्षा बलों के आकलन के मुताबिक, घाटी में हालात काफी हद तक नियंत्रण में आ चुके हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है ताकि हालात न बिगड़ें। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर की स्थिति पर बेहद बारीकी से नजर रखी जा रही है। सटीक आकलन के बाद ही हर कदम उठाया जा रहा है।

केंद्रीय विद्यालयों के दाखिले में ओबीसी का भी कोटा

सरकार ने मानी वर्षों पुरानी मांग

आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी यह लाभ देने पर मंत्रालय करेगा विचार, अभी तक सिर्फ एससी-एसटी और दिव्यांगजनों को ही दिया जा रहा था आरक्षण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राहत देने वाली एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में आरक्षण देने की उनकी वर्षों पुरानी मांग मान ली है। अब इन विद्यालयों के प्रवेश में ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मिलना शुरू हो जाएगा। इन विद्यालयों में अब तक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) और दिव्यांगजनों को ही प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को इसे लेकर अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले इस प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी अपनी सहमति दे चुका है। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालयों में अब सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीबों को छोड़कर एससी, एसटी और ओबीसी सभी को प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्द ही सामान्य वर्ग के गरीबों को भी प्रवेश देने के मामले में आरक्षण देने पर विचार करेगा। बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीबों को मौजूदा मोदी सरकार ने ही दस फीसद आरक्षण देने का फैसला लिया था। फिलहाल इसका लाभ उन्हें उच्च शैक्षणिक संस्थानों सहित सरकारी नौकरियों में मिल रहा है।

प्रतीकात्मक फोटो

एससी को 15 और एसटी को 7.5 फीसद आरक्षण

मौजूदा समय में तय नियमों के तहत केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों में एससी को 15 फीसद और एसटी को 7.5 फीसद आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को भी तीन फीसद आरक्षण का लाभ मिलता है। केंद्रीय विद्यालयों के प्रवेश में आरक्षण का यह लाभ पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान मिलता है, जबकि नवोदय विद्यालयों में छठीं कक्षा में प्रवेश के दौरान दिया जाता है।

ओबीसी आयोग ने उठाई थी मांग

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में आरक्षण देने की यह मांग ओबीसी आयोग ने उठाई थी। इतना ही नहीं साथ ही दोनों ही विद्यालयों के प्रवेश में कानून के तहत तय 27 फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की थी।

14 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बीमा की सुविधा दी है। इस सुविधा के बाद दुर्घटना होने या कर्मचारियों की मृत्यु पर पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 19 दिसंबर 2019

दुष्कर्म के मुकदमों की धीमी चाल से कोर्ट चिंतित, लिया स्वत: संज्ञान

सख्त रुख ▶ गति बढ़ाने के लिए शुरू की कानून के अनुपालन की समीक्षा, केंद्र, राज्य सरकारों व हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरलों को नोटिस जारी

माला दीक्षित, नई दिल्ली

महिलाओं से दुष्कर्म के बढ़ते मामलों और न्याय में देरी से लोगों में घर करती हताशा व बेचैनी ने सुप्रीम कोर्ट को चिंतित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मुकदमों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। कोर्ट ने बुधवार को ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने क्रिमनल जस्टिस सिस्टम की रफ्तार बढ़ाने और मौजूदा कानून व न्याय प्रणाली को लागू करने की स्थिति जानने के लिए पुलिस थाने से लेकर अदालत तक का हर स्तर का सारा रिकॉर्ड और स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा सभी हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरलों को नोटिस जारी किया है। मामले पर कोर्ट सात फरवरी को फिर सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने महिलाओं से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए क्रिमनल जस्टिस सिस्टम की समीक्षा करने पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में मदद करने के लिए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को न्यायमित्र नियुक्त किया है। कोर्ट ने लूथरा को सारी जानकारी और सूचनाएं एकत्रित होने के बाद कानून लागू करने और न्याय की रफ्तार बढ़ाने व व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी करने के बारे में सुझाव देने को कहा है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अनुरोध किया है कि वह इस संबंध में न्यायमित्र लूथरा को पूरा सहयोग दें। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार के गृह सचिव, और राज्यों के मुख्य सचिवों व डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सभी हाई कोर्टों के रजिस्ट्रार जनरलों को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल सभी राज्यों और हाई कोर्टों से सूचना मंगाने में सहयोग करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

मुकदमों में देरी लोगों में हताशा और बेचैनी पैदा करती है : कोर्ट ने कहा कि निर्भया कांड से पूरा देश हिल गया था। उसके बाद ऐसे मामलों में प्रभावी जांच और त्वरित निपटारे के लिए आपराधिक कानून में संशोधन किए गए। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अपेक्षित नतीजे अभी भी नहीं मिले हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में दुष्कर्म के 32,559 मामले दर्ज हुए। कोर्ट ने कहा कि हाल ही में देखने में आया है कि ऐसे मामलों में देरी से लोगों में हताशा और बेचैनी पनप रही है। निर्भया का एक अकेला मामला नहीं है जिसे अंतिम मुकाम तक पहुंचने में इतनी देर लगी। वास्तव में तो यह एक ऐसा मामला था जिसमें लोगों के गुस्से को देखते हुए संबंधित एजेंसियों ने फुर्ती से काम किया।

तेजी लाने के लिए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा : कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में क्रिमनल कानून के अनुपालन को देखना होगा। इस बारे में जमीनी हकीकत जानने के लिए जांच एजेंसी, मेडिको फॉरेंसिक एजेंसी, अभियोजन एजेंसी, कानूनी सहायता, पुनर्वास और यहां तक कि अदालत तक से सूचना एकत्र कर देखनी होगी ताकि स्थिति का समग्र अंदाजा मिल सके।

कोर्ट ने किए ढेरों सवाल : कोर्ट ने ऐसे मामलों को दर्ज करने के लिए पुलिस थानों में महिला अधिकारी की उपलब्धता से लेकर अपनी बात बताने में असमर्थ पीड़िता की बात समझाने के लिए विशेषज्ञ की उपलब्धता तक का ब्योरा मांगा है। यह भी पूछा है कि क्या राज्यों में ऐसे मुकदमे दर्ज करने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पीड़िता की चिकित्सीय जांच के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों तक मेडिकल किट की उपलब्धता और फॉरेंसिक जांच लैब की स्थिति भी पूछी है। पूछा है कि क्या कानून में तय दो महीने की अवधि के भीतर पुलिस ऐसे मामलों की जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर रही है। क्या अदालतें तय दो महीने की अवधि में ऐसे मुकदमों का निपटारा कर देती हैं। क्या अदालतें मुकदमों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुनवाई का केस कैलेंडर तैयार करती हैं ताकि मुकदमे का निपटारा तय समय में पूरा हो। क्या अदालतों में ऐसे मुकदमों की सुनवाई के लिए पर्याप्त महिला जज और ढांचागत संसाधन मौजूद हैं। ऐसे मामलों की एफआइआर दर्ज न करने पर संबंधित पुलिस कर्मी को सजा का प्रावधान है, कितने मामलों में ऐसा हुआ है, ब्योरा दो। इतना ही नहीं कोर्ट ने निर्भया फंड के खर्च का ब्योरा भी मांगा है।

कोर्ट में चली सुनवाई पर पूरे दिन थी निर्भया के दोषियों की नजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के दोषियों के चेहरे उतर गए। तिहाड़ जेल सूत्रों की मानें तो दोषियों को जब इसके बारे में पता चला तो सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर गईं। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि थोड़ी देर बाद ही पटियाला हाउस कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। वहां सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में दोषियों को नोटिस जारी कर याचिका दायर करने के लिए सात दिन का वक्त दिया जाए, तब उनके चेहरे पर उम्मीद का भाव नजर आया। इसके बाद जब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख सात जनवरी तय की, तब दोषियों के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें थोड़ी कम हो गईं।

जेल सूत्रों का कहना है कि चारों दोषियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई। अक्षय, मुकेश व पवन जेल संख्या-दो स्थित वीडियो कांफ्रेंस रूम में थे तो विनय जेल संख्या चार में। सुनवाई के दौरान सभी शांत थे, लेकिन उनके चेहरे से मायूसी झलक रही थी। सबसे ज्यादा चिंता अक्षय के चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी याचिका की सुनवाई चंद घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और याचिका को ठुकरा दिया गया। लेकिन जब सभी को यह पता चला कि जेल प्रशासन अब उन्हें अपनी-अपनी याचिका दायर करने के लिए नोटिस जारी कर सात दिनों का वक्त देगा तो इनकी चिंता थोड़ी कम हुई। जेल सूत्रों का कहना है कि आज की गतिविधि के बाद दोषी मुकेश को इस बात की उम्मीद जगी है कि अब उसकी ओर से पक्ष रखने के लिए वकील उपलब्ध होगा। जेल सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से जेल संख्या-तीन स्थित फांसी घर में जारी गतिविधि के बीच चारों दोषी परेशान थे। हालांकि ये तभी से परेशान रहने लगे जब 29 अक्टूबर को जेल प्रशासन की ओर से चारों दोषियों को नोटिस जारी कर दया याचिका दाखिल करने को सात दिन का समय दिया था। ये तब और परेशान रहने लगे, जब जेल परिसर में इनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष कदम उठाए और एक जेलकर्मी की डयूटी इनके साथ लगा दी। इतना ही नहीं इनकी स्वास्थ्य जांच भी नियमित तौर पर होने लगी।

पुनर्विचार याचिका खारिज होते ही अक्षय के घर में मातम

जागरण टीम, औरंगाबाद

▶ वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म में दोषी अक्षय के स्वजन बोले, लड़ते रहेंगे लड़ाई

▶ पत्नी ने कहा–खराब संगत में पड़कर किया होगा गलत कार्य

दिल्ली के निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए अक्षय कुमार सिंह उर्फ अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को खारिज होने के बाद उसके स्वजनों में मातम पसर गया है। वह बिहार के औरंगाबाद जिला स्थित गांव लहंगकर्मा का रहने वाला है। फांसी पर अदालत की मुहर बरकरार रखने की जानकारी मिलते ही मां मालती देवी और पत्नी पुनीता देवी फफक पड़ीं। परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे भी उतर गए। अक्षय को एक सात वर्ष का पुत्र भी है।

सुबह से कर रहे थे फैसले का इंतजार : अक्षय के स्वजन सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में थे। वे पूजा-अर्चना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही याचिका खारिज होने की सूचना मिली, उनकी आंखें छलक उठीं।

मेरे पति ने गलत संगत में बुरा कार्य किया : पुनीता : पुनीता ने कहा कि पति ने खराब संगत में पड़कर गलत कार्य किया होगा। हम न्याय की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। रामनगर पंचायत की मुखिया मालती देवी व ग्रामीण प्रभु सिंह ने कहा कि हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वह इतना खराब कैसे हो गया। अक्षय पर पहले से कोई आरोप नहीं थे।

सरकार से करेंगे माफी की अपील : अक्षय के भाई विनय सिंह ने कहा कि निर्भया के स्वजनों को न्याय मिलना चाहिए, पर ध्यान यह भी रहे कि किसी का परिवार न उजड़े। हम लोग सरकार से सजा माफ करने की अपील करेंगे। उनका कहना था कि घटना के बाद कंपनी ने मेरे साथ भाई अभय सिंह को भी निकाल दिया। घर पर जमीन नहीं है। किसी तरह दिल्ली में रहकर कार्य करते थे, लेकिन घटना के बाद से गांव में रहकर मजदूरी कर रहे हैं। अक्षय की फांसी की सजा के फैसले के बाद से हम लोग बेचैन रहते हैं।

पवन ने वारदात के समय खुद को बताया नाबालिग

जासं, नई दिल्ली : निर्भया मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि 2012 में जब अपराध हुआ तब वह नाबालिग था। याचिका पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सुरेश कैट के समक्ष सुनवाई होगी। खुद को नाबालिग साबित करने की मांग करते हुए पवन कुमार ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों द्वारा उसकी हड्डी का परीक्षण नहीं किया गया था। दोषी पवन ने कहा कि जेजे एक्ट की धारा 7ए के तहत वह किसी भी अदालत के समक्ष जा सकता है और मामले में अंतिम फैसला होने के बावजूद भी किसी भी स्तर पर इसकी पहचान कराई जा सकती है। पवन ने हाई कोर्ट से मांग की कि वह संबंधित प्राधिकारियों को उसकी उम्र को सुनिश्चित करने के लिए हड्डी की जांच कराने के संबंध में निर्देश दे।

न्यूज गैलरी

भाजपा नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद हंसराज हंस, पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वहीं, दिल्ली के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता को पेशी से छूट दे दी। वहीं, अदालत ने प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। (जासं)

नियमों के उल्लंघन पर ओला व उबर के खिलाफ भी करें कार्रवाई

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि ओला और उबर अगर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी नियमों मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब दिल्ली सरकार के अधिवक्ता नौसाद अहमद खान ने पीठ से कहा कि नए वाहन अधिनियम उबर व ओला पर भी लागू होते हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि ओला-उबर को भी शहर में अपना वाहन चलाने के लिए पंजीकरण कराना होगा और लाइसेंस लेना होगा। (जासं)

आप विधायकों की अयोग्यता में हमारी कोई भूमिका नहीं : चुनाव आयोग

जासं, नई दिल्ली : विधानसभा की सदस्यता से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अनिल बाजपेयी व देवेंद्र सहरावत को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आप विधायकों को विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए जाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग ने कहा कि वह एक संवैधानिक संस्था हैं और उनका काम पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने 30 सितंबर को आयोग सहित दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय तथा शिकायतकर्ता आप विधायक सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पीठ ने इससे पहले 8 जुलाई को दोनों की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे अयोग्यता की कार्रवाई से विधानसभा अध्यक्ष को अलग रखने की मांग की थी। पीठ ने टिप्पणी की थी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई विसंगति नहीं है और यह भी नहीं लगता है कि वह पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रहे हैं। यह टिप्पणी कर पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। सौरभ भारद्वाज ने 10 जून को दिल्ली विधानसभा में एक याचिका दाखिल कर दोनों बागी विधायक बाजपेयी व सहरावत को अयोग्य करार देने की मांग की थी।

न्यूनतम 2.25 करोड़ प्रति एकड़ हुआ कृषि भूमि का सर्कल रेट

जिले का नाम	ग्रीन बेल्ट गांवों के लिए प्रस्तावित दरें	शहरीकृत गांवों के लिए प्रस्तावित दरें	ग्रामीण गांवों के लिए प्रस्तावित दरें
साउथ	5.00	5.00	5.00
नार्थ	3.00	3.00	3.00
वेस्ट	3.00	3.00	3.00
नार्थ–वेस्ट	3.00	3.00	3.00
साउथ–वेस्ट	3.00	4.00	3.00
नई दिल्ली	5.00	5.00	5.00
सेंट्रल दिल्ली	0.00	2.50	2.50
साउथ–ईस्ट	0.00	4.00	2.50
शाहदरा	2.25	2.25	2.25
नार्थ–ईस्ट	0.00	2.25	2.25
ईस्ट	0.00	2.25	2.25

नोट : सभी दरें प्रति एकड़, रकम करोड़ में

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

2008 के बाद पहली बार दिल्ली में कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि का सर्कल रेट 53 लाख से बढ़ा कर 2.25 करोड़ से 5 करोड़ तक करने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। अब इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। दिल्ली में अब कोई भी जमीन अधिग्रहण की जाएगी तो उसका रेट 2.25 करोड़ से 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बीच दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि अभी तक दिल्ली में कृषि भूमि का सर्कल रेट 53 लाख रुपये प्रति एकड़ था। उनकी सरकार ने इसमें बढ़ोतरी की थी, लेकिन तत्कालीन उपराज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया था। इस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आने के बाद एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कृषि भूमि जो ग्रीन बेल्ट में है, शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में है, उसके सर्कल रेट में वृद्धि का फैसला किया गया है।

जाफराबाद हिंसा : नौ गिरफ्तार, 18 हिरासत में

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

जाफराबाद-सीलमपुर रोड पर हिंसा के बाद पुलिस ने दो थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे उत्तर-पूर्वी जिले में धारा-144 लगा दी है। इसके साथ दिनभर संवेदनशील जाफराबाद, सीलमपुर, ब्रह्मपुरी, वेलकम और मुस्तफाबाद में पुलिस अधिकारी जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकालते रहे। पुलिस ने उपद्रवियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी थी। बुधवार शाम तक नौ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 18 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 23 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 12:00 बजे पुलिस मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद हर्ष विहार और सोनिया विहार को छोड़कर अन्य सभी थानाक्षेत्रों में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही संवदेनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसका असर असर बुधवार को देखने को भी मिला और हालात सामान्य नजर आए। इससे जहां लोगों का जमावड़ा लगना बंद हो गया। वहीं सुबह दस बजे के बाद इन इलाकों में दुकानें भी खुलने लगीं। दोपहर तक 90 फीसद से अधिक दुकानें खुल चुकी थीं। हालांकि, इन दुकानों में आम दिनों की तरह भीड़ नहीं थी। सड़क पर भी कम ही लोग थे। पुलिस अधिकारी, अमन कमेटी और इलाके के अन्य प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर बुधवार दिन भर अलग-अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकालते रहे। इस दौरान भी ड्रोन से आसपास नजर रखने के साथ वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च के दौरान अर्धसैनिक बलों की दस कंपनियों के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहे। पूर्वी रेंज के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार खुद पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए पांच ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जिले में धारा-144 लगने के कारण कई जगहों पर बुधवार को नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन रद हो गए। सीलमपुर विधायक इशराक खान ने धरने का एलान किया था। इसके साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान ने नंदनगरी एसडीएम दफ्तर के पास धरना आयोजित किया था। लेकिन ये दोनों रद करने पड़े।

जाफराबाद में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स की महिला सुरक्षाकर्मी। जागरण

पुलिस ने दंगा करने, हत्या के प्रयास, सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने समेत अन्य धाराओं में सीलमपुर, जाफराबाद और दयालपुर थाने में तीन अलग-अलग एफआइआर दर्ज की हैं। दयालपुर थाने के मुस्तफाबाद में देर रात हुई हिंसा के मामले में केस दर्ज किया। फिलहाल जिले में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है।
–आलोक कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी रेंज

गृह मंत्रालय को पुलिस ने सौंपी रिपोर्ट, अफवाह बताई हिंसा की वजह

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान सीलमपुर के जाफराबाद इलाके में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है सोशल मीडिया से अफवाह फैलाकर हिंसा फैलाई गई है। आगे भी इस तरह की घटना की आशंका बनी हुई है। इन पर अंकुश लगाने के लिए साइबर सेल की टीमें फेसबुक व वाट्सएप ग्रुपों पर नजर रख रही हैं।

मुख्यालय सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को जाफराबाद में हिंसक प्रदर्शन के बाद विशेष आयुक्त अपराध शाखा सतीश गोलचा ने बुधवार को गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा है कि सोशल मीडिया पर रोजाना भ्रामक व फर्जी वीडियो पोस्ट कर अफवाह फैलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व साइबर सेल की टीमें 24 घंटे सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही हैं, ताकि अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी। गोलचा ने बताया कि वाट्सएप ग्रुपों की पहचान कर आरोपितों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जामिया नगर हिंसा के बाद स्पेशल ब्रांच ने जिला पुलिस को सूचना दे दी थी कि उत्तर-पूर्वी जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में भी हिंसा हो सकती है। लिहाजा अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा ड्रोन आदि की व्यवस्था पहले से की गई थी। तभी पथराव शुरू होते ही पुलिस ने कई ड्रोन को उड़ा कर उपद्रवियों के बारे में पता लगाया। शांति बहाल होने के लिए अमन कमेटियों के साथ थाना पुलिस लगातार बैठकें कर रही है।

गृह मंत्रालय ने पुलिस से कहा है कि अफवाह फैलाने में अगर कोई नेता भी है तो पुलिस उनके खिलाफ भी कानून संगत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करे। देश में अशांति फैलाने वाले किसी भी दल के नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा।

जामिया मिल्लिया मामले में अंतरिम राहत नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के बाद हिंसा के मामले में दो छात्राओं की याचिका पर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई पर अंतरिम राहत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। जामिया छात्रा लदीदा फरजाना एवं अयेश रेन्ना ने याचिका में हिंसा के दौरान हिरासत में लिए गए जामिया एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को रिहा करने की भी मांग की थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार एवं सॉलिसिटर जनरल के बीच तीखी बहस हुई।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में पक्ष रखते हैं और उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि दोनों महिला याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और इन्हें तत्काल कार्रवाई से अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसने कहा कि मेहरा केंद्र व दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए हैं। उन्होंने कहा मेहरा का ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने पीठ को मौखिक जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़े मामले को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ही सुना जाएगा। इस दौरान महिला छात्राओं की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ सीम ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई पर अंतरिम राहत दी जाए। हालांकि, तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि एकल पीठ को मामले को मुख्य न्यायमूर्ति की पीठ के समक्ष भेजा जाना चाहिए। उन्होंने इस पर वह मुख्य पीठ के समक्ष बहस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष की दलील सुने बगैर तत्काल कार्रवाई पर अंतरिम राहत न दी जाए। इसके बाद पीठ ने सुनवाई को 19 दिसंबर के लिए मुख्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा।

अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी एवं सिद्धार्थ सीम के माध्यम से दायर याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा जामिया एवं एएमयू में हिरासत में लिए गए सभी छात्रों की सूची वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ इन छात्रों को उनके परिजनों एवं वकीलों से मिलने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। छात्रों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को समाप्त किया जाए।

एनआरएचएम घोटाले में दंपती हुए बरी

जासं, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले में एक दंपती को बरी कर दिया। मामला आगरा से जुड़े टैक्सी बिल मामले का था। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, एनआरएचएम स्कीम के प्रचार-प्रसार के लिए आगरा के सीएमओ ऑफिस में 2005 से 2011 तक मैसर्स ओम ट्रैवल्स एजेंसी से कुछ टैक्सी किराये पर ली गई थी। न्यू आगरा के रहने वाले फर्म के मालिक एवं टैक्सी संचालक अरुणा सक्सेना और उनके पति सुधीर कुमार सक्सेना जिले में टैक्सी चलवाने का काम करते थे। दंपति ने स्वास्थ्य विभाग को सात वर्षों तक किराये पर टैक्सी दी थी, जिसमें उन्होंने 42 टैक्सी को रजिस्टर्ड कराकर उनका बिल लगाकर विभाग से लाखों रुपये का किराया वसूला था।

जेवर एयरपोर्ट

शेष जमीन अधिग्रहण में विलंब सरकारी खजाने पर पड़ेगा भारी

विकासकर्ता कंपनी को प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा सिक्योरिटी मनी का 0.1 फीसद, बीस फीसद जमीन के किसानों ने अभी तक नहीं उठाया है मुआवजा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शेष बीस फीसद जमीन का अधिग्रहण करने में जिला प्रशासन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। अधिकरण में मुआवजा राशि जमा कराने की प्रशासन की चेतावनी के बावजूद किसान इसके लिए तैयार नहीं है। जमीन पर कब्जा मिलने में देरी प्रदेश सरकार के खजाने पर भारी पड़ेगी। प्रदेश सरकार को जेवर एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी को प्रतिदिन के हिसाब से सिक्योरिटी मनी सुरक्षा राशि का 0.1 फीसद भुगतान करना होगा। शासन के विशेष सचिव सूर्य पाल गंगवार ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर जमीन अधिग्रहण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा।

जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसमें 1239.14 हेक्टेयर जमीन किसानों की है, जबकि शेष जमीन पुनर्ग्रहण से ली गई है। जिला प्रशासन अक्टूबर में अस्सी फीसद जमीन अधिग्रहण कर यमुना प्राधिकरण को सौंप चुका है। लेकिन बीस फीसद जमीन का अधिग्रहण करने में जिला प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। तीस अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वह बीस फीसद जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया एक माह में पूरी कर कब्जा ले। यह समय सीमा तीस नवंबर को बीत गई। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील करते हुए मुआवजा उठाने व जमीन पर कब्जा देने का आह्वान किया था।

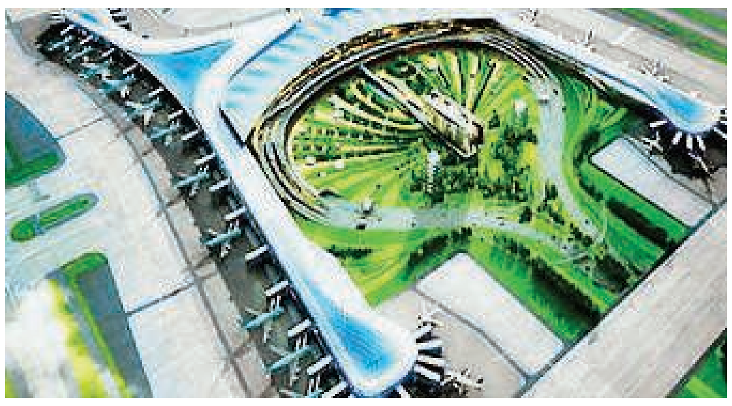

प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट का प्रारूप। फाइल

इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि किसानों ने अगर मुआवजा नहीं उठाया तो प्रशासन धनराशि को अधिकरण में जमा कराकर जमीन पर कब्जा ले लेगा लेकिन प्रशासन अभी तक ऐसा नहीं कर सका है। जबकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी नियाल व विकासकर्ता कंपनी के बीच कंसेशन एग्रीमेंट तक सौ फीसद जमीन पर कब्जा होना जरूरी है। एग्रीमेंट के दिन अगर विकासकर्ता कंपनी को सौ फीसद जमीन पर भौतिक कब्जा नहीं दिया जाता है तो उसे सिक्योरिटी मनी जो कि सौ करोड़ रुपये है, का प्रतिदिन के हिसाब से 0.1 फीसद कंपनी को भरपाई के रूप में देना होगा। इससे प्रदेश सरकार के खजाने पर भार पड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित 38 सौ परिवारों के पुनर्वास एवं व्यवस्थापन का असर भी जेवर एयरपोर्ट के निर्माण पर पड़ेगा। परिवारों के पुनर्वास के लिए जेवर बांगर में 48.097 हेक्टेयर का अधिग्रहण होना है। जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण के लिए गांव में बृहस्पतिवार को जन सुनवाई करेगा और ग्रामीणों की आपत्ति लेगा।

अब राजधानी के वकीलों के चैंबर में जलेगी 'घरेलू' बिजली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वकीलों को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली सरकार की तरफ से वकीलों को चैंबर के लिए घरेलू दर पर बिजली दी जाएगी। पहले यह व्यावसायिक रेट पर मिलती थी। साथ ही दो सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर फंड के 50 करोड़ रुपये की राशि किस प्रकार खर्च होगी इसका भी एलान किया।

वकीलों व उनके परिवार के लिए पांच लाख का मेडिक्लेम दिया जाएगा। वकील के लिए 10 लाख का जीवन बीमा होगा। महिला वकीलों के लिए क्रेच की सुविधा दी जाएगी। साथ ही अब वकीलों को दिल्ली के न्यायालयों में ई-लाईब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां वकीलों के लिए सरकार की तरफ से इतनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में वकीलों के जो चैंबर हैं, उनमें अभी तक बिजली की व्यावसायिक दर लगती थी। अब वकीलों के चैंबर में उपयोग की गई बिजली पर घरेलू दर लगेगी। घरेलू कनेक्शन में बिजली के 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है और 400 यूनिट तक आधा रेट लगता है। यह सभी फायदे अब वकीलों को भी अपने चैंबर में मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वकीलों की एक 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने जो चार मांगे रखी थीं वह मान ली गई हैं। कमेटी ने सभी छह जिला अदालतों में ई-लाइब्रेरी सुविधाओं को स्थापित करने की सिफारिश की थी। इसे भी मान लिया है।

54 फीसद आबादी युवा है भारत की, सरकार इसे अपनी शक्ति बनाना चाहती है। इसीलिए युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने इस संबंध में कई योजनाएं शुरू की हैं।

सबका प्रतिनिधित्व सच्चा प्रतिनिधित्व

लोकतंत्र का मतलब आम जनता का शासन। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। बीते सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस परिभाषा पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने के चलते जनप्रतिनिधि गैरसमानुपातिक हो गए हैं। सबके सही और समान प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा की सीट संख्या 543 से बढ़ाकर एक हजार की जानी चाहिए।

ऐसे तय हुई लोकसभा सीट संख्या

लोकसभा की वर्तमान सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। इस जनगणना में देश की आबादी 55 करोड़ थी। दस लाख की आबादी पर एक सीट की अवधारणा के चलते तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 तय की गई। 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब है कि 1971 की आबादी के दोगुने से भी अधिक। इस लिहाज से अब एक लोकसभा सदस्य पर 22.29 लाख लोगों का औसत बैठता है। इस अनुपात को कम किए जाने की दरकार है। तभी हम जनप्रतिनिधित्व की आदर्श कल्पना को साकार कर सकते हैं।

कहां कितना अनुपात

प्यू रिसर्च के अनुसार दुनिया के कई लोकतंत्रों में जनप्रतिनिधि और जनता का अनुपात इससे बहुत कम है।

1:7.47 लाख अमेरिकी प्रतिनिधि सभा

1: 2.72 लाख जापान

1: 1.64 लाख ऑस्ट्रेलिया

राज्यों पर असर

आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों को अगर बढ़ाया गया तो कई राज्यों में ये सीटें वर्तमान के मुकाबले कम तो कई राज्यों में अधिक हो जाएंगी। कार्नेगी इंडिया का एक विश्लेषण बताता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर अगर लोकसभा की सीटें तय की गईं तो दक्षिण के राज्यों में सीटें कम हो जाएंगी। तमिलनाडु में सात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संयुक्त रूप से पांच, केरल में पांच सीटें कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आठ, बिहार में छह और राजस्थान में पांच सीटों का इजाफा होगा। ऐसे में यह फैसला विवाद की वजह भी बन सकता है।

एक और विकल्प

ऐसे में प्रतिनिधित्व के अनुपात को सुधारने के लिए एक और विचार को कारगर माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार देश को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि इसमें सीट संख्या की बात नहीं होती, लेकिन मुख्य चिंता समानुपातिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की है। वर्तमान चुनावी प्रणाली के तहत किसी भी उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंद्वी से एक वोट अधिक मिलने पर विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दुनिया के कई आधुनिक लोकतंत्रों में समानुपातिक प्रणाली लागू है। जिसमें राजनीतिक दलों को चुनाव में मिले मतों के आधार पर संसद की सीटें बांटी जाती हैं।

नफा-नुकसान

समानुपातिक चुनावी प्रणाली का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इससे पूर्ण बहुमतवाद से बचा जा सकेगा। वहीं इसका विरोध करने वाले इससे अस्थिर गठबंधन को बढ़ावा मिलने की दलील देते हैं।

सहयोग बढ़ाने पर भारत-अमेरिका में अहम वार्ता

कूटनीति ▶ फॉगी बॉटम में रक्षा मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने समकक्षों के साथ की बैठक

2020 के लिए टू प्लस टू वार्ता में होंगे महत्वपूर्ण फैसले

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत और अमेरिका के बीत टू प्लस टू वार्ता बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्यालय फॉगी बॉटम में शुरू हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वार्ता में अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क एस्पर और माइक पोंपियो से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय यह दूसरी वार्षिक वार्ता है। पहली वार्ता नई दिल्ली में हुई थी।

वार्ता में चारों नेताओं के साथ दोनों देशों के उच्च अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं, जो आपसी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। दोनों देशों के मंत्री और अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस साल चार मुलाकातों में लिए फैसलों के अमल पर भी चर्चा कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने वर्ष 2020 के लिए सहयोग के बिंदु तय किए हैं। फॉगी बॉटम में संयुक्त वार्ता से पहले रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की अलग-अलग बैठक भी हुई।

इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन पहुंचने पर राजनाथ सिंह का स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ। यहां पर अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने राजनाथ के साथ हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा की। इसी दौरान नजदीक बह रही पोटोमैक नदी के पार बने विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में दोनों देशों के विदेश मंत्री आपसी हितों की चर्चा कर रहे थे।

वाशिंगटन में बुधवार को टू प्लस टू वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (दाएं तरफ, आगे से दूसरे) और विदेश मंत्री एस जयशंकर (दाएं तरफ, आगे से तीसरे) तथा अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर (बाएं तरफ, आगे से पहले) और विदेश मंत्री माइक पोंपियो (बाएं तरफ, आगे से दूसरे)। एपी

बोइंग ने भारत में विमान विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का किया प्रस्ताव

विमान निर्माता कंपनी ने नौसेना और वायुसेना की जरूरत के मद्देनजर भारत में जेट विमानों के विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। कंपनी ने कहा कि यदि भारत सरकार उसे विमानों की आपूर्ति करने का ठेका प्रदान करे तो वह भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित कर सकती है। कंपनी खास कर नौसेना के लिए विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने में सक्षम 57 मल्टी रोल लड़ाकू विमान (एमआरसीबीएफ) की खरीद की योजना पर निगाह रखे हुए है। बोइंग ने कहा है कि उसके एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत से उड़ान की दृष्टि से बहुत अनुकूल जेट होंगे।

राजनाथ ने अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का दौरा किया

वाशिंगटन, एएनआइ : भारत-अमेरिका की 2+2 वार्ता से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी नौसैनिक अड्डे का दौरा किया। नौरफोक नेवल बेस में उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक क्षमताओं का मुआयना किया। साथ ही बोइंग फाइटर जेट विमानों का भी कौशल देखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि निकट भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होंगे।

राजनाथ सिंह ने विगत मंगलवार को ट्वीट किया कि उन्होंने अमेरिका के ओशियाना में स्थित नौरफोक नौसैनिक वायु अड्डे को देखा और एफ/ए-18ई विमानों का प्रदर्शन भी देखा। इस नौसैनिक अड्डे पर उन्हें यूएए ड्वाइट डी. एसिनहोवर, निमित्ज क्लास वायुसैनिक बेड़ा भी देखने को मिला। हमने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को परिलक्षित होते देखा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विदेश मंत्री एस.जयशंकर, अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रंगला, रक्षा सचिव अजय कुमार और भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। सिंह के नौसैनिक वायु अड्डे के दौरे से स्पष्ट है कि भारत बहुत ही गंभीरता से भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए अमेरिकी युद्धक विमानों के विकल्पों पर विचार कर रहा है। एफ/ए-18ई विमानों के निर्माता बोइंग ने भारत को अपने युद्धक विमानों का ब्लॉक-3 देने की पेशकश की है। अमेरिकी नौसैनिक अधिकारियों ने बताया कि इसमें एडवांस विमानों के वहन की क्षमता तो है ही, इनकी कीमत भी कम है और प्रति फ्लाइट घंटे के हिसाब से इसके संचालन का खर्च भी कम है।

अल्पसंख्यकों के लिए भारत स्वर्ग व पाक नरक के समान

नई दिल्ली में बुधवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों से मिलते केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (मध्य में)। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर साफ किया है कि नागरिकता कानून में संशोधन से किसी भारतीय मुसलमान या अन्य नागरिक की नागरिकता पर खतरे का सवाल ही नहीं उठता है। नकवी ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए नरक और भारत को उनके लिए स्वर्ग बताया और इस कानून के बारे में देश में अफवाह फैलाने और लोगों को गुमराह करने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया।

विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए नकवी ने कहा कि 'सत्यमेव जयते' की जगह 'झूठमेव जयते' पर विश्वास करने वाले दुष्प्रचार से सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 'झूठमेव जयते' के राजनीतिक दुष्प्रचार का पर्दाफाश करने में 'सत्यमेव जयते' एक दिन सफल होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक अखाड़े में बुरी तरह पराजित हुए हैं, वे अराजकता फैलाकर देश में भरोसे और भाईचारे का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लोकतंत्र की ताकत के सहारे ऐसे तत्वों को मात देनी होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बताया कि भारत में अल्पसंख्यक विकास की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को जोड़कर भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों की साजिश का पर्दाफाश करना होगा। उनके अनुसार, नागरिकता संशोधन कानून अमानवीय प्रताड़ना झेलने वालों को मानवीय सम्मान देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि संविधान के अलावा भारत में बहुसंख्यक समाज के डीएनए में मौजूद धर्मनिरपेक्षता व सौहार्द यहां अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मान, संवृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करता है और यही भारत की विविधता में एकता की शक्ति है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ विभाग पर बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने की मुहिम, स्वास्थ्य बीमा से आधे प्रीमियम से चलेगा काम

रेलवे के बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने की मुहिम के तहत रेलवे की स्वास्थ्य सेवाएं इंश्योरेंस के जरिए निजी अस्पतालों में हो सकती है। हाल ही में संपन्न रेलवे की परिवर्तन संगोष्ठी में रेल कर्मचारियों के निजी अस्पतालों में इलाज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति और इस कारण रेलवे पर बढ़ते वित्तीय दबाव को लेकर चिंता जताई गई।

अधिकारियों की ओर से सुझाव आया कि बीमा सूची में सम्मिलित अस्पतालों में इलाज कराने के कारण रेलवे को सालाना हजार-डेढ़ हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी पड़ती है। यदि यही इलाज हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए कराया जाए तो आधे प्रीमियम से काम चल सकता है। इसलिए अस्पतालों की सूची समाप्त कर कर्मचारी का हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए और रेलवे को उसका प्रीमियम भरना चाहिए। इससे खर्च तो घटेगा ही, कर्मचारियों को भी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की ज्यादा आजादी मिलेगी। अभी रेलवे में सभी जोन तथा उत्पादन इकाइयां अपने-अपने इलाकों के चुनिंदा निजी अस्पतालों तथा डायग्नास्टिक सेंटरों को सूचीबद्ध (एंपैनल) कर उनके साथ सीजीएचएस, ईसीएचएस अथवा ईएसआइ रेट पर इलाज की सुविधा देने के लिए समझौता करते हैं। पूरे देश में सभी जोनों व उत्पादन इकाइयों ने दो सौ से ज्यादा अस्पताल एंपैनल कर रखे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों से जुड़े जोनों में एंपैनल्ड अस्पतालों व डायग्नॉस्टिक केंद्रों की संख्या सबसे ज्यादा है।

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रतिभागियों को 50 फीसद छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र : 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के चयनित प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल तक आने जाने के लिए रेलवे बेसिक किराये पर 50 फीसद रियायत प्रदान करेगा। हालांकि, यह छूट उन्हीं युवा प्रतिभागियों को मिलेगी, जिनकी मासिक आमदनी पांच हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह रियायत विशेष प्रावधान के तहत ट्रेनों की सामान्य सेवा के लिए प्रदान की गई है, जो सेकेंड या स्लीपर श्रेणी के टिकट के बेसिक किराये पर लागू होगी। विशेष ट्रेनों या कोचों में यह सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही यह छूट सिर्फ उन्हीं प्रतिभागियों को मिलेगी, जिनके निवास स्थान से कार्यक्रम स्थल 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर होगा। छूट पाने के लिए अभ्यर्थी को रेलवे के तय प्रारूप पर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक या प्रभागीय वाणिज्य प्रबंधक को आवेदन करना होगा। आवेदन पर संबंधित राज्यों के मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव की संस्तुति जरूरी है। हालांकि, रियायत उन अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगी, जिनके आने-जाने की व्यवस्था केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राजकीयकृत विश्वविद्यालयों की तरफ से की गई हो। ज्ञात हो, रेलवे की दशा और दिशा सुधारने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है

कब क्या हुआ?

प्रथम पृष्ठ से आगे

24 अक्टूबर, 2016 : सायरस मिस्त्री को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाया गया। रतन टाटा अंतरिम चेयरमैन बने।

20 दिसंबर, 2016 : मिस्त्री परिवार की दो कंपनियों, सायरस इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा सन्स के बोर्ड के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी, मुंबई का दरवाजा खटखटाया।

12 जनवरी, 2017 : टाटा सन्स ने टीसीएस के तत्कालीन सीईओ एवं एमडी एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का चेयरमैन बनाया।

06 फरवरी, 2017 : मिस्त्री को टाटा संस के निदेशक मंडल से भी हटा दिया गया।

17 अप्रैल, 2017 : एनसीएलटी मुंबई ने मिस्त्री परिवार की दोनों इंवेस्टमेंट कंपनियों की अपील खारिज की।

27 अप्रैल, 2017 : दोनों कंपनियों ने एनसीएलटी की तरफ से अपील खारिज किए जाने को एनसीएलएटी (एनक्लैट) में चुनौती दी।

21 सितंबर, 2017 : एनक्लैट ने दोनों निवेश कंपनियों की अपील स्वीकार की, लेकिन मिस्त्री की अन्य याचिकाएं खारिज कर दीं।

29 अगस्त, 2019 : एनक्लैट ने मिस्त्री की तरफ से निजी क्षमता पर दायर याचिका स्वीकार कर ली और इसकी सुनवाई दो इंवेस्टमेंट कंपनियों की मुख्य याचिकाओं के साथ करने का फैसला किया।

18 दिसंबर, 2019 : एनक्लैट ने मिस्त्री को वापस टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बनाने का आदेश दिया।

स्कूली बच्चों को मिड डे मील ही नहीं नाश्ता भी मुहैया कराएगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बजट में किया शामिल

▶ नई शिक्षा नीति के फाइनल ड्राफ्ट में भी दी गई जगह, स्वयंसेवी संस्थाओं को दी जाएगी जिम्मेदारी

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब दोपहर के भोजन के साथ सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बजट में प्रस्ताव के साथ-साथ इसे नई शिक्षा नीति के फाइनल ड्राफ्ट में भी प्रमुखता से रखा गया है। दूसरी तरफ, स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाने का काम शिक्षकों की जगह पूरी तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, कई राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम को कर भी रही हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आने वाले बजट में इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बच्चों को नाश्ते में क्या दिया जा सकता है, इसे लेकर भी राज्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं। स्कूली बच्चों को नाश्ता देने का प्रस्ताव इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे बिना नाश्ता किए पढ़ने चले आते हैं। इस प्रकार वे मिड डे मील मिलने तक भूखे रह जाते हैं।

दूसरी तरफ, स्कूलों में खाना बनाने का काम शिक्षकों से छीनकर गैरसरकारी या स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, क्योंकि मिड डे मील की जिम्मेदारी होने के कारण शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में स्कूलों का लर्निंग आउटकम (सीखने का स्तर) लगातार बिगड़ रहा है। यही वजह है कि सरकार अब शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के काम में लगाए रखना चाहती है।

प्रतीकात्मक

मिड डे मील को लेकर सरकार के स्तर पर यह सारी कवायद ऐसे समय में की जा रही है, जब खाने की गुणवत्ता को लेकर आयेदिन शिकायतें आती रहती हैं। हालांकि, इसकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें सामाजिक भागीदारी से जुड़े प्रयास भी शामिल हैं। इसके तहत एक समिति गठित की गई है, जिसमें गांव के प्रबुद्ध लोगों के साथ अभिभावकों को भी रखा गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर 18 विवि ने एमईएससी के साथ किया समझौता

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन कॉलेजों सहित 18 कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों ने बुधवार को मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल परिषद (एमईएससी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत गेमिंग, एनिमेशन, फिल्म निर्माण एवं विजुअल आर्ट्स जैसे स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे। एमईएससी इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को एक समारोह में कहा, 'कौशल शिक्षा किसी भी देश के विकास की धुरी है जिससे कुशल युवा कार्यबल तैयार करने में मदद मिली है। यह वक्त की जरूरत है। भारत की युवाओं की आबादी इसकी बहुमूल्य संपत्ति है। कुल आबादी में 54 फीसद युवा हैं।' पोखरियाल एचआरडी मंत्रालय और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मंथन इंपेकेबल एकेडमिया को संबोधित कर रहे थे।

रमेश पोखरियाल निशंक। फाइल

1993 बम धमाकों के दोषी भुल्लर की सजा माफी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली, एएनआइ : 1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की उम्रकैद की सजा माफ करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस एस. रविंद्र भट की पीठ ने युवक कांग्रेस के पूर्व नेता मनिंदर सिंह बिट्टा की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बिट्टा ने अपनी याचिका में भुल्लर की सजा माफ किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। इसका मतलब था कि उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी थी और सरकार उसकी सजा में कमी नहीं कर सकती थी। उल्लेखनीय है कि 2001 में टाडा अदालत ने भुल्लर को मौत की सजा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका और राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद भुल्लर की पत्नी ने उसकी बीमारी और सरकार की ओर से उसकी दया याचिका पर फैसले में देरी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी, लिहाजा 2014 में शीर्ष अदालत ने उसकी मौत का सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

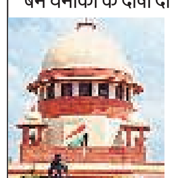

सुप्रीम कोर्ट फाइल

सबको आवास

गरीबों का बसेरा बनाने वालों को पुरस्कृत करेगी सरकार

ब्लाक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे ग्राम प्रधान व सचिव

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए मकान बनाने वाली योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिवों (ग्राम सेवक) को सरकार सम्मानित करेगी। गरीबों का बसेरा बनाने वालों को सरकार ब्लाक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नवाजेगी। इसके लिए लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा को चुना गया है, जहां के मुखिया के साथ वहां निचले स्तर पर कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी को पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है।

हर परिवार के सिर पर छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कुल 2.95 करोड़ आवास बनाए जाने हैं। वर्ष 2016 से लेकर 2022 तक 'सबको आवास' देने का निश्चय परवान चढ़ने लगा है इसके पहले चरण में प्रस्तावित एक करोड़ आवास बनाए जाने थे, जो लगभग पूरे हो चुके हैं। योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जो वर्ष 2021-22 तक चलेगा। इस दौरान कुल 1.95 करोड़ आवास बनाए जाने हैं।

गरीबों के आवास बनाने की योजना को रफ्तार देने के लिए सरकार ने ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिवों अथवा आवास सहायकों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। इसके तहत मुखिया, सरपंच अथवा ग्राम प्रधानों का चयन कर लिया गया है। चयन की प्रक्रिया भी निचले स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। प्रत्येक ब्लाक से दो ग्राम प्रधान और दो ग्राम सचिव चुने गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ब्लाक स्तरीय चयनित नामों की जिला स्तर की प्रतिस्पर्धा में नामित किया गया जिसमें से दो नाम चुने गए। इसके बाद प्रदेश स्तर पर जिलों से पहुंचे नामों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में भी दो नाम ही चुने गये हैं। यानी प्रत्येक राज्य से दो नाम राष्ट्रीय स्तर पर भेजे गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 62 चुनिंदा लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश, जिला और ब्लाक स्तर पर चुने गए बाकी लोगों भी पुरस्कृत किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधानों के चयन की यह प्रक्रिया केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुझाया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगले तीन सालों में लगभग दो करोड़ ग्रामीण गरीबों के आवास बनाए जाने हैं, जो एक बड़ा अभियान होगा। इसमें ग्राम प्रधानों और सचिवों की अहम भूमिका को देखते हुए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया गया है।

गरीबों की आवासीय योजना में सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर लाभार्थियों के नामों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में नए नामों को जोड़ना संभव नहीं है, जबकि नामों को सूची से हटाया जा सकता है। देश के विभिन्न राज्यों में 14 लाख से अधिक ऐसे लाभार्थी भी हैं, जो भूमिहीन हैं। उनके लिए जमीन का बंदोबस्त करना राज्यों का दायित्व है। उसके लिए राज्यों से लगातार आग्रह किया जा रहा है।

योजना में आवास बनाने का दायित्व लाभार्थी को सौंप दिया गया है। जबकि सरकारी तौर पर उसके खाते में तीन किस्तों में पैसा जमा कराया जा रहा है। पहली किस्त नींव, दूसरी किस्त दीवार बनाने और तीसरी किस्त छत की ढलाई के समय दिया जाता है। निर्माण के हर स्टेज का फोटो ग्राम प्रधान और ग्राम सचिवों को ऑन लाइन भेजना पड़ता है। डिजिटल निगरानी की प्रणाली से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है।

2.95 करोड़ आवास बनाये जाने हैं देश में पीएमजीएवाई के तहत

01 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं योजना के पहले चरण में

1.95 करोड़ लोगों को पक्की छत मिल जाएगी 2022 तक

प्रतीकात्मक फोटो

कह के रहेंगे

माधव जोशी

81 विधानसभा सीटों में 65 में मतदान संपन्न हो गया है झारखंड में। इन 65 सीटों में 26 सीटों पर महिलाएं वोट करने में पुरुषों से आगे रही हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 19 दिसंबर 2019

चुनावी रण ▸ झारखंड की अपनी पहली और आखिरी चुनावी सभा में जमकर बरसीं कांग्रेस महासचिव

प्रियंका की चुनौती, देश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों पर बोलें पीएम

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

कहा, प्रधानमंत्री कांग्रेस का नाम ले लेकर बहाने बनाते हैं

अश्विनी रघुवंशी, पाकुड़

झारखंड के पाकुड़ जिले के बरहड़वा में बुधवार को आयोजित चुनावी सभा में लोगों का अभिभावदन स्वीकार करतीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। जागरण

झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस साहिबगंज में कांग्रेस को ललकारा था, उसी धरती से ठीक चौबीस घंटे के भीतर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि देश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों पर जवाब दें। वह बोलीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक ने बच्ची के साथ गलत काम किया। फिर भी विधायक मजे में थे। लोगों ने दबाव बनाया तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। दुखद है, ऐसा काम करने वाले झारखंड के एक और भाजपा विधायक (नाम नहीं लिया) के साथ प्रधानमंत्री ने मंच पर आकर प्रचार किया।

राज्य विधानसभा चुनाव में बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा की अपनी पहली और अंतिम सभा हुई। चुनाव प्रचार की समाप्ति के ठीक एक घंटा पहले, प्रियंका ने कहा, 'प्रधानमंत्री हमें चुनौती देते हैं। एसपीटी एक्ट में बदलाव की भाजपा की सोच पर बोलिए, भूख से लोगों की मौत पर जवाब दीजिए, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार पर झारखंड की जनता को सच बताइए, महिला सुरक्षा पर बोलिए। नरेंद्र मोदी जवाब दें कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं या बंटवारे के पीएम।' उन्होंने कहा, 'फेल होने वाला बच्चा पाठशाला में बहाने बनाता है। मोदी जी भी कांग्रेस का नाम ले लेकर बहाने बनाते रहते हैं। बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था, तबाह किसान, त्राहिमाम कर रहे छात्र, बढ़ती महंगाई, छोटे दुकानदारों की परेशानी, भोजन एवं पानी तक नहीं मिलने की बात उठती है तो मोदी जी का एक ही बहाना है, कांग्रेस। मोदी जी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, पांच साल सरकार चला चुके हैं, अब कोई बहाना नहीं बना सकते। वास्तव में भाजपा के लोग प्रचार में सुपर हीरो हैं, काम में जीरो।'

बदहाल अर्थव्यवस्था पर आवाज उठी तो देश को बांट दिया : प्रियंका ने कहा कि देश की बदहाल होती अर्थव्यवस्था पर आवाज उठने लगी तो तुरंत देश को बांटने का काम किया गया। 1600 करोड़ रुपये खर्च कर असम में एनआरसी कराया गया। रजिस्टर में लाखों भारतीयों का नाम नहीं आया तो नागरिकता संशोधित कानून बना दिया।

गेरुवा पहन बहू बेटियों की लूट लेते हैं इज्जत : हेमंत

यूपीए की ओर से मुख्यमंत्री के पद के लिए पेश किए गए हेमंत सोरेन ने इस सभा में विवादित बयान दे दिया। राहुल गांधी ने रेप इन इंडिया की बात कही थी। प्रियंका ने बढ़ते दुष्कर्म पर नरेंद्र मोदी को जवाब देने की चुनौती दी तो हेमंत सोरेन बोले, 'यहां गेरुवा पहन बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है।' उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उसे सबने देखा है। इज्जत लूटने वाला अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं तो अस्मत गंवाने वाली बेटी को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि गो तस्करी के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है। भाजपा का भगवान राम के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम ने समाज को जोड़ा था। ये लोग समाज को तोड़ते हैं। सिर्फ अपने लाभ के लिए श्रीराम का नाम लेते हैं।

अंतिम चरण का भी चुनाव प्रचार समाप्त

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का चुनाव प्रचार भी बुधवार को समाप्त हो गया। पांचवें और अंतिम चरण की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इसी के साथ प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस की प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गजों ने अंतिम दिन अपने-अपने दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कीं। अंतिम दौर की सीटों में 11 सीटों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इनमें राजमहल, पाकुड़, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, सारठ, पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महगामा शामिल हैं। सुरक्षा कारणों से शेष पांच सीटों बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर तथा शिकारीपाड़ा में सुबह सात बजे से शाम तीन बजे तक ही मतदान होगा।

छह जिलों में स्थित हैं सभी 16 सीटें : अंतिम दौर की सभी 16 सीटें छह जिलों में स्थित हैं। साहिबगंज जिले में राजमहल, बोरियो व बरहेट, पाकुड़ जिले में लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ व महेशपुर, जामताड़ा जिले में नाला व जामताड़ा, दुमका जिले में शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा व जरमुंडी, देवघर जिले में सारठ तथा गोड्डा जिले में पोड़ैयाहाट, गोड्डा व महगामा शामिल हैं। इन सीटों में सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि नौ सीटें सामान्य श्रेणी की हैं।

'मोदी सरकार के कामकाज से बौखलाए विपक्षी फैला रहे भ्रम'

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में विधिपूर्वक पूजा-अर्चना की। इस दौरान जेपी नड्डा के माथे पर तिलक लगाते पुजारी। इसके बाद नड्डा ने देवघर के चितरा स्टेडियम में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित किया। जागरण

जागरण संवाददाता, देवघर/दुमका

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को झारखंड के देवघर के चितरा स्टेडियम में चुनावी सभा की। कहा कि मोदी सरकार के कामकाज से विपक्षी बौखला गए हैं। वे भ्रम फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से ही राज्य का कायाकल्प हो सकता है। मोदी की चर्चा करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। अल्पसंख्यक महिलाओं के हक व सम्मान की खातिर तीन तलाक को खत्म किया। नागरिकता संशोधन कानून बनाकर शरणार्थियों को नागरिक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस, झामुमो, राजद व अन्य पार्टियों का गठबंधन लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि इस सरकार के शासनकाल में जो काम अधूरे रह गए हैं, नई सरकार पूरा करेगी। डबल इंजन वाली सरकार से विकास को काफी गति मिलेगी।

दुमका के काठीकुंड में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि शिकारीपाड़ा में युवा नेता परितोष को मौका दें। यहां जिसे पहले चुना, वह तो बूढ़ा हो गया है। जान लें कि गंदा पानी एक जगह रहने से वह और गंदा होता है। साफ पानी दीजिए। भाजपा का युवा नेता काम करेगा। यहां सांसद सुनील सोरेन ने भी सभा को संबोधित किया।

भोपाल के माखनलाल विवि से 23 छात्र निष्कासित विधानसभा में हंगामा

नईदुनिया, भोपाल

▸ दो प्रोफेसरों के विवादित ट्वीट से शुरू हुआ बवाल, 25 छात्रों पर केस
▸ राज्य विस में विपक्षी दल भाजपा ने की कार्रवाई वापस लेने की मांग

भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों के विवादित ट्वीट के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अब सियासी रंग ले चुका है। विवि ने प्रदर्शनकारी 23 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। इस मामले में 25 छात्रों के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई गई है। बुधवार को यह मामला भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के शून्यकाल में उठाया और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई निरस्त करने की मांग की। सरकार ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अनुबंधित प्रोफेसर दिलीप मंडल और मुकेश कुमार ने समाज विशेष को लेकर लगातार कई विवादित ट्वीट किए थे। इससे नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया था। इसे लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति दीपक तिवारी ने पहले तो पुलिस बुला ली थी और इसके बाद उन पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज करा दिया था। इस दौरान छात्रों की पुलिस ने जमकर लात-घूसों से पिटाई भी की थी। मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने घटना के दिन के विश्वविद्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे थे। इसके आधार पर 23 छात्रों को चिह्नित किया था। जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट दस सदस्यीय अनुशासन कमेटी को रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर ही 23 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था।

पूर्व सीएम का आरोप-छात्रों पर लाठियां बरसाईं : पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विस में आरोप लगाया कि छात्रों ने सबसे पहले ज्ञापन दिया था और मांग पूरी नहीं होने पर धरना दिया। उनका धरना शांतिपूर्ण था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाईं और सीढ़ियों से घसीटकर नीचे फेंका। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों को भोपाल शहर से 20 किलोमीटर दूर बिलखिरया थाना ले जाया गया। अपनी मांगों पर आंदोलन करने वाले 25 छात्रों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करा दी गई और 23 छात्रों को बाद में निष्कासित भी कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मुद्दे पर छात्रों का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि माखनलाल विवि के शिक्षण विभाग में कुछ लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

अब शिवराज-प्रज्ञा पर ट्वीट : पत्रकारिता विवि के अनुबंधित प्रो. दिलीप मंडल और मुकेश कुमार ने पहले समाज विशेष को लेकर विवादित ट्वीट किए थे। उसे लेकर मचे बवाल के बीच ही मंडल ने अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा छात्रों का साथ देने पर कटाक्ष किया।

सरकार को छात्रों के हित की चिंता : गोविंद सिंह

विस में मौजूद संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि छात्रों के हितों की सरकार को भी चिंता है। वे भी छात्र राजनीति से ही राजनीति में आए हैं। विवि से घटना की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

पहले छात्र लिखित में माफी मांगें : विवि

विवि प्रशासन के निर्णय के विरोध में बुधवार को पूर्व छात्रों, अभाविप, करणी सेना समेत कई संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों पर की गई एफआइआर और निष्कासन की कार्रवाई वापस लेने की मांग करते हुए रैक्टर श्रीकांत सिंह से मुलाकात की। रैक्टर ने कहा कि जब तक छात्र लिखित में माफी नहीं मांगेंगे तब तक कार्रवाई वापस नहीं ली जाएगी।

मप्र में कुलपति चयन में अब राज्य सरकार का होगा दखल

नईदुनिया, भोपाल

▸ भाजपा ने कहा, यह कुलाधिपति के अधिकारों में कटौती

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन में अब राज्य सरकार का भी दखल होगा। चयन समिति में सरकार का प्रतिनिधि रखना अनिवार्य हो गया है। मप्र विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 में यह प्रावधान किया गया है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच यह विधेयक पारित हो गया।

विधेयक पर चर्चा करते हुए विधायक विश्वास सारंग ने इस संशोधन को राज्यपाल (कुलाधिपति) के अधिकारों में कटौती बताया। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या विवि इंदौर के कुलपति की नियुक्ति को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की जिद के कारण संशोधन हो रहा है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस पर मंत्री पटवारी ने विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाने को लेकर राज्यपाल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल के अधिकारों में कटौती नहीं की जा रही है। इससे हम चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवि के संचालन और कमियों के लिए सरकार जिम्मेदार है, तो सरकार का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है। आपने किया, अब आप ही काट रहे हैं। शिवराज ने कहा कि मंत्री कुतर्क से विषय बदल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि हम डिवीजन की मांग नहीं कर रहे, लेकिन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना चाहिए। इस पर अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कहा कि एक विधेयक के बारे में मैंने चर्चा की है, जिसे फिर से बुलाया गया है। आप चाहें तो उसका अवलोकन कर लें। जो राज्यपाल जी का आदर-सम्मान होना चाहिए, वह हम कर रहे हैं। वह शीघ्र ही आ रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इसे हठधर्मिता बताया और विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। सरकार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगी। बुधवार को विपक्ष की नाराजगी के बीच विधानसभा में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 भी पारित हो गया। इस विधेयक पर भी विपक्ष फिर से विचार करने को कह रहा था।

मंत्री-विधायक देंगे संपत्ति का ब्योरा

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक अपनी और अपने आश्रितों की संपत्ति का ब्योरा हर साल विधानसभा में देंगे। इस आशय का संकल्प विधानसभा में बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। भाजपा ने इस दायरे में आइएएस-आइपीएस और दूसरे वर्गों के अधिकारियों को भी लेने की मांग की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने प्रदेश के सभी विधायकों व उनके परिवार के आश्रितों की संपत्ति का ब्योरा हर साल विधानसभा में देने संबंधी संकल्प प्रस्तुत किया। इसमें प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सभी सदस्य अपनी तथा उनके परिवार के आश्रितों का हर साल 31 मार्च की स्थिति में अपनी आस्तियों व दायित्वों (संपत्ति व देनदारियों) का विवरण 30 जून तक विधानसभा के प्रमुख सचिव को दे देंगे। इसके आधार पर विधानसभा की वेबसाइट पर विधायकों व उनके आश्रितों की संपत्ति व देनदारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि यह इसलिए लाया गया है क्योंकि आम जनता आरोप लगाती है कि विधायक के पास चुनाव के पहले टूटी साइकिल थी और आज देखो क्या स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इसे बिना दांत और नाखून वाला संकल्प बताते हुए कहा कि जब तक इसमें दंड का प्रावधान कर कानून का रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भाजपा के समय में कोनार डैम को कुतर गए चूहे : ओवैसी

जागरण संवाददाता, गोड्डा : 'भाजपा के पांच साल के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उलटे 2200 करोड़ रुपये खर्च कर बनाए गए कोनार डैम के बांध को चूहों ने कुतर डाला। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की रघुवर सरकार के विकास का पैमाना क्या रहा होगा।' ये बातें बुधवार को झारखंड के महगामा विधानसभा क्षेत्र के श्रीमतपुर मेला मैदान में एआइएमआइएम के प्रमुख व हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि ये रुपये पीएम और सीएम के थे क्या, ये रुपये गरीब आवाम के थे। ओवैसी ने कहा कि ठंड से बचने के लिए गरीबों को दिए जाने वाले कंबल को भी भाजपा सरकार ने नहीं छोड़ा। यहां भी घोटाला कर नया रिकार्ड कायम किया। आज लोगों को शुद्ध पेयजल मयस्सर नहीं हो पा रहा है, दलितों बस्तियों में खुले स्कूल बंद करा दिए गए हैं।

भाजपा हमें दे सात-आठ सीटें काटेंगे बसपा का वोट : आठवले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ केंद्रीय मंत्री व आरपीआइ अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी को दिया प्रस्ताव
▸ बोले, महाराष्ट्र में आने वाला है सियासी भूकंप, भाजपा बनाएगी सरकार

रामदास आठवले फाइल

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआइ) उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पैर जमाने के प्रयास में है। पार्टी अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रस्ताव दिया है कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें सात-आठ सीटें दे तो वह बसपा का वोट काटेंगे। वह बुधवार को राजधानी लखनऊ में थे।

एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य : वीवीआइपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में आठवले ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्होंने विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें मांगी हैं। उन्होंने बताया कि आरपीआइ के प्रदेश अध्यक्ष महराजगंज के पवन गुप्ता बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य एक करोड़ सदस्य बनाने का है, जो अभी मात्र 25 लाख हैं। उन्होंने कानपुर के आशीष पांडेय को रिपब्लिकन मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित किया।

जल्द होगा ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि ओबीसी के 27 फीसद कोटे का पिछड़ा, अति पिछड़ा के आधार पर वर्गीकरण जल्द होगा। मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। गौरतलब है कि पिछड़ों में अति पिछड़ों को आरक्षण की मांग लंबे समय से उठ रही है।

ओपी चौटाला की रिहाई पर फिर सुनवाई करे सरकार : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ चौटाला की याचिका पर दिल्ली सरकार के फैसले को किया रद
▸ केंद्र की अधिसूचना का हवाला देकर पूर्व सीएम मांग रहे रिहाई

ओमप्रकाश चौटाला फाइल

शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की चुनौती याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने जल्द रिहाई के आवेदन को खारिज करने के दिल्ली सरकार के फैसले को रद करते हुए निर्देश दिया कि चौटाला की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे। ओपी चौटाला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उम्र और दिव्यांगता के आधार पर रिहाई की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अधिवक्ता अमित साहनी के माध्यम से दायर याचिका में ओपी चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के हवाले से दलील दी थी। अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसद दिव्यांग अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार रिहाई पर विचार कर सकती है। याचिका में चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 83 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं। याचिका में चौटाला ने कहा था कि वह अप्रैल 2013 में 60 फीसद दिव्यांग हो चुके थे और जून 2013 में पेसमेकर लगाए जाने के बाद से वह 70 फीसद से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं। इस तरह से वे जल्दी रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। इसे देखते हुए उन्हें रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए दिल्ली सरकार ने सुनवाई में कहा था कि क्योंकि यह भ्रष्टाचार का मामला है और भारत सरकार की जिस अधिसूचना के तहत चौटाला राहत की मांग कर रहे हैं वह इस पर लागू नहीं होता। चौटाला के अधिवक्ता अमित साहनी ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को अधिसूचना का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी सात साल की सजा पूरी हो चुकी है। ऐसे में समयपूर्व रिहाई करने की मांग को दिल्ली सरकार द्वारा खारिज करना न्यायसंगत नहीं है।

वर्ष 2000 के 3206 शिक्षक भर्ती मामले में विशेष सीबीआइ अदालत ने वर्ष 2013 में ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत 53 लोगों के खिलाफ सजा सुनाई थी। इसमें तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा के निदेशक आइएएस अधिकारी संजीव कुमार भी शामिल थे।

राजनीति का अखाड़ा न बनें लोकतंत्र के मंदिर : बिरला

रखी बात

विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू, लोस अध्यक्ष ने किया उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, देहरादून

देहरादून में बुधवार को देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का उद्घाटन करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (मध्य में), उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (दाएं) और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल (बाएं)। जागरण

देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 79 वां दो दिवसीय सम्मेलन बुधवार से देहरादून में शुरू हो गया। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदनों के सुचारू संचालन पर जोर देते हुए कहा कि सभा में वाद-विवाद, सहमति-असहमति और चर्चा हो, लेकिन इसमें गतिरोध नहीं होना चाहिए। विरोध में भी गतिरोध न हो, यही विधायिका की मर्यादा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी। उन्होंने कहा कि विधायी निकाय लोगों की आकांक्षाओं व आस्था के मंदिर हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन संस्थाओं में जनता के विश्वास को सुदृढ़ कर इसे मजबूत बनाया जाए। लिहाजा, लोकतंत्र के इन मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा न बनने दें।

सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की मजबूती की दृष्टि से यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों को एक मंच प्रदान करता है। देश में मतदान का बढ़ता प्रतिशत ये बयां करता है कि लोकतंत्र के मंदिरों के प्रति जनता का विश्वास दृढ़ हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह प्रयास हो कि सबके सहयोग से सदन ज्यादा से ज्यादा चलें। हर परिस्थिति में संसदीय मर्यादा और प्रतिष्ठा को ऊंचाई तक ले जाएं। इस क्रम में उन्होंने लोकसभा सत्रों का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि जनहित से जुड़े विषयों को सरकार तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे में शून्यकाल का महत्व बढ़ गया है।

पारदर्शिता पर दिया जोर

लोस अध्यक्ष ने विधानमंडलों में पेपरलेस व्यवस्था, संसदीय समितियों की मजबूती व पारदर्शिता पर भी जोर दिया। कहा कि इस सम्मेलन के परिणाम भी आएंगे। तीन समितियों की रिपोर्ट सम्मेलन में रखी जाएगी, जिन पर जनवरी में लखनऊ में मंथन होगा। मार्च तक इनकी सिफारिशों को विधानमंडलों में लागू करने का प्रयास होगा।

सपा सांसद आजम खां के खिलाफ कुर्की का नोटिस

जागरण संवाददाता, रामपुर

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अदालत में हाजिर न होने पर सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में इन तीनों के खिलाफ अपर जिला जज छह की अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। इस मामले में अदालत ने पहले दो बार गैर जमानती वारंट भी जारी किए। इसके बाद भी ये लोग अदालत में हाजिर नहीं हुए।

बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई की। मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना कोर्ट में पेश हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से तीनों आरोपितों के कुर्की वारंट जारी किए जाने का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने तीनों के खिलाफ कुर्की के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए। अब धारा 82 के तहत नोटिस जारी होगा, जो इनके घर पर चस्पा होगा, जिसमें चेतावनी दी जाएगी कि अगर वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कुर्की की जाएगी। अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 जनवरी लगी है।

क्या है मामला : भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसी साल तीन जनवरी को यह मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए हैं। एक प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से और दूसरा लखनऊ के अस्पताल से जारी किया गया। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आजम और डॉ. तजीन फात्मा पर झूठा शपथ पत्र देने का आरोप लगाया। इस मामले में कोर्ट ने पहले तीनों के वारंट और फिर गैर जमानती वारंट जारी किए। हाजिर न होने पर अब कुर्की के लिए नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

14 घंटे की ढील दी गई मेघालय की राजधानी शिलांग में बुधवार को कर्फ्यू में। हालांकि, मोबाइल और इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहा। राज्य को इनर लाइन परमिट के तहत लाने के लिए गुरुवार को विधानसभा के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

हिंसा के पीछे शामिल तत्वों पर सख्त हुई असम सरकार

संजय मिश्र, गुवाहाटी

- अमीनुल हक समेत पीएफआइ के दो लोग गिरफ्तार
- एनआइए व केंद्रीय एजेंसियों की मदद से उपद्रवियों की हो रही शिनाख्त

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध की आड़ में सूबे में हुई हिंसा को परदे के पीछे से संचालित करने वालों के खिलाफ असम सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस क्रम में विवादास्पद संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के असम प्रमुख अमीनुल हक समेत कुछ दूसरे लोगों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि सख्ती के बावजूद सूबे में आंदोलन पूरी तरह थम नहीं रहा, हालांकि यह शांतिपूर्ण है। असम सरकार के कर्मचारियों ने भी बुधवार को एक दिन के लिए कामकाज का बहिष्कार कर आंदोलन को अपना समर्थन दिया।

सीएए को लेकर चल रहे विरोध की संवेदनशीलता के बीच असम पुलिस लगातार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और कुछ दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर 11-12 दिसंबर की रात को गुवाहाटी समेत दूसरे जिलों में हुई हिंसा में शामिल लोगों की शिनाख्त कर रही है। इसी आधार पर अब तक 280 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पीएफआइ के दो लोगों-अमीनुल हक और मुमाजिल की बुधवार को कामरूप जिले से हुई गिरफ्तारी पुलिस की विशेष जांच टीम के लिए बड़ी अहम मानी जा रही है। पीएफआइ को गुवाहाटी में जनता भवन (राज्य सचिवालय) के सामने हुई भारी हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।

गुवाहाटी में बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करते लोग। प्रेट्र

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने इसके पीछे पीएफआइ की साजिश होने का खुलकर आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन की आड़ में सचिवालय को जलाने का षड्यंत्र था। असम पुलिस एनआइए व दूसरी एजेंसियों की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सुबूतों व वीडियो फुटेज का अध्ययन कर हिंसा में शामिल उपद्रवी तत्वों की शिनाख्त और गिरफ्तारी कर रही है। साथ ही इसके पीछे राजनीतिक समर्थन के तार ढूंढ़े जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से सचिवालय पर हमले में वामपंथी शहरी नक्सलियों और इस विचार से जुड़े एक बड़े शिक्षाविद के शामिल होने की बात भी कही गई है। हेमंत बिस्व सरमा के अनुसार वीडियो सुबूत असम के युवक कांग्रेस अध्यक्ष कमरुल इस्लाम चौधरी की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता काजी तन्वी तंजुम को सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हुए देखा गया है। इसी संदेह में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि असम में नेता विपक्ष देवब्रत सैकिया ने राज्य सरकार के दावों को फिर खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश के तहत भाजपा ये झूठा प्रचार कर रही है। वैसे नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन के शुरुआती दिनों को छोड़ दें तो पूरे असम में अब विरोध शांतिपूर्ण चल रहा है और इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। 'आसू' के तीन दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के आखिरी दिन पूरे सूबे में बड़ी संख्या में लोगों ने गिरफ्तारी दी। गुवाहाटी विश्वविद्यालय कैंपस में बुधवार को बड़े विरोध प्रदर्शन में सूबे के साथ विवि के छात्रों व प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें सीएए को असम की भाषा-संस्कृति के खिलाफ बताते हुए संगठित आंदोलन के लिए सूबे के सभी छात्रों का एक समूह बनाने का फैसला लिया गया। विवि के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी छात्रों के साथ खुलकर आंदोलन में उतरने की बात कही।

आंदोलन को बड़ा समर्थन राज्य कर्मचारियों के एक दिवसीय कामकाज का बहिष्कार करने से भी मिला। ऑल असम सरकारी कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष वासव कलीता ने आंदोलन में कर्मचारियों के समर्थन की घोषणा की। हालांकि असम सरकार ने चेतावनी दी है कि सरकारी कर्मचारी सीमा से आगे बढ़े तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहिष्कार पर उनका वेतन भले नहीं कटेगा, मगर एक दिन की छुट्टी काटी जाएगी।

नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मांगा था स्टे : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर झूठे प्रचार का लगाया आरोप
- कहा, कोर्ट से सिर्फ नोटिस जारी करने की की गई थी मांग

सुप्रीम कोर्ट फाइल

कांग्रेस ने नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने (स्टे) की मांग के आरोपों को झूठा प्रचार बताया है। साथ ही कहा है कि उन्होंने कोर्ट से कभी भी स्टे नहीं मांगा था। उनकी ओर से सिर्फ मुख्य और आतंरिक दोनों ही याचिकाओं में नोटिस जारी करने की मांग की गई थी। कांग्रेस का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की ओर से नागरिकता कानून पर रोक नहीं लगाने के आदेश के बाद सामने आया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने बुधवार को संयुक्त रूप से पत्रकारों से चर्चा में कहा कि जो लोग स्टे की मांग को लेकर मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, वह कौन हैं, हम जानते है। उन्होंने इसके साथ ही 22 जनवरी को अगली सुनवाई को लेकर भी अपना पक्ष रखा। साथ ही कहा कि तब तक यह भी साफ हो जाएगा कि सरकार कैसे नागरिकता देगी? इसके नियम-कायदे क्या होंगे? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय संबंधों के खिलाफ है, क्योंकि हर देश का एक अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य होता है। जिसे सभी को मानना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। साथ ही समानता के अधिकारों के भी खिलाफ है।

कांग्रेस ने इसके साथ ही 28 दिसंबर को देश भर में भारत बचाओ-संविधान बचाओ के नारे से साथ मार्च की भी जानकारी दी। साथ ही बताया कि यह सभी प्रदेशों की राजधानियों में निकाला जाएगा।

आक्रोश ▶ महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उठी आवाज

पुणे, ठाणे व सोलापुर में भी विरोध प्रदर्शन

असम मूल के छात्रों और पेशेवरों ने कानून वापस लिए जाने की मांग की

पुणे, प्रेट्र : महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को पुणे में असम मूल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि ठाणे और सोलापुर में स्थानीय लोगों ने कानून के विरोध में मार्च निकाला।

पुणे में असम मूल के करीब 200 छात्र और पेशेवर संभाजी गार्डेन के बाहर एकत्र हुए और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ठाणे जिले के मुंब्रा में प्रदर्शनकारियों ने शिमला पार्क से रेलवे स्टेशन तक मार्च निकाला और बाद में एक रैली की। इस दौरान इलाके की अधिकतर दुकानें बंद रही और ऑटो रिक्शा सड़कों से नदारद रहे। सोलापुर में विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने जिला अदालत से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला और बाद में डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें सीएए को वापस लिए जाने की मांग की गई है।

महाराष्ट्र के ठाणे में बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रेट्र

मद्रास विवि के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी

चेन्नई : मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों के एक वर्ग का सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। छात्र कानून वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अपना विरोध जारी रखेंगे, वहीं विश्वविद्यालय परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी बरकरार रखी गई है।

मेंगलुरु पुलिस का आग्रह, कानून का अनुपालन करें

मेंगलुरु : शहर के पुलिस आयुक्त पीएस हर्षा ने लोगों से कानून का अनुपालन करने का आग्रह किया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर कई ऐसे संदेश फैलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों से 20 और 23 दिसंबर को बड़ी संख्या में जुटने का लिए कहा जा रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है।

डिब्रूगढ़ और शिलांग में कर्फ्यू में ढील

गुवाहाटी : असम में हालात सामान्य हो रहे हैं। गुवाहाटी में मंगलवार को ही कर्फ्यू हटा लिया गया था। जबकि डिब्रूगढ़ में बुधवार को कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील दी गई। हालांकि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। विमान और रेल सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। वहीं, मेघालय की राजधानी शिलांग में भी बुधवार को कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील दी गई। जबकि मोबाइल और इंटरनेट पर प्रतिबंध यहां भी जारी रहेगा।

हिंसक प्रदर्शनों के पीछे उग्रवादी व कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका

नीलू रंजन, नई दिल्ली

- असम में हिंसक प्रदर्शनों के पीछे उल्फा की सक्रियता के सुबूत
- दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका की आशंका

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे आतंकी और उग्रवादी संगठनों की भूमिका सामने आने लगी है। असम में हुए हंगामे के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन उल्फा का हाथ होने के सुबूत मिलते ही तत्काल वहां असम राइफल्स और सेना को तैनात किया गया। दिल्ली समेत देश के अन्य भागों में हिंसा के पीछे कुछ कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है और जांच एजेंसियां इसके लिए सुबूत एकत्रित करने में जुटी हैं।

सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि असम में हिंसक प्रदर्शनों के जरिये नागरिकता कानून का जनता द्वारा विरोध बताया जा रहा था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। एक एजेंसी की ओर से केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन को उग्रवादी संगठन उल्फा समर्थन कर रहा था और उसके उग्रवादियों के बीच आंदोलनकारियों को हथियार मुहैया कराने की बात भी की जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार उल्फा के एक उग्रवादी ने डिप्टी चैयरमैन प्रदीप गोगोई को आंदोलनकारियों को हथियार मुहैया कराने की बात भी कही। वह जानता था कि उग्रवादी संगठन के पास मौजूद हथियारों का 60 फीसद ग्रामीणों के बीच बांटना सही रहेगा या नहीं। यही नहीं, प्रदीप गोगोई 11 दिसंबर को असम के लाकुवा, सिवसागर में अपने सहयोगियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुआ था। इसके साथ ही रिपोर्ट के अनुसार 12 दिसंबर को लोताखील गुवाहाटी में नागरिकता कानून के विरोध में भारी प्रदर्शन के दौरान खुद उल्फा का महासचिव अनूप चेतिया और उनका सहयोगी प्रांजीत सैकिया भी मौजूद था। रिपोर्ट के बाद असम सरकार और केंद्र ने तत्काल कदम उठाते हुए असम राइफल्स के साथ-साथ सेना को उतारकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और उल्फा की साजिश को नाकाम कर दिया।

वहीं, दिल्ली समेत अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों के पीछे प्रतिबंधित कट्टरवादी संगठनों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है और एजेंसियां उनकी पहचान में जुट गई हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है। इस सिलसिले में गिरफ्तार लोगों में एक भी छात्र नहीं है। अब इन गिरफ्तार लोगों के बैकग्राउंड की जांच की रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किसी कट्टरपंथी संगठन से तो नहीं जुड़े थे।

जामिया की घटना से सीख लेते हुए सीलमपुर इलाके में हिंसक प्रदर्शन कर रही भीड़ की ड्रोन कैमरे से रिकार्डिंग कर ली गई, ताकि उनमें से हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस सिलसिले में सोशल मीडिया के साइट्स और वाट्सएप के कुछ ग्रुप की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है ताकि असली साजिशकर्ताओं की पहचान की जा सके।

बवाल के बाद परिणिति चोपड़ा से हरियाणा सरकार ने झाड़ा पल्ला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड अंबेसडर परिणिति चोपड़ा के नागरिकता संशोधन कानून पर आए ट्वीट के बाद सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। इस ट्वीट के बाद हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगेंद्र मलिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और मैं इस विभाग को देख रहा हूं, अब परिणिति चोपड़ा हमारी ब्रांड अंबेसडर नहीं हैं।

हालांकि कोई यह नहीं बता रहा कि परिणिति को हटाया कब गया। पुलिस कार्रवाई को बर्बर बताने वाली परिणिति को ब्रांड अंबेसडर बनाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के हिमायती हैं। अंबाला की परिणिति को हरियाणा सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड अंबेसडर बनाया था। तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को विश्वास में नहीं लिया गया था और उन्होंने इसका खुला विरोध किया था। कई भाजपा नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी।

लिखा, देश को लोकतांत्रिक कहना छोड़ दें

परिणिति ने ट्वीट में लिखा है कि अगर नागरिकों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने से हर बार यही होता रहे तो सीएए को भूल जाइये। हमें एक बिल पास करना चाहिए और अपने देश को लोकतांत्रिक देश कहना छोड़ देना चाहिए। अपने मन की बात कहने के लिए निर्दोष लोगों की पिटाई की जा रही है? यह बर्बर है।

सीएए वापसी की मांग लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंची बसपा

- ज्ञापन सौंप पार्टी ने विरोध करने वालों पर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया है

नई दिल्ली, प्रेट्र : बसपा सांसदों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को विभाजनकारी बताते हुए बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इसे वापस लेने तथा इसका विरोध करने वालों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

राज्यसभा में बसपा संसदीय दल के नेता सतीश मिश्रा और लोकसभा में पार्टी के नेता दानिश अली की अगुआई में पार्टी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद अली ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में बसपा के 13 सांसदों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंप कर यह मांग की गई है। उन्होंने कहा, 'हमने राष्ट्रपति को बताया कि पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सीएए संबंधी विधेयक संसद में पेश किए जाने से पहले ही इसे देश के लिए विभाजनकारी बताते हुए आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। इस कानून को लेकर आज देशव्यापी आंदोलनों के कारण उपजे हालात ने हमारी नेता की आशंका को सही साबित किया है।'

जामिया में पुलिस की कार्रवाई को बताया गैरकानूनी

बसपा ने राष्ट्रपति से दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लखनऊ के नदवा कॉलेज सहित देश के अन्य इलाकों में इस कानून के विरोध में किए गए आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग भी की। पार्टी सांसदों ने 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विवि में दिल्ली पुलिस द्वारा बिना इजाजत के प्रवेश कर पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज को गैरकानूनी बताते हुए इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है।

बंगाल में भाजपा सांसद निशिथ प्रमाणिक और खगेन मुर्मू गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ स्टेशन पर हुई तोड़फोड़
- हालात का जायजा लेने जाते समय पुलिस ने रोका, दिया धरना

बंगाल में मालदा के सुकांत मोड़ पर पुलिस ने बुधवार को भाजपा सांसद निशिथ प्रमाणिक व खगेन मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ प्रदेश भाजपा के महासचिव रथींद्र बोस तथा जिला नेता गोविंद मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, भाजपा सांसदों सहित सभी नेताओं को दो घंटे बाद छोड़ दिया गया। बताया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हरीशचंद्रपुर स्टेशन पर व्यापक तोड़फोड़ की गई थी। भाजपा सांसद व नेता तोड़फोड़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने जा रहे थे।

इंग्लिशबाजार थाने की पुलिस ने दोनों सांसदों और अन्य नेताओं को सुकांत मोड़ पर रोक दिया। विरोध में भाजपा सांसदों ने रास्ते में ही धराना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि सीएए का विरोध करने वालों ने शुक्रवार को हरीशचंद्रपुर स्टेशन पर व्यापक तोड़फोड़ की थी। इस घटना में हुए नुकसान को देखने एवं स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए ये दोनों भाजपा सांसद रवाना हुए थे। सांसदों की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेरकर प्रदर्शन किया। पुलिस वहां से दोनों सांसदों को थाने ले गई। इसके पहले कूचबिहार से भाजपा सांसद निशिथ प्रमाणिक ने पत्रकारों को बताया कि वे उत्तर मालदा से सांसद खगेन मुर्मू और जिला नेताओं के साथ हरीशचंद्रपुर जा रहे थे। प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से उपद्रवियों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीबीआइ अधिकारी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, राज्यपाल को अपमानित होना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य पुलिस सवालों के घेरे में है। भाजपा सांसद ने कहा, जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा।

मुर्शिदाबाद में विजयवर्गीय से धक्का-मुक्की : सीएए को लेकर बंगाल में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम में प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। उनके साथ धक्का-मुक्की की। काले कपड़े लिए हुए लोगों ने 'कैलाश विजयवर्गीय गो बैक' के नारे भी लगाए। विजयवर्गीय ने बाद में ट्वीट कर घटना की जानकारी देते हुए कहा, 'नवग्राम में मेरी गाड़ी को घेर लिया गया। प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। एसपी व डीजी ने फोन तक नहीं उठाया। बंगाल में अराजक सरकार के शासन में कुछ भी हो सकता है। यहां कोई सुरक्षित नहीं है।' उन्होंने यह ट्वीट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ साझा किया है। साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर प्रदर्शन का वीडियो भी साझा किया है।

ममता ने शाह से कहा–भाजपा कार्यकर्ताओं को करें नियंत्रित

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- बोलीं–एनआरसी की आग में कई राज्य जल रहे और आप कह रहे यह लागू होगा ही होगा

ममता बनर्जी फाइल

सीएए और एनआरसी के खिलाफ बुधवार को लगातार तीसरे दिन सड़क पर उतरीं बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास की जगह सबका सर्वनाश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आग बुझाना आपका काम है। आप भाजपा कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करें।

ममता ने शाह पर हमला करते हुए कहा कि अब आप सिर्फ भाजपा नेता नहीं हैं बल्कि केंद्रीय गृहमंत्री भी हैं। आपसे देश का ध्यान रखने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की अपील करूंगी। आपका काम आग बुझाना है। आप यह सुनिश्चित करें कि देश सीएए की आग में न जले। ममता की अगुआई में बुधवार को हावड़ा मैदान से कोलकाता के एस्प्लानेड स्थित डोरिना क्रॉसिंग तक सीएए और एनआरसी विरोधी जुलूस निकला गया। जुलूस की समाप्ति पर ममता ने कहा-'जब तक भाजपा देश में नहीं थी, वो कुछ नहीं हुआ, जो अब हो रहा है। अभी जम्मू-कश्मीर, असम, त्रिपुरा, उत्तर-पूर्व दिल्ली जल रहे हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि देश में एनआरसी होगा ही होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?'

कितने जेल और डिटेंशन कैंप बनाओगे : ममता ने कहा-'कितने जेल और कितने डिटेंशन कैंप बनाओगे, पहले नक्शा दिखाओ। आप इस तरह हमें नजरंदाज नहीं कर सकते।' ममता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा-'सीएए और एनआरसी को वापस लीजिए, वरना मैं देखती हूं कि आप इसे यहां कैसे लागू करते हैं। याद रखें कि बहुमत होने से सब कुछ करना नहीं चलेगा। आप सिर्फ 35 फीसद वोट लेकर सत्ता में आए है। 65 फीसद लोगों ने आपको नापसंद किया है।'

आधार कार्ड नहीं चलेगा तो क्यों किया करोड़ों खर्च : ममता ने कहा कि अब अमित शाह कह रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का सुबूत नहीं है, फिर हर चीज से उसे लिंक क्यों किया जा रहा है? आधार कार्ड नहीं चलेगा तो क्यों बनवाया गया? 6000 करोड़ रुपये आधार कार्ड पर खर्च क्यों किए गए? वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा तो क्या भाजपा जो कहेगी, वही चलेगा। आधार नहीं, पैन नहीं, वोटर कार्ड नहीं तो आप नागरिक नहीं, ये क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर 90 फीसद फेक वीडियो भाजपा के फंड से चलते हैं।

असंवैधानिक और अनैतिक है सीएए : ममता ने कहा-'सीएए असंवैधानिक व अनैतिक है। हम चाहते हैं कि हमारा यह आंदोलन देश का आंदोलन बने। सभी जाति, धर्म, वर्ग का आंदोलन बने लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होना चाहिए। आग लगाना आसान है, बुझाना कठिन। हम आग जलाने नहीं, बुझाने का काम करते हैं।

आज रानी रासमणि रोड में सभा करेंगी ममता : मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए का विरोध जारी रहेगा जब तक कि इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। आगे के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए ममता ने कहा कि गुरुवार को छात्रों और युवाओं की सभा रानी रासमणि रोड में होगी। वे भी इसमें हिस्सा लेंगी। इसके बाद शुक्रवार को पार्क सर्कस मैदान में अपराह्न 3.30 बजे सीएए-एनआरसी के खिलाफ सभा की जाएगी। शुक्रवार को आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। 24 दिसंबर को तृणमूल की ओर से बड़ा जुलूस निकाला जाएगा और इसके बाद आगे दिल्ली में भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

दो टूक

जगदीप ने सीएए को लेकर बंगाल के हालात पर मुख्य सचिव व डीजीपी संग की बैठक, मालदा व मुर्शिदाबाद के हालात पर चिंता जताकर वहां जाने की जताई इच्छा

'सीएम संविधान से परे नहीं, करना होगा कानून का पालन'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल में सीएए के विरोध के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह कानून भारतीय नागरिकों के हितों को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी संविधान से परे नहीं हैं। उन्हें भी कानून का पालन करना होगा।

बुधवार को राजभवन में मुख्य सचिव राजीव सिन्हा व राज्य पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) वीरेंद्र के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि निर्वाचित सरकार पूरी तरह से कानून से बंधी होती है। यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बना है। मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली है और सीएए संविधान का हिस्सा है, इसलिए राज्य सरकार इससे अलग नहीं है। मुख्यमंत्री को संविधान के अधीन बने इस कानून का पालन करना ही होगा, क्योंकि वे संविधान से परे नहीं हैं।

धनखड़ ने आगे कहा, 'मैं मुख्यतया मालदा और मुर्शिदाबाद के हालात से चिंतित हूं। वहां भय का माहौल है। मैंने वरिष्ठ नौकरशाहों को कहा है कि मैं खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहता हूं लेकिन पहले मुझे राज्य के प्रशासनिक तंत्र को भरोसे में लेना होगा।' सीएए को लेकर लोगों से शांति बहाली की अपील करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे या तो गुमराह हो रहे हैं या अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री से मुलाकात की जताई इच्छा : सोमवार को जब मुख्य सचिव राजीव सिन्हा, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वीरेंद्र बुलावे के बावजूद राज्यपाल से मिलने नहीं पहुंचे थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री को तलब किया था, लेकिन मंगलवार को केवल डीजीपी ही राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बुधवार को मुख्य सचिव व डीजीपी दोनों ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने अब मुख्यमंत्री से मुलाकात की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा-'यह समय मतभेद भूलकर साथ काम करने का है और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मुझसे मिलेंगी।'

जगदीप धनखड़ फाइल

हालात को सामान्य करने में सीएम सक्षम : चंद्रिमा

राज्यपाल के मालदा व मुर्शिदाबाद जाने की इच्छा जताने पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, 'मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि महामहिम और भाजपा नेताओं को वहां जाने की जरुरत क्यों महसूस हो रही है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो करना है, वह कर रही हैं और वे इसमें सक्षम हैं।' उन्होंने आगे कहा–'मालदा–मुर्शिदाबाद में अभी पर्यटन के लिए जाना जरूरी नहीं है, फिर यह सवाल क्यों। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, वह तो कर नहीं रही और भाजपा नेता बेवजह राजनीति कर रहे हैं। मेरी राज्यपाल से एक जिज्ञासा है कि कैसे महामहिम बोल रहे हैं कि यह कानून मानना होगा, जबकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है।'

जनमत मुद्दा

क्या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय मुस्लिम समाज का तथाकथित भय भ्रम की उपज है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। MUDDA लिखें, स्पेस देकर YES या NO लिखकर 57272 पर भेजें।

800 करोड़ रुपये का नियम विरुद्ध निवेश करने के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल की जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के तीन तत्कालीन अधिकारियों रमाशंकर विश्वकर्मा, अनिल भार्गव और सुभाष शर्मा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया है।

शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत

मौसम का प्रकोप ▸ कोहरा बरपा रहा कहर, तापमान में गिरावट जारी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दो दिनों में रिकार्ड तोड़ पड़ रही सर्दी के बीच बुधवार को शीतलहर ने समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। अलबत्ता, कुछ राज्यों में हल्की धूप जरूरत निकली, मगर हवाओं के चलते लोगों को राहत नहीं मिली। कोहरा भी कहर बरपा रहा है। तापमान में गिरावट बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश में तो सर्दी ने चार लोगों की जान ले ली है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने दो दिन स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते जनजीवन खासा प्रभावित है।

पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों तक पहुंची उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड और बिहार सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। शीतलहर चलने से गलन बढ़ गई है। कोहरे ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इससे ठिठुरन और बढ़ गई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम विभाग के अनुसार 1971 से अब तक 18 दिसंबर को प्रदेश में कभी इतनी ठंड नहीं पड़ी। यहां अधिकतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मध्य प्रदेश के दतिया में न्यूनतम तापमान तो चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी के आलम का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 25 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।

कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। पूरी वादी में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदू शून्य से नीचे बना हुआ है। सर्दी का आलम यह है कि तालाब और झीलें ही नहीं, घरों में पीने का पानी भी जमने लगा है। घर पर एक बालटी में रखा पानी बर्फ में तब्दील हो जाने के बाद उसे दिखाती महिला। कामरान रशीद बट

सिर्फ घुसपैठिए करें चिंता, काई और नहीं : जावडेकर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर छात्रों के विरोध के पीछे तमाम तरह के फैलाए गए भ्रम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इससे छात्रों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला नहीं, इसलिए इससे घुसपैठियों को अवश्य ही चिंता करने की जरूरत है।

प्रकाश जावडेकर फाइल

जावडेकर ने सतत विकास पर आयोजित सम्मेलन के बाद सीएए पर छात्र आंदोलन से जुड़े के सवालों के जवाब में संवाददाताओं से कहा, 'देश में एक संवेदनशील सरकार है जो सभी की बात सुनती है। छात्रों या किसी अन्य को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए।' उन्होंने कहा, 'सभी पक्षों से शांति बनाने की सभी लोगों ने अपील की है और हम भी यह अपील करते हैं कि शांति से ही हर समस्या का हल होता है।'

जावडेकर ने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर लोगों की भिन्न राय हो सकती है। इस कानून पर भी मत-मतांतर हो सकते हैं, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाना ना तो किसी सरकार के लिए स्वीकार्य है ना ही इससे समस्या का कोई हल निकल सकता है।

नागरिकता कानून से भारतीय मुस्लिमों का लेना-देना नहीं : अहमद बुखारी

जेएनएन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि इस कानून से भारतीय मुस्लिमों का कोई संबंध नहीं है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों पर ही इस कानून का असर पड़ेगा।

राजधानी समेत देशभर में हो रहे प्रदर्शनों पर इमाम बुखारी ने कहा कि प्रदर्शन करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है जिससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसमें संयम बरतना चाहिए। लोग भावनाओं पर भी नियंत्रण रखें। यह समझें कि अभी एनआरसी कानून नहीं बना है।

बंगाल में मुस्लिमों को जागरूक करेंगे संघ और भाजपा: इस कानून को लेकर सर्वाधिक विरोध-प्रदर्शन कर रहे बंगाल के मुस्लिमों को समझाने के लिए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभियान चलाएंगे।

संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि मुस्लिम समाज गलत जानकारी का शिकार हो गया है, जिसे जल्द ही समझाने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक संघ ने दक्षिण बंगाल और कोलकाता में अभियान शुरू कर दिया है। वहीं, भाजपा माह के आखिर में अपने कार्यकर्ताओं को सीएए के बारे में बताने के लिए दो दिन की वर्कशॉप करेगी।

नवीन ने कहा-मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं

उधर, भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से भारतीय नागरिकों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह कानून केवल विदेशी नागरिकों के लिए है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) का समर्थन नहीं करते हैं।

एसजीपीसी ने कहा, मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए

पंजाब के रूपनगर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि एसजीपीसी और अकाली दल ने इस कानून के लिए विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर मांग की थी। इस कानून से आपसी भाईचारक सांझ भी बढ़ेगी, लेकिन इस कानून में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

सौरव गांगुली की बेटी साना ने जताई प्रतिक्रिया

जासं, कोलकाता : पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की बेटी साना ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। 18 साल की साना ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विख्यात लेखक खुशवंत सिंह की 2003 में लिखित पुस्तक 'द एंड ऑफ इंडिया' की एक उक्ति पोस्ट की है।

इस पुस्तक में कहा गया है कि प्रत्येक फांसीवादी शासन व्यवस्था खुद को बरकरार रखने के लिए कुछ संप्रदायों व समूहों का इस्तेमाल करती है और उनके जरिए अपनी विचारधारा को बचाए रखती है। वे शुरू में एक या दो समूहों के माध्यम से यह काम शुरू करती है, जो वहीं खत्म नहीं हो जाता। सिर्फ घृणा के बूते आंदोलन कर दूसरे को डरा-धमकाकर खुद को बरकरार रखते हैं। आज जो मुसलमान और ईसाई नहीं होने के कारण खुद को सुरक्षित मान रहे हैं, वे झूठमूठ स्वर्ग में वास कर रहे हैं।'

इस बीच, सौरभ गांगुली ने कहा है कि यह पोस्ट सही नहीं है। साना को इस मामले से अलग रखा जाना चाहिए। वह राजनीति समझने के लिए अभी काफी छोटी है।

शशि थरूर समेत 23 लेखकों को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजनेता और लेखक शशि थरूर और नाटककार नंद किशोर आचार्य समेत 23 लेखकों को इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगामी 24 फरवरी को दिल्ली में इन सभी को ताम्र पत्र और एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को साहित्य अकादमी ने इन नामों की घोषणा की।

कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक 'एन इरा ऑफ डार्कनेस' के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, जबकि नंद किशोर आचार्य को उनकी हिंदी कविता 'छीलते हुए अपने को' के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबर की अध्यक्षता में इन पुरस्कारों का प्रस्ताव 23 भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्णायक मंडल और साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा रखा गया।

इनमें सात कवि फुकन चंद्र बसुमतारी (बोडो), निलबा खांडेकर (कोंकणी), मनीष अरविंद (मैथिली), वी मधुसूदन नायर (मलयालम), अनुराधा पाटिल (मराठी), पेन्ना मधुसूदन (संस्कृत) व उपन्यास लेखन के लिए जयश्री गोस्वामी महंत (असमिया), एल बिरमंगल सिंह (मणिपुरी), चो. धर्मन (तमिल) और बंदि नारायण स्वामी (तेलुगु) को यह पुरस्कार मिल रहा है।

छह लेखकों को लघुकथा श्रेणी के लिए चुना गया है जिनमें अब्दुल अहद हजिनी (कश्मीरी), तरुण कांति मिश्रा (ओडिया), कृपाल कजाक (पंजाबी), रामस्वरूप किसान (राजस्थानी), काली चरण हेंब्रम (संताली), और ईश्वर मुरजनी (सिंधी) शामिल हैं। वहीं, विजया (कन्नड़) और शफी किदवई (उर्दू) को उनके रचनात्मक गैर-कथा साहित्य, आत्मकथा और जीवनी पर लेखन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। निबंध लेखन के लिए चिन्मय गुहा (बंगाली), ओम शर्मा जंडरी (डोगरी), और रतिलाल बोरिसगर (गुजराती) का नाम प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में 136 दिन बाद पहली बार नमाज...

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 136 दिन बाद बाद पहली बार श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में बुधवार को सामूहिक तौर पर नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान या बाद में कोई जिहादी या कश्मीर की आजादी का नारा नहीं गूंजा। जुलूस भी नहीं निकला। गत पांच अगस्त से पहले जामिया में राष्ट्रविरोधी जुलूस व पत्थरबाजी की घटनाएं सामान्य मानी जाती रही हैं। इस मस्जिद की कश्मीर की सियासत में शुरू से ही बहुत अहमियत रही है। सुल्तान सिकंदर द्वारा इसका निर्माण 1394 में शुरू कराया गया और यह 1402 में बनकर तैयार हुई थी। प्रेट्र

गलत ट्रेन में चढ़ी महिला से पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई

जागरण संवाददाता, कानपुर

▸ कानपुर-अमृतसर सुपरफास्ट ट्रेन में महिला टीटीई व जीआरपी की दबंगई, रेल मंत्री से शिकायत

▸ परिवार भी था साथ, 1980 रुपये जुर्माना भी वसूला गया

फगवाड़ा स्टेशन से गलत ट्रेन में परिवार सहित चढ़ी महिला के साथ हद दर्जे की बदसुलूकी की गई। ट्रेन में मौजूद टीटीई और जीआरपी ने महिला और उसके परिवार के साथ अभद्रता की और दबंगई करते हुए 1980 रुपये जुर्माना वसूला। रेल स्टाफ का इतने से भी मन नहीं भरा तो अमृतसर स्टेशन पर जेल भेजने की धमकी देकर पैर पकड़वाकर माफी मंगवाई। महिला ने ट्विटर पर रेल मंत्री से इसकी शिकायत की है। मामला कानपुर-अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है। सोमवार रात यहां से अमृतसर के लिए रवाना होने वाली इस ट्रेन में कानपुर का ही स्टाफ था।

पीड़ित महिला यात्री वीना रानी ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि वह हिसार की रहने वाली है। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल जाने के लिए पति प्रदीप, दो स्वजनों और बच्चों समेत दिल्ली से चलने वाली अमृतसर इंटरसिटी में आरक्षण कराया था। ट्रेन फगवाड़ा से मंगलवार सुबह 9:32 बजे चली थी। इसी समय कानपुर-अमृतसर एक्सप्रेस आ गई और गलती से परिवार समेत ट्रेन में चढ़ गई। वीना का आरोप है कि जब महिला टीटीई टिकट चेक करने आई तो गलती का एहसास हुआ। टिकट दिखाकर अगले स्टेशन पर उतारने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं मानी और एक हजार रुपये मांगे। मना करने पर अभद्रता की और जीआरपी को बुला लिया। जीआरपी ने स्वजनों से धक्का-मुक्की की और जेल भेजने की धमकी दे डाली। दबाव डालकर 1980 रुपये का जुर्माना लिया। इसके बावजूद अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। अमृतसर स्टेशन पहुंचने के बाद एक रेस्टोरेंट में ले गए और जेल भेजने की धमकी देकर पैर पकड़वाकर सभी से माफी मंगवाई। स्टेशन डायरेक्टर हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि अभी तक मामले की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलते ही जांच की जाएगी।

दुष्कर्म के बाद बच्ची के हत्यारे को फांसी की सजा

जागरण संवाददाता, रामपुर

उप्र के रामपुर में छह साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में छह माह में फैसला सुना दिया गया। अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दुष्कर्म और हत्या का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। यहां की एक कालोनी में रहने वाली छह साल की बच्ची सात मई 2019 को घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। गुमशुदगी भी दर्ज कराई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। डेढ़ माह बाद उसका शव कालोनी के पीछे एक अर्धनिर्मित मकान में मिला। मुहल्ले का ही एक युवक बच्ची को बहाने से वहां ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। बच्ची की पहचान छुपाने के लिए शव पर तेजाब डालकर जला दिया था।

परिजनों ने बच्ची के कपड़ों और चप्पलों से पहचान की थी। पुलिस ने बच्ची के मोहल्ले में ही रहने वाले नाजिल के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर ही उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 23 जून को पुलिस ने उसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दो अगस्त को उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पॉक्सो एक्ट के मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत ने पांच सितंबर को आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई की। मुकदमे में नौ गवाह पेश किए गए, जिसमें आठ अभियोजन की ओर से पेश किए गए थे। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश विनोद कुमार 13 दिसंबर को नाजिल को दोषी सिद्ध कर दिया। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया।

जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपित ने फिर की हैवानियत

जासं, बरेली

दुष्कर्म के मामले में जमानत पर छूटे आरोपित ने जेल से निकलने के आठ दिन के अंदर एक और वारदात को अंजाम दे दिया। सो रही किशोरी के घर में घुसा और तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। सात साल पहले वह किशोरी की बड़ी बहन से भी ऐसी हैवानियत कर चुका था। पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे। आरोपित सोनू इससे पहले भी दुस्साहस करता रहा। सात साल पहले उसने किशोरी की बड़ी बहन से दुष्कर्म किया था। उस वक्त घटना से आहत युवती के माता, पिता कई दिन घर से बाहर नहीं निकले थे। कुछ दिन बाद दोनों की जहर खाने से मौत हो गई थी। तब कहा गया था कि बेटी से दुष्कर्म के बाद वे अवसाद में थे। गौरतलब है कि आरोपित बड़ी बहन से किए गए दुष्कर्म के मामले में ही जमानत पर छूटा है।

पीड़ित किशोरी शिकायत करने पहुंची तो थाना पुलिस दिनभर टकराती रही। देर शाम मुकदमा दर्ज किया गया। उप्र के बरेली स्थित बिशारतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती अपने दो भाइयों के साथ रहती है। मंगलवार को बड़ा भाई गांव से बाहर गया था। छोटा भाई घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था। आरोप है कि उसी समय सोनू उर्फ सुदेश दीवार फांदकर घर के अंदर घुस आया और तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। बुधवार सुबह होते ही भाई व अन्य परिजन बिशारतगंज थाने पहुंचे और तहरीर दी। थाना पुलिस ने जांच की बात कहकर पीड़ित पक्ष को वहां से टरका दिया। थानाध्यक्ष बिसारतगंज राजेश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत केसा दर्ज कर लिया है।

> पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही हैं।
> **-शैलेश पांडेय, एसएसपी, बरेली।**

भोपाल में टीवी अभिनेत्री पर की अश्लील टिप्पणी, विरोध करने पर पीटा

नईदुनिया, भोपाल: भोपाल के बस स्टैंड के पास खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकली एक टीवी अभिनेत्री पर वहां खड़े मनचलों ने अश्लील टिप्पणी कर दी। युवती और उसके साथियों ने विरोध किया तो आरोपितों ने अभिनेत्री के साथ मारपीट कर दी। घटना सोमवार रात एक बजे नादरा बस स्टैंड पर हुई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

हनुमानगंज थाना पुलिस के मुताबिक मूलतः इंदौर की रहने वाली 22 वर्षीय युवती मुंबई में विभिन्न टीवी सीरियल में काम करती है। उसके साथ काम कर चुकी एक सहेली गांधी नगर इलाके में रहती है। अभिनेत्री दो दिन पहले सहेली की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए मुंबई से भोपाल आई थी। सोमवार रात को अभिनेत्री और उसकी सहेली अपने एक दोस्त के साथ नादरा बस स्टैंड स्थित होटल पर गई थी। रात करीब एक बजे खाना खाने के बाद वे लोग बस स्टैंड पर पहुंचे, तभी यह घटना हुई। एएसआइ घूमेंद्र सिंह ने बताया कि अभिनेत्री की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट करने का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

गृह मंत्रालय को भेजा पीएसए के तहत बंद 40 लोगों की रिहाई का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▸ जम्मू कश्मीर प्रशासन की सूची में कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान व सरपंच भी शामिल

▸ पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के बाद बनाया गया था बंदी

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बनाकर देश की विभिन्न जेलों में भेजे गए 40 लोगों की रिहाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इनमें कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट नजीर अहमद रोंगा, जमात-ए-इस्लामी के प्रवक्ता एडवोकेट जाहिद अली के अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दो नेता शौकत बख्शी और मुश्ताक अजमल शाह भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूची में उत्तरी कश्मीर से संबंध रखने वाला एक सरपंच भी शामिल है।

पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन अलगाववादी और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के भी कई नेताओं को हिरासत में लिया था। इनमें से 450 को पीएसए के तहत बंदी बनाया गया है और अधिकांश को उत्तर प्रदेश व हरियाणा की जेलों में रखा गया है।

प्रस्ताव में इन लोगों के नाम शामिल : संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों की रिहाई के लिए आग्रह किया गया है, उनमें से अधिकांश को पांच अगस्त के आसपास ही हिरासत में लिया गया है। इनमें नजीर अहमद रोंगा, शौकत बख्शी और मुश्ताक अजमल शाह, उत्तरी कश्मीर में जिला बारामुला के रहने वाले सरपंच जहूर अहमद मीर के अलावा फिरदौस अहमद बाबा, बिलाल अख्तर, खालिद जरगर, अब्दुल रशीद शिगन, आरिफ शेख, शकील बट, लतीफ मीर और हिलाल जान के नाम प्रमुख हैं।

राज्य की परिस्थितियों के आधार पर होगा रिहाई का फैसला

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इन सभी लोगों के मामलों को जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के आधार पर देखेगा और उसके आधार पर ही रिहाई का फैसला लेगा। अलबत्ता, जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन के गृह विभाग ने कथित तौर पर इस सूची में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए हैं, जिनके मामलों पर पीएसए संबंधी मामलों के लिए गठित समीक्षा समिति ने किसी तरह की नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दी है। इसके अलावा सूची तैयार करते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जब भी इन लोगों की रिहाई का फैसला लेगा, इन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।

कुछ लोगों को पहले भी किया जा चुका है रिहा

कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन मुबीन शाह को पीएसए से मुक्त किया है। शाह का मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा था। इसके अलावा राज्य प्रशासन ने गत सप्ताह कुलगाम के रहने वाले परवेज अहमद पाला को भी अदालत के निर्देशानुसार पीएसए से मुक्त किया था। पाला कैंसर पीड़ित हैं और उसे सात अगस्त को जिलाधिकारी कुलगाम के निर्देशानुसार पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था।

गलत धंधा

मुजफ्फरपुर में बच्चों के खरीदने बेचने का धंधा करने वाला अस्पताल संचालक पकड़ा गया, महिलाओं को गर्भ न गिराने की सलाह देकर अस्पताल में करता था भर्ती, नौ माह पूरा होने पर नॉर्मल या ऑपरेशन से कराता था प्रसव

नर्सिंग होम में चल रहा था अनचाहे गर्भ से बच्चों को 'चुराने' का रैकेट

जागरण टीम, भागलपुर

बच्चों की चोरी कर उन्हें मुंहमांगी कीमत पर बेचने वाले झोलाछाप डॉक्टर विजय चौधरी के नर्सिंग होम में अनचाहे गर्भ से बच्चे को 'चुराने' का धंधा भी चल रहा था। ग्रामीण परिवेश की महिलाएं गर्भपात कराने के लिए मुजफ्फरपुर स्थित उसके मां भगवती सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में आती थीं। अविवाहित युवतियां और गरीब महिलाएं इस गिरोह का शिकार बनती थीं। कुछ युवतियों को पुलिस, समाज का भय दिखाया जाता था, तो गरीब महिलाओं को धन का लोभ दिया जाता था। फिर विजय उन्हें अस्पताल में भर्ती करता था, या अपने नर्सिंग स्कूल के हॉस्टल में रख लेता था। नौ माह पूरा होने पर नॉर्मल या ऑपरेशन से प्रसव कराता था। इसके बाद बच्चे को रख लेता था। बाद में उसे बेच देता था। पुलिस ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन या अन्य स्थानों से गिरोह में शामिल महिलाओं से बच्चों की चोरी भी कराता था। अस्पताल में ही चोरी के बच्चे की बोली लगती थी। इस धंधे में कई बड़े लोग भी शामिल हैं।

पकड़ी गईं बच्चा चोर महिलाओं ने किया पर्दाफाश: बच्चा चोर गिरोह के सरगना विजय चौधरी को बुधवार सुबह आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी करते मुंगेर तारापुर की कल्पना कुमारी पकड़ी गई थी। पूछताछ में उसने 3 दिसंबर को लखीसराय स्टेशन से पिपरिया थाना क्षेत्र के ढाई वर्षीय बच्चा के चोरी होने की जानकारी दी। स्टेशन पर लगे सीसी कैमरे के फुटेज से बच्चा चोरी की आरोपी मुंगेर तारापुर की सारिका की पहचान हुई। कल्पना ने बताया कि बच्चा चोरी का मास्टर माइंड मुजफ्फरपुर के भिखनपुर स्थित मां भगवती हॉस्पिटल का संचालक विजय कुमार चौधरी है। पुलिस जब वहां पहुंची तो विजय कुमार चौधरी पकड़ा गया। सारिका भी मौके से पकड़ी गई। उसने कहा कि एएनएम की पढ़ाई करने आई थी, उसके बाद हॉस्पिटल संचालक से शादी कर ली। विजय कुमार चौधरी पहले से ही शादीशुदा था।

लड़का होगा, पता चलते ही बरगलाने लगता था

रेल पुलिस गिरफ्त में आई कल्पना कुमारी ने बताया कि जो महिला गर्भपात कराने पहुंचती थी, विजय चौधरी पहले उसका अल्ट्रासाउंड करता था। यदि लड़का हुआ तो वह महिला को फुसलाना शुरू कर देता था। खास तौर से वैसी महिलाओं को निशाना बनाता था, जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थी। कल्पना ने दावा किया कि वह लोग भी अपने गांव-क्षेत्र में ऐसी महिलाओं की खोज में रहती थीं, जो गर्भ के बच्चे को बोझ मान रही। महीने में एक-दो ऐसी महिलाएं-युवतियां मिल ही जाती थीं। विजय वैसी महिलाओं को अपने खर्च पर प्रसव तक इलाज कराता था। यदि किसी बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाता था, तो उसके लिए अस्पताल में वार्मर की भी व्यवस्था थी। प्रसव के बाद महिला को मोटी रकम देता था। फिर नवजात को बेच देता था। जिनकी संतान नहीं होती थी, वैसे लोग नर्सिंग होम से संपर्क रखते थे। जैसे ही नया बच्चा मिला उसे फौरन बता देती थी। महिलाओं ने स्वीकार किया है कि लड़की की कीमत ज्यादा नहीं मिलती थी। इस कारण लड़के को ही टारगेट किया जाता था।

बड़े-बड़े लोगों से संपर्क, नेपाल से दिल्ली तक नेटवर्क

अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात और चोरी कर लाए गए बच्चों की देखभाल के लिए विजय ने अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ भी रखा था। वहां शिशु गहन जांच चिकित्सक केंद्र (एसएनसीयू) भी है। बिहार के अलावा उसके संपर्क दिल्ली और नेपाल तक में हैं। गिरोह से कई महिलाएं, लड़कियां और पुरुष जुड़े हैं।

बिजनौर कोर्ट में हुई हत्या को लेकर हाई कोर्ट सख्त, शीर्ष अधिकारी तलब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

उप्र स्थित बिजनौर के सीजेएम कोर्ट में फायरिंग कर हत्यारोपित की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट गंभीर है। घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी को 20 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने जिला जज की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिया। जिला जज की रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने विशेष खंडपीठ गठित की थी। कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर व आगरा के बाद प्रदेश में यह तीसरी घटना है, जब अपराधियों ने अदालत के अंदर घुसकर जेल से पेशी पर लाए गए आरोपित की हत्या की है। इस घटना से अदालतों की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

जिला अदालतों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने कई सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अदालतों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स का गठन करें।

अधिवक्ताओं का जारी हो परिचय पत्र

हाई कोर्ट ने जिला अदालतों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले की अदालतों में एडवोकेट रोल का निर्माण किया जाय। सभी अधिवक्ताओं को परिचय पत्र जारी किया जाए। वादाकारियों को भी प्रवेश के लिए पास जारी किए जाएं। अधिवक्ता परिचय पत्र अपने साथ रखें और सुरक्षाकर्मी द्वारा मांगे जाने पर दिखाएं, क्योंकि यह व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए है।

190 घटनाएं पत्थरबाजी की दर्ज हुई हैं पांच अगस्त के बाद से कश्मीर घाटी में। इसमें संलिप्त 250 लोग अभी जेल में हैं। साथ ही जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के 171 प्रयास हुए।

प्रकाश सिंह कमेटी की जांच रिपोर्ट का चैप्टर बंद

फैसला ▸ रिपोर्ट पर दो सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होने को बनाया आधार

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की हिंसा में 41 लोग मारे गए थे

- इस रिपोर्ट में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम को भी गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया था
- राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कह दिया कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट आधी-अधूरी थी

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद सामने आई प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट का चैप्टर अब बंद हो चुका है। इसलिए उसकी रिपोर्ट के दोबारा से अध्ययन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी यह रिपोर्ट अधिकृत नहीं थी। मालूम हो कि इस हिंसा में 41 लोग मारे गए थे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधारों की लड़ाई लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के लिए न केवल सरकार व अफसरों में तालमेल की कमी को जिम्मेदार ठहराया था, बल्कि राज्य में पुलिस के बढ़ते राजनीतिकरण पर चिंता जताते हुए उसमें सुधार की जरूरत बताई थी। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका। राज्य सरकार हालांकि बार-बार कहती रही है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमिन (सार्वजनिक मंच) पर डाला जा चुका है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का दावा है कि सरकार प्रकाश सिंह रिपोर्ट के अहम तथ्यों को छिपा रही है और उन्हें उजागर नहीं कर रही है। इस रिपोर्ट में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम को भी गलत ढंग से इस्तेमाल किया गया था। दुष्यंत की ओर से कानूनी कार्रवाई के बाद प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट से उनका नाम हटा लिया गया था। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को साफ कह दिया कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट आधी-अधूरी थी और उसमें कई ऐसी खामियां थी, जिनका जिक्र करना अब ज्यादा जरूरी नहीं समझते। प्रकाश सिंह के नेतृत्व वाली कमेटी में तीन सदस्य थे, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार हुई, उस पर सभी तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर न होकर मात्र एक ही सदस्य के हस्ताक्षर थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इस रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के प्रति कमेटी के सदस्यों में मतभेद थे और वह एक दूसरे से सहमत नहीं थे। पुलिस में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप से जुड़े सवाल पर अनिल विज ने कहा कि पुलिस में सुधारों के लिए वह अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। जल्द ही पुलिस सुधार के नतीजे सामने आने लगेंगे।

केपी सिंह और विजयवर्धन थे प्रकाश सिंह के साथ कमेटी में शामिल

12 से 22 फरवरी 2016 तक हरियाणा के आठ जिलों में आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव हुए थे। इन दंगों की जांच के लिए सरकार ने 2 मार्च 2016 को प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, जिसमें आइपीएस डा. केपी सिंह और आइएएस विजयवर्धन को भी शामिल किया गया था।

जानिये, क्या कुछ था प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में

450 पन्नों की रिपोर्ट में 90 अफसरों की नाकामी का जिक्र था।

90 अधिकारियों की भूमिका ठीक नहीं रही।

- अफसरों ने जानबूझकर हिंसा को रोकने में कोताही बरती।
- रोहतक में 30 अफसर दंगे के दौरान तमाशबीन बने रहे।
- अफसरों ने माना, वे कार्रवाई के लिए आदेश का इंतजार करते रहे।

पंचकूला हिंसा क्या सरकार की नाकामी : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

साध्वी यौन शोषण में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि पंचकूल में उन तीन दिनों तक जो कुछ भी हुआ क्या यह सरकार की नाकामी थी? यह सब हुआ कैसे, इसका सामने आना बेहद जरूरी है। क्या सरकार के पास इस बारे में कोई खुफिया जानकारी नहीं थी? हाई कोर्ट ने इस पर कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता से जवाब मांगा है। वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि जब उनका पक्ष पूछा जाएगा तो वह जवाब देंगे।

बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शर्मा, जस्टिस आरके जैन एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने पूछा कि कैसे तीन दिनों तक लाखों डेरा प्रेमियों को पंचकूला में आने की इजाजत दी गई। जो पुलिस शाम सात बजे के बाद किसी पार्क में एक लड़का और लड़की को बैठने तक नहीं देती उसी पुलिस ने तीन दिन और रात तक लाखों डेरा प्रेमियों को क्यों बिना किसी कारण बैठने दिया। कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता ने कहा कि यह सीधे तौर पर सरकार की नाकामी है। सरकार पूरे मामले में डेरे के साथ मिलकर चलती नजर आई। मामले को दो फेज में देखा जाना चाहिए। पहला फेज जब लाखों डेरा प्रेमी पंचकूला में तीन दिन तक बैठे रहे, तब सरकार ने इन्हें हटाने की कोशिश तक नहीं की। दूसरा फेज जब गुरमीत को दोषी करार दिया गया तो सरकार ने दंगों में शामिल इन्हीं डेरा प्रेमियों पर कड़ी कार्रवाई की।

अगर सरकार ने पहले ही ठोस कार्रवाई की होती तो जान व माल के नुकसान को रोका जा सकता था। गुप्ता ने कहा कि दूसरे फेज में सरकार ने जिम्मेदारी से काम किया। हालांकि इस कार्रवाई में 32 लोगों की मौत हुई। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती तो जान माल का कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था। बावजूद इसके इस घटना में सरकार और डेरा दोनों जिम्मेदार हैं।

पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कहा कि इस पूरे मामले में उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई। पंजाब सरकार ने पहले ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर लिए थे और अब तक इस मामले में सरकार के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं है।

मप्र में नकदी सहित चेक से लाखों की रिश्वत लेते इंजीनियर गिरफ्तार

नईदुनिया, शहडोल

- 37 करोड़ से ज्यादा के बिल भुगतान को लेकर मांगे थे 2.20 करोड़
- 15 लाख में माना, 10 लाख नकद और पांच लाख रुपये की चेक ली

मध्य प्रदेश की रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक इंजीनियर को दस लाख रुपये नकद के साथ ही पांच लाख रुपये चेक से लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) राजेश तिवारी ने 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत सीधी जिले में किए गए काम के बकाया 37 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिल के भुगतान के लिए पहले 2.20 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। बाद में वह 1.80 करोड़ रुपये मांगने लगा और अंततः 15 लाख रुपये लेने को तैयार हुआ था।

जेई तिवारी के खिलाफ सीधी के आजाद नगर कोटहा में रहने वाले ठेकेदार भानू प्रकाश कचेर ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी। भानू ने बताया कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर सीधी जिले में सौभाग्य योजना के तहत लगभग 37 करोड़ 27 लाख रुपये का काम किया था। उस दौरान जेई राजेश तिवारी सीधी में ही पदस्थ था। एक जून को तिवारी का ट्रांसफर सीधी से शहडोल हो गया। इसके बाद भी तिवारी भानू पर बिल के भुगतान के लिए दो करोड़ 20 लाख रुपये देने का दबाव बनाता रहा। तय योजना के मुताबिक 17 दिसंबर को रुपये दिए जाने की बात हुई। मंगलवार को ही भानू शहडोल आ गया, लेकिन जेई ने रुपये नहीं लिए। उसने कहा कि बुधवार को मॉर्निंग वॉक के समय वह रुपये लेगा। उसने वहां भी राशि नहीं ली। अंत में सुबह नौ बजे तिवारी ने भानू को अपने घर के पास बुलाया और 15 लाख ले लिए। इसमें 10 लाख नकद और पांच लाख रुपये का चेक आरोपित के ही नाम का था। जैसे ही जेई ने रुपयों से भरा बैग लिया वैसे ही घात लगाकर बैठी लोकायुक्त टीम ने उसे धरदबोचा।

मध्य प्रदेश के रीवा में रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार जेई राजेश तिवारी। नईदुनिया

> यह मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच की जा रही है।
> **-राजेंद्र कुमार वर्मा एसपी, लोकायुक्त, रीवा**

पुलिस ने जिसे सबसे पहले पकड़ा था वही हो गया दोषमुक्त

राज्य ब्यूरो, जयपुर

शहबाज अहमद। फाइल

जयपुर बम धमाकों के आरोपित शहबाज ने ही ईमेल किया था, यह साबित नहीं हो सका

जयपुर बम धमाकों के मामले में आरोपित बनाए गए पांच लोगों में से एक के मामले में राजस्थान पुलिस की जांच खरी साबित नहीं हुई। आरोपित शहबाज हुसैन को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। साथ ही यह माना कि उसके खिलाफ ऐसे कोई सुबूत नहीं हैं, जिससे उसे दोषी माना जाए। जबकि यह वही आरोपित है, जिसे राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सबसे पहले पकड़ा था।

जयपुर में बम धमाके 13 मई 2008 को हुए थे और 14 मई 2008 को एक ईमेल दो टीवी चैनलों को भेजा गया था, जिसमें इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन द्वारा लिए जाने का दावा किया गया था। राजस्थान पुलिस ने इस पर शहबाज हुसैन को सितंबर 2008 में गिरफ्तार किया था। आरोप यह था कि उसने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्थित साइबर कैफे नवीन कंप्यूटर्स से यह ईमेल किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि यह मेल किसने किया था। अभियुक्त शहबाज के खिलाफ इस बारे में कोई सुबूत नहीं मिला। इसके साथ ही यह भी साबित नहीं हुआ कि शहबाज धमाकों के इस मॉड्यूल में शामिल होकर जयपुर के बम धमाकों के षड्यंत्र में अन्य अभियुक्तों के साथ शामिल था।

जब्त कंप्यूटर से भी पुष्टि नहीं : कोर्ट ने माना कि उक्त साइबर कैफे से जब्त कम्प्यूटर से भी शहबाज की इस वारदात में लिप्त होना साबित नहीं हुआ है। इस बारे में पेश एफएसएल रिपोर्ट पूरी तरह से अभियोजन के पक्ष में नहीं है। इसका कोई पुराना अपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।

कस्टमर रजिस्टर ही जब्त नहीं किया : कोर्ट ने आदेश में कहा कि पुलिस ने साइबर कैफे में रखा हुआ कस्टमर रजिस्टर ही जब्त नहीं किया, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता कि 14 मई 2008 की रात सवा आठ से साढ़े आठ के बीच कौन से कस्टमर वहां आए थे। इसी से शहबाज का साइबर कैफे का इस्तेमाल किया जाना प्रमाणित हो सकता था। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में भी अभियोजन पक्ष शहबाज के खिलाफ अपराध साबित करने में कड़ी से कड़ी जोड़ने में विफल रहा है।

अन्य मामलों में आरोपित होने से जेल से नहीं छूटेगा : कोर्ट द्वारा जयपुर ब्लास्ट मामले में बरी किए जाने के बाद भी शहबाज अभी रिहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ जयपुर जेल में मारपीट के एक केस में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इस मामले में जमानत के बाद ही वह जेल से छूट पाएगा।

15 मिनट में दहल गया था गुलाबी शहर

राज्य ब्यूरो, जयपुर

13 मई 2008 की शाम को 15 मिनट के भीतर गुलाबी शहर के नाम से विख्यात जयपुर का ऐतिहासिक परकोटा क्षेत्र सीरियल ब्लास्ट से दहल गया था। खौफ के सौदागरों ने मंदिरों में आरती के लिए जा रहे लोगों, व्यस्त बाजारों में सड़क पर कारोबार करने वाले गरीब लोगों और मासूमों को निशाना बनाया।

12 जजों ने की सुनवाई : बम धमाकों के पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने विशेष कोर्ट गठित की थी। केस की 12 जजों ने सुनवाई की। इनमें से छह नियमित जज थे और छह के पास अतिरिक्त प्रभार था। फैसला सुनाने वाले जज अजय कुमार शर्मा की छह अक्टूबर 2018 को इस विशेष कोर्ट में पोस्टिंग हुई थी। उन्होंने इस केस की नियमित सुनवाई की और आखिरकार फैसला सुना दिया। शर्मा अगले माह जनवरी में रिटायर हो जाएंगे।

विस्फोट के बाद एटीएस का गठन : जयपुर में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट से सबक लेते हुए राजस्थान सरकार ने एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) का गठन किया था। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्रालय कई बार राज्य सरकार से एटीएस के गठन को लेकर कह चुका था, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था।

यूं एक के बाद एक हुए थे विस्फोट

- 13 मई 2008 की शाम करीब 7.20 बजे पहला बम धमाका ऐतिहासिक हवामहल के सामने खंदा माणक चौक में हुआ।
- दूसरा धमाका शाम 7.25 बजे बड़ी चौपड़ के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास हुआ।
- तीसरा बम धमाका शाम करीब 7.30 बजे छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ
- चौथा बम धमाका भी शाम 7.30 बजे इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ
- पांचवा बम धमाका भी उसी वक्त चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर हुआ। यहां सर्वाधिक 25 लोगों की मौत हुई। लोग भगवान की आरती के लिए जा रहे थे।
- छठा धमाका शाम 7.32 बजे जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ।
- सातवां बम धमाका शाम 7.35 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ।
- आठवां धमाका शाम 7.36 बजे जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ

11 वर्ष सात माह बाद फैसला

प्रथम पृष्ठ से आगे

धमाकों के 11 साल सात माह बाद बुधवार को विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज अजय कुमार शर्मा ने करीब 250 पेज के फैसले में आरोपितों को भादंवि की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 302 (हत्या), 307 (प्राणघातक हमला), 121ए (देश के खिलाफ अपराध), 124ए (राष्ट्रद्रोह), 153 ए (वैमनस्य फैलाना) और विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत दोषी माना है। इन धाराओं में चारों दोषियों को फांसी से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 1272 और आरोपित पक्ष की ओर से 24 गवाह पेश किए गए थे।

बाटला हाउस एनकाउंटर में ये मारे गए : मुहम्मद आतिफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद।

ये तीन हैं फरार : मिर्जा शादाब बेग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा और मुहम्मद खालिद।

एडीसी बैंक मानहानि मामले में सुरजेवाला को मिली जमानत

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : एडीसी बैंक मानहानि मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को यहां की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छूट संबंधी याचिका पर अदालत 15 फरवरी 2019 को सुनवाई करेगी। भाजपा अध्यक्ष एवं गृहमंत्री अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशक हैं। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अहमदाबाद जिला सरकारी (एडीसी) बैंक पर वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद घोटाले का आरोप लगाया था। इसे लेकर एडीसी बैंक की ओर से गांधी व सुरजेवाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 499 व 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत में पेश हुए सुरजेवाला ने खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने 15 हजार रुपये के बांड पर सुरजेवाला को जमानत दे दी। इस मामले में राहुल जुलाई में ही पेश हो गए थे, उन्हें जमानत भी मिल गई थी। सुरजेवाला हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हो सके थे। उनके वकील ने अदालत में हाजिरीमाफी की अर्जी लगाई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्टेट एनबी मुंशी ने अर्जी को ठुकराते हुए सुरजेवाला के खिलाफ 11 अक्टूबर को जमानती वारंट जारी कर दिया था।

राज्य सरकारें छह महीने में गंगा के सभी ट्रीटमेंट प्लांट पूरे करें : एनजीटी

- कहा-उत्तराखंड, उप्र, झारखंड, बिहार व बंगाल गंगा व सहायक नदियों में गंदे नाले व औद्योगिक कचरे को गिरने से रोकें
- उप्र सरकार को कानपुर के रनिया और कंचनपुर गांव में क्रोमियम की डंपिंग रोकने का निर्देश

पर्यावरण से संबंधित फैसलों का यहीं होता है निस्तारण। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा नदी में गंदे नाले गिरने नहीं बंद होने पर प्रशासन को फटकार लगाई है। साथ ही संबंधित सभी लंबित सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं को अगले साल 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। एनजीटी का कहना है कि उत्तराखंड को छोड़ कर दिशा-निर्देशों के बावजूद किसी ने भी गंदे नालों के ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं किया है।

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के दायरे में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर कोई जानकारी नहीं है। साथ ही मैदानी इलाकों में बाढ़ प्रभावित डूब क्षेत्र को लेकर भी कोई योजना सामने नहीं आई है। उत्तराखंड के अलावा किसी अन्य राज्य ने नालों की संख्या का ब्योरा नहीं दिया है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को नदी से विमुख करके किस दिशा में मोड़ा जा रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को गंगा और उसकी सहायक नदियों में गंदे नाले और औद्योगिक कचरे को गिरने से रोकने को कहा है। साथ ही उन्होंने नदी के डूब क्षेत्रों को भी चिन्हित करने को कहा है। साथ ही प्रशासन को इन क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने का भी निर्देश दिया है।

खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह कानपुर के रनिया और कंचनपुर गांव में क्रोमियम की डंपिंग को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जैव विविधता पार्क के विस्तार के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और उसे अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।

खंडपीठ ने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिव के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की गठित निगरानी समिति को भी उसी तरह कार्य प्रगति पर नजर रखनी होगी, जैसे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रख रहे हैं। सभी राज्यों को अपनी अगली तिमाही कार्य प्रगति रिपोर्ट ई-मेल के जरिए 31 मार्च, 2020 तक भेजनी होगी। उल्लेखनीय है कि पिछली बार एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानपुर में रनिया और राखी मंडी में गंगा नदी में घातक क्रोमियम का कचरा गिरने देने पर वहां प्रदूषण कर रही 22 टेनेरियों पर 280 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर भी 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। एनजीटी ने कहा कि पिछले 43 सालों से समस्या का निस्तारण नहीं किया गया, इसीलिए वहां भूमिगत जल भी दूषित हो गया है और लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए घातक हो गया है।

गया के आर्मी कैडेट अब आइएमए देहरादून में लेंगे प्रशिक्षण

नई दिल्ली, प्रेट्र : बिहार के गया स्थित ओटीए में प्रशिक्षण ले रहे आर्मी कैडेट अब देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में प्रशिक्षण ले सकेंगे। जल्दी ही उन्हें आइएमए भेजा जाएगा। गया में खाली हो रही जगह में जल्दी ही सिख लाइट इन्फैंट्री रेजीमेंटल सेंटर बन जाएगा। यह जानकारी बुधवार को सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख कर कहा था कि गया में भारतीय सेना के आफिसर ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) को बंद करना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा था, 'अकादमी ने क्षेत्र में न केवल रोजगार के अवसर मुहैया कराए बल्कि अर्थव्यवस्था में योगदान भी दिया। इसने क्षेत्र में सुरक्षा बोध पैदा करने के अलावा इलाके में बड़ी संख्या में लोगों के जीवनयापन को बल भी दिया।' सेना के अधिकारी ने बुधवार को कहा कि ओटीए गया में कैडेट द्वारा खाली की जा रही जगह पर सिख एलआइ (लाइट इन्फैंट्री) रेजीमेंटल सेंटर बनेगा। वर्तमान में यह उप्र के फतेहगढ़ में राजपूत रेजीमेंटल सेंटर के साथ है।

एचडीआइएल की संपत्तियों की नीलामी पर वधावन को आपत्ति नहीं

मुंबई, प्रेट्र : एचडीआइएल के प्रबंध निदेशक सारंग वधावन ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट से कहा कि उसके रियलिटी समूह की संपत्तियों की नीलामी पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक से एचडीआइएल ने बड़ा कर्ज ले रखा है। संपत्तियों की बिक्री से कर्ज की वसूली की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।

सारंग के पिता राकेश वधावन एचडीआइएल के प्रवर्तक हैं। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सारंग ने एक जनहित याचिका पर जवाब देते हुए अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। याचिका में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा व प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जब्त संपत्तियों के त्वरित निस्तारण और ग्राहकों के जमा रुपये को शीघ्र लौटाए जाने की मांग की गई है। जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस एसपी तावड़े की पीठ ने वधावन को जवाब व संपत्तियों के ब्योरे का हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे। वधावन ने हलफनामे में संपत्तियों की सूची का भी उल्लेख किया है।

सीबीआइ ने एक और चिटफंड कंपनी के निदेशक को किया गिरफ्तार

जासं, कोलकाता : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने एक और चिटफंड कंपनी के निदेशक को निवेशकों से करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम नंदा चंदा है। वह चिटफंड कारोबार करने वाली अमानत ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक हैं। गौरतलब है कि बंगाल में सारधा चिटफंड घोटाले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला था कि कोलकाता की यह कंपनी कथित तौर पर चिटफंड कारोबार में लिप्त था और चंदा ने गैरकानूनी तरीके से उच्च रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों के जरिये करीब तीन करोड़ रुपये जुटाए थे। बाद में निवेशकों के पैसे की धांधली की गई। गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से 19 दिसंबर तक सीबीआइ की रिमांड पर भेज दिया गया।

विधायक चैंपियन की गिरफ्तारी पर रोक से हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हरिद्वार स्थित खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद चैंपियन की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा से निलंबित खानपुर के विधायक चैंपियन और झबरेड़ा (हरिद्वार) से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के बीच लंबे समय से सियासी लड़ाई चल रही है। देशराज के जाति प्रमाणपत्र का मामला अरसे से सुर्खियों में है। शासन की स्क्रूटनी कमेटी उसे सही ठहरा चुकी है। देशराज ने आरोप लगाया था कि फुरकान, पप्पू व पहल सिंह ने विधायक चैंपियन के साथ साजिश रचकर उन्हें व उनके परिवार को सार्वजनिक रूप से गाली देने के साथ ही जाति व बिरादरी पर तंज कसा था। उनकी पत्नी बैजयंती पर भी जाति, रंग के आधार पर भेदभाव करते हुए अपमानित कर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसी के बाद बैजयंती ने पप्पू सिंह, पहल व फुरकान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

शिखर पर उम्मीद

फैसले के बाद आकाश चूम रही गगनचुंबी राममंदिर की चाहत

रामलला से जुड़ी भव्य भावनाओं के साथ गृहमंत्री की घोषणाओं से परवान चढ़ीं आकांक्षाएं

रघुवरशरण, अयोध्या

सुप्रीम फैसले के बाद से रामलला के गगनचुंबी मंदिर की चाहत गगन चूम रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान से यह पूरी तरह परवान चढ़ चुकी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीन माह के भीतर मंदिर निर्माण के लिए शासकीय न्यास का गठन होना है। सवा माह बाद भी सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, पर गृहमंत्री ने इस बीच अपने बयान में दो बार यह कहकर उम्मीदों को शिखर का स्पर्श दिया है कि रामलला का मंदिर गगनचुंबी होगा।

गृहमंत्री की घोषणा रामनगरी की भावनाओं के अनुरूप ही है। रामजन्मभूमि के लिए सदियों चले संघर्ष के दौरान रामलला के मंदिर की भव्यता से जुड़ी परिकल्पना हाशिए पर रही। सारी कोशिश रामजन्मभूमि को विवाद से मुक्ति दिलाने तक केंद्रित रही है। अब निर्णय आने के साथ मंदिर की भव्यता से जुड़ी परिकल्पना पूरी शिद्दत से परिलक्षित हुई है। यह साध इतनी प्रबल है कि रामजन्मभूमि न्यास कार्यशाला में शिलाओं को जिस मंदिर के लिए गढ़ा जा रहा था, वह अब छोटा प्रतीत होने लगा है। रामजन्मभूमि न्यास की ओर से प्रस्तावित मंदिर 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा एवं 128 फीट ऊंचा है।

रामनगरी के अन्य मंदिरों की तुलना में रामजन्मभूमि न्यास के मंदिर की भव्यता असंदिग्ध है पर दुनिया के भव्यतम मंदिर की चाहत के मुकाबले रामजन्मभूमि न्यास की ओर से प्रस्तावित मंदिर कहीं नहीं ठहरता। रामजन्मभूमि न्यास के ही सदस्य पूर्व सांसद डॉ. राम विलासदास वेदांती ने फैसला आने के बाद रामलला का मंदिर दो सौ एकड़ परिसर में बनाए जाने के साथ इसकी ऊंचाई 1011 फीट होने की आकांक्षा जताई थी तो इससे पूर्व मंदिर निर्माण की दावेदारी से जुड़ी संस्था रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इसकी ऊंचाई 1008 फीट होने की इच्छा जता चुके हैं। रामकथा मर्मज्ञ मोरारी बापू भी भव्यतम मंदिर की साध जाहिर करते हुए कह चुके हैं कि रामलला का मंदिर ऐसा हो जैसा दुनिया में दूसरा न हो। राममंदिर की अदालत में पैरोकारी करते रहे नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास रामलला के मंदिर की ऊंचाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तावित श्रीराम की 251 मीटर ऊंची से सवा गुना अधिक चाहते हैं।

भगवान राम की प्रतिमा के लिए अब माझा बरहटा में सर्वे

आनंदमोहन, अयोध्या

भगवान राम की प्रतिमा स्थल के लिए अयोध्या के माझा बरहटा और माझा जमथरा में जमीन को लेकर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। चार-चार लेखपालों की दो टीमें बनी हैं। एक टीम को बरहटा में गाटों की पड़ताल तो दूसरी टीम पर जमथरा के राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। बरहटा में प्रस्तावित स्थल के गाटों की पड़ताल खासतौर से की जा रही है। सोमवार से चल रही प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। डीएम अनुज कुमार के अनुसार गाटा का सर्वे कर जल्द ही अंतिम फैसला ले लिया जाएगा।

भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए पहले मीरापुर द्वाबा में लगभग 62 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया था। जमीन अधिग्रहण से पहले राजकीय निर्माण निगम की टीम 21 नवंबर को परीक्षण के लिए पहुंची थी। स्थलीय निरीक्षण के बाद इस जमीन को प्रतिमा की स्थापना के लिए अनुपयुक्त करार दे दिया गया। हालांकि, उसी दिन माझा बरहटा और जमथरा के प्रस्तावित स्थल भी टीम को दिखाए गए थे।

सूत्रों के अनुसार, अब शासन को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद माझा बरहटा में गाटों का सर्वे शुरू किया गया है। यहां परिसंपत्तियों का आकलन किया जाना है। अगर जमीन के चयन पर मुख्यमंत्री की मुहर लगी तो सर्किल रेट के आधार पर किसानों को मुआवजा देकर यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी आरपी यादव को शासन नामित कर चुका है। वहीं, माझा जमथरा का सर्वे पहले भी हो चुका है। प्रस्तावित जमीन पर मकान का निर्माण नहीं है। यहां लगभग 350 हेक्टेयर जमीन नजूल की है। इसे भी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रखा गया है।

हरियाणा में पांच साल से अध्यापक कर रहे थे छात्राओं का यौन शोषण

अमित धवन, हिसार

हरियाणा में हिसार जिले के एक सरकारी स्कूल में पांच साल से शिक्षकों द्वारा छात्राओं का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपित शिक्षक मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्में दिखाते, उन्हें प्रलोभन देते और नहीं मानने पर फेल कर देने का भय दिखाते। इन्कार करने पर छात्राओं को प्रताड़ित किया जाता। इतना ही नहीं, छात्राओं को चीटियों के बिल पर बैठाकर कटाया जाता था। अब पुलिस ने तीन अध्यापकों के खिलाफ जेजे एक्ट और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया है। दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं।

आदमपुर ब्लॉक के इस सरकारी स्कूल में बीते पांच साल से छात्राओं को प्रताड़ित किया जाता रहा, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। छात्राओं ने तत्कालीन प्राचार्य से इसकी शिकायत की तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। कुछ दिन पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुनीता यादव पॉक्सो एक्ट के तहत जागरूकता शिविर में पहुंचीं तो मामला सामने आया। छात्राओं के मुताबिक शिक्षक शाम साढ़े छह बजे तक एक्सट्रा क्लास तक लगाते थे। इसमें रोका तो सभी छात्राओं को रोका जाता था, लेकिन किसी एक का चयन कर वे मनमानी करते थे।

गत सितंबर में तबादला नीति के तहत सभी शिक्षकों का स्कूल बदल दिया गया था, लेकिन आरोपितों में दो अस्थायी होने के कारण यहीं रह गए, जबकि तीसरे ने दिव्यांगता का हवाला देकर तबादला रद करवा लिया। तबादले के बाद स्कूल में आई एक महिला अध्यापक को भी आरोपित शिक्षकों ने तंग किया था।

> छात्राओं ने पूर्व प्राचार्य और अन्य स्टाफ को बताया था तो उसकी भी जांच होगी। कमेटी का गठन किया जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
> **– अशोक कुमार मीणा, उपायुक्त, हिसार।**

दैनिक जागरण

यदि गलती सुधारना चाहते हैं तो पहले उसे स्वीकार करना सीखिए

नागरिकता कानून की परख

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग को जिस तरह अस्वीकार किया उससे एक बड़ी हद तक इस प्रचार की हवा ही निकली कि यह कानून इस कदर संविधान विरोधी है कि तुरंत खारिज हो जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए इस मामले की सुनवाई को लेकर वैसी कोई तत्परता नहीं दिखाई जैसी तमाम याचिकाकर्ता चाह रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून की संवैधानिकता की परख तय हो गई है तब फिर क्या यह उचित नहीं होगा कि उसका हिंसक विरोध करना बंद किया जाए? कम से कम उन्हें तो यह काम करना ही चाहिए जो संविधान, लोकतंत्र और न्याय की दुहाई देने लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि इस कानून के अराजक विरोध के पीछे एक बड़ी वजह अज्ञानता भी है और शरारत भरी राजनीति भी। इसी राजनीति के तहत नागरिकता कानून को लेकर सुनियोजित तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है। जो इस सच से परिचित हो रहे हैं कि नागरिकता कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना-देना नहीं उन्हें प्रस्तावित एनआरसी से भयाक्रांत करने की कोशिश हो रही है। कोई एनआरसी को नागरिकता कानून का हिस्सा बताने में जुटा है तो कोई उसे धार्मिक आधार पर नागरिकों की पहचान की कवायद साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसे शरारत के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो प्रस्तावित एनआरसी की प्रक्रिया ही नहीं तय की गई है।

नागरिकता कानून को लेकर जारी दुष्प्रचार के खिलाफ केंद्र सरकार को और अधिक सक्रियता दिखाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि यह साफ है कि कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन लोगों को बरगलाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। वास्तव में इसी कारण नागरिकता कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नागरिकता कानून को लेकर किस तरह राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम हो रहा है, इसका संकेत इससे भी मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दायर करीब साठ याचिकाओं में से एक बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों या फिर नेताओं ने दायर की हैं। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं, लेकिन यह तो विचित्र है ही है कि नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले दल लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भी उकसा रहे हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जो एक समय बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए वैसी ही राहत चाह रहे थे जैसी उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के जरिये दी जाने वाली है।

कार्यशैली पर सवाल

उत्तराखंड परिवहन निगम की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर निगम सुर्खियों में है। अब टाटा कंपनी से 150 नई बसें खरीदने का मामला चर्चा में है। खामियों से भरी इन बसों को हालांकि परिवहन निगम कंपनी को वापस कर रहा है और बताया जा रहा है कि सभी बसों का गियर बॉक्स बदला जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि बस खरीद से पहले विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा किया गया, फिर खराब बसें कैसे पहुंच गईं। यहां तक कि परिवहन निगम के अधिकारी इसके लिए गोवा भी गए। मामला तब खुला जब चालकों ने बसों का परीक्षण किया। पता चला कि बसों का गियर लीवर सही नहीं है। अब दिल्ली के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (सीआइआरटी) की रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि गियर लीवर खराब हैं। जांच में यह भी पता चला कि गियर लीवर के मेन प्वाइंट के ठीक पीछे जो यात्री सीट दी गई है, वह खतरनाक है। यात्री का पांव गियर लीवर से टकरा सकता है और इससे हादसे का खतरा है। यह अलग बात है कि मामले के तूल पकड़ने पर हरकत में आए अफसरों ने बसों की तकनीकी जांच सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दिल्ली से कराने के आदेश भी दिए। साथ ही टाटा कंपनी को होने वाले 37 करोड़ के भुगतान पर भी रोक लगा दी गई। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अशोका लीलैंड की बसों में भी खामियां सामने आई हैं। परिवहन निगम ने बसों का जो डिजाइन कंपनी को सौंपा था, उसका अनुपालन ही नहीं किया गया। साफ है कि परिवहन निगम की कार्यप्रणाली में कहीं तो खोट है। आखिर निगम की टेक्निकल टीम ने पहले इन खामियों को क्यों नहीं पकड़ा। यदि परिवहन निगम के पास बसों की खरीद से पहले के परीक्षणों के लिए फुलप्रूफ सिस्टम है तो ये नौबत क्यों आई। सवाल यह भी है कि सिर्फ टाटा ही नहीं, अशोका लीलैंड से खरीदी जाने वाली बसों में कमियां दिखीं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, निगम के कुछ परिचालक सवारियों को बेटिकट यात्रा कराने से नहीं हिचकिचाते तो बसों में अवैध तरीके से सामान ढोने के मामले भी सामने आते रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वजह यह है कि परिवहन निगम में हजारों यात्री सफर करते हैं और यह उनकी सुरक्षा का सवाल है। जरा सी चूक सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। यह सही है कि दोनों कंपनियों को बसों को दुरुस्त करने को कह दिया गया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। परिवहन निगम को अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर संदेश देने की भी जरूरत है।

दुष्कर्म पर नेताओं का दिखावटी आक्रोश

जगदीप एस छोकर

जेएस वर्मा समिति के इस निष्कर्ष की अनदेखी जारी है कि चुनावी प्रक्रिया में ठोस सुधार किए बिना महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी करना असंभव है

हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या कर उसके शव को जलाने की जो नृशंस घटना घटी उससे पूरे देश में गम और गुस्सा दिखाई दिया। देश भर के लोगों का रोष स्वाभाविक भी था, लेकिन जो आक्रोश संसद में और संसद के बाहर विभिन्न दलों के नेताओं ने जाहिर किया वह कुछ अटपटा-सा लगा। अटपटा इसलिए कि जो नेता इस बर्बरता पर इतना आक्रोश दिखा रहे थे उन्हें यह बात क्यों नहीं याद आई कि उनके अपने ही दल इसी मुद्दे पर क्या करते हैं? इस घटना पर छह दलों के नेताओं ने सबसे अधिक आक्रोश जताया। ये दल हैं समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम , तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। इनमें से दो दलों भाजपा और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए जिन्होंने अपने शपथपत्र में लिखा था कि अदालतों में उनके विरुद्ध दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को टिकट देने में ये दो दल अकेले नहीं हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वाइएसआर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने भी ऐसे कई उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिनके विरुद्ध दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे थे। बाकी आक्रोश दिखाने वाले नेताओं के दल भी इसमें पीछे नहीं हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में दुष्कर्म के मुकदमे वालों को टिकट भले ही न दिया हो, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि कोई बाकी दलों से अलग नहीं है। बसपा ने लगातार तीन लोकसभा चुनावों 2004, 2009 और 2014 में दुष्कर्म के आरोप वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए। सपा ने भी ऐसा ही किया था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते दिनों उन्नाव के चर्चित दुष्कर्म मामले में जिस कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया वह भाजपा से निष्कासित विधायक है।

किसी भी समाज के लिए यह बहुत दुखदाई होगा कि उसकी संसद में ऐसे सदस्य हों, जिन पर दुष्कर्म जैसे घृणित अपराध के आरोप लगे हों। खेद है कि हमारी वर्तमान संसद में तीन सदस्य ऐसे हैं जिन पर दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे हैं। ये तीन सांसद भाजपा, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह तो देश की सर्वोच्च पंचायत और लोकतंत्र के मंदिर संसद का हाल है। अगर हम विधानसभाओं में जाएं तो वहां की हालत तो और भी खराब है। अगर दुष्कर्म से आगे बढ़कर ऐसे उम्मीदवारों या विधायकों की संख्या देखें जो 'महिलाओं के विरुद्ध आरोपों' में आरोपित हैं तो वह संख्या और भी अधिक हो जाती है। सवाल है कि दुष्कर्म के खिलाफ नेताओं का यह आक्रोश दिखावटी क्यों है?

आज से करीब सात साल पहले हैदराबाद जैसी बर्बर दुष्कर्म की घटना दिल्ली के वसंत विहार इलाके में घटी थी। चूंकि यह बर्बरता देश की राजधानी में हुई इसलिए उसे लेकर विरोध-प्रदर्शन कहीं ज्यादा देखने को मिला। यह रोष जनता में तो था ही, राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उसकी बहुत भर्त्सना की और कानून को

अवधेश राजपूत

और भी सख्त बनाने की मांग की। इस विरोध के कारण तत्कालीन केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई। उसे देश के आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया। साथ ही यह बताने के लिए कहा गया कि आखिर इन कानूनों में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ मुकदमे बिना किसी विलंब के चलें? किस तरह ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई कर दोषियों को और भी कड़ी सजा दी जा सके? इसमें कोई दो राय नहीं कि जेएस वर्मा समिति ने बहुत मेहनत से काम किया। उसने 30 दिनों में ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में उसने बहुत सारे सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पर कानून में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए, लेकिन जैसा कि देख सकते हैं कि अपराधियों पर उनका कोई खास असर नहीं हुआ। हैदराबाद की जघन्य घटना से भी यह साबित होता है।

जेएस वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट में 44 पृष्ठों का एक अध्याय भी लिखा था, जिसका शीर्षक है 'चुनाव सुधार'। उस अध्याय में लिखा है कि देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो चुनावी प्रक्रिया में ठोस सुधार किए बिना महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी करना असंभव है। समिति ने यह भी कहा था कि जब तक संसद में ऐसे लोग बैठे होंगे जो आपराधिक मामलों में आरोपी हैं तब तक देश की कानून बनाने की शैली और तौर-तरीके पर भी विश्वास करना बहुत कठिन है। समिति ने लिखा कि वह यह जानकर चकित रह गई कि उस समय छह विधायक ऐसे थे जिन्होंने स्वयं शपथ लेकर लिखा था कि उनके विरुद्ध दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे हैं। समिति इस पर भी बहुत चकित हुई थी कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनावों में 27 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए जिनके विरुद्ध दुष्कर्म के मुकदमे चल रहे थे। समिति ने उच्चतम न्यायलय के विचारों का जिक्र करते हुए कहा था कि स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे होने पर संसद ने अगस्त 1997 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राजनीति के अपराधीकरण पर घोर चिंता जाहिर की गई थी। उसमें कहा गया था कि राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने के भरसक प्रयत्न किए जाएंगे। उस अध्याय के अंत में समिति ने लिखा कि राजनीति में अपराधीकरण तभी समाप्त हो सकता है जब राजनीतिक दल यह करना चाहेंगे।

समिति ने आगे लिखा कि हम तो राजनीतिक दलों से केवल निवेदन, प्रार्थना, विनती ही कर सकते हैं कि वे इन सब अच्छे इरादों को वास्तव में कारगर करें। यही बात 25 सितंबर, 2018 को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय के समक्ष आई। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने एक जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना की कि जिनके विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और जिनका संज्ञान न्यायालय ले चुका है उन्हें चुनाव में उम्मीदवार बनाने पर कानूनी तौर पर रोक लगाई जाए। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करने से यह कहकर मना कर दिया कि कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, लेकिन साथ ही उसने संसद से भी कहा कि ऐसे कानून की देश को शीघ्र आवश्यकता है। इसके बाद न्यायालय ने संसद से गुजारिश की कि वह देशहित में जल्द से जल्द यह कानून बनाए। यह बहुत ही दुख की बात है कि इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। आखिर इस सबको देखते हुए हैदराबाद जैसी भयावह घटनाओं पर उनकी ओर से आक्रोश व्यक्त करना अगर दिखावा नहीं है तो और क्या है?

(लेखक आइआइएम अहमदाबाद में प्रोफेसर, डीन एवं डायरेक्टर इंचार्ज रहे हैं)

response@jagran.com

अज्ञानता से उपजा हिंसक विरोध

रामिश सिद्दीकी

नागरिकता कानून पर अशांति फैलाने वाले अपनी ऊर्जा जाया करने के साथ ही अपनी छवि से भी खेल रहे हैं

संसद से नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने और उसके कानून का रूप लेने के बाद देश का माहौल यकायक बदल गया। इसका देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है। बंगाल और दिल्ली में तो विरोध के नाम पर बड़े पैमाने पर आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली। इस हिंसा में सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस कानून को लेकर हर किसी के पास कुछ न कुछ कहने को है, लेकिन नागरिकता कानून कोई नया कानून नहीं है। इसमें तो संशोधन कर यह व्यवस्था भर की गई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार उन अल्पसंख्यकों को तय प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जाएगी जो दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। केवल अल्पसंख्यकों को इसीलिए शामिल किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लाम राजकीय धर्म है।

इसका विरोध कर रहे लोग इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए यह भी कह रहे हैं कि उन्हें एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर स्वीकार नहीं। लोकतांत्रिक देश में कोई किसी भी कानून का विरोध कर सकता है, लेकिन अभी तो विरोध के बहाने हिंसा अधिक हो रही है। इसी कारण सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह विरोध हो रहा है या फिर अराजकता फैलाई जा रही है?

हालांकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि नागरिकता कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई वास्ता नहीं और यह कानून तो उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों को नागरिकता देने का है, न कि किसी की नागरिकता लेने का, फिर भी विरोध के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। जिन तीन पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार लोगों के पास भारत भाग आने के अलावा यदि कोई विकल्प है तो यही कि या तो वे मारे जाएं या फिर अपना धर्म त्याग दें। क्या यह एक हकीकत नहीं और क्या इसी कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लगातार तेजी से कम नहीं होते जा रहे हैं? नागरिकता कानून का पूर्वोत्तर में जो विरोध हो रहा है वह शेष देश के विरोध से अलग है। पूर्वोत्तर के लोगों को भय है कि पड़ोसी देशों से आए लोगों को यदि नागरिकता मिली तो उनकी संस्कृति और भाषा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे किसी खतरे की आशंका शेष देश के लोगों को नहीं-भले ही वे हिंदू हों या मुसलमान, फिर भी आम मुसलमानों में यही डर भरा जा रहा है कि यह कानून उनके

खिलाफ है या फिर इससे उनका अहित हो सकता है। यह एक सोचा-समझा कुप्रचार है। यह कुप्रचार बार-बार के इस स्पष्टीकरण के बाद भी जारी है कि देश के किसी भी नागरिक को न तो नागरिकता कानून से डरने की जरूरत है और न ही प्रस्तावित एनआरसी से। यदि नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी को लेकर सबसे ज्यादा आशंका मुस्लिम समाज के बीच है तो इसका एक बड़ा कारण मुस्लिम समाज का नेतृत्व है जो अपने लोगों को सही जानकारी देने के बजाय उन्हें बरगलाने और उनमें असुरक्षा की भावना भरने का काम कर रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते मुस्लिम समाज को किस्म-किस्म के खतरों का भय दिखाकर उसे सड़क पर उतारने का काम एक लंबे अरसे से होता चला आ रहा है। यह अभी भी हो रहा है। यह नकारात्मक राजनीति तो बर्बादी का रास्ता है। दुर्भाग्य से यह नकारात्मक राजनीति शिक्षा संस्थानों में भी देखने को मिल रही है। नकारात्मक राजनीति में फंसा कोई समाज ढंग से तरक्की नहीं कर सकता। समाज को समृद्ध करने वाले शिक्षा संस्थान आज राजनीतिक टकराव और अशांति का केंद्र बन रहे हैं, जबकि इस्लाम में शांति को सबसे बड़ी अच्छाई कहा गया है।

शांति के माहौल को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। मानव इतिहास साक्षी है कि शांति का माहौल और सकारात्मकता दुनिया में प्रगति और विकास का आधार है। इस्लाम की शिक्षाओं का सार यही है कि जिस समाज में अशांति होगी वहां लोग सामान्य गतिविधि में संलग्न नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमानों को सकारात्मकता की डोर थामने की जरूरत है और साथ ही ऐसे खुदगर्ज नेताओं से खुद को बचाने की भी जिन्हें समाज की कम और अपने स्वार्थ की चिंता ज्यादा है। पैगंबर मुहम्मद साहब ने ज्ञान प्राप्त करने पर बहुत अधिक जोर दिया और उसे सभी के लिए जरूरी बताया, लेकिन आज मुस्लिम समाज में शिक्षा की कमी का मसला बार-बार उठता है। ऐसा क्यों है, इस पर आम मुसलमानों को ही सोचना होगा, क्योंकि उनके तथाकथित नेता तो इस पर विचार ही नहीं करना चाहते।

जितना जरूरी ज्ञान हासिल करना है उतना ही नकारात्मक विचारों से दूर रहना। पैगंबर साहब का सबसे ज्यादा जोर शांति पर रहा। एक अवसर पर पैगंबर साहब और उनके साथी उम्रहा के लिए मदीना से मक्का की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उन्हें हुदैबिया नामक स्थान पर रोक दिया गया। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि मक्का में तीर्थयात्रा पर आने के लिए किसी को रोका नहीं जाता था। इस रोक के बावजूद पैगंबर साहब ने शांति की बहाली को महत्व दिया और वह अपने विरोधियों के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए और वह भी तब जब संधि की शर्तें विरोधियों के पक्ष में थीं। इसे हुदैबिया संधि कहा गया। यह संधि केवल इसलिए संभव हो पाई, क्योंकि पैगंबर साहब ने शांति को सर्वोपरि समझा। यह प्रसंग इस्लाम में शांति के महत्व को दर्शाता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि पहले न्याय मिले फिर शांति आएगी, लेकिन हर कीमत पर शांति इस्लाम का प्रमुख सिद्धांत है। समाज में जब शांति होगी तभी सभी समस्याओं के हल का अवसर मिल सकता है। आज क्या हो रहा है? उग्र और अराजक विरोध का सहारा लिया जा रहा है। आखिर सड़कों पर उतरे कितने लोग जानते हैं कि नागरिकता कानून किसके लिए है? अशांति फैलाने वाले केवल अपनी ऊर्जा ही जाया नहीं कर रहे, बल्कि उसे दूसरों के हित में इस्तेमाल करने के साथ ही अपनी छवि से भी खेल रहे हैं। मुस्लिम समाज को समझना होगा कि यदि वह नकारात्मकता को नहीं त्यागता तो वह अपनी अज्ञानता से उपजी असुरक्षा की भावना से बाहर भी नहीं आ सकता।

(लेखक इस्लामिक मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भिक्षालय

यह दृष्ट संसार अनेक प्रकार के याचकों अथवा भिखारियों का एक बड़ा अभिनय स्थल है। यहां भांति-भांति के अभिनयों एवं भाव-भंगिमाओं द्वारा मनुष्य अपने जीवन यापन के तरीके ढूंढता रहता है। बिना प्रभुकृपा के न उसे अच्छा परिवेश मिल सकता है, न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा ही। जीवनपर्यंत विगत कर्म का लेखा-जोखा उसे वही-वही करने को उत्प्रेरित करता रहता है जो-जो उस कर्म के तहत उसे करना होता है।

बार-बार अज्ञानता के अहंकार एवं अंधकार में डूबा जीव अथवा मनुष्य हर अच्छे काम का श्रेय स्वयं को देने का भ्रम करता रहता है, लेकिन इस रहस्य से प्रायः अनभिज्ञ रहता है कि यदि किसी भी अच्छे, उत्तम एवं सफल काम का मूल केवल वही है तो फिर वह कार्य उसके जीवन की इतनी लंबी अवधि बीतने पर भी पहले क्यों नहीं संपन्न हुआ? भिखारी जीव ईश्वर से जब-तब याचक बन कुछ न कुछ मांगता रहता है। उन्हीं की अनुकंपा से कुछ पाकर इतराता है और अपनी अज्ञानतावश स्वयं को कर्ता मानता रहता है। जब-जब कर्ता भाव से चालाकीवश मनुष्य अपने लक्ष्य को छल-बल से प्राप्त करना चाहता है तो लक्ष्य उससे उतना ही दूर होता चला जाता है और परेशानियां मुफ्त में उसकी चालाकियों का परीक्षण करने के लिए तैयार रहती हैं। प्रभुकृपा का याचक व्यक्ति कोई भी कार्य कर्ताभाव से नहीं करता, बल्कि याचना के उपरांत मिले किसी भी प्रकार के प्रभु निर्णय को ही अपना प्रारब्ध मान वह निष्काम भाव से अपने अभीष्ट की ओर अग्रसर होता चला जाता है। निष्कंटक पथ में स्वयं लक्ष्य अपने को उसे सौंपने को तत्पर रहते हैं। प्रभु द्वारा अपने भक्त के लिए सुनिश्चित मार्ग में बाधाएं अथवा कष्ट झांकने का भी साहस नहीं जुटा पातीं।

इस संसार रूपी भिक्षालय में भिक्षुक बन प्रभुकृपा के पुण्य-प्रसाद से कोई भी रंक राजा बनने का गौरव हासिल कर सकता है। इसके विपरीत संपूर्ण वैभवों से परिपूर्ण नृप भी मानसिक रूप में भिक्षुक सा जीवन जीने के लिए विवश हो सकता है।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

पीड़ा देता हिंसक वातावरण

अंशुमाली रस्तोगी

अपनी ही आंखों के सामने अपने ही देश, समाज और नागरिकों को जलते देखना भला किसे अच्छा लगेगा

यह हमें क्या हो गया है? किस राह चल पड़े हैं हम? जिधर आंख उठाकर देखो, उधर ही हिंसा और उपद्रव नजर आ रहा है। सड़कों पर जो हिंसा है वह तो है ही, सोशल मीडिया पर भी यही सब रात-दिन चल रहा है। भड़काऊ तस्वीरें, बयान, बातें वहां परोसी जा रही हैं। लिखने की आजादी है तो क्या कुछ भी, बिना सोचे-समझे, लिखेंगे। हर कोई लगा पड़ा है, राजनीति की गंगा में अपने हाथ धोने। इस पर खुद ही लगाम कसिए। क्या सोशल मीडिया पर यही सब करने के लिए आए थे हम! यह मंच हिंसा पैदा करने के लिए तो नहीं था! एक जरिया हमें मिला था अपनों से जुड़े रहने का। दुनिया को खुद से जोड़े रखने का। दूरियों को कम करने का। अपनी बात को अपने तक ही सीमित न रख, पूरी दुनिया में फैलाने का। नए रिश्ते कायम कर उन्हें नया नाम, नई पहचान देने का। वक्त-जरूरत किसी की मदद करने का। अपने विचारों को लिखने और दूसरे के विचारों को पढ़ने का। तर्कपूर्ण बहस करने का। कुछ अच्छा पढ़ने का। किंतु हमने तो इस खूबसूरत माध्यम को अपनी कुत्सित राजनीति और सांप्रदायिक सोच से नष्ट कर डाला।

कोई भी संवेदनशील व्यक्ति किसी भी तरह की हिंसा और उपद्रव को सहन नहीं करेगा। उसे हिंसात्मक वातावरण पीड़ा देगा। अपनी ही आंखों के सामने अपने ही देश, समाज और नागरिकों को जलते देखना भला किसे अच्छा लगेगा। हिंदू-मुसलमान होने से पहले हम एक इंसान हैं, यह मत भूलिए। मन में एक-दूसरे के प्रति इंसानियत का भाव रखते हैं, लेकिन किसी के भी बहकावे में आकर हम अपनों के दुश्मन बन जाएं, कितना कठिन है इसे जज्ब कर पाना। जरा सोचिए। कितनी खराब आदत बना ली है हर मसले को 'राजनीतिक रंग' देने की। नेता तो राजनीति का दांव खेल निकल लेंगे, मगर हम-आप कभी धर्म तो कभी जाति की संकीर्णताओं में बांट दिए जाएंगे। मत भूलें हम हिटलर के नहीं भगत सिंह, विवेकानंद, गांधी, आजाद, डॉ. आंबेडकर के देश हैं। कितने ही क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त करवाया था। उन्होंने कभी हमें बंटने नहीं दिया। देश की एकता को मजबूत रखा। खुद फना हो गए, ताकि हम और हमारी पीढ़ियां एक आजाद और सुरक्षित जीवन जी सकें।

ऐसा कुछ भी गलत अपने देश में न होने दें कि पड़ोसी मुल्क हम पर हंसे। निरंतर फैल रही हिंसा को हमें ही रोकना होगा। देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना होगा। अभी हाल ही में हमने गांधी की 150वीं जयंती मनाई है। उनके दिखाए-बताए रास्तों पर चलने का प्रण लिया है, गांधीवाद और गांधी-मार्ग की तारीफ की है। फिर, उसके बाद यह बहशीपन! जरा ठंडे दिमाग से सोचिए इस पर कि हम यह क्या और क्यों कर रहे हैं? यह मुल्क हम सब का है। इसकी साझी विरासत है। क्यों आते हैं किसी के बहकावे में। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। इस हिंसा का जवाब देना होगा हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी को। जरा बताएं, उनसे आंखें मिलाकर क्या दे पाएंगे हम उन्हें जवाब? बोलें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकर हैं)

मेलबाक्स

किसके हितों की अनदेखी

'भारतीय हितों की अनदेखी' शीर्षक से शंकर शरण का लेख जिन मान्यताओं को आधार बनाकर लिखा गया है एकबारगी उनकी समीक्षा आवश्यक है। जैसे-पहली मान्यता है कि दुनिया भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखती है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। संविधान में भारत को एक 'पंथनिरपेक्ष' राष्ट्र घोषित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की है। दूसरी मान्यता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिये हिंदू समेत छह अल्पसंख्यक समुदायों को शरण देने का विरोध हो रहा है, जबकि वास्तविकता में विरोध पड़ोसी देशों में इन उत्पीड़ित समुदायों को शरण देने को लेकर नहीं, बल्कि शरण देने में बरते जा रहे भेदभाव को लेकर है। एक समुदाय विशेष को उसमें शामिल न करने को लेकर है। एक मान्यता यह भी है कि शिक्षा में हिंदू ग्रंथों की अनदेखी की गई है, लेकिन इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि हमने अपने विद्यार्थी जीवन में 'गीता 'और 'रामायण 'जैसे ग्रंथों के अंशों को पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ा है। हालांकि इस लेख की कुछ बातों पर सहमत हुआ जा सकता है। जैसे कश्मीर विस्थापन के मुद्दे पर देश के बौद्धिक वर्ग की चुप्पी, अक्सर चयनात्मक विरोध करने की उनकी प्रवृत्ति आदि निंदनीय हैं और देश के लिए हानिकारक भी। हिंसक प्रवृतियों के समर्थन को तो बुद्ध और गांधी के इस देश ने कभी स्वीकारा ही नहीं। हिंसा करने वालों पर उचित और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वे किसी भी धर्म, संप्रदाय या पंथ से जुड़े हों। एक और मान्यता है कि यूरोपीय देशों की मुस्लिम आव्रजन पर पाबंदी की नीति का भारत को अनुसरण करना चाहिए। यहां लेखक यह भूल गए कि यूरोप के बहुसंख्यक धर्म 'ईसाइयत' और इस्लाम में काफी साम्य है। दोनों सामी धर्म हैं और अपने प्रचार-प्रसार में संलग्न भी। अतः उनकी टकराहट स्वाभाविक है, परंतु भारतीय परिस्थितियों में मुस्लिम आव्रजन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आजाद भारत सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता रहा है। 'वसुधैव कुटुंबकम' तथा 'सर्वधर्म समभाव' इस संस्कृति की विशेषता हैं। मेरी मुख्य आपत्ति शंकर शरण द्वारा भारत को 'हिंदू राष्ट्र' एवं 'दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र' कहने और 'भारत की आत्मा और नियति को हिंदू धर्म से जोड़ने' पर है, क्योंकि इस देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों, राष्ट्र की नींव तैयार करने वाले दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने धर्म को भारत के निर्माण का आधार नहीं माना था।

अनुराग यादव, नेहरू विहार, नई दिल्ली

देश प्रेम सर्वोपरि

नागरिक संशोधन कानून का कुछ स्वार्थी किस्म के लोग विरोध कर रहे हैं। किसी भी बात का समर्थन अथवा विरोध करना हमारा अधिकार है। क्या कोई भी कानून हमको सार्वजनिक वाहनों, इमारतों, किसी व्यक्ति विशेष को अथवा किसी भी प्रकार से जान-माल की हानि पहुंचाने का अधिकार देता है? शिक्षित वर्ग खासकर विद्यार्थियों को राजनीतिक फायदे के लिए मोहरा बनाया जाता है। विद्यार्थियों के बीच कुछ असामाजिक तत्वों के पकड़े जाने से यह पता चलता है कि हम अपराधी किस्म के लोगों की चक्रव्यूह का शिकार हो रहे हैं। कितने उपद्रवियों को तो यह भी नहीं पता की हम विरोध कर किस बात पर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई भाईचारे के साथ रहते हैं। कई मुस्लिम गुरुओं ने भी इस बिल को ठीक मानकर लोगों से शांति की अपील की है जो देश के आपसी प्यार और भाईचारे के लिए अच्छी बात है। वहीं ऐसे स्वार्थी किस्म के लोगों से अपने समाज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। धर्म तथा जाति से पहले देशप्रेम है।

आचार्य राम कुमार बघेल, पलवल

मंथन करने की है जरूरत

नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में छात्रों द्वारा शुरू हुआ आंदोलन अब एक समुदाय के आंदोलन में तब्दील होता दिख रहा है। छात्रों की आड़ में हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों का नुक्सान किया जा रहा है। जिस देश के लिए लड़ रहे हैं, उसकी ही संपत्ति को नष्ट भी कर रहे हैं। जामिया में पुलिस की बर्बरता बहुत ही निंदनीय है। इस पर जांच जरूरी है, लेकिन विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुक्सान पहुंचाने वाले लोग भी किसी अपराधी से कम नहीं हैं। लड़ाई कानून को लेकर है इसे दो समुदायों की लड़ाई न बनाया जाए।

आशीष, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

57 अरब यूरो का नुकसान ब्रिटेन को हो सकता है, यदि वह हार्ड ब्रेक्जिट की प्रक्रिया को अंजाम देता है तो, जर्मनी के बैर्टेल्समन फाउंडेशन की एक अध्ययन रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई है।

आजकल

और मजबूत हो सकते हैं भारत-ब्रिटेन संबंध

जनवरी 2013 के आखिरी सप्ताह में लंदन से लिखी जाने वाली पटकथा अब शायद 31 जनवरी, 2020 को अपने अंजाम तक पहुंच जाए। यह अलग बात है कि इसमें ऐसे कई सवाल निहित होंगे जिनके आधार पर भविष्य की कड़ियां निर्मित की जाएंगी। लेकिन इसमें अहम सवाल यह होगा कि ब्रिटेन के 'ग्रेट ब्रेक्जिट डन' के बाद उसकी तस्वीर क्या होगी? क्या वह ग्लोबल ब्रिटेन बनेगा या फिर एक अलग-थलग पड़ जाने वाला राष्ट्र जिसे अभी कई आंतरिक विभाजनों से भी गुजरना होगा?

डॉ. रहीस सिंह
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

पिछले दिनों ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए संपन्न चुनावों के परिणाम कई संदेश समेटे हुए हैं, इसलिए इनकी ब्रिटेन व यूरोप सहित पूरी दुनिया के लिए महत्ता बढ़ जाती है। इन चुनावों से जुड़ी पहली बात यह है कि बीते चार वर्षों में तीसरी बार आम चुनाव हुए हैं, इसलिए अब ब्रिटेन की जनता ने राजनीतिक स्थायित्व का चुनाव किया है। लेकिन दृढ़ नेतृत्व के रूप में बोरिस जॉनसन को चुनना ब्रेक्जिट को ही नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को अहम मानते हैं, यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है। क्या इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि भारत में जिस राष्ट्रवाद की परिकल्पना के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिटेन उसी परिकल्पना के तहत भारत को साथ लेकर आगे बढ़ने का मन बना चुका है?

ब्रिटेन का राष्ट्रवादी नजरिया एक निश्चित संदेश देता है और इस बात का समर्थन करता है कि भारत ने पिछले दिनों कुछ कानूनों में परिवर्तन किया या जो नए कानून बनाए, ताकि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, का पुरजोर समर्थन करता है। हां एक बात ध्यान देनी होगी कि पश्चिमी दुनिया में जो 'नेशन फर्स्ट' की बयार चली है वह किस हद तक दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के हितों को प्रभावित कर सकती है। अभी तक यह देखने में आया है कि डोनाल्ड ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' उदारवाद की बजाय संरक्षणवाद का समर्थन करता है। अगर यही ट्रेंड यूरोपीय देशों द्वारा अपनाया गया तो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक स्पेस कम होने की आशंका है।

इन मुद्दों पर लड़े गए थे चुनाव : ब्रिटेन में कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिन पर चुनाव लड़ा गया जैसे- ब्रेक्जिट, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, अपराध, अर्थव्यवस्था, कार्बन उत्सर्जन और स्कॉटलैंड। इनमें नेशनल हेल्थ सर्विस या अपराध जैसे मुद्दे तो आधारभूत थे जो ब्रिटेन के सामान्यजन को प्रभावित करते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस का उद्देश्य ब्रिटेन के सभी लोगों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन लेबर पार्टी इस सर्विस पर खर्च में 4.3 प्रतिशत वृद्धि करने का वादा कर रही है और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन बोरिस जॉनसन पर इस सर्विस को अमेरिका को 'बेचने के लिए' रखने का आरोप लगा रहे थे। विशेष बात यह है कि ब्रिटेन के चुनाव में अपराध और सजा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाते थे, लेकिन हाल में लंदन ब्रिज पर हुए हमले ने इसे एक अहम मुद्दा बना दिया था। इस चुनाव में तीन मुद्दे अहम माने जा सकते हैं। पहला- स्कॉटलैंड की आजादी, दूसरा अर्थव्यवस्था और तीसरा ब्रेक्जिट। वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड की आजादी के लिए हुए जनमत संग्रह ने ब्रिटेन में एक अभूतपूर्व परिस्थिति पैदा कर दी थी। स्कॉटलैंड का अधिकांश मतदाता यूरोपीय यूनियन में बने रहना चाहता है, क्योंकि वह मान रहा है कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए बोरिस जॉनसन के सामने यह चुनौती होगी ब्रेक्जिट की भावना से स्कॉटलैंड के लोगों को दूर रखना।

अर्थव्यवस्था और ब्रेक्जिट कमोबेश एक दूसरे से जुड़े मुद्दे माने जा सकते हैं। इन चुनावों में जो घोषणापत्र राजनीतिक दलों ने जारी किए गए, उनमें से केवल स्विनसन की लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के ही आर्थिक घोषणापत्र को ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज ने सही माना। कारण यह कि इसने मामूली कर वृद्धि और खर्च को बढ़ाने का वादा किया था। इसके विपरीत कंजरवेटिव पार्टी करों में कटौती करते हुए सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करने का वादा लेकर चुनाव मैदान में उतरी थी, जबकि लेबर पार्टी ने 'अर्थव्यवस्था के नियमों को फिर से तय करने' का वादा किया था ताकि सभी को लाभ मिल सके। यदि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का माइक्रो-आब्जर्वेशन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि कंजरवेटिव्स का वादा परिस्थितियों से बहुत तालमेल नहीं खाता।

बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट पूरा करने के संदेश को जनता के बीच लेकर गए थे तो मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन क्या बोरिस जॉनसन की बात से जनता यह जान पाई कि ब्रेक्जिट का अंकगणितीय लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी? जॉनसन चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे थे कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो वे नई संसद में आधिकारिक रूप से 'विदड्रॉल समझौता' कहे जाने वाली ब्रेक्जिट डील को पास करवा लेंगे और 31 जनवरी को यूके को यूरोपीय संघ से निकाल लेंगे। इसके बाद 2020 के अंत कर उनकी कोशिश रहेगी कि वे स्वतंत्र रूप से यूरोप, अमेरिका और दूसरे अहम साझेदारों के साथ नए व्यापारिक समझौते कर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन की जनता ने बोरिस जॉनसन को इसलिए बहुमत दिया है कि वे ब्रिटेन को ईयू से जल्द से जल्द बाहर निकालें। लेकिन सवाल यह उठता है कि यूके और ईयू इससे किस तरह से प्रभावित होंगे। इन पर पड़ने वाला प्रभाव ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रिश्तों को भी प्रभावित करेगा। दरअसल ब्रेक्जिट के पीछे एक गुलाबी तस्वीर यह दिखाई जा रही है कि वर्तमान समय में जर्मनी व फ्रांस का यूरोपीय संघ पर नियंत्रण है और ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन स्वतंत्र राष्ट्र होगा, उसकी अपनी नीतियां होंगी और वह एक दिन पुराना वैभव फिर से प्राप्त कर लेगा। लेकिन जर्मनी के बैर्टेल्समन फाउंडेशन की स्टडी के अनुसार यदि हार्ड ब्रेक्जिट (यानी बिना समझौते के ब्रेक्जिट) होता है तो इसका असर भी व्यापक होगा। ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन ईयू के देश भी इसकी चपेट में आएंगे। इस स्टडी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की वार्षिक आय में करीब 57 अरब यूरो का नुकसान हो सकता है, जबकि ईयू को 40 अरब यूरो का। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भी शुरू में नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

फिलहाल ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की पुनर्स्थापना में बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा जिससे आर्थिक प्रक्रिया और मंद पड़ेगी। शायद इसे ही देखते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के गंभीर आर्थिक और राजनीतिक परिणाम होंगे। रही बात भारत पर इसके असर की तो इस संबंध में मिले-जुले आकलन एवं अनुमान सामने आ रहे हैं।

बहरहाल बोरिस जॉनसन को सत्ता तक ले जाने में उनके प्रो-इंडिया फार्मूले की निर्णायक भूमिका रही है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि नई सरकार भारत के साथ बेहतर संबंध रखेगी। यह भी संभव है कि 31 जनवरी को यूके के यूरोपीय संघ से निकालने के बाद बोरिस जॉनसन जितनी तेजी से यूरोप, अमेरिका और दूसरे अहम साझेदारों के साथ नए व्यापारिक रिश्ते स्थापित करने की दिशा में बढ़ेंगे, उतनी तेजी से ब्रिटेन में भारत के लिए स्पेस निर्मित होगा। ऐसी स्थिति में हम मान सकते हैं कि 'टू ग्रेट नेशंस, वन ग्लोरियस फ्यूचर' के निर्माण की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में 'अपराजेय संयोजन' (अनबीटेबल कॉम्बिनेशन) कहीं अधिक ताकत प्राप्त करेगा।

ब्रिटेन के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। फाइल फोटो

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद ब्रेक्जिट

ब्रेक्जिट के पश्चात भारत पर पड़ने वाले प्रभावों और भारत-ब्रिटेन संबंधों को कुछ अन्य बिंदुओं के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इसका असर करेंसी अस्थिरता के रूप में दिख सकता है, क्योंकि पाउंड व यूरो के अवमूल्यन की आशंका है। कुछ अर्थविशेषज्ञों के अनुसार पाउंड में 20 प्रतिशत गिरावट की आशंका है, ब्रिटेन में वृद्धि हासिल कर रही भारतीय कंपनियों को इससे खासा नुकसान हो सकता है। हालांकि भारत सरकार लघु और मध्यम अवधि में करेंसी अस्थिरता से समग्र व्यापार पर पड़ने वाला प्रभावों का आकलन कर रही है। लेकिन भारत सरकार को ब्रेक्जिट को ध्यान में रखकर 'सिंगल-करेंसी ब्लॉक' के साथ साथ मुक्त व्यापार पर फिर से कार्य (री-वर्क) करने जरूरत होगी।

ब्रेक्जिट के बाद कमोडिटी और कच्चे तेल की कीमतों के लंबे समय तक कमजोर बने रहने की संभावना है। यह स्थिति भारत के लिए अनुकूल होगी। ब्रेक्जिट के पश्चात ब्रिटेन तुलनात्मक रूप से कमजोर होगा और उसे व्यापार तथा निवेश भागीदारों की ज्यादा जरूरत होगी। उस स्थिति में भारत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह स्थिति स्वयं ब्रिटेन के हित में कितनी होगी? इस संशययुक्त परिणाम से दोनों देशों के संबंध निर्देशित होंगे। ब्रेक्जिट का असर वैश्विक आर्थिक विकासदर (ग्लोबल ग्रोथ) पर भी पड़ेगा। यह कमजोर पड़ेगी लिहाजा कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए। इस स्थिति का भारत पर मिश्रित असर होना चाहिए। लेकिन ब्रेक्जिट के पश्चात भारत की टाटा ग्रुप समेत कई कंपनियों के राजस्व पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है।

ब्रिटेन भारतीय कंपनियों के लिए गेटवे ऑफ ईयू की तरह रहा है। इसलिए ब्रेक्जिट भारतीय कंपनियों के लिए अल्पकालिक संकट उत्पन्न कर सकता है। वैश्विक वित्तीय बाजार में चूंकि अस्थिरता की संभावनाएं हैं जिससे दुनिया भर के बाजारों में सिकुड़न पैदा हो सकती है। चूंकि पाउंड प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी के मुकाबले कमजोर होगा जिसे मजबूती की जरूरत होगी। इसे भारत अकेले मजबूती नहीं दे सकता यानी उसे अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। सेंसेक्स एवं निफ्टी के भी इस बदलाव से शार्ट-टर्म दबावों से गुजरने की आशंका है। यही नहीं, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन जटिल 'ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर' से बाहर निकल आएगा। ऐसे में भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में एक डीरेगुलेटेड और फ्री मार्केट की उम्मीद कर सकती हैं, जो उनके लिए दीर्घकाल में लाभ लेकर आ सकता है। ब्रेक्जिट से ब्रिटेन को नए ट्रेडिंग पार्टनर, पूंजी तथा श्रम के स्रोत खोजने की जरूरत होगी। ब्रिटेन को बहुत अधिक संख्या में कुशल श्रम की आवश्यकता होगी और अंग्रेजी बोलने वाली जनसंख्या के साथ भारत के लिए यह फायदेमंद होगा। यूरोप से माइग्रेशन न होने की वजह से ब्रिटेन अन्य देशों के माइग्रेशन के लिए सक्षम होगा, जो कि भारत के हित में है।

भारत पिछले कई वर्षों से यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश में लगा हुआ था। पिछले वर्ष मार्च में ब्रसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता को देखते हुए माना जा रहा था कि इस मुद्दे पर निकट भविष्य में समझौता हो सकता है। कहा जा रहा था कि यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के रहने से इस दिशा में तेजी से प्रगति होगी। लेकिन अब जब ब्रिटेन खुद यूरोपीय संघ से निकल रहा है, तो मुक्त व्यापार समझौते का भविष्य भी अधर में लटकता दिख रहा है।

खरी-खरी

एक रूह... जो कुछ भी नकार सकती है

शांतिलाल जैन

मिस्टर डिनायल में नकारने की एक अद्भुत प्रतिभा है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? इसके लिए आपको उनकी रूह को महसूस करना होगा। रूह जो समूचे आर्यावर्त में भटक रही है और मौका-जरूरत इस या उस शरीर में आवाजाही करती रहती है। आजाद भारत में उसकी आवाजाही सबसे ज्यादा अमात्य परिषद में देखी गई है। कुछ दिनों पहले ही उसे वित्त-प्रमुख के शरीर में देखा गया, जो कह रहे थे कि जीडीपी गिरी नहीं है, ये हमारे अर्थव्यवस्था चलाने का नया अंदाज है। वो सीमांत प्रदेश-प्रभारियों में दिखाई पड़ती है, जो असामान्य परिस्थितियों को स्थिति के सामान्य होने का नया अंदाज कहते हैं। आप उससे कहिए कि देश में भुखमरी है। वो तुरंत जनपरिषद के सदस्यों के भोजन करते हुए फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर डालेगी। फिर आप ही से पूछेगी, 'बताइए श्रीमान, कहां है भुखमरी?'

वो मृत्यु को नकार सकती है, 'ये किसानों की आत्महत्याएं नहीं हैं, यह तो यमदूतों द्वारा आत्माएं ले जाने का नया अंदाज है।' वो अनावृत्त होते नायकों से कहलवा देती है, 'ये सियासत में खजुराहो को साकार करने का हमारा नया अंदाज है।'

एक बार मैंने रूह से पूछा, 'तुम गंभीर से गंभीर मसलों को भी इतनी मासूमियत से कैसे नकार लेती हो?' वह बोली- शुतुरमुर्ग मेरे इष्टदेव हैं। मैं उनसे प्रेरणा और शक्ति ग्रहण करती हूं। तूफान आने से पहले रेत में सिर छुपा लेती हूं। जब गुजर जाता है, तब सवाल करने वालों से ही सवाल पूछ लेती हूं कि कहां है तूफान? जवाब सुने बगैर रेत में फिर सिर घुसा लेती हूं।

संकटों से निपटने का उसका ये अंदाज आर्यावर्त के राज-मंदिर की हर प्रतिमा में उतर आया है। उसके डिनायल अवाक कर देने वाले होते हैं। मिस्टर डिनायल की रूह दंगे करवाने वालों में समा सकती है, दुष्कर्म करने वालों में समा सकती है। वह आपको न्याय के पहरेदारों में मिलेगी, वह पावर की हर पोजीशन में मिलेगी। इस रूह का कोई चेहरा नहीं होता, वो बेशर्म होना अफोर्ड कर पाती है। दिल भी नहीं होता, निष्ठुर होना अफोर्ड कर पाती है। जिगर तो होता ही नहीं है, तभी तो वो कायराना हरकतें कर पाती है।

वो जिस शरीर में उतर आती है, उसमें सच स्वीकार करने का माद्दा खत्म हो जाता है।

ट्वीट-ट्वीट

जाफराबाद (दिल्ली) की भीड़ ने कई पुलिसकर्मियों को घायल किया, इन तस्वीरों को किसी सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया? कोई मानवाधिकार वाला इनके लिए रोया, सड़कों पर कोई कैंडल लेकर निकला? क्या पुलिस की वर्दी में इंसान नहीं होता।
स्वामी दीपांकर@swamidipankar

'असम में हालात कुछ हद तक सामान्य हो गए', पर जापानी प्रधानमंत्री एबी शिंजो को अपना असम दौरा रद करना पड़ा। ऐसी हिंसा के कारण पहले से ही शंकालु जापानी कंपनियां भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में निवेश करने से और ज्यादा हिचकेंगी। चीन यही तो चाहता है कि वहां कोई विदेशी कंपनी निवेश करने के लिए ही न जाए।
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

ऐसी काफी संभावनाएं हैं कि मुशर्रफ को सुनाई गई फांसी की सजा पर तामील होने से तो रही, लेकिन अगर कोई जज किसी पूर्व सेना प्रमुख और तानाशाह को राष्ट्रद्रोह के मामले में सजाए मौत सुनाए तो यह पाकिस्तान के इतिहास में एक बड़ा पड़ाव है।
शेखर गुप्ता@ShekharGupta

हिमाचल प्रदेश डायरी

हंगामा है क्यों बरपा, 'नाटी' ही तो की है

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

बीते दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए धर्मशाला पहुंचे पक्ष-प्रतिपक्ष का एक भोज मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी की याद दिला गया। उनकी इस गजल को हर कोई पसंद करता है। गुलाम अली के माध्यम से यह जन-जन में पहुंची थी... 'हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है/ डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है।' सत्र के बीच मुख्यमंत्री की ओर से रात्रिभोज का आयोजन किया गया था। सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के विधायक, अफसर और पत्रकारों को भी बुलाया गया था। मुख्यमंत्री मेजबान के सभी से मिले।

कुछ चुनिंदा बड़े अफसरों के चेहरे से नाराजगी टपक रही थी, कुछ विधायकों के चेहरे खिले हुए थे और कुछ 'राडार' पर चल रहे मंत्री खुश दिखने का पूरा उपक्रम कर रहे थे। मंच भी बना था जहां संगीत से जुड़े लोग गा रहे थे। फिर नाटी यानी हिमाचल के सामूहिक परंपरागत नृत्य की बारी आई। वातावरण नाचने का बन गया। इस बीच मुख्यमंत्री भी नाचे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि यह जश्न आखिर किसलिए? अगले दिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह इस प्रकार के आरोपों से आहत हैं। वह चाहते तो बात को आई-गई समझ कर टाल देते, लेकिन उन्होंने इसे महसूस किया और सदन में सफाई दी जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था मंशा यही थी कि सब इकट्ठे हों।

लेकिन इस पर बवाल किया जा चुका था। तिल के इस ताड़ में असल मुद्दे गुम हो गए। इसे कहते हैं मुद्दाविहीनता के आलम से मुद्दा तलाशना। एक चित्र अक्सर ध्यान आकृष्ट करता है जिसमें प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार, दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर राम लाल और एक अन्य मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नाटी कर रहे हैं। कुछ चित्रों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी नाटी करते हुए दिखते हैं। साफ है कि उन कार्यक्रमों में अगर तब के प्रतिपक्ष के लोग होते, तो उन्हें भी नाचने से परहेज न होता। लेकिन ये कोई मुद्दे नहीं थे। यह भी मुद्दा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस के कुछ लोग और वामपंथी विधायक राकेश सिंघा क्यों नाचे। क्या नेताओं का नाचना गुनाह है?

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोकनृत्य नाटी का एक दृश्य। (प्रतीकात्मक)

अगर पक्ष और प्रतिपक्ष सदन में तल्ख तेवरों में बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या यह है कि वे बाहर भी तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ें? नाटी अगर संस्कृति का हिस्सा है, खिन्नू वाला गीत अगर संस्कृति का हिस्सा है तो क्या उन पर नाचने वाले राजनीतिज्ञ 'विदेशी तत्व' हैं? क्या उन्हें हक नहीं नाचने का? वे इंसान नहीं? सरकार के करीब हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं अपेक्षाएं होती हैं। यह अलग बात है कि कभी इधर, कभी उधर दौड़ाए जाने वाले 'खिन्नू' यानी गेंद वाले गीत पर रमेश धवाला जम कर नाचे। हंगामा बरप गया, यह और बात है जबकि थोड़ी सी नाटी ही तो की थी।

त्रासदी यह है कि सवाल उठाने वाले वहां खामोश हो जाते हैं जहां चोरी या डाके की बात आती है। धर्मशाला में विधानसभा सत्र के नाम पर कितनी गाड़ियां किसकी मर्जी या हेकड़ी से चलती हैं, क्या उस फिजूलखर्ची में केवल पक्ष और प्रतिपक्ष या अधिकारी ही शामिल हैं? कितने बैरियरों पर आज भी हफ्ता मांगा जाता है, क्या वह चोरी नहीं है? कितने अस्पताल सिर्फ रैफरल यूनिट बन गए हैं, उस पर बात क्यों नहीं? आयुर्वेदिक घोटाला कितने दिनों के बाद जांच को निर्णायक मोड़ पर देखेगा? कितने सामान्य प्रसव के मामलों को गंभीर बता कर टांडा या आइजीएमसी भेज दिया जाता है, यह मुद्दा क्यों नहीं? बड़े-बड़े पीएचडीधारकों, इंजीनियरों, एमफिल किस्म के लोगों से पटवारी की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं हुई, क्या यह मुद्दा नहीं है? भर्ती में युवाओं का दम फूल रहा है, क्या यह मुद्दा नहीं है? चिट्टा कितने भविष्य काले कर रहा है, इस पर बात कौन करेगा? मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे प्रदेश के ऊर्जा विभाग को और हाथ चाहिए, इस क्या यह मुद्दा नहीं है? सवाल यह भी एक दिन के रात्रिभोज के न करने से क्या प्रदेश कर्ज के जाल से मुक्त हो जाएगा? सीएजी की रपट के सवाल मुद्दा होने चाहिए न कि नाचना-गाना।

कुछ बातों का ध्यान सरकार को भी रखना चाहिए था। एक तो इस भोज का समय बदला जा सकता था। छह दिवसीय सत्र में जब रोज वाकआउट धारावाहिक प्रसारित हो रहा था, शाम को इस प्रकार के मंजर को दुनिया स्वाभाविक रूप से अजूबे के तौर पर ही देखती। यह परंपरा से हटकर था, लेकिन नई परंपरा के लिए भी माकूल वक्त हो तो परिणाम अच्छे आते हैं। दूसरा, जहां यह मुद्दा हो जाए कि मेरे निमंत्रण पत्र पर मुख्यमंत्री का नहीं, किसी और का नाम है, वहां परिपक्वता की उम्मीद किससे करें? जहां तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से अधिक सफेद कैसे की तर्ज पर यह देखा जा रहा हो कि कौन किस मेज पर बैठा, वहां किससे कहें कि यह मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र में लोक समेत जितने स्तंभ हैं, वे मुद्दों के करीब रहें तो यह ठीक जी लेगा।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

प्रणब मुखर्जी के सुझाव से सहमत हैं कि संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए?

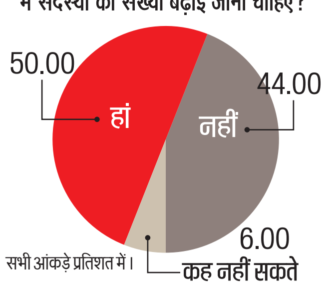

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
विपक्षी दलों द्वारा सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग करना उचित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कौवा लेकर उड़ गया बाबू तेरे कान,
यह सुन दौड़ लगा दिए किंतु न देखा कान।
किंतु न देखा कान मान लीं बातें झूठी,
सीएए पर रार है इसी भांति अनूठी।
खड़ा किए कुछ लोग बना कर इसको हौवा,
भले कान के पास न फटका कोई कौवा।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुशर्रफ को मृत्युदंड

सजा से सदमे में पाकिस्तान की सेना

पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रहे चुके जनरल परवेज मुशर्रफ को बचाकर सेना अपने 'दबदबे' को बचाना चाहती है। इसलिए पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा मुशर्रफ को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद से टॉप सैन्य लीडरशिप सकते में है

शाहिद ए चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक 76 वर्षीय जनरल परवेज मुशर्रफ फिलहाल दुबई के एक अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद छह के तहत अदालत ने मुशर्रफ को देश में आपातकाल लगाने के लिए दोषी पाया, जो नवंबर 2007 में वहां लगाई गई थी।

दरअसल पाकिस्तान के 72 वर्ष के वजूद में लगभग आधे समय तक सेना ने शासन किया है जिसमें तीन अन्य जनरलों- अयूब खान, याह्या खान (जिन्होंने अयूब खान से कमान संभाली) और जिया-उल-हक ने भी जबरन सत्ता पर कब्जा किया और संविधान का उल्लंघन किया। लेकिन इनमें से किसी को भी ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा। लिहाजा मुशर्रफ पहले सैन्य शासक हैं जिन पर मुकदमा चलाया गया और देशद्रोह का दोषी पाया गया।

लेकिन इस फैसले पर सेना ने गुस्सैल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानूनी प्रक्रिया को अनदेखा किया गया है। सेना की इस प्रतिक्रिया से यह अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि मुशर्रफ फांसी के फंदे पर लटकने से बच जाएंगे और उन्हें दुबई से पाकिस्तान लाने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मुशर्रफ से सेना का विशेष लगाव है। हां, यह संभव है कि उनके कुछ चाहने वाले अब भी सेना में मौजूद हों। दरअसल, इस प्रतिक्रिया को सेना बनाम सिविलियन की दृष्टि से देखना गलत न होगा। सेना किसी भी सूरत में प्रशासनिक कार्यों में अपने दखल पर विराम लगा देखना नहीं चाहती, वह चाहे अदालत के जरिये ही क्यों न हो।

सेना की मीडिया सेल इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों की रैंक एंड फाइल ने विशेष अदालत के फैसले को दुःख व गुस्से के साथ सुना है। जबकि सेना प्रवक्ता आसिफ गफूर ने कहा, 'एक पूर्व सेना प्रमुख, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन व पाकिस्तान का राष्ट्रपति, जिसने देश की 40 वर्ष से अधिक सेवा की हो, देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़े हों, वह निश्चित रूप से गद्दार नहीं हो सकता।'

पाकिस्तान का सिविल राजनीतिक तंत्र चाहता है कि सेना सिर्फ सीमा पर या बैरकों में रहे, और देश के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करे। नवंबर 2007 में आपातकाल घोषित होने पर पाकिस्तान की जनता ने इसके विरुद्ध आंदोलन किया था। मुशर्रफ द्वारा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को 'बर्खास्त' किए जाने पर वकील भी सड़कों पर उतर आए थे। इन सबके कारण जहां पाकिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें लौटीं, जो उसके इतिहास में पहली बार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने में भी सक्षम रहीं, वहीं सेना को भी एहसास हो गया कि वह 'तख्ता पलट से राज' नहीं कर सकती। इसलिए उसने रणनीति बदलते हुए 'प्रॉक्सी शासन' को अपनाया और जनता से अपने ही नुमाइंदे (इमरान खान) का 'चुनाव' करवा लिया। अब सेना को डर है कि कहीं 'प्रॉक्सी शासन' व्यवस्था भी उसके हाथ से न निकल जाए, इसलिए उसे यह दिखाने की जरूरत है कि हुक्मरानी अभी उसी की चल रही है। इसीलिए वह मुशर्रफ को बचाकर स्वयं को बचाने का प्रयास कर रही है। वह ऐसा मार्ग नहीं खुलने नहीं देना चाहती जो बाद में उसके लिए ही परेशानी का कारण बन जाए।

पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद छह के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बल प्रयोग या किसी अन्य असंवैधानिक तरीके से संविधान को रद करता है या उलट-पलट करता है या स्थगित करता है या प्रसुप्तावस्था में रखता है या ऐसा करने की साजिश करता है तो वह उच्च राजद्रोह का दोषी होगा। उच्च राजद्रोह के लिए 'उच्च राजद्रोह (सजा) कानून, 1993, के तहत सजा मौत या आजीवन कारावास है। पाक में कोई ऐसा सैन्य शासक नहीं हुआ जिसने अनुच्छेद छह को ताक पर न रखा हो और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि भविष्य में कोई अन्य सैन्य शासक ऐसा नहीं करेगा। इसलिए भी सेना के लिए मुशर्रफ को फांसी से बचाना आवश्यक हो जाता है।

मुशर्रफ के संदर्भ में फैसला 2-1 के बहुमत से किया गया। विशेष अदालत की खंडपीठ के प्रमुख थे पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ और दो अन्य सदस्य थे सिंध हाई कोर्ट के न्यायाधीश नजर अकबर व लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश शाहिद करीम। न्यायाधीश अकबर निर्णय से असहमत थे।

अब मुशर्रफ के समक्ष विकल्प क्या हैं? वह दुबई से शायद इंग्लैंड चले जाएं, जहां से उन्हें वापस लाना कठिन हो जाए, खासकर इसलिए कि उन्हें वापस लाने या फांसी देने में सेना की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। दूसरा यह कि 30 दिनों के भीतर वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, जिसके लिए उन्हें स्वयं अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, जाहिर है वह ऐसा सेना से सुरक्षा की गारंटी मिलने पर ही करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट मुशर्रफ की अपील को ठुकरा देता है तो वह क्षमा के लिए राष्ट्रपति से अपील कर सकते हैं। मुशर्रफ ने अभी खुद कुछ नहीं कहा है कि वह क्या करेंगे, शायद विस्तृत निर्णय आने के बाद वह अपनी योजना तैयार करें।

परवेज मुशर्रफ। फाइल फोटो

हालांकि दिसंबर 2007 में आपातकाल हटाने के बाद मुशर्रफ ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विधेयक पारित कराए थे, लेकिन नवाज शरीफ की सरकार ने दिसंबर 2013 में उनके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराया और मार्च 2014 में जब वह अदालत में मौजूद थे तो उन पर आरोप लगाए गए, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वह दोषी नहीं हैं। वर्ष 2016 में वह पाकिस्तान छोड़ गए कुछ सप्ताह बाद लौटने का वायदा करते हुए, पर वह लौटे नहीं, शायद लौटेंगे भी नहीं।
- इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

5500 प्रवासी परिंदों की संख्या हो सकती है दून के आसन वेटलैंड में। देश के पहले कंजरवेशन रिजर्व आसन वेटलैंड में प्रवास पर आए परिंदों की विधिवत गणना जनवरी में हो सकती है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 19 दिसंबर 2019

बिस्मिल के घर को अब भी संग्रहालय का इंतजार

शाहजहांपुर में खिरनीबाग मोहल्ला स्थित शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का मकान (नीले रंग से रंगा हुआ)। जागरण

अंबुज मिश्र, शाहजहांपुर

काकोरी कांड : शहीदी दिवस पर विशेष

- **शहादत के 92 साल बाद भी नहीं दिया ध्यान, बरसों से उठ रही है मांग**

शाहजहांपुर का खिरनीबाग मोहल्ला...। यहां कालीबाड़ी मंदिर के सामने तंग गलियों में स्थित है क्रांतिकारी शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का घर। वह बिस्मिल, जिनके नाम पर देश के तमाम शहरों में संग्रहालय बने हुए हैं। तुर्की में उनके नाम पर शहर बसा हुआ है, पर उनके घर की कोई सुध नहीं ले रहा। बिस्मिल के शहीद होने के बाद अब उस घर में दूसरे लोग रहते हैं। इसे संग्रहालय बनाने की मांग तो उठी थी, मगर आगे नहीं बढ़ सकी।

इस तरह बिका यह मकान : 100 गज से भी कम दायरे वाले जिस मकान में राम प्रसाद बिस्मिल रहा करते थे, अब जर्जर हो चुका है। मकान में रहने वाले रविशंकर से मुलाकात हुई। वह बोले कि इस घर को उनके बाबा नारायण लाल ने करीब 70 वर्ष पहले खरीदा था। रविशंकर के पिता राजाराम व बाबा नारायण लाल अब जीवित नहीं हैं। इस घर में रविशंकर, राजाराम के भाई रामकुमार, अरविंद, शिवकुमार परिवार के साथ रह रहे हैं। बताया जाता है कि बिस्मिल के शहीद होने के बाद उनकी बहन शास्त्री देवी काफी समय तक इस मकान में रहीं। उन्होंने आर्थिक जरूरत में विद्याराम नाम के व्यक्ति को यह घर बेचा। विद्याराम ने एक दूसरे परिवार को घर दे दिया। उस परिवार ने नारायण लाल के नाम बैनामा कर दिया।

देश में बने हैं स्मारक व स्टेशन : बिस्मिल के नाम पर देश में कई स्मारक बने हैं। बिस्मिल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मूल निवासी थे। वहां उनके नाम पर म्यूजियम बना हुआ है। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में स्मारक बना है। गोरखपुर की जिस जेल में बिस्मिल को फांसी दी गई। वहां उनके नाम का स्मारक बना हुआ है। जिले में रोजा व कहिलिया स्टेशन के बीच पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। शहर में विभिन्न स्थानों पर प्रतिमाएं लगी हैं।

तुर्की में बसा शहर : तुर्की के पहले राष्ट्राध्यक्ष कमाल पाशा रामप्रसाद बिस्मिल से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके नाम पर जिला ही बसा दिया। उस जिले के अंदर शहर भी है, जिसका नाम है बिस्मिल शहर। तुर्की के दियारबाकिर राज्य में स्थित यह शहर आज अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां कई पार्क व घूमने के स्थान हैं। दियारबाकिर शब्द का अर्थ है बागियों का स्थान। यह जिला राज्य के दक्षिण पूर्व में आनातोलिया नामक जगह पर है।

नौ अगस्त को हुआ था काकोरी कांड : नौ अगस्त, 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचींद्रनाथ बख्शी, मन्मथनाथ गुप्त आदि डाउन लाइन की सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दीं थीं। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां व ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर, 1927 को अलग-अलग जेलों में फांसी दी गई थी।

काकोरी कांड के दूसरे शहीद अशफाक उल्ला खां का घर शहर के जलालनगर मोहल्ले में स्थित है। उनकी मजार का 65 लाख रुपये की लागत से सुंदरीकरण कराया गया है। वहीं तीसरे शहीद ठाकुर रोशन सिंह के खुदागंज गांव के नवादा दरोवस्त में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की सौगात देने के साथ ही कई कार्य कराए थे।

'यूएस' को कलाम ने दिया था 'जल ग्राम' का आइडिया...

खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़... ▸ केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के गांव जखनी को देश का पहला जल ग्राम घोषित किया है

राजू मिश्र, बांदा

जल संरक्षण

सूखे से पस्त जिस बुंदेलखंड में बोरिंग फेल हैं, सूखे कुंए मुंह चिढ़ाते हैं, पानी को लेकर हाहाकार बना रहता है, वहीं बांदा जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर बसा गांव जखनी समस्त संकटों को धता बताकर अचरज का विषय बन गया है। केंद्र सरकार ने जखनी को देश का पहला जल ग्राम घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' में इस गांव का जिक्र और तारीफ कर चुके हैं। यह संभव हुआ उमाशंकर पांडेय के बूते, जिन्हें जल ग्राम का यह आइडिया किसी और ने नहीं अग्निपुरुष डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। उमाशंकर गत दो दशक से बुंदेलखंड में सर्वोदय आदर्श जल ग्राम स्वराज अभियान चला रहे हैं।

इनका नाम उमाशंकर पांडेय है, लेकिन लोग यूएस पुकारते हैं। बताते हैं, मां ने मुझसे दो ही बातें कहीं थीं। कुछ ऐसा काम करना जिससे कुल का खूब नाम हो। दूसरा, कभी दिव्यांगता का सहारा मत लेना। मां को दिए वचन व्यर्थ नहीं गए...। सेवा कार्यों की बदौलत इनके गांव का नाम देश-दुनिया में कुछ ऐसा गूंजा कि हर जगह उसकी मिसाल दी जाने लगी है। सदियों से उपेक्षित बुंदेलखंड की सबसे बड़ी त्रासदी रही कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि तो कभी जलसंकट। सूखा और अतिवृष्टि तो कुदरत की देन है, लेकिन जलसंकट को चुनौती मानकर उमाशंकर कुछ इस तरह जुटे कि आज उनके गांव में मात्र दस से पंद्रह फीट खोदाई करने पर पानी निकल आता है।

- **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कर चुके इस गांव का जिक्र**
- **गांव के नौ तालाब, तकरीबन तीस कुंए भीषण गर्मी में भी पानी से लबालब रहते हैं, बन गया बुंदेलखंड का सर्वाधिक पैदावार वाला गांव**

जखनी को भारत का पहला जल ग्राम बनाने वाले सर्वोदयी कार्यकर्ता उमाशंकर पांडेय। जागरण

एक समय ऐसा भी था जब जखनी गांव में बोरिंग भी सफल नहीं हो पाती थी। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने उमाशंकर को वाटर विलेज यानी जल ग्राम विकसित करने का आइडिया दिया था। कोई मशीन नहीं। कोई ज्ञान नहीं। कुछ खास शिक्षा नहीं। बस फावड़ा और डलिया के सहारे यूएस ने इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया। गांववाले इस पुनीत कार्य में सहभागी बने। एक ही धुन थी, एक ही नारा था- खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़। करीब दो दशक पहले शुरू की गई इस मुहिम का प्रतिफल है कि इस गांव के नौ तालाब, तकरीबन तीस कुंए भीषण गर्मी में भी पानी से लबालब रहते हैं। बांदा और आसपास के क्षेत्रों में हर कहीं जखनी की ही सब्जी मिलती है।

पानी की उपलब्धता का नतीजा है कि यहां के कृषक सुखी हैं, आत्मनिर्भर हैं और खेती से भरपूर पैदावार लेते हैं। किसान ही नहीं यहां के मवेशी भी हृष्ट-पुष्ट दिखते हैं। जखनी में जितनी स्वच्छता दिखती है उतनी अन्य गांवों में नहीं। जखनी को भारत का पहला जल ग्राम बनाने के पीछे छिपी सर्वोदयी कार्यकर्ता उमाशंकर पांडेय की लगन के सभी कायल हैं। कोई अनुदान, न पुरस्कार, न सलाह। सिर्फ और सिर्फ एक धुन...। जब सूखे से तिलमिलाते बुंदेलखंड के किसान थक-हारकर मौत को गले लगा रहे थे, जखनी में एक भी किसान ने कर्ज के बोझा से उकता कर मौत को गले नहीं लगाया।

> जखनी के कायाकल्प के पीछे कोई स्वार्थ या लोभ नहीं जुड़ा। यही वजह रही कि कभी किसी पुरस्कार या सम्मान की चाहत नहीं रही। इच्छा है तो बस इतनी कि मेरी शिनाख्त जल योद्धा के तौर हो।
>
> **– उमाशंकर पांडेय, संयोजक, सर्वोदय आदर्श जल ग्राम स्वराज अभियान समिति**

> मैं कई बार जखनी का दौरा कर चुका हूं। जल संकट से जूझते बुंदेलखंड में जखनी गांव किसी करिश्मे से कम नहीं।
>
> **– हीरा लाल, जिलाधिकारी, बांदा, उप्र**

सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे अधिक पैदावार : जखनी बुंदेलखंड का इकलौता ऐसा मॉडल गांव है, जहां सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे अधिक पैदावार होती है। इस साल जखनी में 21 हजार क्विंटल बासमती पैदा हुआ है जबकि अगले बरस के लिए पैदावार का लक्ष्य 25 हजार क्विंटल गांववालों ने खुद ही तय किया है। उमाशंकर पांडेय कहते हैं कि सरकार चाहे तो जखनी के सुखद परिणामों का लाभ ले सकती है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

हिमालय में होने वाली मौसमी उथल-पुथल की पहेली सुलझाएगा 'मोडिस'

जागरण विशेष ▸ भारतीय वैज्ञानिक ने स्वीडन विवि के साथ मिलकर मोडिस तकनीक विकसित की

पर्वत श्रृंखला के दुरूह क्षेत्रों का भी मिल सकेगा हाल, जलवायु परिवर्तन पर नजर रखना होगा आसान

रूमा सिन्हा, लखनऊ

शोधकर्ताओं के लिए अब बर्फ से ढके हिमालय में होने वाली मौसमी उथल-पुथल पहेली नहीं रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखना हो, बर्फ पिघलने की दर आंकनी हो या क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना हो..., 'मोडिस' के जरिये यह सब कुछ आसान होगा।

मोडिस यानी सेटेलाइट मॉडरेट रिजॉल्यूशन इमेजिनिंग स्पेक्ट्राडायोमीटर। इससे प्राप्त आंकड़ों के जरिये हिमालय की हर हलचल का सटीक अनुमान लगाना संभव होगा। लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान (बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलिओसाइंसेज, बीएसआइपी) के वैज्ञानिक मयंक शेखर ने स्वीडन यूनिवर्सिटी के साथ यह तकनीक विकसित की है। इस युक्ति के जरिये सेटेलाइट (उपग्रह) आंकड़ों की मदद से दुरूह स्थानों को भी खंगाला जा सकता है। यह शोध प्रतिष्ठित रिमोट सेंसिंग जर्नल में चार दिसंबर को प्रकाशित हुआ है। माना जा रहा है कि दुनिया भर के शोधकर्ता अब आसानी से हिमालयी क्षेत्रों में अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा सकेंगे। शोधकर्ता शेखर ने बताया कि अभी तक हिमालयी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त आकड़ों की कमी बड़ी समस्या थी। पश्चिमी हिमालय के अध्ययन के लिए मुक्तेश्वर और जोशीमठ स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के केंद्र पर ही मुख्य रूप से निर्भर रहना पड़ता था। यहां सौ वर्ष का डेटा उपलब्ध है। बाकी मौसम केंद्र महज 40-50 वर्ष ही पुराने हैं। यही नहीं, दुरूह परिस्थितियां होने के कारण कई मौसम केंद्रों से डेटा प्राप्त करना भी अकसर मुश्किल होता है। ऐसे में हिमालयी क्षेत्र में शोध के लिए डेटा की उपलब्धता बड़ी चुनौती थी। शेखर बताते हैं कि हिमालय के सटीक अध्ययन के लिए क्लाउड फ्री डेटा की जरूरत होती है। इसलिए हमने अपने शोध के लिए काल्पा, काजा, नामगिया सहित मौसम विभाग के 11 केंद्रों से सात जुलाई, 2002 से 31 दिसंबर, 2009 और 13 दिसंबर, 2015 से 30 सितंबर, 2019 के बीच का संग्रहित डेटा जुटाया। फिर मोडिस के माध्यम से इसकी तुलना उपग्रहों से प्राप्त डेटा से की। स्वीडन यूनिवर्सिटी के साथ किए गए इस शोध में पाया कि हिमालय में हवा (एयर) और भू-सतह (सरफेस) के तापमान में मजबूत संबंध हैं। यानी हिमालय में होने वाली उथल-पुथल को गहराई से जानने के लिए केवल मौसम केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर रहने के जरूरत नहीं।

मयंक ने दावा किया कि मोडिस युक्ति से सेटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर सटीक जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े शोध के इच्छुक हैं, उनके लिए नई राह खुली है। हिमालय या आर्कटिक जैसे क्षेत्रों के अध्ययन में मोडिस से प्राप्त होने वाले डेटा का प्रयोग कर वहां बदलते तापमान का ग्लेशियर पर पड़ने वाला प्रभाव, बर्फ पिघलने की दर, जल वाष्प, पारिस्थितिकी आदि की सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है।

प्रतीकात्मक चित्र। साभार : हंसइंडिया

> हमने स्थापित किया कि हिमालय में हवा और भू-सतह के तापमान में मजबूत संबंध हैं। अब इसे मोडिस यानी सेटेलाइट मॉडरेट रिजॉल्यूशन इमेजिनिंग स्पेक्ट्राडायोमीटर के माध्यम से विश्लेषित किया जा सकता है और सटीक डेटा जुटाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े शोधों में यह मीटर मील का पत्थर साबित होगा।
>
> **– मयंक शेखर, वैज्ञानिक, बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान, लखनऊ**

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

मानुषी छिल्लर को पेटा का सलाम, बनीं देश की हॉटेस्ट वेजीटेरियन

जागरण संवाददाता, रोहतक : हरियाणा के रोहतक की बेटी व पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के प्रयासों को पेटा (पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) ने सराहा है। पशुओं के प्रति उनके प्रेम और फैंस को लगातार पशुओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर मानुषी को वर्ष 2019 का हॉटेस्ट वेजीटेरियन भारतीय चुना गया है। पेटा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मानुषी ने अपने खाने से ये साबित कर दिया है कि शाकाहारी खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पेटा इंडिया उन्हें एनिमल-फ्रेंडली होने के लिए सम्मानित करता है।

मानुषी छिल्लर। फाइल

अक्सर अपनी खूबसूरती और इंटेलिजेंस के लिए चर्चा में रहने वालीं मानुषी का पैट्स के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वह अपने डॉग की खाने-पीने से लेकर सभी जरूरतों का बखूबी ख्याल रखती हैं। मानुषी अपने प्रशंसकों को अक्सर विभिन्न मंचों से पशुओं के प्रति दया भाव रखने के लिए अपील करती रहती हैं। मानुषी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। वह यश चोपड़ा बैनर तले बन रही फिल्म पृथ्वीराज में सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इससे पहले वह कई फिल्म अवार्ड समारोह में दिखाई दे चुकी हैं।

डिप्लोमेसी की मेज पर हाथियों का 'हंगामा'

श्वेतांक शंकर उपाध्याय, लखीमपुर

- **भारत-नेपाल सीमा पर दोनों ओर चक्कर लगाने वाले 200 हुड़दंगी हाथियों को लेकर बढ़ी रार**
- **पीलीभीत में पीसीसीएफ नेपाल के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, ढूंढ़ा जाएगा सच**

भारत-नेपाल सीमा पर दोनों देशों में चक्कर लगाने वाले करीब 200 हाथियों का हंगामा डिप्लोमेसी की मेज पर पहुंच गया है। ये हाथी आखिर किसके साथी हैं? दोनों ही देश के अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे हैं। कोई उन्हें अपना मानने को तैयार नहीं है। हाथियों के लगातार उत्पात पर अब टकराव कदर बढ़ गया है कि दोनों देशों के बीच बैठकें बुलानी पड़ रही हैं। गुरुवार को एक बार फिर पीलीभीत में प्रदेश के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ सुनील पांडेय शुक्लाफाटा, नेपाल के वाइल्ड लाइफ वार्डन लक्ष्मण प्रसाद कौड़ियाल के साथ बैठक बुलाई गई है, जिसमें हाथियों के जटिल सवाल का हल तलाशे जाएंगे।

लखीमपुर स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथियों के कई ऐसे झुंड हैं, जो आए दिन किसानों की फसलें बर्बाद करते हैं। उनपर हमलाकर मौत के घाट उतार देते हैं। हर बार वन विभाग के अधिकारी इन्हें नेपाल का बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि नेपाल के अधिकारी हाथियों को भारत का बताते हैं। इस दफा इन हाथियों का हंगामा पीलीभीत से बरेली तक कहकर बनकर टूटा। इसके बाद ही 16 नवंबर को बफरजोन के संपूर्णानगर रेंज में इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बैठक हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया।

नेपाल के लालझाड़ी कॉरिडोर में अब भी उत्पात मचा रहा है हाथियों का झुंड। प्रतीकात्मक

इधर, हाथियों का एक झुंड दुधवा पार्क के गौरीफंटा रेंज की सीमा से सटे नेपाल के लालझाड़ी कॉरिडोर में अब भी उत्पात मचा रहा है। फसलों को रौंदने के साथ ही किसानों पर भी हमला कर रहे हैं। यही वजह है, पीलीभीत में भारत-नेपाल सीमा से सटे फारेस्ट डिवीजनों की बैठक में बातचीत की मेज पर हाथियों का हंगामा ही छाया रहेगा।

> नेपाल से हाथी पिछले तीन दशक से यहां आते रहे हैं। शुरू में कुछ दिन रुककर वापस चले जाते थे। पिछले कई वर्षों से भोजन की उपलब्धता के कारण ये हाथी कई-कई महीनों तक यहां रुकने लगे हैं। बैठक में हाथियों सहित कई बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी।
>
> **– डॉ. अनिल कुमार पटेल, उप निदेशक बफरजोन, लखीमपुर खीरी**

बाबा दरबार के निर्माल्य से बनने लगी आर्गेनिक खाद

जागरण संवाददाता, वाराणसी : श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले माला-फूल और बेल पत्र से बनी आर्गेनिक खाद अब खेतों में धन धान्य बरसाएगी। आर्ट आफ लिविंग के सहयोग से इसे बनाने का कार्य बुधवार को शुरू हो गया। इसे 500 ग्राम व एक किलोग्राम के पैकेट में हेल्प डेस्क से बेचा जाएगा। बागवानी के लिए छोटे पैकेट में भी खाद उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह व आर्ट आफ लिविंग के न्यासी दीपक ने इसका संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। सीईओ ने फूल-पत्तियों से बनी खाद के फायदे बताए। कहा कि अब बाबा को चढ़ाए जाने वाले फूल-पत्तियों का सदुपयोग किया जा सकेगा। आर्ट आफ लिविंग के न्यासी दीपक ने बताया कि लोग खाद का उपयोग किचन गार्डन व घर में लगाए गए तुलसी के पौधे में भी कर सकेंगे। डिप्टी कलेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास व आर्ट आफ लिविंग के बीच खाद निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत निर्माल्य से खाद बनाकर मंदिर के अलावा बाहरी हेल्प डेस्क पर भी छोटे-छोटे पैकेट में बिक्री की जाएगी।

मुट्ठी उतार रही नशा माफिया का सरूर

रमेश सिंगटा, शिमला

एक अकेला क्या कर लेगा...। वही अंगुली वाली बात। पंजाब उड़ता पंजाब बन गया, हिमाचल लगभग उड़ान भरने की तैयारी में है...। उत्तराखंड पहले ही पहाड़ पर है...। अंगुलियां हारीं तो मुट्ठी का विचार आया। ताकत अधिक होती है। इसलिए असर भी दिख रहा है। पहाड़ी राज्यों का मॉडल हिमाचल नशे से बचा रहे, इस मंशा से पुलिस अधिकारियों की अंतरराज्यीय बैठकें हो रही हैं। इससे समन्वय से सूचना और सूचना से सजा तक का रास्ता आसान होने की उम्मीद बंधी है। पाया गया है कि अब सूचनाएं अधिक साझा की जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पहल पर उत्तर भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समन्वय बैठक की थी। अब इन राज्यों की डीजीपी के स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। एक साल के अंदर तीसरी बैठक हुई है। इनसे प्रदेश को नशे के कारोबार से जुड़े तस्करों के बारे में खुफिया सूचनाएं पहले से अधिक प्राप्त हो रही हैं। इनके आधार पर कई मामलों में त्वरित कार्रवाई भी हुई है। पहली जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2019 तक एनडीपीएस के तहत 595 मामलों में फैसला आया है। 278 केसों में दोषियों को सजा सुनाई गई है। राज्य पुलिस का दावा है कि वह हिमाचल को उड़ता पंजाब बनाने से रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ पाठ पढ़ाया जा रहा है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईरान से आ रहा नशा : पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में पैदा नशा भारत के युवाओं की जिंदगी तबाह कर रहा है। भारत में हेरोइन का नशा इन्हीं तीन देशों से आ रहा है। डीजीपी एसआर मरडी ने इसकी पुष्टि की है। चिट्टा भी हेरोइन का ही रूप है। यह क्रॉस बॉर्डर, दुबई, नेपाल के रास्ते भारत में पहुंचता है। हिमाचल में भी अब काफी मात्रा में हेरोइन और चिट्टा पकड़ा जा रहा है।

नशे पर नकेल

- **हिमाचल की पहल पर उत्तर भारत के राज्यों के पुलिस अधिकारी साझा कर रहे सूचनाएं**
- **डेढ़ साल में एनडीपीएस एक्ट के 595 मामलों में 278 को सजा**
- **एनडीपीएस एक्ट में सख्त प्रावधानों वाला विधेयक एक साल से केंद्र के पास लंबित**

सजा की दर 46.72 फीसद

पहली जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2019 के आंकड़ों के अनुसार एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए आरोपितों की सजा दर 46.72 फीसद रही है। 595 मामलों में फैसला आया, जिसमें 278 को सजा हुई।

विधेयक को साल से केंद्र की मंजूरी का इंतजार

प्रदेश हाई कोर्ट राज्य सरकार को कई बार निर्देश जारी करता रहा है। इनमें कहा गया कि अगर नशा रोकने के लिए प्रभावी अभियान न चलाए तो सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो जाएगा। कोर्ट ने तो यहां तक टिप्पणी कर रखी है कि केंद्र को इसके खिलाफ मृत्यु दंड का प्रावधान करना चाहिए।

पड़ोसी राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तस्करों को मौत की सजा देने की पैरवी करते आए हैं। हिमाचल ने एनडीपीएस एक्ट में और सख्त प्रावधान जोड़े। चरस की छोटी मात्रा को भी गैरजमानती बनाया, लेकिन एक साल से विधेयक केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित है।

हालात

ग्रामीण अंचल में किसानों को जैविक उत्पाद तैयार करने की जानकारी तक नहीं, किसान न तो जैविक खाद तैयार करना जानते, न जैविक खेती के मूल तौर-तरीके ही

उत्तरकाशी में सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रही जैविक खेती

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्रामीण अंचल में किसानों को जैविक उत्पाद तैयार करने की जानकारी तक नहीं। वह न तो जैविक खाद तैयार करना जानते हैं और न जैविक खेती के मूल तौर-तरीके ही। यही वजह है कि उत्तरकाशी जिले में घोषित जैविक ब्लॉक डुंडा में पांच प्रतिशत किसानों पास भी जैविक खाद के पिट नहीं हैं।

राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने की कवायद शुरू हुई थी। वर्ष 2003 में जैविक उत्पाद परिषद का गठन किया गया। इसके ठीक 12 वर्ष बाद 2015 में हर जिले में जैविक ब्लॉक चुने गए। इसी के तहत उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक को जैविक ब्लॉक बनाने की तैयारी शुरू हुई। जैविक उत्पाद परिषद की ओर से दो वर्ष पहले ब्लॉक के सात हजार किसानों का चिह्नीकरण किया गया। इन सभी के खेतों में जैविक खाद तैयार करने के लिए जैविक खाद पिट तैयार करवाए जाने थे। लेकिन, हकीकत यह है कि पूरे ब्लॉक में सिर्फ 300 किसानों के ही जैविक खाद पिट बनाए जा सके।

कृषि विभाग और जैविक बोर्ड के पास बजट न होने के कारण जैविक खाद पिट की योजना जहां की तहां ठहर गई। साथ ही गांव में जैविक खेती जागरुकता कार्यक्रम पर भी ब्रेक लग गया। कृषि विभाग के अनुसार वह किसानों को जैविक बीज और जैविक दवाइयां दे रहा है। लेकिन, इस बात का विभाग के पास कोई प्रमाण नहीं है कि किसानों के तैयार उत्पादों के कितने सैंपल भरे गए। कितने किसानों के खेतों की मिट्टी जांचकर उसके अनुरूप जैविक दवाइयां दी गईं।

> विभाग को अभी केवल यही निर्देश हैं कि किसानों को जैविक बीज और दवाइयां उपलब्ध करानी है। किसी काश्तकार के उत्पाद की अभी सैंपलिंग नहीं की गई है। इसके लिए अभी कोई अलग से बजट भी नहीं है।
>
> **– गोपाल सिंह भंडारी, प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी**

उत्तरकाशी के जैविक ब्लॉक डुंडा में उगाई जा रही चौलाई की फसल की आज तक जैविक उत्पाद के रूप में नहीं हुई सैंपलिंग। फाइल फोटो

अतिक्रमण से 60 साल में 20 मीटर तक सिकुड़ गई गंगा

आयुष शर्मा, देहरादून

जीवनदायिनी गंगा बीते 60 वर्षों में अतिक्रमण से कई जगह सात से 20 मीटर तक सिकुड़ गई है। यह बात गंगा को नया जीवन प्रदान करने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत किए जा रहे शोधों में सामने आई है। गंगा की घटती चौड़ाई की सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही हालात रहे तो भविष्य में स्थिति और भी खतरनाक होने की आशंका है।

बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक संघ (आइएनसीए) की 39वीं कांग्रेस में गंगा पर अध्ययन कर रहे पीयूष गुप्ता ने पिछले 60 वर्षों के दौरान गंगा में आए बदलावों की जानकारी दी। पीयूष नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बतौर असिस्टेंट रियल टाइम इंफॉरमेशन स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1958 से 1972 के बीच अमेरिका की एजेंसी सीआइए की ओर से ली गई सेटेलाइट तस्वीरों का आज की तस्वीरों से मिलान करने पर पता चलता है कि गंगा अपने बहाव का पैटर्न बदल चुकी है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव और अतिक्रमण के कारण गंगा के बहाव क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। बकौल पीयूष, 60 के दशक में सीआइए ने गंगा की आठ हजार से ज्यादा सेटेलाइट तस्वीरें ली थीं। यह तस्वीरें नासा की वेबसाइट पर मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नमामि गंगे प्रोजक्ट में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है।

इन राज्यों में हुए बदलाव : गंगा के बेसिन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते हैं। इन राज्यों के जिन शहरों से गंगा गुजरती है, वहां गंगा का बहाव कहीं घटा तो कहीं बढ़ा है। नदी के घुमाव भी खत्म होते जा रहे हैं। चौड़ाई में भी कमी दर्ज हुई है।

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...
नई दिल्ली, गुरुवार, 19 दिसंबर, 2019
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

शहर की फिजाओं में शुद्ध साहित्य की हवा बहती थी

दिल्ली मेरी यादें

एक बहुत बड़े लेखक हुए ठाकुर प्रसाद सिंह उन्होंने मुझसे एक बात कही थी...मुझसे क्या अक्सर लिखने पढ़ने वाले साहित्य में रुचि रखने वालों से कहा करते थे कि 'किसी युवा को 30 का होते-होते दिल्ली पहुंच जाना चाहिए' मैंने भी उनकी बात का अनुसरण किया और 1984 में 24 साल की उम्र में दिल्ली नौकरी के लिए आ गया। उन दिनों दिल्ली में एशियाड खेलों की तैयारी हो रही थी। जगह-जगह फ्लाईओवर बन रहे थे। तेजी से दौड़ना सीखने लगी थी दिल्ली।

वैसे नौकरी से पहले भी दिल्ली से नाता जुड़ गया था। हुआ यूं कि 1982 में मेरी शादी दिल्ली में ही हो गई, वह भी दिल्ली की ही लड़की से। मैं ठहरा उप्र के गांव का लड़का और पत्नी मिली दिल्ली वाली। तभी तो जब दिल्ली की बसों में चढ़ता तो वह लपक कर चढ़ जातीं और मैं सोचता था कि यहां की बस भी अपने लखनऊ मिजाज में चलेगी, जहां बस वाला तसल्ली से बस रोकता है पान की गिलोरी मुंह में दबाता है, फिर आराम से चलता है। बहरहाल कुछ दिन में मैं भी दिल्ली वाले ट्रैक पर आ गया। दिल्ली तब तक सरपट दौड़ना सीख चुकी थी। उसके दौड़ते पहियों के साथ कदमताल करके चलना जरूरी था। मैं यूपीएससी के माध्यम से 1984 में दिल्ली आया था, मानव संसाधन मंत्रालय में मेरी पहली नौकरी लगी। उसके कुछ दिन बाद बैंक में नौकरी हो गई। मुझे दिल्ली की बोली-वाणी भी कुछ भिन्न लगी। हरियाणा वाला टोन रहता, मैं अपने साथियों से पूछता यह कैसे बोलते हैं, कभी-कभी बड़ा धक्का सा पहुंचता था कि किस तरह बात कर रहे हैं। फिर वो मुझे बताते ये तो मुहब्बत की भाषा है। बहरहाल धीरे-धीरे मैं उसे भी समझ गया। अब यहां अवध वाली मिठास कहां मिलेगी।

अब जब दिल्ली में बाहर से कोई आकर बसता है तो सबसे पहले रहने के लिए ठिया ढूंढता है मेरी ससुराल उत्तम नगर में थी, मेरे ससुर जी भी ठहरे लेखक...हमने भी वहीं किराए का ठिया तलाश लिया। तब जो वहां बसे फिर उस जगह को बदलने का कभी मन नहीं हुआ। दरअसल वहां आसपास रामदरश मिश्र, ललित शुक्ल, रामविलास शर्मा, गिरिजा माथुर जैसे साहित्यकार जो रहते रहे। थोड़ी ही दूरी पर राजौरी गार्डन में प्रताप सहगल, नरेंद्र मोहन जैसे कई वरिष्ठ साहित्यकारों के भी घर रहे। अब घर के आसपास भी साहित्यिक माहौल और कनॉट प्लेस में जहां बैंक में राजभाषा प्रबंधक की नौकरी थी उससे कुछ दूरी पर ही कॉफी हाउस जैसे साहित्यिक ठिए मतलब घर से लेकर दफ्तर तक साहित्यिक आनंद था। राजौरी गार्डन में भी कई साहित्यकारों के घर में गोष्ठी हुआ करती थीं। नरेंद्र मोहन के साथ कोशकारी भी करता था। दिल्ली की फिजाओं में शुद्ध हिंदी की साहित्य की हवा बहती नजर आती थी। असल में मेरी साहित्यिक भूमि दिल्ली में ही आकर परवान चढ़ी जब विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, उदय प्रकाश किस किस के नाम लूं पचासों साहित्यकारों से साहित्यिक सदगुणों का अनुसरण कर रहा था। जिस वर्ष मैं दिल्ली आया दिल्ली में 'विचार कविता' का आंदोलन चल रहा था। जिसकी अगुवाई राम दरश मिश्र, प्रताप सहगल, नरेंद्र मोहन बलदेव वंशी जैसे बड़े दिग्गज कर रहे थे। 1980 के आसपास का समय कविताओं के आंदोलनों का दौर कहा जाता है। फिर 1990 के आसपास का दौर आया दलित आंदोलन का। तब कविताओं में, कहानियों में सभी तरह के लेखन में दलित, पिछड़ा वर्ग, सताई हुई आवाजें, कमजोर लोग पर चिंतन ज्यादा हुआ। लंबे समय तक यह चरम पर रहा। यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी गोष्ठियों में इन आंदोलनों में साहित्यिक पृष्ठभूमि में यह सब काफी निकट से देख रहा था।

हालांकि नौकरी के साथ साहित्य के लिए समय चुराना पड़ता था। इसलिए तो बाल स्वरूप राही ने लिखा भी है 'जिनके सपनों में आग होती है वो रात भर करवटें बदलते हैं' वही कुछ था। जीवन और जीविका में संतुलन बनाकर चलता रहा। दिल्ली में साहित्यिक गोष्ठियों के बहाने कई खानपान के अच्छे ठिकाने भी मिल गए, खासकर मिठाइयों के। जंतर-मंतर के पास मलिक स्वीट्स था। ऐसे ही जब बैंक की तरफ से चांदनी चौक की ब्रांच में जाया करते थे तो वहां सैंकड़ों साल पुरानी मिठाइयों की दुकान से मिठाई खाने को मिलती। बंगाली मार्केट, गोल मार्केट यह हमेशा स्मृतियों में जीने वाले ठिए हैं।

मनु त्यागी से बातचीत पर आधारित

हिंदी अकादमी दिल्ली पुरस्कार से सम्मानित डॉ ओम निश्चल, द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी सृजन एवं मूल्यांकन, शब्द सक्रिय है (कविता-संग्रह), बैंकिंग वांग्मय सीरीज जैसी पुस्तकें लिख चुके हैं। भले बैंक में वरिष्ठ राजभाषा प्रबंधक रहे, लेकिन व्यस्तता के बीच भी लेखन की जिंदगी को शौक से जीते रहे।

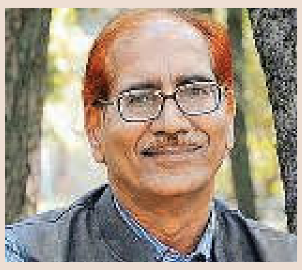

लेखन के फूल जब बाल मन में ही खिलने लगते हैं तो मंजिलें कहां से कहां ले जाती हैं। तभी कश्मीर की छोटी सी लड़की ने दिल्ली के साहित्यिक दिग्गजों के बीच एक उभरते सितारे सी चमक बिखेरी और वह चमक बढ़ती चली गई। न उपसर्ग, न प्रत्यय वाली चंद्रकांता की बातें होती थीं। उनकी 'कथा सतीसर' पर आज भी लगातार शोध हो रहे हैं। मूलरूप से कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली लेखिका ने न केवल हिंदी भाषा को अपनाया, बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी बड़ी भूमिका निभाई। आज उम्र के 80 प्लस के पड़ाव पर भी हिंदी भाषा का संवर्धन करने में पीछे नहीं रहती। प्रियंका दुबे मेहता ने लेखिका चंद्रकांता से कश्मीर से दिल्ली तक की यात्रा, साहित्यिक गोष्ठियों की यादें और यहां की साहित्यिक चहल-पहल पर विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

किताबों के संसार में...अपने घर में बने छोटे से पुस्तकालय के बीच लेखिका चंद्रकांता • जागरण

लेखन की धरा बन गई है दिल्ली

बातचीत

• मूल रूप से कश्मीरी हैं लेकिन आपकी लेखनी में हमेशा हिंदी के प्रति ही लगाव व स्नेह दिखा?

मेरी लेखन में रुचि घर के परिवेश की वजह से पैदा हुई। पिता प्रो रामचंद्र पंडिता वैसे तो अंग्रेजी भाषा पढ़ाते थे लेकिन हिंदी के बड़े प्रचारक थे। उन्होंने कश्मीर में हिंदी भाषा को बचाने के लिए मुहिम चलाई थी। इस सब को देखकर मेरे मन में हिंदी के लिए सम्मान पैदा हुआ और मैं भी पिता की इस मुहिम में जुट गई। हिंदी में एमए किया और राजस्थान, हैदराबाद व उप्र व हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हिंदी भाषा को बचाने के लिए संस्थाएं बनाईं।

• वक्त के साथ बदलते हिंदी के स्वरूप को किस नजरिए से देखती हैं?

भले ही अंग्रेजी विश्व की संस्कृति से जोड़ती है लेकिन हिंदी देश की पहचान बनाती है। ऐसे में इस भाषा को युवाओं को अपनाना चाहिए। संचार क्रांति के इस दौर में हिंदी की पहचान व पैठ लोगों के बीच बढ़ी है। किसी भी भाषा को थोड़ा लचीला होना चाहिए ताकि वह लोगों के समीप जा सके।

• कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक रहीं हैं और फिर दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में आपका पहला अनुभव किस प्रकार का रहा?

मैं जब दिल्ली आई तो एक बात देखी कि उस वक्त लोग बाहर वालों का उस अंदाज में स्वागत नहीं कर पाते थे। उस समय के लेखक और प्रकाशक पहले मुझसे कटते थे, मुझे अनदेखा करते थे तो मुझे यह चीज समझ में नहीं आती थी।

• ...तो खुद को स्थापित करने में किस तरह की चुनौतियां पेश आईं?

यहां सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोग नए लेखकों को उस तरह से प्रोत्साहित करने की प्रवृति नहीं रखते थे। शुरुआती दौर में मेरी कहानी परछाइयां छपी थी और उसी के साथ नरेंद्र कोहली की एक कहानी छपी थी। ऐसे में दिल्ली आकर सबसे पहले उनसे मिलना हुआ। उन्होंने एक संस्था बनाई जिसकी बाद में मैं सेक्रेटरी भी बनी। उसके बाद लोगों से मिलने-जुलने का अवसर मिला। यहां आकर मुझे प्रकाशकों को लेकर आसानी हुई। पहली बार उसी गोष्ठी में भीष्म साहनी, भवानी भाई, मन्नू भंडारी आदि को देखा।

• जब आप दिल्ली आईं थीं उसी वक्त महिला लेखकों का दखल भी बढ़ रहा था। ऐसे में आपके लिए कितनी प्रतिस्पर्धा थी? उस वक्त भी स्त्री की व्यथा कागज पर उतरती थी और आज भी, ऐसे में कितना अंतर पाती हैं?

मैं जब यहां आई तो मुझे लगा कि यहां के लेखक वर्ग में, खासकर महिला लेखकों में मुझे लेकर एक ईर्ष्या की भावना थी। लोगों ने मुझे काफी बाद में स्वीकार किया। उस दौर में लेखन में सामाजिकता पर बल था। पुरुष लेखकों में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, राकेश मोहन, अमृत राय लिखते थे। अमृत राय से मैं खासी प्रभावित भी थी। उस वक्त तक स्त्री के बारे में लोग लिखने लगे थे, स्त्री बोलने लगी थी। उस दौर में स्त्री 'व्यक्तित्व' पर बात होती थी और आज स्त्री 'अस्तित्व' पर बात होती है। यह बहुत बड़ा फर्क था। उस दौर में कृष्णा सोबती काफी आगे थीं। 'मित्रो मरजानी' जैसी कहानी सदियों आगे की थी। उषा प्रियंवदा बाद में आई थीं। फिर मन्नू भंडारी थी। उनमें एक संयम था, यह नहीं कहूंगी कि कृष्णा सोबती में संयम नहीं था, बस उनकी सोच समय से बहुत आगे की थी। आज वह आम है।

• यहां पहली पुस्तक को प्रकाशित करवाने में कितना वक्त लगा?

मेरे भाई दिल्ली में ही शिक्षा विभाग में बड़े पद पर थे। मुझे लगा कि वे मेरी मदद करेंगे लेकिन उन्होंने पिता जी की तरह मुझसे कह दिया कि तुम्हें किसी की मदद की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है, तुम अपने आप पर भरोसा रखो। उस समय तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि मैं बहुत उम्मीदों से गई थी। खैर, उसके बाद मैं सीधा राजकमल प्रकाशन के दफ्तर चली गई। तब मुझे नहीं पता था कि राजकमल इतना बड़ा प्रकाशक है और वहां कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी जैसे लेखक ही छपते थे। मैं किसी को जानती तो थी नहीं। वहां गई तो मुझे भवानी भाई मिल गए जो किसी तरह मुझे जानते थे। उस समय शीला जी ने देखा कि अगर भवानी भाई किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ होगा। मैंने उन्हें अपनी पुस्तक दी और उन्होंने कहा कि वे पढ़कर एक महीने तक मुझे बताएंगी। अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी देखिए, मैं पंद्रह दिन में ही उनके पास चली गई। उन्होंने तब तक किताब पढ़ी नहीं ती और मैं उसे वापस ले आई। हालांकि उसके बाद उन्होंने 'ऐलान गली जिंदा है' का प्रकाशन किया।

• लेखन पर शहर का प्रभाव जरूर दिखता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ?

जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं 1980 में दिल्ली आई तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तब तक मैं तीन किताबें और कहानियां लिख चुकी थी। ऐसे में कुछ लोग जानते थे। फिर धीरे-धीरे गोष्ठियों में जाने लगी, सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगी और परिचय और लेखन के क्षेत्र में विस्तार होता चला गया।

• तब लेखकों और प्रकाशकों की क्या स्थिति थी?

उस समय शीला जी जैसे लोग पुस्तक स्वयं पढ़ते थे। फिर नाम छोटा हो या बड़ा वे केवल लेखन व कथ्य को देखकर ही प्रकाशन करते थे। यही कारण था कि मेरी गलती के बावजूद न केवल शीला जी ने मेरी पुस्तक पढ़ी बल्कि उसके बाद मुझे फोन करके घर बुलाया और कहा कि मेरी पुस्तक पढ़कर उन्होंने असली कश्मीर को जाना है। इसके बाद उन्होंने घर बुलाया और मुझे एक पेन भेंट किया। उस समय वहां कृष्णा सोबती आईं और मैं वहां से निकल गई।

• दिल्ली में गोष्ठियों से जुड़ी कुछ यादें?

मैं उस समय ग्रेटर कैलाश में रहती थी। वहीं आसपास मृदुला गर्ग, नरेंद्र कोहली और मंजुल रहते थे। खूब लेखक आया करते थे। भीष्म साहनी, भवानी भाई, महीप सिंह सभी मिलते थे। अधिक बैठकियां कनॉट प्लेस में होती थीं। बाराखंभा रोड पर राजस्थान सूचना केंद्र के ऊपर एक स्थान था वहां जमावड़ा लगता था। 1980 की बात है, मैं उस समय जैनेंद्र जी को ज्यादा नहीं जानती थी। मृदुला ने मुझे उनसे मिलवाया। मैंने अपने दो लघु उपन्यास 'अर्थांतर' और 'अंतिम साक्ष्य' उन्हें पढ़ने को दिए। और संकोच करते हुए उनसे यह भी पूछा कि कैसे लगे? उन्होंने जवाब दिया, देखो मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, अर्थांतर मुझे समझ में नहीं आया। अंतिम साक्ष्य पढ़कर मुझे लगा कि 'मैं तुम्हें गले लगाऊं'। बाद में गोष्ठी में उसकी बहुत सराहना की। उससे मेरा उत्साह बढ़ने लगा।

• आपको क्या लगता है, दिल्ली आकर आपके लेखन को एक अलग अंदाज, एक अलग दिशा मिली?

दिल्ली में ही मैंने 'ऐलान गली जिंदा है' लिखी। इसके लिए मैं मनोहर श्याम जोशी की ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे लिखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह अर्थांतर-विरांतर तो ठीक है लेकिन कुछ नया लिखो। कश्मीर को लोगों ने अभी तक सिर्फ सैलानी दृष्टि से जाना पढ़ा है तुमने वहां कि जिंदगी जी है, उसे लिखो। मुझे प्रेरणा मिली। और इसकी बहुत सराहना हुई।

• साहित्यिक बैठकियों के अलावा दिल्ली में आप कहां जाती थीं? पहले और आज की दिल्ली में क्या बदलाव देखती हैं?

हम घूमने फिरने भी जाते थे। कनॉट प्लेस, लाजपत नगर व साउथ एक्स जाते थे। मेरे पहनावे में हैदराबाद का प्रभाव था, तो साउथ एक्स में उस तरह की साड़ियां मिलती थीं। करोल बाग का तब बड़ा चाव था क्योंकि वह नया था। आज तो करोल बाग में पैदल चलने की जगह नहीं मिलती। पहले खुली सड़कें, शुद्ध आबोहवा और मेलजोल का माहौल था। आज ऐसा नहीं रहा है। लोग बढ़ते गए दिल्ली सिमटती सी गई।

• दिल्ली की साहित्यिक गोष्ठियों की कुछ और यादें?

उस समय का एक और नाम लेना चाहूंगी जिसने मुझे विस्तार का मौका दिया। दिनेश नंदिनी डालमिया नए लेखकों को प्रोत्साहित करती थीं। लोगों से मिलती, पढ़ती और सुनती थीं। मैं उनसे रशियन कल्चर सेंटर में मिली थी। उन्होंने मेरी पुस्तक 'अपने-अपने कोणार्क' पढ़ा था। वे मिली तो बड़े अधिकार से बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने गोष्ठियां करवाईं। कमलेश्वर, महीप सिंह को बुलाया। कथा सतीसर की चर्चा में पर कमलेश्वर व मानवर सिंह, निर्मला जैन, कवि अजित कुमार, जगदीश चतुर्वेदी थे। मुझे याद है कि मैंने उस समय राजेंद्र यादव को मंच पर नहीं बुलाया था तो वे नाराज हो गए थे, तब उन्होंने हंस पत्रिका में लिखा, 'इधर सुना है कि चंद्रकांता ने भारी-भरकम उपन्यास लिखा है लेकिन मैंने पढ़ने की जरूरत नहीं समझी।' हालांकि उनसे मेरे अच्छे संबंध थे, वे मुझे 'सतीसरी' बुलाते थे लेकिन उस लेख के लिए मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया।

• आज का लेखन आपको किस दिशा में जाता नजर आता है ?

लेखन अपनी दिशा अपने आप तय करता है। लेखकों का आना उत्साहवर्धक बात है लेकिन मुश्किल यह है कि सभी बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। लेखकों को शुरुआत में बहुत अहंकार होता है। नए लेखकों में परिपक्वता नहीं है। कुछ लोग अच्छा लिख भी रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं लेकिन कई लोग क्या लिखना चाहते हैं, पता ही नहीं चलता। वे भाषा शिल्प में ही फंस कर रह जाते हैं। शिल्प की कारीगरी मात्र से अच्छा लेखन नहीं होता। लेखन समय, मेहनत चाहता है, यह एक तरह की तपस्या है।

मिलते रहे सम्मान

हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान (2008), व्यास सम्मान (2005), बाल मुकुंद गुप्ता सम्मान, चंद्रावती शुक्ल सम्मान, हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार (2005) राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान (2006), कल्पतरु सम्मान, कल्पना चावला सम्मान सहित कई बड़े सम्मान अपने नाम किए।

आइसीसीआर में समृद्ध होगी संस्कृति की समझ

फुर्सत का ज्ञान

भारतीय कला व संस्कृति की समझ को समृद्ध करना चाहते हैं। यहां के नृत्य-संगीत, विविध राज्यों के तीज-त्योहार को गहराई से जानना-समझना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप वहां जाएं ही। दिल्ली में बैठ कर भी उनके बारे में अच्छी जानकारी पा सकते हैं। जी हां, आइपी एस्टेट आजाद भवन रोड स्थित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर) पुस्तकालय में कई ऐसी दुर्लभ किताबें हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप भारत के विविध रूपों से रूबरू हो पाएंगे। बीते 69 वर्षों से पुस्तकालय भारत के इतिहास, संस्कृति व कला को संजोए हुए है।

स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी (1953), साहित्य अकादमी (1954), ललित कला अकादमी (1954) जैसे संस्थानों की स्थापना की। इसी क्रम में भारतीय कला व संस्कृति को संजोए रखने के लिए उन्होंने 1950 में आइपी एस्टेट आजाद भवन रोड स्थित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर) की स्थापन की, जिसमें विद्यार्थियों व शोधार्थियों के लिए खासतौर पर एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया।

गोश-ए-आजाद में मौलाना की 10 हजार पुस्तकें : इस पुस्तकालय में करीब 10 हजार किताबें ऐसी हैं, जिन्हें मौलाना आजाद ने स्वयं लिखी और भेंट की हैं। ये किताबें दुर्लभ हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मौलाना आजाद की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए गोश-ए-आजाद नाम से एक अलग कमरा बनाया गया है, जहां सिर्फ मौलाना आजाद की ही पुस्तकें हैं। यह सभी पुस्तकें उर्दू, फारसी व अरबी में लिखी हुई हैं। मौलाना आजाद पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए यह पुस्तकालय काफी महत्व रखता है।

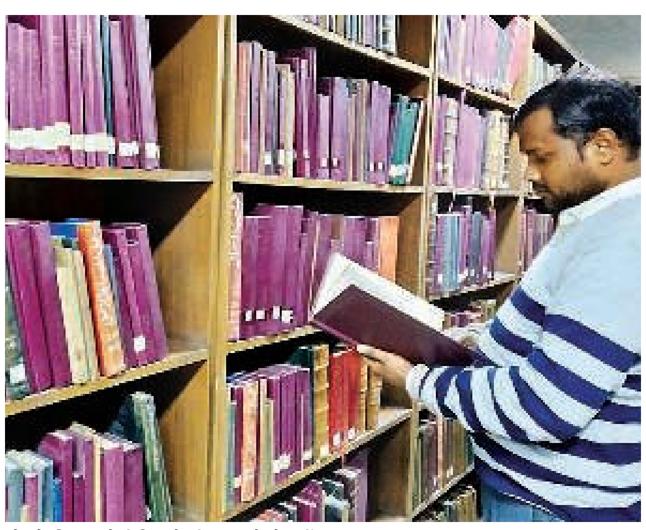

शोध के लिए उपयोगी किताबों की तलाश में शोधार्थी • जागरण

खुलने का समय : सुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे तक आप कभी भी यहां आ सकते हैं।
ऐसे पहुंचे : नजदीकी मेट्रो स्टेशन आइटीओ से पैदल चलकर यहां पहुंचा जा सकता है।

पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन : तरजुमन-उल-कुरआन, भागवत गीता अरबी व अन्य पांडुलिपियां और उसमें समाहित ज्ञान जनसुलभ हो सके इसके लिए उनका डिजिटाइजेशन कर दिया गया है।

पठनीय पुस्तकों का संग्रह : यहां कई ऐसी किताबें हैं जो बेहद रोचक और पठनीय है। इनमें इंडिका, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंसेंट मॉन्यूमेंट इन बंगाल 1895, आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द टॉम्ब ऑफ अकबर, वॉयसलेस इंडिया,द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एंपिरियर अकबर, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, द होली कुरआल, द ओशन हिस्ट्री, 41 ईयर्स ऑफ इंडिया, तर्जुमानुल कुरआन, वीमेन इन मनुस्मृति, कनटेंपरेरी रेलीवेंस ऑफ सूफीज्म आदि दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। इसके अलावा दुर्लभ हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के वॉल्यूम जिनमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड 1792, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्पेनिश अमेरिका, इटली आदि किताबें यहां सहज उपलब्ध हैं।

इतिहास पर लिखी पुस्तकों का विशेष संग्रह : अगर आप ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब और दिल्ली के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां इन राज्यों पर विस्तार से लिखी किताबें मिल जाएंगी। वहीं एशिया, जापान, अरब, यमन, साउथ एशिया व इराक आदि देशों के इतिहास पर लिखी पुस्तकें भी हैं तो एनसिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मोर्या डायनेस्टी, रीजन ऑफ अशोका, मुस्लिम कॉनक्वेस्ट, मुगल एंपायर, ब्रिटिश रूल 1785-1947, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखी पुस्तकें भी हैं। इसके अलावा नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक और कोशकारों की जीवनी भी पढ़ सकेंगे।

मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रतिमा • जागरण

शोध में सहायक किताबें : अगर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध कर रहे हैं और उनके बारे में जानकारी चाहिए तो यहां कई ऐसी पुस्तकें मिलेंगी। महात्मा गांधी पर लिखी गांधी एंड चरचिल, गांधी हिज लाइफ एंड वर्क्स जैसी करीब 100 पुस्तकें हैं। सिलेक्टेड कर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरु के करीब 30 वॉल्यूम यहां उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, रबिंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, श्रीअरबिंदो, समर गुहा द्वारा सुभाष चंद्र बोस पर लिखी नेताजी डेड और अलाइव?, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नेशनल मूवमेंट, प्राइम मिनिस्टर 1977 आदि बड़े राजेनताओं पर लिखी गई पुस्तकों का भंडार है।

कला व संस्कृति की समृद्ध किताबें : अगर आप विविध कलाओं में पारंगत होना चाहते हैं, उनकी बारीकियां सीखना चाहते हैं तो यह पुस्तकालय बिल्कुल उपयुक्त है। यहां भाषण कला, कला तकनीक, धार्मिक चित्रकला, रेखा कला, फोटोग्राफी, संगीत, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, मनोरंजक कला, मूर्तिकला, चित्रकला, प्लास्टिक आर्ट, सजावटी कला, हस्तशिल्प, कपड़ा कला, वास्तुकला आदि पर लिखी कई किताबें ऐसी हैं जो आपको शायद ही कहीं और मिले।

-रितु राणा

एक मार्केट जहां शरणार्थियों को मिली पहचान

काम की दुकान

दिल्ली के नामचीन बाजारों में आपने खूब खरीदारी की होगी, वर्षों से वहां आते-जाते भी होंगे, लेकिन उनके बसने और बनने के पीछे की कहानी शायद ही जानते हों। यहां ज्यादातर मार्केट की बसावट के पीछे अपना एक दिलचस्प इतिहास है। उन्हीं में से एक है लोधी कॉलोनी स्थित खन्ना मार्केट। दक्षिणी दिल्ली की सबसे पुराने मार्केट में शुमार इस मार्केट में लोग डिजाइनर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खान-पान से लेकर गिफ्ट आदि की खरीदारी करने आते हैं। यहां करीब 125 एकल मंजिला दुकानें हैं, जहां लोगों की तमाम जरूरतें पूरी हो जाती हैं।

वर्ष 1953 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेहर चंद खन्ना ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए यह मार्केट बसाई थी। इसलिए इसका नाम उनके नाम पर ही खन्ना मार्केट रख दिया गया। यहां दिल्ली के राम सिंह भोज और चिदंबरम के न्यू मद्रास होटल जैसे प्रमुख भोजनालय हैं।

आम से लेकर खास हैं ग्रोवर के दीवाने : यहां एक दुकान है ग्रोवर शॉप जो वर्ष 1969 से घरेलू सामानों के लिए अपनी खास पहचान बनाए हुए है। यहां आपको सुई-धागा से लेकर कपड़े, सजावटी गिफ्ट आइटम, टीवी, और फ्रीज तक मिल जाएंगे। मार्केट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष व ग्रोवर्स शॉप के मालिक रवींद्र ग्रोवर कहते हैं कि इस बाजार में खरीदारी करने वालों में आम से लेकर खास तक शामिल हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति, नेता व कलाकार भी यहां खरीदारी करने आते हैं। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का निवास जोर बाग में ही है, इसलिए उनके घर का सामान भी यहीं से जाता है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित की बहन रमा भी यहीं से खरीदारी करती हैं। एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल भी इनके ग्राहक हैं।

छाबड़ा जी भी हैं प्रसिद्ध : खन्ना मार्केट की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध दुकान है छाबड़ा स्टोर। आज से 65 वर्ष पहले छाबड़ा स्टोर राशन डिपो हुआ करता था। दुकान के मालिक विपिन छाबड़ा कहते हैं कि 1980 में उनके पिता कृष्ण लाल छाबड़ा ने इसे ग्रोसरी स्टोर में तब्दील कर दिया। वह पाकिस्तान स्थित जिला गुजरात के रहने वाले थे। बंटवारे के बाद जब वे दिल्ली आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था।

क्रिकेटर युवराज के पिता का था आना-जाना : वैसे तो छाबड़ा स्टोर पर कई नामचीन लोग खरीदारी करने आते रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह यहां खूब आया करते थे। आज भी उनके घरेलू सामानों की खरीदारी यहीं से होती है। विपिन दुकान से जुड़ी पुरानी यादें ताजा करते हुए कहते हैं कुछ वर्ष पहले 15 अगस्त के दिन स्मृति इरानी उनकी दुकान पर बच्चों के साथ आई थीं। तब वह एक टीवी कलाकार तो थीं, पर मंत्री नहीं बनी थीं। बच्चों के खाने-पीने का सामान यहीं से लेकर गई थीं।

65 वर्ष पहले छाबड़ा स्टोर राशन डिपो हुआ करता था। खन्ना मार्केट स्थित छाबड़ा स्टोर • जागरण

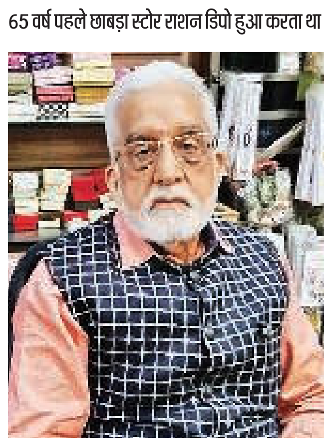

रवींद्र ग्रोवर • जागरण

खुलने का समय : सुबह 10 से रात 10 बजे तक।
ऐसे पहुंचे : जोर बाग नजदीकी मेट्रो स्टेशन से पैदल चलकर यहां पहुंचा जा सकता है।

चिदंबरम में लें साउथ इंडियन का मजा : अगर खरीदारी कर थक गए हों और कुछ खाने की इच्छा हो तो चिदंबरम रेस्त्रां का रुख कर सकते हैं। यह यहां का सबसे पुराना रेस्त्रां है। यहां बेहतरीन साउथ इंडियन खाना मिलता है यही वजह है कि दिनभर खाने वालों की यहां भीड़ लगी रहती है।

कपड़ों के लिए दास है न : तरह-तरह के डिजाइनर कपड़ों की खरीदारी करने का मन हो तो यहां दास क्लोथ हाउस और तिलक टेक्सटाइल से बेहतर कुछ भी नहीं। फुलकारी यहां की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध दुकानें हैं। वहीं जरनल स्टोर में रोयाल स्टोर, सुपर स्टोर, बंसी स्टोर बेहद पुराने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के लिए साइकल वर्क्स, आरके विजन का नाम हर किसी की जुबान पर है। यहां जगदीश स्टूडियो नाम से प्रसिद्ध फोटोग्राफी की दुकान भी है।

-रितु राणा

2014 से 2019 के बीच आरआइएल की कमाई सबसे ज्यादा

मुंबई : पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति में तेज उछाल आया है। मोती लाल ओसवाल ने वेल्थ क्रिएशन स्टडी 2019 में बताया है कि 2014-19 की अवधि में आरआइएल की संपत्ति में सबसे ज्यादा 5.6 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही इंडियाबुल्स वेंचर्स और इंडसइंड बैंक ने भी इस अवधि में काफी संपत्ति अर्जित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान कंपनियों की संपत्ति में तेज और सिलसिलेवार तरीके से इजाफा हुआ है। हालांकि इस मामले में सरकारी कंपनियां काफी पीछे रहीं। (आइएएनएस)

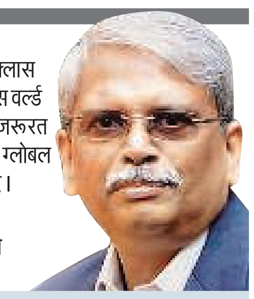

आइटी उद्योग वर्ल्ड क्लास है क्योंकि वहां गवर्नेंस वर्ल्ड क्लास है। इससे सीखने की जरूरत है। हमें ग्लोबल लिस्टिंग और ग्लोबल फंडिंग पर काम करना चाहिए।
— क्रिस गोपालकृष्णन
सह-संस्थापक, इन्फोसिस

सेंसेक्स	41,558.57	▲ 206.40	
निफ्टी	12,221.65	▲ 56.65	
सोना	₹ 38,828	▲ ₹8	प्रति दस ग्राम
चांदी	₹ 45,649	▲ ₹14	प्रति किलोग्राम
डॉलर	₹ 70.97	▼ ₹0.01	
क्रूड (ब्रेंट)	$ 64.89		प्रति बैरल

नए सामाजिक सुरक्षा कोड से बहुरेंगे कर्मचारियों के दिन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- खतरनाक उद्यमों में इकलौता कर्मचारी भी आएगा ईएसआइ के दायरे में
- वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स में छोटे से छोटे प्रतिष्ठान का पंजीकरण होगा जरूरी

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को होगा लाभ। प्रतीकात्मक फोटो

कर्मचारियों के दिन थोड़े बहुरने वाले हैं। संशोधित सामाजिक सुरक्षा कोड में पांच वर्ष से कम अवधि के फिक्स टर्म रोजगार में भी ग्रेच्युटी तथा खतरनाक उद्योगों में इकलौते कर्मचारी को भी ईएसआइ के दायरे में लाने के प्रावधान प्रमुख हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड में कर्मचारियों के घर और दफ्तर के बीच आवागमन के दौरान दुर्घटना की स्थिति में नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों ने स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की बात कही। इसके बाद इस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी। अगले सत्र में विधेयक पुनः पेश होने की उम्मीद है।

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अब 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर भी ईएसआइ लागू हो सकेगा। हालांकि इसे स्वैच्छिक रखा गया है। यदि कोई प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी का ईएसआइ में नामांकन नहीं कराता तब भी कर्मचारी को ईएसआइ के लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। कोड के तहत पहली अनुसूची का विस्तार कर 20 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों को ईपीएफ, ईपीएस तथा ईडीएलआइ के दायरे में ला दिया गया है।

असंगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए कोड में सभी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। भले ही उसमें कितने भी कर्मचारी हों। असंगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए श्रम विभाग पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय निकायों के स्तर पर 'वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर' स्थापित किए जाएंगे। ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर्स के साथ अल्पकालिक कांट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवर व जोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी ब्वाय वगैरह, जिन्हें गिग तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करेगी। यहां तक कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर कार्य करने वाले, घरों में काम करने वाले तथा फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इन पर आश्रित भाइयों, बहनों आदि को भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। ठेका कर्मचारियों के मामले में प्रधान नियोक्ता अंशदान करेगा। दूसरे राज्यों से आए कर्मचारियों को आधार से जुड़े खास तरह के नंबर दिए जाएंगे।

बीएमएस ने किया स्वागत

भारतीय मजदूर संघ ने इन संशोधित प्रावधानों का स्वागत किया है। नए कोड में असंगठित कर्मचारियों के लिए ईपीएफ, ईएसआइ, सेस आधारित बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्कीम तथा अन्य वेलफेयर स्कीमों को आपस में मिलाने के बजाय अलग-अलग रखा गया है। बीएमएस ने कहा कि ईएसआइ की भांति कर्मचारियों को अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लाभ का अधिकार भी बिना नियोक्ता की सहमति के मिलना चाहिए। बीएमएस ने ईपीएफ में कर्मचारियों के योगदान को नए कोड में भी 10 फीसद करने के प्रावधान का विरोध किया है।

आइडीबीआइ से लेनदेन करते रहें सरकारी विभाग : मंत्रालय

- कई विभागों द्वारा अपनी जमा राशि और एफडी निकालने के आए हैं मामले
- इसी साल जनवरी में एलआइसी ने किया है बैंक का अधिग्रहण

मुंबई, प्रेट्र : वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों द्वारा आइडीबीआइ से जमा राशि निकालने पर चिंता जाहिर की है। मंत्रालय ने सरकारी विभागों और एजेंसियों से कहा है कि वे एलआइसी के मालिकाना हक वाले बैंक से लेनदेन जारी रखें। बिजनेस में कमी के चलते बैंक इस समय संकट से गुजर रहा है। विभागों को लिखे गए पत्र में मंत्रालय ने बताया है कि आइडीबीआइ उन्हें बैंकिंग सेवाएं देने में पूरी तरह से सक्षम है। उससे लेनदेन सामान्य तरीके से करते रहें। लेनदेन में किसी तरह का संकट नहीं है। पत्र में याद दिलाया गया है कि इस बैंक का प्रमोटर एलआइसी है, जिस पर पूरी तरह से सरकार का अधिकार है।

अब इस बैंक में सरकार और एलआइसी की हिस्सेदारी 97.46 परसेंट है। मंत्रालय ने 17 तारीख को लिखे इस पत्र में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बहुत से विभागों और एजेंसियों ने इस बैंक से अपना जमा और अन्य तरह के फंड निकाल लिए हैं। ये विभाग सरकारी कारोबार में बैंक को साझेदार भी नहीं बना रहे हैं।

गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में एलआइसी ने आइडीबीआइ में 51 परसेंट हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद आरबीआइ ने इसे निजी बैंक की श्रेणी में डाल दिया था। मंत्रालय ने कहा है कि आइडीबीआइ में सरकार की हिस्सेदारी 46.46 परसेंट है, जबकि एलआइसी पूरी तरह से सरकारी अधिकार वाली कंपनी है। इस तरह परोक्ष रूप से सरकार इसमें 97.46 परसेंट की हिस्सेदारी रखती है।

न्यूज गैलरी

उदयपुर में जुटेंगे विभिन्न देशों के मार्बल विशेषज्ञ

उदयपुर : पत्थर उद्योग में हुए तकनीकी परिवर्तन को लेकर उदयपुर में 19 व 20 दिसंबर को इंटरनेशनल स्टोन टेक्नोलॉजी कांफ्रेंस 'ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम' का आयोजन होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, फिक्की और रीको की ओर से आयोजित होने वाली इस कांफ्रेंस में इसमें विभिन्न देशों से स्टोन व प्रौद्योगिकी एक्सपर्ट और नामी कंपनियों के विशेषज्ञ आएंगे। यहां विभिन्न सत्रों में स्टोन प्रोसेसिंग यूनिट, रिसर्च एंड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोन प्रौद्योगिकी, मल्टी वायर टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन के सीईओ मुकुल रस्तोगी ने बताया कि इस बार द्विवार्षिक कांफ्रेंस का आयोजन उदयपुर में हो रहा है। (राज्य ब्यूरो)

क्वाड्रीसाइकिल पर भी अप्रैल से बीएस-6 मानक लागू

नई दिल्ली : सरकार ने क्वाड्रिसाइकिल पर भी अप्रैल, 2020 से उत्सर्जन के बीएस-6 मानक लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में सड़क मंत्रालय की ओर से नियमों में संशोधन कर क्वाड्रीसाइकिल के उत्सर्जन मानक जारी किए गए हैं। क्वाड्रीसाइकिल पर बीएस-6 मानक लागू करने के लिए केंद्रीय मोटर नियमावली के नियम 115 में संशोधन किया गया है। अभी क्वाड्रीसाइकिल पर बीएस-4 मानक ही लागू हैं। संशोधन के बाद अब अन्य मोटर वाहनों की तरह ही पहली अप्रैल, 2020 और उसके बाद देश में बनने वाले सभी क्वाड्रीसाइकिल वाहनों का निर्माण बीएस-6 मानकों के अनुरूप करना जरूरी होगा। (जागरण ब्यूरो)

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सुधार के लिए मांगी सलाह

नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बेहतर बनाने के लिए ज्वैलरी उद्योग से सलाह मांगी है। गोयल ने कहा कि घरों में बेकार पड़े सोने को उपयोग में लाया जाना चाहिए। इससे सोने के आयात में कमी आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। सरकार 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई थी। हालांकि कम रिटर्न के चलते यह स्कीम आंशिक रूप से ही सफल हो सकी। इसमें सुधार के जरिये और आकर्षक बनाने का प्रयास है। (प्रेट्र)

नीति आयोग के मेडिकल डिवाइस बिल की तारीफ

नई दिल्ली : मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस बिल की तारीफ की है। मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बिल को तैयार किया गया है। इसके साथ ही बिल में मेडिकल डिवाइसेस के आयात पर निर्भरता को कम करने का प्रयास भी किया गया है। मेडिकल डिवाइस के आयात पर करीब 39,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। बिल में मेक इन इंडिया के तहत डिवाइस निर्माण को बढ़ावा देने की बात है। (आइएएनएस)

जीएसटी के 28 परसेंट की स्लैब में आएगी हर तरह की लॉटरी

निर्णय ▸ औद्योगिक प्लाटों की लीज पर अपफ्रंट भुगतान से छूट

जीएसटी काउंसिल में पहली बार वोटिंग से लिया गया फैसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

निर्मला सीतारमण। एएनआइ

देश में हर प्रकार की लॉटरी अब जीएसटी की 28 परसेंट दर के दायरे में आएंगी। अभी तक राज्यों द्वारा संचालित और राज्यों से अधिकृत निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित लॉटरी पर जीएसटी की अलग अलग दरें लागू थीं। इस फैसले पर पहुंचने के लिए जीएसटी काउंसिल में पहली बार वोटिंग की मदद ली गई। इसके अतिरिक्त काउंसिल की बैठक में रेवेन्यू की धीमी रफ्तार पर अधिकारियों की समिति को अगली बैठक में विस्तृत ब्योरे के साथ फिर से प्रजेंटेशन देने को कहा गया है।

बुधवार को काउंसिल की 38वीं बैठक में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्लाटों की लंबी अवधि वाली लीज पर भी छूट देने का फैसला किया है। ऐसे प्लाट जिनमें 20 परसेंट से अधिक की हिस्सेदारी केंद्र या राज्य सरकारों की है, उन्हें अपफ्रंट भुगतान से छूट मिलेगी। अभी तक यह छूट केंद्र या राज्य की 50 परसेंट से अधिक की भागीदारी होने पर मिलती थी। काउंसिल का यह फैसला पहली जनवरी, 2020 से लागू होगा। सूत्रों का कहना है कि इस विषय पर पंजाब ने बैठक में काफी अधिक दबाव बनाया। जहां तक लॉटरी पर जीएसटी दरों में एकरूपता लाने का सवाल है, रेवेन्यू सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि अभी तक देश में लॉटरी पर दो दरें लागू थीं।

राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर जीएसटी की दर 12 परसेंट थी जबकि निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित लॉटरी पर 28 परसेंट की दर से जीएसटी लागू था। दरों में एकरूपता बनाने के प्रस्ताव पर काउंसिल में सहमति नहीं बन पाने के कारण वोटिंग करानी पड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सहमति बनाने के सभी प्रयास किए गए। इसलिए काउंसिल की भावना को ध्यान में रखते हुए इस पर वोटिंग कराई गई जिसका प्रावधान काउंसिल के नियमों में भी है। माना जाता है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 21 राज्यों ने और विरोध में सात राज्यों ने वोट किया। लॉटरी पर नई दर पहली मार्च, 2020 से लागू होगी।

वूवन और नॉन वूवन पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन बैग पर 18 परसेंट का यूनिफार्म रेट लागू करने का निर्णय भी हुआ है। बदलाव पहली जनवरी से लागू होगा। अन्य प्रक्रियागत निर्णयों के बारे में पांडेय ने बताया कि रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर लगने वाली पेनाल्टी पर भी राहत देने का फैसला हुआ है। इसके तहत जिन टैक्सपेयर ने जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 के दौरान जीएसटीआर-1 के जरिये रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे यदि 10 जनवरी 2020 तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें लेट फीस नहीं देनी होगी। लेकिन यदि वे इस तारीख तक भी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं तो उनके ई-वे बिल ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 के जरिये सालाना रिटर्न दाखिल करने और जीएसटीआर-9 के जरिये रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। काउंसिल ने जीएसटी अधिनियम में कुछ बदलावों को भी मंजूरी दी है जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा।

राजस्व संग्रह में सुस्ती बड़ी चिंता, फिलहाल दरों में बदलाव नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्व संग्रह बढ़ाने के उपायों पर विचार हुआ। हालांकि काउंसिल ने रेवेन्यू बढ़ाने के किसी भी विकल्प पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अधिकारियों की समिति ने रेवेन्यू की मौजूदा स्थिति और उसे बढ़ाने के सुझावों पर एक प्रजेंटेशन काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया। काउंसिल ने समिति को कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल कर अगली बैठक में फिर से प्रस्तुत करने को कहा गया है।

प्रजेंटेशन में कुछ स्लैब बदलने का भी सुझाव दिया गया। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे गलत कदम बताया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्यों की तरफ से रेवेन्यू कलेक्शन की प्रक्रिया में मौजूद गड़बड़ियों को रोकने के उपाय करने को कहा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि प्रजेंटेशन इस बात का आभास देता है कि अभी कई चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कंपनसेशन सेस के जरिये होने वाले कलेक्शन की रफ्तार इस बात की आशंका पैदा करती है कि फरवरी, 2020 के बाद सरकार के पास राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 'मैं पहले भी यह स्पष्ट कर चुकी हूं कि केंद्र राज्यों को कंपनसेशन देने के लिए वचनबद्ध है।' केंद्र ने दो दिन पहले ही राज्यों को 35298 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर जारी किए थे।

विकास पर खर्च के लिए राज्यों ने मांगी अधिक धनराशि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में उठा मुद्दा
- फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य में राहत की मांग भी की गई

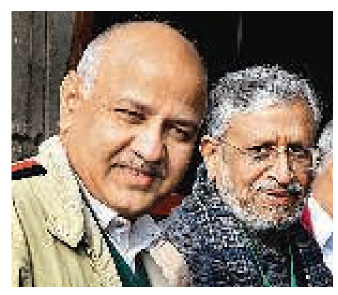

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी। एएनआइ

विकास कार्यों पर खर्च के लिए राज्य अगले बजट में न केवल ज्यादा राशि चाहते हैं, बल्कि फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्यों में भी राहत की गुंजाइश तलाश रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आइजीएसटी के बकाया के भुगतान का मुद्दा भी उठाया।

बैठक में गोवा, हरियाणा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, दिल्ली, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ 17 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सीतारमण ने बैठक में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के उपायों पर काम कर रही है। इस मौके पर राज्यों ने कहा कि मौजूदा वक्त में देश में सरकारी खर्च में वृद्धि की आवश्यकता है। इसलिए राज्यों को विकास कार्यों पर खर्च के लिए अधिक धनराशि की दरकार होगी।

राज्यों की वित्तीय हालत के मद्देनजर प्रदेश सरकारों पर राजकोषीय संतुलन बनाए रखने का दबाव रहता है। इसकी वजह से सरकारें एक सीमा से अधिक अपने व्यय को विस्तार नहीं दे पातीं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बैठक में बिहार और केरल के वित्त मंत्रियों ने फिस्कल डेफिसिट की सीमा को चार परसेंट तक बढ़ाने का सुझाव दिया। वैसे भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट 3.6 से 3.8 परसेंट के बीच रह सकता है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों को मिलने वाली राशि का मुद्दा उठाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे केंद्रशासित प्रदेशों को केवल केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता है। वह भी 2001-02 से 325 करोड़ रुपये पर सीमित है। जबकि बाकी सभी राज्यों को हर साल बढ़ा हुआ हिस्सा मिलता है। सिसोदिया ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7150 करोड़ रुपये और 2020-21 के लिए 8150 करोड़ रुपये की मांग की।

आधा पेराई सीजन खत्म फिर भी नहीं चलीं 67 चीनी मिलें, उत्पादन घटा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- गन्ने की फसल खराब होने से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में उत्पादन प्रभावित
- अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की हालत बेहतर, बढ़ रहा उत्पादन

प्रतीकात्मक फोटो

आधा पेराई सीजन खत्म होने के बावजूद देश में 67 चीनी मिलों में अब भी चीनी उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। इसके चलते चीनी का उत्पादन 35 फीसद तक घट गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे चीनी उत्पादक राज्यों में पिछले साल के मुकाबले कम चीनी मिलों में पेराई शुरू हो पाई है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के मुताबिक इस बार इन राज्यों में गन्ने की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। गन्ना कम होने की वजह से मिलों में पेराई चालू नहीं हो सकी है। 15 दिसंबर तक देश की 406 मिलों में चीनी उत्पादन होने लगा था, जबकि पिछले साल की इस अवधि तक 473 मिलों में पेराई हो रही थी। चीनी के उत्पादन में 35 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई है। अभी तक 45.81 लाख टन चीनी उत्पादित हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 70.54 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। उत्तर प्रदेश में इस ट्रेंड के विपरीत 119 मिलों में पेराई होने लगी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 116 मिलों में पेराई हो रही थी। इसी तरह चीनी का उत्पादन 21.25 लाख टन हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.31 लाख टन अधिक है। दूसरा चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में 124 मिलों में पेराई शुरू हो गई है, जो अब तक 7.66 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले साल की इसी अवधि तक 178 मिलों में चीनी का उत्पादन हो रहा था और कुल 29 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका था।

तीसरे सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में 63 मिलें चल रही हैं, जिनमें 10.62 लाख टन का उत्पादन हुआ है। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 3.32 लाख टन कम है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की फसल को मानसून की बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इन राज्यों में गन्ने से चीनी की रिकवरी दर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तमिलनाडु में अभी तक छह मिलों में पेराई हो रही है जबकि पिछले साल अब तक 16 मिलों में चीनी का उत्पादन हो रहा था। गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी चीनी का उत्पादन हो रहा है, लेकिन गति धीमी है। चीनी की मांग और आपूर्ति में इस सीजन में अंतर बढ़ सकता है, जिससे बाजार में चीनी कीमतें तेज हो सकती हैं।

सेल से रॉयल्टी के तीन हजार करोड़ की मांग पर लगी रोक

राज्य ब्यूरो, रांची

- झारखंड सरकार ने सेल की चार माइंस के लिए सौंपा है मांग पत्र
- हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस एके द्विवेदी की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए मांग पत्र पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही, राज्य सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड सरकार ने सेल से करीब तीन हजार करोड़ रुपये की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च, 2020 को होगी। इस संबंध में सेल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें सरकार के मांग पत्र को चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान सेल के अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सेल के चाईबासा स्थित मेगाहाता बुरू, किरीबुरू, दुर्गाइबूरू व धोबिल के लौह अयस्क खदानों के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का मांग पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कंपनियों को द्वितीय नवीकरण की अवधि से लेकर अब तक जमा की गई रॉयल्टी की राशि के बराबर की राशि जमा करनी है। सरकार जिस नियम का हवाला दे रही है, उसके अनुसार यह राशि देय नहीं है। सरकार ने नियमों के बाबत जो विश्लेषण किया है, वह गलत है। यह सेल पर लागू नहीं होता है। केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है, जबकि नियम के तहत मांग पत्र निर्गत करने का आधार केंद्र सरकार की अधिसूचना होनी चाहिए।

झारखंड सरकार ने बताया कि इस मामले में सरकार द्वारा नियमों का विश्लेषण सही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नई अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं है। माइनिंग एक्ट की अनुसूची दो के अनुसार रॉयल्टी की दर निर्धारित है। उसी के तहत मांग पत्र जारी हुआ है। इसलिए वादी को अंतरिम राहत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सेल को अंतरिम राहत देते हुए सरकार के मांग पत्र पर रोक लगा दी है।

फिएट-प्यूगो के विलय से बनेगी दुनिया की चौथी बड़ी ऑटो कंपनी

मिलान, एपी : ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी फिएट क्रिस्लर ने फ्रांस की पीएसए प्यूगो के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। विलय के बाद बनने वाली कंपनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटो निर्माता होगी। हालांकि नई कंपनी के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

दोनों कंपनियों की ओर से साझा वक्तव्य में कहा गया है कि विलय के बाद बनने वाली कंपनी के सीईओ कार्लो टेवरेस होंगे, जो पीएसए के सीईओ हैं। वहीं फिएट के चेयरमैन जॉन एल्कॉन नई कंपनी के चेयरमैन होंगे। फिएट के वर्तमान सीईओ माइक मनले विलय के बाद भी कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। हालांकि उनकी भूमिका अभी तय नहीं की गई है। विलय प्रक्रिया पूरी होने में 12 से 15 महीने का वक्त लगेगा। दोनों कंपनियों की ओर से कहा गया है कि नई कंपनी प्रति वर्ष 87 लाख कारों का निर्माण करेगी। पीएसए प्यूगो फ्रांस मूल की कंपनी है। फिलहाल दुनिया में तीन बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में टोयोटा, फॉक्सवैगन और रेनो-निसान के नाम शामिल हैं।

बढ़त का दौर

विदेशी निवेशक घरेलू बाजारों पर हैं मेहरबान, ग्लोबल संकेतों से भी बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा

रिकॉर्ड पथ पर सेंसेक्स का सफर जारी

प्रतीकात्मक फोटो

मुंबई, प्रेट्र : प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का दौर बरकरार है। सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को भी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। पिछले सत्र में भी दोनों सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए थे। बुधवार के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 206.40 अंक यानी 0.50 परसेंट उछाल के साथ 41,558.57 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 56.65 अंक की तेजी दर्ज की गई। यह 12,221.65 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्यादा 3.37 परसेंट का उछाल देखा गया। इसके साथ ही सन फार्मा, एशियन पेंट्स, आइटीसी, एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.53 परसेंट तक की तेजी दर्ज करने में सफल रहे। वहीं एनक्लैट के फैसले के चलते टाटा ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखी गई। टाटा मोटर्स के शेयर 3.05 परसेंट तक लुढ़क गए। एचयूएल, एसबीआइ, यस बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और बजाज फाइनेंस के शेयर 1.79 परसेंट तक की गिरावट के साथ बंद हुए।

जानकारों के मुताबिक स्टॉक विशेष से जुड़े मामलों के साथ ही घरेलू बाजारों में लगातार बढ़ रहे विदेशी निवेश ने भी बाजारों का मूड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले सत्र में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 728.13 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस दौरान एशिया के अन्य बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। यूरोपीय शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में कुछ तेजी दर्ज करने में सफल रहे।

एनक्लैट के फैसले के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों में गिरावट : टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री को पद पर बहाल करने के एनक्लैट के फैसले के बाद बुधवार को टाटा ग्रुप के शेयरों में चार परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में टाटा ग्लोबल बेवरेज के शेयर 4.14 परसेंट लुढ़ककर बंद हुए। वहीं टाटा कॉफी में 3.88 और टाटा मोटर्स के शेयरों में 3.05 परसेंट की गिरावट देखी गई। टाटा केमिकल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा पावर के शेयरों में भी 2.48 परसेंट तक की नरमी दर्ज की गई। हालांकि टीसीएस के शेयर 0.07 परसेंट की मामूली बढ़त दर्ज करने में सफल रहे।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

जेपी इन्फ्रा : संकट से गुजर रही जेपी इन्फ्रा के लिए एनबीसीसी की बोली को मंजूरी मिलने के बाद इसके शेयरों में तेज उछाल देखा गया। बुधवार को बीएसई में कंपनी के शेयर 9.88 परसेंट उछाल के साथ 1.78 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। वहीं एनएसई में कंपनी के शेयरों में 9.09 परसेंट का उछाल आया। यहां यह 1.80 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा : बुधवार को इस सरकारी कर्जदाता के शेयरों में तीन परसेंट से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में बैंक के शेयर 3.28 परसेंट की गिरावट के साथ 98.90 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में इसके शेयरों में 3.23 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। गौरतलब है कि आरबीआइ ने कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 5,250 करोड़ रुपये का एनपीए कम करके दिखाया है।

इन्फोसिस : कंपनी द्वारा अमेरिका में लगा जुर्माना चुकाने की हामी भरने के बाद इसके शेयरों में तेजी देखी गई। बुधवार को बीएसई में इसके शेयर 0.44 परसेंट की तेजी के साथ 732.50 रुपये के भाव पर बंद हुए। वहीं एनएसई में भी इसके शेयरों में 0.38 परसेंट का उछाल आया। इन्फोसिस ने शेयर बाजारों को बताया था कि इसने कैलीफोर्निया के अटार्नी जनरल के साथ मामला निपटा लिया है।

इन्फोसिस ने अमेरिका में बड़े मामले का निपटारा किया

- कंपनी ने कहा, मामला खत्म करने को जुर्माना भरने के लिए तैयार
- वीजा नियमों के दुरुपयोग के आरोप में लगा है करीब छह करोड़ का जुर्माना

वाशिंगटन, प्रेट्र : आइटी सेक्टर की दिग्गज भारतीय कंपनी इन्फोसिस के खिलाफ अमेरिका में आठ लाख डॉलर (करीब 5.68 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। कंपनी मामला निपटाने के लिए यह रकम चुकाने को तैयार हो गई है, जिसे बाजार सकारात्मक नजरिये से देख रहा है।

इन्फोसिस पर आरोप है कि उसने कैलिफोर्निया में विदेशी कर्मचारियों के वर्गीकरण में गड़बड़ी की और टैक्स फ्रॉड किया। मामले साल 2006 से लेकर 2017 के बीच के हैं। अमेरिका के इस राज्य में इन्फोसिस के करीब 500 कर्मचारी हैं। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेकेरा ने कहा कि इन्फोसिस ने इनके लिए एच-1बी वीजा की जगह बी-1 वीजा का इस्तेमाल किया। गलत तरीके से किए गए इस वर्गीकरण का मकसद कैलिफोर्निया में लागू पेरॉल टैक्स से बचना था। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, डिसएबिलिटी इंश्योरेंस और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग टैक्स इसमें शामिल है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कर्मचारियों को स्थानीय नियमों के मुताबिक वेतन-भत्तों के भुगतान के लिए भी एच-1बी वीजा की जरूरत पड़ती है। बेकेरा ने कहा, 'आज का सेटलमेंट दिखाता है कि कैलिफोर्निया के कानून से बचने की कोशिश करना फायदेमंद नहीं है। इन्फोसिस गलत वीजा के आधार पर कर्मचारियों को लेकर आई। कंपनी की सोच थी कि यह तरीका अपनाकर वह कम वेतन-भत्तों का भुगतान करेगी और कुछ टैक्स से बच जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।' इन्फोसिस यह मामला निपटाने के लिए जुर्माने का भुगतान करने को तैयार हो गई है, लेकिन उसने तमाम आरोपों से इन्कार किया है।

25 आतंकी ढेर हो गए अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में सेना की कार्रवाई में, सेना ने बुधवार को बताया कि लड़ाकू विमान की मदद से पिछले 24 घंटों के दौरान तालिबान के गढ़ शाह वली कोट जिले में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

ट्रंप का विपक्ष पर हमला, महाभियोग की मुहिम को अवैध बताया

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में अपने खिलाफ महाभियोग के बने आसार से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने पूरी मुहिम को अवैध और भेदभाव वाला बताया है जिसके जरिये डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार को गिराना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, विपक्ष ने लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया है और दबाव डालकर राष्ट्रपति पद से उन्हें हटाना चाहता है। इसके लिए वह यूक्रेन में जोसेफ बिडेन के खिलाफ जांच का सहारा ले रहा है।

ट्रंप ने ये टिप्पणियां प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नेंसी पेलोसी को लिखे पत्र में की हैं। सदन में सांसद महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप पर लगाए जाने वाले आरोपों पर बहस करने वाले हैं। इस बहस में तय होगा कि ट्रंप पर किन आरोपों पर महाभियोग चलाया जाए। अपने छह पेज के पत्र में ट्रंप ने महाभियोग के लिए की गई जांच पर आपत्ति जताई है। उन्होंने पेलोसी, डेमोक्रेट सांसदों, बिडेन और एफबीआइ पर हमला बोला है। पेलोसी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रतिनिधि सभा को भेदभाव का अड्डा बना दिया है। ऐसा उनके (ट्रंप के) प्रति व्यक्तिगत ईर्ष्या के भाव के चलते किया।

ट्रंप ने कहा कि उन्हें सत्ता से हटाने की इस मुहिम से नवंबर 2020 में होने वाले चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पोलिंग बूथ तक पहुंचते-पहुंचते यह मुहिम बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी।

प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है, उससे पहले ही उच्च सदन सीनेट से उसे रोकने के संकेत मिलने लगे हैं। सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है।

सैन फ्रांसिस्को में फेडरल बिल्डिंग के सामने राष्ट्रीय महाभियोग रैली के दौरान पोस्टर दिखाती महिला प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर प्रतिनिधि सभा में वोटिंग होनी है। इससे पहले देशभर में उनके खिलाफ रैलियां निकाली गईं। एएफपी

स्पेस फोर्स गठित करने पर अमेरिकी सीनेट की मुहर

52 लाख करोड़ रुपये के रक्षा बजट में किया गया प्रावधान

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने मंगलवार को सालाना रक्षा बजट पर अपनी मुहर लगा दी। इस बजट में स्पेस फोर्स गठित करने का प्रावधान भी किया गया है। इस बजट से जुड़े बिल में अमेरिकी सेना की नई शाखा के तौर पर अंतरिक्ष बल की स्थापना की बात कही गई है। यह वायुसेना के नियंत्रण में रहेगी।

सीएनएन के अनुसार, सीनेट ने 738 अरब डॉलर (करीब 52 लाख करोड़ रुपये) के रक्षा बजट के बिल को भारी बहुमत से पारित किया। आठ के मुकाबले 86 मतों से पारित नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (एनडीएए) अब ह्वाइट हाउस भेजा जाएगा। जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर से यह कानून बन जाएगा। निचले सदन प्रतिनिधि सभा में गत सप्ताह यह बिल 48 के मुकाबले 377 मतों से पारित किया गया था। सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष जिम इंहोफ ने कहा, 'हमने अंतरिक्ष के मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया है। हम और हमारे सहयोगियों के सामने एक बड़ी कमी है कि रूस और चीन के पास अंतरिक्ष बल हैं, लेकिन हमारे पास नहीं।'

ट्रंप ने दिया था आदेश : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन को स्पेस फोर्स गठित करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने कहा था, 'मैंने पेंटागन को स्पेस फोर्स गठित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए कहा है। हमारे पास एयर फोर्स है लेकिन हमें उसके आगे जाना है, स्पेस फोर्स बनानी है। स्पेस फोर्स भी एयर फोर्स जैसी होगी।'

जापान की महिला पत्रकार ने जीता हाई प्रोफाइल मी टू केस

टोक्यो, एएफपी : 'मी टू' अभियान के तहत दो साल पहले जापान में सहकर्मी रिपोर्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार शिओरी इतो ने कानूनी लड़ाई जीत ली है।

टोक्यो की एक अदालत ने बुधवार को इस हाईप्रोफाइल मामले में शिओरी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जाने-माने टीवी पत्रकार नोरीयुकी यामागुची को 33 लाख येन (करीब 21 लाख रुपये) का हर्जाना भरने का आदेश सुनाया। यामागुची को जापान के पीएम एबी शिंजो का करीबी बताया जाता है। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है।

वर्ष 2017 में 'मी टू' अभियान के तहत दुनियाभर में कई महिलाओं ने अपने खिलाफ हुए यौन अपराधों को सामने लाने का साहस दिखाया था। इसी के तहत शिओरी ने भी यामागुची पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। यामागुची ने इस आरोप को झूठा बताते हुए शिओरी पर 13 करोड़ येन (करीब 8 करोड़ रुपये) की मानहानि का मुकदमा किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

टोक्यो में मंगलवार को अदालत के फैसले के बाद प्रेसवार्ता में सिर झुकाते टीवी पत्रकार नोरीयुकी यामागुची। रायटर

टोक्यो में अदालत के फैसले के बाद मीडिया को प्रतिक्रिया देते समय महिला पत्रकार शिओरी इतो की आंखें भर आईं। एएफपी

अब रूस अंतरिक्ष से रखेगा बैलेस्टिक मिसाइलों पर नजर

मॉस्को, एएफपी : रूस ने बुधवार को अंतरिक्ष से संचालित होने वाले मिसाइल वार्निंग सिस्टम पर से पर्दा हटा दिया। रूस ने यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेस फोर्स बनाने के प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद में मतदान से पहले उठाया है। रूस ने अपने नए सिस्टम का नाम कुपोल रखा है जिसका मतलब डोम होता है। इसे इस तरह से डिजायन किया गया है कि यह अंतरिक्ष से ही बैलेस्टिक मिसाइल पर छोड़े जाने वाले स्थान से ही नजर रखेगा। यह बात रूसी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और सिस्टम के बारे में वितरित लिखित विवरण में कही गई है। इस सिस्टम के तहत चेतावनी देने वाले तीन सेटेलाइट रूस ने पहले ही छोड़ रखे हैं। टुंड्रा नाम के ये सेटेलाइट 2015 से अंतरिक्ष में कार्यरत हैं। कुपोल को कहां स्थापित किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि यह अमेरिका के सर्विलांस सिस्टम एसबीआइआरएस की स्थापना को ध्यान में रखकर स्थापित होगा।

रूसी सेनाओं के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव ने कहा है कि नया सिस्टम अंतर महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइलों को खोजने की रूस की क्षमता को बढ़ाएगा। रूस ने अपने नए सिस्टम की घोषणा अमेरिकी कांग्रेस के नई स्पेस फोर्स के लिए 738 अरब डॉलर की स्वीकृति के एक दिन बाद की है। अमेरिका की यह नई फोर्स एयरफोर्स के अंतर्गत कार्य करेगी। रूस ने इस तरह की फोर्स का 2015 में ही गठन कर रखा है और वह एयरफोर्स के अंतर्गत कार्य करती है।

विद्रोही तेवर ▶ पाक सेना ने कहा कि पूर्व प्रमुख ने देश से धोखा नहीं किया

मुशर्रफ की मौत की सजा को चुनौती देगी पाक सरकार

सेना के रुख के बाद सतर्क हुए इमरान, आनन-फानन में एलान

▶ विशेष अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 76 साल के मुशर्रफ के लिए सजा का एलान किया

▶ 2016 में विदेश जाने के बाद वापस नहीं लौटे मुशर्रफ, इस समय वह दुबई में रह रहे हैं

इस्लामाबाद, प्रेट्र : देशद्रोह के लिए मौत की सजा पाए पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के समर्थन में सेना के आने के बाद पाकिस्तान सरकार ने आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। मंगलवार को सैन्य तानाशाह मुशर्रफ को छह साल चले मुकदमे उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। मुशर्रफ इलाज के लिए अनुमति लेकर 2016 में विदेश गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे। इस समय वह दुबई में रह रहे हैं।

विशेष अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 76 साल के मुशर्रफ के लिए सजा का एलान किया। उन्हें 2007 में संविधान का उल्लंघन कर देश में आपातकाल लागू करने के मामले में दोषी पाया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर कहा कि उसके पूर्व प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने कभी भी देश के साथ धोखा नहीं किया। उनके खिलाफ अदालत के ताजा फैसले से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवानों को बहुत दुख हुआ है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा- एक पूर्व सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की कमेटी के अध्यक्ष और राष्ट्रपति रहे मुशर्रफ देशद्रोही नहीं हो सकते।

उन्होंने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की सेवा की और देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, उन्हें कैसे धोखेबाज कहा जा सकता है। विशेष अदालत ने कानूनी प्रक्रिया के दौरान इन सभी तथ्यों की अनदेखी की। मामले में बचाव के मूलभूत अधिकार का भी हनन हुआ। सेना की ओर से आए इस बयान से इमरान सरकार पर मामले पर विचार के लिए काफी दबाव बन गया। पाकिस्तान में पहली बार किसी सैन्य प्रशासक के लिए अदालत ने मौत की सजा का एलान किया है।

सेना के इस सार्वजनिक बयान से सतर्क हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने तत्काल अपने दो विश्वस्त अधिकारियों को सैन्य अधिकारियों को समझाने के लिए भेजा। जिनेवा में मौजूद इमरान की ओर से इन अधिकारियों ने सेना को बताया कि सरकार मुशर्रफ के खिलाफ आए इस आदेश को ऊंची अदालत में चुनौती देगी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान और प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आशय की घोषणा की। खान ने कहा कि आदेश जारी करने का समय भी खुद पर सवाल खड़े करता है। आदेश तब जारी हुआ जब मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में चिंताजनक स्थिति में दाखिल हैं और वह इस समय आइसीयू में हैं।

परवेज मुशर्रफ। फाइल

चीन ने सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर चर्चा की अपील वापस ली

▶ अमेरिका से बातचीत के बाद एजेंडे से कश्मीर मुद्दे को हटाया

▶ चीनी प्रस्ताव के विरोध में फ्रांस ने वीटो कर दिया था

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर चर्चा से संबंधित अनुरोध चीन के वापस लेने की खबरों के बीच पाकिस्तान ने झूठा दावा किया है कि इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में चर्चा हुई है।

पाकिस्तान की इमरान सरकार ने बुधवार को झूठा दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर निजी स्तर पर चर्चा की है। पाकिस्तान के आधिकारिक रेडियो ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से यह दावा किया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान का दावा एकदम झूठा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर निजी चर्चा हुई ही नहीं। चूंकि चीन के प्रस्ताव के विरोध में फ्रांस ने वीटो कर दिया था। हालांकि फ्रांस के राजनयिक से जुड़े सूत्र ने इससे पहले बताया था कि मंगलवार को सुरक्षा परिषद की बैठक में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी।

ऐसी सूचना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति का हवाला देते हुए 12 दिसंबर को परिषद को पत्र लिखा था। इसके बाद इस्लामी देश के सदाबहार मित्र चीन ने 15 सदस्यों वाले सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। मंगलवार दोपहर को सुरक्षा परिषद के विमर्श कक्ष में अनौपचारिक बैठक के दौरान 'अन्य मुद्दों' के अंतर्गत इस विषय पर भी चर्चा की संभावना थी। इस तरह की बैठक सार्वजनिक रूप से नहीं होती। बंद कमरे में गुप्त मंत्रणा होती है। बैठक में कही गई बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच सलाह-मशविरे के लिए इस तरह की अनौपचारिक बैठकों का आयोजन होता है। हालांकि, सुरक्षा परिषद में चर्चा से पहले के घटनाक्रमों के चलते यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वनियोजित योजना के अनुसार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी।

एक यूरोपीय राजनयिक अधिकारी ने सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक से पहले कहा कि कश्मीर पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि चीन ने अपना अनुरोध वापस ले लिया है। सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग ने उत्तर कोरिया में स्थिति पर सुरक्षा परिषद की राय के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कश्मीर पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, इस पर चीनी राजदूत ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं इस विषय पर कुछ और कहने की स्थिति में हूं। हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद को पाकिस्तान के विदेश मंत्री से एक पत्र मिला है जिसमें सुरक्षा परिषद में इस विषय पर चर्चा का अनुरोध किया गया है और वहां इस पर चर्चा हो रही है।' इस बारे में जब उनसे फिर से सवाल पूछा गया कि चीन ने परिषद में चर्चा का अनुरोध किया था और फिर इसे वापस ले लिया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक अन्य राजनयिक सूत्र ने बताया कि चीन और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है कि वे एजेंडे में कश्मीर मुद्दे को शामिल नहीं करेंगे। दिसंबर में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता चीन और अमेरिका के पास है।

अगस्त में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद पाकिस्तान ने पोलैंड को पत्र लिखकर सुरक्षा परिषद में चर्चा का अनुरोध किया था क्योंकि पोलैंड अगस्त में परिषद का अध्यक्ष था। इसके बाद चीन ने सुरक्षा परिषद में अनौपचारिक बैठक की मांग की थी। हालांकि, 16 अगस्त को कश्मीर मुद्दे पर हुई सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई या फिर इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली संगठन से कोई बयान भी नहीं आया।

पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 12 दिसंबर को परिषद को पत्र लिखा था। फाइल

अमेरिका में हत्याकांड की साजिश रच रहा सऊदी छात्र हिरासत में

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका के न्यू मेक्सिको प्रांत के अलबुकर्क शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे सऊदी अरब के एक छात्र को हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अभियोजन की मांग पर मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने न्यू मेक्सिको यूनिवर्सिटी के छात्र हसन अलकहतानी (27) को हिरासत में रखने का आदेश दिया। यह मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब हाल ही में अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे सऊदी वायुसेना के सेकेंड लेफ्टिनेंट ने फ्लोरिडा के पेंसाकोला स्थित नौसेना अड्डे पर गोलीबारी कर तीन लोगों की जान ले ली थी।

हसन को पुलिस ने बीते शुक्रवार को घरेलू हिंसा के मामले में पकड़ा था। उस पर पत्नी और अन्य लोगों से मारपीट व जान से मारने की धमकी के आरोप हैं। हसन पर अलबुकर्क स्थित अपने घर में अवैध रूप से हथियार रखने का मामला भी चल रहा है। हसन के खिलाफ तहकीकात के दौरान संघीय जांच एजेंसी एफबीआइ को पता चला कि वह यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के अलावा कुछ अन्य लोगों की हत्या की साजिश रच रहा है।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन को 18 माह की जेल

सियोल, एएफपी : दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने स्मार्टफोन और चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन ली सांग-हून को 18 माह जेल की सजा सुनाई है। ली को यह सजा श्रमिक यूनियन की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में मिली है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग समूह की प्रमुख सहायक कंपनी है।

सियोल की सेंट्रल डिस्ट्रिक कोर्ट ने मंगलवार को सैमसंग के चेयरमैन ली और कार्यकारी उपाध्यक्ष कांग क्यूंग-हून को श्रमिक यूनियन कानून के उल्लंघन का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को 18-18 माह जेल की सजा सुनाई। ली और कांग पर सैमसंग की ग्राहक सेवा इकाई से जुड़ी यूनियन को कमजोर करने वाली गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया था। सजा के एलान के तुरंत बाद सैमसंग के दोनों शीर्ष अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। अभियोजकों के अनुसार, दोनों ने अपने अधीनस्थों को यूनियन में शामिल कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने और उनकी निजी जानकारियां जुटाने को कहा था। कर्मचारियों को प्रभावित करने के प्रयास में उनके कर्ज और गर्भावस्था जैसी जानकारियां भी जुटाई गई थीं।

कंपनी ने मांगी माफी : सैमसंग ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी कर इस कृत्य के लिए माफी मांगी। कंपनी ने कहा, 'हम विनम्रतापूर्वक यह स्वीकार करते हैं कि अतीत में कंपनी की श्रमिक संगठनों के प्रति सोच और समझ समाज की उम्मीदों के अनुरूप नहीं थी। हम आगे मिलकर काम करने और कर्मचारियों के सम्मान के आधार पर श्रमिक-प्रबंधन के बीच रचनात्मक संबंधों की उम्मीद करते हैं।'

सैमसंग इलैक्ट्रानिक्स के चेयरमैन ली संग-हून। फाइल फोटो

पासपोर्ट रिन्यू कराने वाले ओसीआइ कार्डधारकों के लिए राहत का एलान

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत सरकार ने 20 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक के ऐसे ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया (ओसीआइ) कार्डधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है जिन्होंने अपने पासपोर्ट रिन्यू (नवीनीकरण) कराए हैं। ऐसे लोग अब 30 जून तक ओसीआइ कार्ड के अलावा पुराने और नए पासपोर्ट के साथ भारत की यात्रा कर सकेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के विदेशी मामलों के विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। दरअसल, पिछले कई महीनों से बड़ी संख्या में ओसीआइ कार्डधारक इस बात की शिकायत कर रहे थे कि आव्रजन और एयरलाइन अधिकारी ओसीआइ के ऐसे प्रावधान की वजह से उन्हें परेशान कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिसे अभी तक लागू भी नहीं किया जा रहा था। इस प्रावधान के तहत पासपोर्ट रिन्यू कराने वाले 20 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए साथ ही साथ ओसीआइ कार्ड रिन्यू कराना भी अनिवार्य है। इसकी जानकारी नहीं होने के कारण कई कार्डधारकों को भारत यात्रा रद करनी पड़ी अथवा बीच रास्ते से लौटना पड़ा था।

विरोध प्रदर्शन

मकाऊ रवाना होने से पहले बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम का पोर्ट्रेट दिखाता लोकतंत्र समर्थक। शी चिनफिंग के मकाऊ दौरे के मद्देनजर बड़ी संख्या में हांगकांग से लोकतंत्र समर्थक वहां रवाना हुए थे। हांगकांग की तरह यह चीन प्रशासित क्षेत्र है। यहां पुर्तगाल का कब्जा था। 20 दिसंबर 1999 को इसे चीन को हस्तांतरित कर दिया गया था। एक देश दो प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत रक्षा और विदेश संबंधी मामलों का उत्तरदायित्व चीन के पास है। जबकि कानून-व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था जैसे मामले स्थानीय प्रशासन के जिम्मे है। एएफपी

शांति वार्ता पर चर्चा करने काबुल पहुंचे अमेरिकी दूत

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में शांति स्थापना के मकसद से स्थानीय नेताओं से बातचीत के लिए अमेरिका के विशेष दूत जालमे खलीलजाद बुधवार को काबुल पहुंचे। इससे पहले वह पिछले सप्ताह पाकिस्तान गए थे। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी मुजीबुर्रहमान रहीमी ने कहा है कि खलीलजाद फिलहाल स्थगित शांति वार्ता को फिर बहाल करने पर चर्चा करेंगे। खलीलजाद और आतंकी संगठन तालिबान के बीच वार्ता हाल में फिर शुरू हुई थी। लेकिन पिछले हफ्ते बगराम स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास तालिबान के आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने वार्ता स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच कतर की राजधानी दोहा में कई दौर की वार्ता हुई थी, जिसे गत सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद कर दिया था। इसके पीछे भी तालिबान द्वारा अमेरिकी सेना पर किया गया हमला था।

आयोजन

अबू धाबी में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा, पश्चिम की जगह पूर्व की ओर देखने की जरूरत

दक्षिण एशिया से निकलेगी मुस्लिम समाज में सुधार की राह

जेएनएन, नई दिल्ली

मुस्लिम समाज में सुधार की राह दक्षिण एशिया से निकलेगी और इसमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह बात 'फोरम फॉर प्रमोटिंग पीस इन मुस्लिम सोसाइटीज' की छठी वार्षिक सभा में कही गई। वक्ताओं ने भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण करार दिया और कहा कि दक्षिण एशिया में नई दिल्ली इस कार्य का नेतृत्व भी कर सकता है। साथ ही पश्चिमी देशों के बजाय पूर्व की ओर देखने की बात कही गई।

बीते दिनों संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में आयोजित इस सम्मेलन में मुस्लिम समाज के बच्चों को दी जा रही शिक्षा, उसमें बदलाव, सुधार, देशों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा भी की गई। इस सभा में 'न्यू अलायंस ऑफ वर्च्यू' चार्टर जारी किया गया। भारत की ओर से इस सभा में शामिल हुए इस्लाम के जानकार और चिंतक रामिश सिद्दीकी ने इस अवसर कहा, 'दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें लगभग एक चौथाई आबादी रहती है। उनमें से अधिकांश भारत में रहते हैं। इसी कारण से दक्षिण एशिया में चार्टर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले भारत सरकार के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हितधारक है।' उन्होंने कहा कि भारत का सहयोग मिलने से हम ना सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि विश्वभर में इस चार्टर का प्रचार करने में सफल हो पाएंगे।'

चार्टर में मुस्लिम समाज के बच्चों की वर्तमान शिक्षा पद्धति की भी बात की गई। कहा गया कि वर्तमान में मुस्लिम बच्चों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसका आधुनिकीकरण बेहद जरूरी है। इसके बिना मुस्लिम समाज की भावी पीढ़ी पीछे छूट जाएगी और समाज इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता कि उसकी पीढ़ी दुनिया में पिछड़ जाए।

फोरम के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला बिन बय्याह ने सभा में कहा, 'कोई भी राष्ट्र अकेले नहीं रह सकता। सह-अस्तित्व और सहयोग एक दूसरे के पूरक हैं। हमें सहयोग और अच्छाई को बढ़ाने की जरूरत है।' बता दें कि शेख अब्दुल्ला बिन बय्याह यूएई की फतवा काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। सभा में नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति यमी ओसिनबाजो ने कहा कि हमारा टकराव मुस्लिम और ईसाई के बीच नहीं है, बल्कि उन लोगों के बीच है जो सहिष्णु हैं और जो असहिष्णु हैं। अपने देश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, 'नाइजीरिया में जिन धर्मस्थलों को आतंकियों ने नष्ट कर दिया था, उन्हें बनाने में ईसाई समाज के लोग आगे आए और हमारी मदद की।' सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक धार्मिक नेताओं, विद्वानों व सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी भी शामिल हुए।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेते विभिन्न देशों के धार्मिक नेता व सरकारी प्रतिनिधि।
साभार : फोरम फॉर प्रमोटिंग पीस इन मुस्लिम सोसाइटीज

सीएए का विरोध गलत

भारत में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को रामिश सिद्दीकी ने गलत बताते हुए इसे वर्तमान की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो अल्पसंख्यक समाज उत्पीड़न झेल रहा है उसे रोकने और उनके संरक्षण की जरूरत है। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना गलत है। इसका विरोध करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए जा रहे आश्वासन पर विश्वास करना चाहिए।

इस्लामोफोबिया पर कंजरवेटिव पार्टी को सुझाव देंगे स्वर्ण सिंह

लंदन, एएनआइ : ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी ने भारतीय मूल के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें इस्लामोफोबिया समेत सामाजिक और धार्मिक मसलों पर सुझाव देने के लिए गठित स्वतंत्र समीक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह समिति भेदभाव और पक्षपात से जुड़ी शिकायतों के बेहतर निपटारे के लिए गठित की गई है।

कंजरवेटिव पार्टी ने प्रोफेसर सिंह की नियुक्ति का साहसिक कदम उन खबरों के बीच उठाया है, जिनमें कहा जा रहा है कि इस पार्टी की सरकार में मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन (एमसीबी) ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से आग्रह किया है कि वह ब्रिटिश मुस्लिमों को आश्वस्त करें। वारविक यूनिवर्सिटी में सामाजिक और सामुदायिक मनोचिकित्सा के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह इस बात की जांच-पड़ताल करेंगे कि कंजरवेटिव पार्टी इस तरह के मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को कैसे बेहतर कर सकती है? कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष जेम्स क्लेवर्ली ने कहा, 'मुझे पार्टी में भेदभाव और पक्षपात की स्वतंत्र समीक्षा के लिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को अध्यक्ष बनाने का एलान करते हुए खुशी हो रही है। कंजरवेटिव पार्टी हमेशा आरोपों पर तुरंत कार्रवाई करती है।' स्वर्ण सिंह समानता और मानवाधिकार आयोग के आयुक्त भी हैं। प्रोफेसर सिंह यह जिम्मेदारी 2013 से संभाल रहे हैं।

स्वर्ण सिंह। फाइल

दैनिक जागरण
कैरेबियाई चुनौती
www.jagran.com
गुरुवार 19 दिसंबर 2019

ये भी जानिए
पहली बार दोनों वनडे कप्तान गोल्डन डक पर आउट हुए। विराट कोहली और पोलार्ड पहली गेंद पर शून्य पर आउट हुए। ओवरऑल वनडे में 12 बार दोनों कप्तान शून्य पर आउट हुए।

वनडे में भारत के लिए हैट्रिक

गेंदबाज	बनाम	स्थान	वर्ष
चेतन शर्मा	न्यूजीलैंड	नागपुर	1987
कपिल देव	श्रीलंका	कोलकाता	1991
कुलदीप यादव	ऑस्ट्रेलिया	कोलकाता	2017
मुहम्मद शमी	अफगानिस्तान	साउथैंप्टन	2019
कुलदीप यादव	वेस्टइंडीज	विशाखापत्तनम	2019

वनडे में सर्वाधिक हैट्रिक

हैट्रिक	गेंदबाज	देश
03	लसित मलिंगा	श्रीलंका
02	वसीम अकरम	पाकिस्तान
02	सकलैन मुश्ताक	पाकिस्तान
02	चामिंडा वास	श्रीलंका
02	ट्रेंट बोल्ट	न्यूजीलैंड
02	कुलदीप यादव	भारत

99 विकेट कुलदीप यादव अपने वनडे करियर में ले चुके हैं। उन्होंने इतने विकेट 55 मैचों में हासिल किए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन पर छह विकेट है

भारत के लिए वनडे में एक ओवर में सर्वाधिक रन

रन	बल्लेबाज	गेंदबाज	जगह	वर्ष
31	अय्यर/रिषभ	रोस्टन	विशाखापत्तनम	2019
28	सचिन/जडेजा	क्रिस ड्रूम	हैदराबाद	1999
27	जहीर/अगरकर	ओलंगा	जोधपुर	2000

00 रन पर आउट हुए विराट कोहली। कोहली विशाखापत्तनम में पहली बार बिना खाता खोले वनडे में आउट हुए हैं। इससे पहले उन्होंने यहां नाबाद 157, 65, 99, 117, 118 रनों की पारी खेली थी

विंडीज के खिलाफ वनडे में भारत की बड़ी साझेदारियां

रन	बल्लेबाज	जगह	वर्ष	विकेट
246	विराट/रोहित	गुवाहाटी	2018	दूसरे
227	राहुल/रोहित	विशाखापत्तनम	2019	पहले
211	रायुडू/रोहित	मुंबई	2018	तीसरे

वनडे में सबसे ज्यादा 150+

स्कोर	बल्लेबाज	देश
08	रोहित	भारत
06	डेविड	ऑस्ट्रेलिया
05	तेंदुलकर	भारत
05	क्रिस गेल	वेस्टइंडीज

रोहित शर्मा का वनडे करियर

वर्ष	शतक	पारी
2007 से 2016	10	147
2017 से जारी	18	66

2013-19 में भारतीय का व्यक्तिगत स्कोर (वनडे)

वर्ष	खिलाड़ी	रन
2013	रोहित	209
2014	रोहित	264
2015	रोहित	150
2016	रोहित	171*
2017	रोहित	208*
2018	रोहित	162
2019	रोहित	159

हैट्रिक लेने के बाद जोश में कुलदीप यादव • प्रेट्र

हैट्रिक यादव

- वनडे में दो हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने कुलदीप
- रोहित ने जड़ा शानदार शतक, भारत ने 107 रनों से मैच जीता

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: कुलदीप यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिना गॉड फादर के भारतीय टीम में हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वह कमाल करते हैं और बिना बात के उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया जाता है। वह देश ही नहीं, विदेश की पिचों पर अपनी कलाई की स्पिन से कमाल दिखाते हैं। इंग्लैंड में हुए विश्व कप के बाद से कुलदीप को बिना बात किए टी-20 टीम से बाहर किया गया। यही नहीं उनकी और युजवेंद्रा सिंह चहल की जोड़ी को तोड़ा गया लेकिन कुलदीप तो कुलदीप ही हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापत्तनम में दूसरे वनडे में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की दूसरी हैट्रिक लेकर भारत को 107 रनों से जीत दिलाई। इस जीत में रोहित की 159 और लोकेश राहुल की 102 रनों की पारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोनों ने पहले विकेट के लिए 227 रनों की साझेदारी की जिससे तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर आ गई।

कुलदीप ने किया बेबस: भारत ने रोहित और राहुल के बाद रिषभ पंत और श्रेयष अय्यर की ताबड़तोड़ पारी की मदद से पांच विकेट पर 387 रन बनाए। कुलदीप की गेंदबाजी की बदौलत कैरेबियाई टीम 43.3 ओवर में 280 रनों पर ऑलआउट हो गई। कुलदीप पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी हैट्रिक ली है। इससे पहले उन्होंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में हैट्रिक ली थी। उन्होंने पारी के 33वें ओवर की चौथी गेंद पर शाई होप (78) को आउट किया जिनका कैच कोहली ने सीमा रेखा के पास शानदार तरीके से लपका। इसकी अगली गेंद पर उन्होंने जेसन होल्डर (11) को चलता किया जो विकेटकीपर रिषभ पंत द्वारा स्टंप आउट हुए। कुलदीप की अगली गेंद अल्जारी जोसेफ के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरी स्लिप पर खड़े केदार जाधव के हाथ में फंस गई। इसके बाद कुलदीप मैदान में दौड़ने लगे। उन्हें कभी ऐसा जश्न मनाते हुए देखा नहीं जाता लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कह रहे थे कि मुझे कम आंकने की भूल मत करना।

पाटा पिच पर अच्छा काम: मेहमान टीम ने पहला मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता था जिसमें भारतीय गेंदबाजों की काफी खिंचाई हुई थी। ओपनर लुइस (30) को सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे शार्दुल ठाकुर (1/55) ने अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। पिछले मैच के हीरो रहे हेटमायर (04) रन आउट हो गए। रोस्टन चेस (04) भी जडेजा का शिकार बने। इसके बाद होप और निकोलस पूरन ने चौथे विकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी करके टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुहम्मद शमी (3/39) ने लगातार दो विकेट लेकर मेहमानों की उम्मीद तोड़ दी। शमी ने पहले पूरन (75) को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। फिर अगली गेंद पर पोलार्ड (00) को पंत के हाथों कैच आउट कराया। होल्डर ने शमी की हैट्रिक पूरी होने नहीं दी। कीमो पॉल (46) को शमी ने बोल्ड करके मेहमान टीम की पारी समेट दी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा सर्वोच्च स्कोर: इससे पहले रोहित इस सीरीज के पहले मैच में 36 रन ही बना पाए थे जबकि राहुल छह रन पर सस्ते में आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह भारत का दूसरा जबकि कुल आठवां सर्वोच्च स्कोर है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही इंदौर में दिसंबर 2011 में पांच विकेट पर 418 रन का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था। रोहित ने राहुल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 227 रन की साझेदारी की। भारतीय टीम अंतिम सात ओवर में 100 रन जोड़ने में सफल रही। श्रेयस अय्यर (53) और रिषभ पंत (39) ने चौथे विकेट के लिए सिर्फ चार ओवर में 73 रन की साझेदारी की।

टूटे रिकॉर्ड: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ओर से पहले विकेट की सर्वोच्च साझेदारी हुई। रोहित और राहुल ने सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा जिन्होंने नवंबर 2002 में राजकोट में 196 रन की साझेदारी की थी। भारत की सलामी जोड़ी ने छठी बार 200 या इससे अधिक रन की साझेदारी करते हुए दूसरे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया की बराबरी की। पहले विकेट के लिए सर्वाधिक बार 200 या इससे अधिक रन की साझेदारी का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है जिसके बल्लेबाजों ने 11 बार यह उपलब्धि हासिल की है। रोहित ने लय में आने के बाद गेंदबाजों की अच्छी खबर ली। रोहित ने 34वें ओवर में 28वां शतक पूरा किया।

स्कोर बोर्ड

टॉस : वेस्टइंडीज (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : रोहित शर्मा

भारत 387/5 (50 ओवर)

बल्लेबाज	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. होप बो. कॉटरेल	159	138	17	05
लोकेश राहुल का. चेस बो. जोसेफ	102	104	08	03
विराट कोहली का. चेस बो. पोलार्ड	00	01	00	00
श्रेयस अय्यर का. होप बो. कॉटरेल	53	32	03	04
रिषभ पंत का. पूरन बो. पॉल	39	16	03	04
केदार जाधव नाबाद	16	10	03	00
रवींद्र जडेजा नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (बा-1, लेबा-3, नोबॉ-1, वा-13) 18
कुल : 50 ओवर में पांच विकेट पर 387 रन

विकेट पतन : 1-227 (राहुल, 36.6), 2-232 (कोहली, 37.3), 3-292 (रोहित, 43.3), 4-365 (पंत, 47.3), 5-373 (अय्यर, 48.6)
गेंदबाजी : कॉटरेल 9-0-83-2, होल्डर 9-0-45-2, खारे पियरे 9-0-62-0, कीमो पॉल 7-0-57-1, अल्जारी जोसेफ 9-1-68-1, रोस्टन चेस 5-0-48-0, कीरोन पोलार्ड 2-0-20-1

वेस्टइंडीज 280 (43.3 ओवर)

बल्लेबाज	रन	गेंद	चौके	छक्के
इविन लुइस का. अय्यर बो. ठाकुर	30	35	05	00
शाई होप का. कोहली बो. कुलदीप	78	85	07	03
शिमरोन हेटमायर रन आउट	04	07	00	00
रोस्टन चेस बो. जडेजा	04	09	00	00
निकोलस पूरन का. कुलदीप बो. शमी	75	47	06	06
कीरोन पोलार्ड का. पंत बो. शमी	00	01	00	00
जेसन होल्डर स्टं. पंत बो. कुलदीप	11	13	00	01
कीमो पॉल बो. शमी	46	42	04	03
जोसेफ का. जाधव बो. कुलदीप	00	01	00	00
खारे पियरे का. कोहली बो. जडेजा	21	18	03	00
शेल्डन कॉटरेल नाबाद	00	03	00	00

अतिरिक्त : (बा-1, लेबा-2, वा-8) 11
कुल : 43.3 ओवर में 280 रनों पर सभी आउट

विकेट पतन : 1-61 (लुइस, 10.6), 2-73 (हेटमायर, 13.1), 3-86 (चेस, 15.6), 4-192 (पूरन, 29.2), 5-192 (पोलार्ड, 29.3), 6-210 (होप, 32.4), 7-210 (होल्डर, 32.5), 8-210 (जोसेफ, 32.6), 9-260 (पियरे, 40.5)
गेंदबाजी : दीपक चाहर 7-1-44-0, शार्दुल ठाकुर 8-0-55-1, मुहम्मद शमी 7.3-0-39-3, रवींद्र जडेजा 10-0-74-2, कुलदीप यादव 10-0-52-3, श्रेयस अय्यर 1-0-13-0

190 छक्के रोहित शर्मा ने भारत में अंतरराष्ट्रीय मैचों में 116 पारियों में जड़े हैं और इस मामले में उन्होंने हमवतन महेंद्र सिंह धौनी को पीछे छोड़ दिया। धौनी ने 208 पारियों में 186 छक्के लगाए थे। रोहित ने एक साल में सबसे ज्यादा 77 छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया

एक वर्ष में वनडे में सर्वाधिक शतक

शतक	बल्लेबाज	वर्ष	पारी	देश
09	तेंदुलकर	1998	55	भारत
07	गांगुली	2000	32	भारत
07	वार्नर	2016	23	ऑस्ट्रेलिया
07	रोहित	2019	26	भारत

वनडे में सर्वाधिक शतक

शतक	बल्लेबाज	देश
49	सचिन	भारत
43	कोहली	भारत
30	पोंटिंग	ऑस्ट्रेलिया
28	रोहित	भारत
28	जयसूर्या	श्रीलंका
27	अमला	द. अफ्रीका

400 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के आठवें और दुनिया के 33वें क्रिकेटर बन गए। सचिन (664) इस मामले में सबसे आगे हैं

36 रन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने वनडे में एक ओवर में बनाए हैं। उन्होंने 2006-07 में सेंट किट्स में नीदरलैंड्स के वेन बुंज के ओवर में छह गेंदों में छह छक्के जड़े थे। इससे पहले श्रीलंका के तिसारा परेरा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2013 में एक ओवर में 35 रन जोड़े थे

31 रन श्रेयस और विकेटकीपर रिषभ पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए जो एक ओवर में सबसे ज्यादा बनाए गए रन की लिस्ट में संयुक्त रूप से छठे नंबर पर है

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा • प्रेट्र

एक नजर में

मुंबई ने जीती ट्रॉफी

धर्मशाला : मुंबई ने पंजाब को एक पारी और 50 रनों से हराकर विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 पर कब्जा जमा लिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेले गए फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन पंजाब की टीम दूसरी पारी में 151 रनों पर ही ऑलआउट हो गई। मुंबई की जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर मुशीर खान ने पंजाब की दूसरी पारी में भी पांच विकेट चटकाए जबकि कप्तान आयुष ने तीन विकेट हासिल किए। मुंबई की ओर से आदित्य पवार व प्रिंस ने 330 रनों से आगे खेलना शुरू किया। मुंबई केवल 13 ही रन जोड़ पाई और 343 रनों पर ऑलआउट हो गई। (जासं)

कप्तानी करेंगे संगकारा

मुंबई : क्रिकेट नियमों के संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने बुधवार को कहा कि वह अपने मौजूदा अध्यक्ष कुमार संगकारा की कप्तानी में अपनी टीम को पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में कुछ मैच खेलने के लिए भेजेगा। श्रीलंकाई टीम के दो मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान में पहुंचने के बाद वहां 10 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई है। एमसीसी ने कहा, क्लब अगले साल फरवरी में लाहौर में एक टीम भेजेगा, जिसमें कुछ मैच शहर में खेले जाएंगे। एमसीसी के मुख्य कार्यकारी और सचिव गॉय लावेंडर ने कहा, पाकिस्तान के लोग एक दशक से घरेलू मैदान पर अपनी टीम को खेलते हुए देखने के लिए तरस गए थे और हाल में देश में टेस्ट क्रिकेट की वापसी को देखना शानदार है। इस दौरे पर एमसीसी के सारे मैच लाहौर के ऐटचेसन कालेज में खेले जाएंगे। लावेंडर टीम के टीम मैनेजर होंगे और एमसीसी के मुख्य कोच अजमल शहजाद इसके कोच होंगे। (रायटर)

पाल्मर बनेंगे भारतीय स्क्वॉश टीम के कोच

नई दिल्ली : दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी डेविड पाल्मर को कुआलालंपुर में होने वाली एशियन टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया जाएगा। भारतीय स्क्वॉश रैकेट महासंघ (एसआरएफआइ) ने पूर्णकालिक कोच नियुक्त करने के बजाय टूर्नामेंट आधारित कोच रखने के तहत ऑस्ट्रेलिया के पाल्मर से संपर्क किया। उन्होंने 25 से 29 मार्च तक चलने वाली एशियन टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम को कोचिंग देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। (प्रेट्र)

खेल मंत्रालय ने दिए कड़े निर्देश

नई दिल्ली : खेल मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल संघों से अपने अकाउंट की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। साथ ही खेल संघों से सीएजी पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा ऑडिट किए गए अकाउंट का भी ब्योरा देने को कहा गया है। खेल संघों को दिशा निर्देशों के पालन और ऑडिट किए गए अपने दावों को 31 मार्च 2020 से पहले राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के समक्ष पेश करने को कहा गया है। (एएनआइ)

टेस्ट की वापसी होगी यादगार : अजहर

क्रिकेट डायरी

कराची, एएफपी: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली ने बुधवार को कहा कि गुरुवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में जीत से वह देश में टेस्ट क्रिकेट की वापसी को यादगार बनाना चाहते हैं।

श्रीलंकाई टीम बस पर मार्च 2009 में हुए आतंकी हमले के बाद यह पाकिस्तान में उनकी पहली सीरीज है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई, जिसका पहला मुकाबला रावलपिंडी में मौसम से प्रभावित रहा, जिससे कारण पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पाकिस्तानी टीम पिछले 10 वर्षों से विदेशों में ही खेल रही थी। अजहर ने कहा कि पाकिस्तान घरेलू मैदान पर खेलने के लिए बेताब था। उन्होंने कहा, 'हम घरेलू सीरीज में खेल रहे हैं और हमें घरेलू हालात का फायदा उठाने की जरूरत है। हम इस सीरीज को जीतना चाहते हैं और इस मौके को यादगार बनाना चाहते हैं।' रावलपिंडी में ड्रॉ के बावजूद पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की। इसमें उसके लिए आबिद अली और बाबर आजम ने शतक जड़कर अपनी टीम को श्रीलंका की छह विकेट पर 308 रन की घोषित पारी के जवाब में दो विकेट पर 252 रन बनाने में मदद की। तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी बीमार होने के कारण दूसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे, जिससे उनकी जगह लेग स्पिनर यासिर शाह लेंगे। वहीं, श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान के घरेलू मैदान पर टेस्ट के जश्न को खराब करना चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका ने कैलिस को बल्लेबाजी सलाहकार बनाया

जोहानिसबर्ग, प्रेट्र: दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस को अगले सत्र के लिए टीम का बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया गया। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने ट्विटर पर कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर कैलिस को टीम का बल्लेबाजी सलाहकार बनाया गया है। वह बुधवार को टीम से जुड़ेंगे।' कैलिस ने सभी प्रारूपों में 519 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर 25534 रन बनाए हैं और 577 विकेट लिए हैं। उन्होंने 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 टी-20 मैच खेले हैं। पांच साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके कैलिस के नाम टेस्ट में 45 और वनडे में 17 शतक हैं। वह आइपीएल में केकेआर के बल्लेबाजी सलाहकार रह चुके हैं। इससे पहले टेस्ट विकेटकीपर मार्क बाउचर को पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका का मुख्य कोच बनाया गया था। उधर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज चार्ल लैंगवेल्ट ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी कोच पद से इस्तीफा दे दिया और अब वह दक्षिण अफ्रीकी टीम के साथ काम करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के क्रिकेट संचालन समिति के चेयरमैन अकरम खान ने पुष्टि की है कि लैंगवेल्ट का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। लैंगवेल्ट ने कहा है कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम के साथ काम करने का प्रस्ताव मिला है, इसलिए उन्होंने बीसीबी से अनुरोध किया है कि उन्हें जाने दिया जाए। लैंगवेल्ट अब दक्षिण अफ्रीकी टीम के गेंदबाजी कोच होंगे।

आरोन फिंच बोले, थ्री डी खिलाड़ी हैं मैक्सवेल: ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच ने ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की राष्ट्रीय टीम में जल्दी वापसी का समर्थन करते हुए कहा है कि उनके जैसे 'थ्री डी क्रिकेटर' को लंबे समय तक बाहर नहीं रखा जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य कारणों से मैक्सवेल ने अक्टूबर में खेल से ब्रेक लिया था, लेकिन हाल ही में भारत दौरे के लिए खुद को उपलब्ध बताया है। उन्हें हालांकि टीम में नहीं चुना गया और उनकी जगह मार्नस लाबुशाने को मौका दिया गया। फिंच ने कहा, 'निश्चित तौर पर वह दुखी होंगे और टीम से बाहर रहने वाले हर खिलाड़ी का निराश होना लाजमी है। उन्होंने हालांकि पिछले कुछ समय से वनडे क्रिकेट में रन नहीं बनाए हैं। वह वापसी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वह थ्री डी खिलाड़ी हैं जिसका काफी असर पड़ता है। वह जल्दी ही रन बनाकर वापसी करेंगे।'

बोल्ट को बॉक्सिंग डे टेस्ट में खेलने की उम्मीद: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को उम्मीद है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच (बॉक्सिंग डे टेस्ट) में अंतिम एकादश में वापसी कर सकते हैं। बोल्ट चोट के चलते पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में नहीं खेल सके थे और न्यूजीलैंड को इस मैच में 296 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

एक बार आता है अंडर-19 विश्व कप जीतने का मौका

जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए मुंबई के बायें हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। 28 दिसंबर को 18 साल के होने वाले यशस्वी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं, जहां उनका परिवार आज भी रहता है। यशस्वी ने 10 साल की उम्र में मुंबई पहुंचने के बाद काफी संघर्ष किया और वहां जूनियर क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। यशस्वी ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए अंडर-19 एशिया कप में भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और मैन ऑफ द सीरीज बने थे। अंडर-19 विश्व कप की तैयारियों पर **यशस्वी जायसवाल** से **उमेश राजपूत** ने बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश :

साक्षात्कार

- **अंडर-19 विश्व कप की तैयारियां कैसी चल रही हैं?**

-हमारी टीम 20 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी। हमारी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। मैं काफी कड़ा अभ्यास कर रहा हूं। वैसे मेरी तैयारी अभी चल रही है। मेरे कोच ज्वाला सिंह ने मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए मुझे कई टिप्स दिए हैं। वहां के विकेटों में थोड़ी उछाल और गति होती है तो वह मुझे उसके अनुसार तैयारी करा रहे हैं।

- **आप छह फुट के हैं। दक्षिण अफ्रीका के उछाल भरे विकेटों पर क्या आपको लंबे कद का फायदा मिलेगा?**

-मैं दक्षिण अफ्रीका में अभी तक खेला नहीं हूं तो मुझे वहां के हालात के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन देखते हैं कि अपनी लंबाई का मैं वहां कितना फायदा उठा पाता हूं।

- **विश्व कप से पहले आपकी टीम को मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच और एक चतुष्कोणीय टूर्नामेंट खेलना है?**

-इसका काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे हम वहां के हालात के अनुकूल अपने को ढाल लेंगे। यही वजह है कि हम थोड़ा पहले भी जा रहे हैं। यह अच्छी तैयारी के लिए है। हमारी लिए यह एक अच्छा मौका होगा।

- **गत विजेता होने का टीम पर कुछ दबाव रहेगा?**

-थोड़ा दबाव तो रहता ही है, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद यह सब बातें पीछे छूट जाती हैं।

- **प्रियम गर्ग भारतीय टीम के कप्तान हैं। आप उनकी कप्तानी में पहले भी खेलें हैं। उनका रवैया कैसा रहता है? साथ ही टीम के कोच पारस महांब्रे से किस तरह का सहयोग मिलता है?**

-प्रियम सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं और टीम में बहुत ही अच्छा माहौल बनाते हैं। उन्हें सभी पर भरोसा है कि कोई भी मैच जिता सकता है। वहीं, पारस सर काफी अनुभवी हैं और हमारे साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। उनसे हमें काफी सहयोग मिलता है। उनके मार्गदर्शन में खेलकर हम काफी लुत्फ उठा रहे हैं।

- **इस साल आपने घरेलू वनडे मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। विजय हजारे वनडे ट्रॉफी में आपने दोहरा शतक भी जड़ा। विश्व कप के लिए आपने कुछ योजना बनाई है?**

-मैं हमेशा एक बार में एक ही मैच को लेकर चलता हूं और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरी प्रक्रिया सही रहे, ताकि परिणाम अपने आप आए।

- **टीम में आप सहित कई खिलाड़ी साधारण पृष्ठभूमि के परिवारों से आए हैं। आप सभी के लिए यह कितनी बड़ी उपलब्धि है?**

-यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सभी के लिए यह बहुत गर्व का पल है कि हम भारत के लिए विश्व कप खेलने जा रहे हैं। हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी पूरी कोशिश इसे अच्छे से निभाने की होगी।

- **आइपीएल के अगले सत्र के लिए गुरुवार को नीलामी होनी है। इसे लेकर कितने उत्साहित हैं?**

-मेरा पूरा ध्यान विश्व कप पर है। देश के लिए अंडर-19 विश्व कप खेलने और जीतने का मौका जीवन में एक बार आता है और आइपीएल की नीलामी हर साल होती है। इसलिए आइपीएल टीम में आने के कई मौके मिलेंगे।

लगेगी बोली आइपीएल के अगले सत्र के लिए देश-विदेश के 332 क्रिकेटर की होगी नीलामी, 66 बल्लेबाज, 103 गेंदबाज, 129 ऑलराउंडर व 34 विकेटकीपर दौड़ में

आज लगेगा क्रिकेटरों का बाजार, खरीदारी को फ्रेंचाइजी तैयार

शिमरोन हेटमायर • प्रेट्र

विशाल श्रेष्ठ • कोलकाता

देश-दुनिया की निगाहें एक बार फिर भारतीय क्रिकेट के मक्का पर हैं। महीनेभर पहले ऐतिहासिक डे-नाइट टेस्ट की मेजबानी कर चुका कोलकाता अब आइपीएल के 13वें सत्र के लिए क्रिकेटरों की नीलामी को तैयार है। कुल 332 खिलाड़ियों के लिए बोलियां लगेंगी, जिनमें 186 भारतीय व 143 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। एसोसिएशट देशों से भी तीन क्रिकेटर हैं। कुल मिलाकर 66 बल्लेबाज, 103 गेंदबाज, 129 ऑलराउंडर और 34 विकेटकीपर। इनमें से कुछ हॉट केक की तरह बिकेंगे, तो कुछ किसी तरह निपटेंगे और कुछ बिना बिके रह जाएंगे। 2020 के आइपीएल से पहले आठों फ्रेंचाइजी अपनी टीम को पूरी तरह मजबूत और संतुलित कर लेना चाहती हैं, इसलिए इस आखिरी बड़े मौके के लिए सभी ने अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से रणनीति तैयार कर ली है।

50 लाख के आधार मूल्य में कुल 78 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें नौ भारतीय और 69 विदेशी हैं

198 घरेलू खिलाड़ी भी नीलामी में शामिल हैं, जिन्हें 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख के तीन आधार मूल्य वर्गों में बांटा गया है

75 लाख के आधार मूल्य के ग्रुप में कुल 16 खिलाड़ी ही शामिल हैं और ये सभी विदेशी हैं

लिन पर भी सबकी नजर: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लिन पर भी सभी फ्रेंचाइजी की नजर है। लिन ने हाल में अबू धाबी में हुई टी-10 लीग में शानदार बल्लेबाजी की थी, जिस पर युवराज सिंह ने कह दिया था कि उन्हें छोड़कर कोलकाता नाइटराइडर्स ने भारी गलती की है। बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा आधार मूल्य (दो करोड़ रुपये) लिन का ही है।

कई खिलाड़ियों का तय होगा भविष्य: मौजूदा नीलामी देश-विदेश के कई खिलाड़ियों का आइपीएल में भविष्य भी तय कर देगी। इस नीलामी में नहीं बिक पाने पर उनका आगे बिक पाना नामुमकिन सा होगा। इनमें रॉबिन उथप्पा, यूसुफ पठान, मनोज तिवारी, पीयूष चावला और डेल स्टेन के नाम खास हैं। कुछ पर उम्र भारी पड़ सकती है तो कुछ पर उनका भारी-भरकम आधार मूल्य। एक करोड़ के आधार मूल्य पर यूसुफ को खरीदार मिल पाना मुश्किल हो सकता है, वहीं दो करोड़ के आधार मूल्य वाले श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज को भी खरीदने में कम ही फ्रेंचाइजी दिलचस्पी दिखाएंगी। उथप्पा पर उनकी उम्र भारी पड़ रही है तो पीयूष के पास फॉर्म नहीं है। एक समय दक्षिण अफ्रीका के सबसे धाकड़ तेज गेंदबाज रहे डेल स्टेन भी उम्र के ढलान पर हैं। पिछली बार वह नीलामी में नहीं बिक पाए थे।

चौंका सकता है 14 साल का नूर: अफगानिस्तान का 14 साल का नूर अहमद नीलामी में सबको चौंका सकता है। 30 लाख के आधार मूल्य वाले इस चाइनामैन गेंदबाज पर यकीनन हरेक टीम दांव लगाएगी। वहीं भारतीय क्रिकेटरों में प्रियम गर्ग, यशस्वी जायसवाल, आर साई किशोर और इशान पोरेल नीलामी में 'छुपे रुस्तम' साबित हो सकते हैं।

हॉट केक बने हेटमायर

कैरेबियाई बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर अचानक हॉट केक बन गए हैं। उन्हें खरीदने को सभी लालायित होंगे। मौजूदा भारत दौरे में हेटमायर का प्रदर्शन शानदार रहा है। तीन मैचों की टी-20 सीरीज में उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा 120 रन बनाए। वहीं, चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले वनडे में भी 139 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। 50 लाख रुपये के आधार मूल्य वाले हेटमायर इससे कई गुना ज्यादा रकम में बिके तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी, वहीं इसकी भी प्रबल संभावना है कि उन्हें मुक्त करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर ही 'राइट-टू-मैच' कार्ड के जरिये फिर से उन्हें रिटेन कर ले।

02 करोड़ के आधार मूल्य में सात खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पांच खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं

1.5 करोड़ के आधार मूल्य में 10 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें सर्वाधिक चार इंग्लैंड, तीन ऑस्ट्रेलिया और दो दक्षिण अफ्रीका के हैं

01 करोड़ के आधार मूल्य में कुल 23 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें तीन भारतीय व 20 विदेशी खिलाड़ी हैं

भारी पड़ता टेस्ट विशेषज्ञ का टैग: भारतीय टेस्ट टीम में मजबूती से पैर जमा चुके चेतेश्वर पुजारा को इस बार भी खरीदार मिलना मुश्किल हो सकता है। कारण, उन पर लगा टेस्ट विशेषज्ञ का टैग है। कुछ ऐसा ही हाल राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वसीम जाफर का भी हुआ था। टेस्ट विशेषज्ञ का ठप्पा लगा होने के कारण उन सबका आइपीएल करियर लंबा नहीं चल पाया था। पुजारा पिछले साल नीलामी में नहीं बिक पाए थे।

किसी की जेब भरी तो किसी की खाली: नीलामी के लिए किसी फ्रेंचाइजी की जेब भरी है तो किसी की खाली। मुंबई इंडियंस के पास नए खिलाड़ी खरीदने को सिर्फ 13.05 करोड़ रुपये बचे हैं, इसलिए उसे संभलकर चलना होगा। ऐसा ही हाल चेन्नई सुपरकिंग्स (14.60 करोड़) का है। किंग्स इलेवन पंजाब (42.70 करोड़) की जेब में काफी रुपये हैं, इसलिए वह ऊंचे दाम लगा सकती है, हालांकि उसकी जरूरतें भी ज्यादा हैं। उसे पूर्व कप्तान रविचंद्रन अश्विन का विकल्प भी तलाशना है। कोलकता नाइटराइडर्स (35.65 करोड़) इस मामले में दूसरे स्थान पर है। विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर 27.90 करोड़ खर्च कर सकती है।

दूसरे दिन ही पारी से जीता हरियाणा

जागरण संवाददाता, रोहतक : लाहली स्टेडियम में हुए रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन ही हरियाणा ने त्रिपुरा पर पारी और 125 रन की जीत दर्ज की।

पहले दिन त्रिपुरा की पहली पारी 68 रन पर सिमटी थी। दूसरे दिन बुधवार को हरियाणा की पहली पारी 242 रन पर खत्म हुई और उसे 174 रन की बढ़त हासिल हुई। दूसरी पारी में त्रिपुरा की टीम मात्र 49 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह हरियाणा ने दूसरे दिन ही मैच जीत लिया। मैच में 12 विकेट लेने और 45 रन बनाने वाले हरियाणा के हर्षल पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

दिन की शुरुआत दो विकेट पर 131 रन से आगे करने वाले हरियाणा की पहली पारी में चेतन्य बिश्नोई ने 67, शिवम चौहान ने 56 और हर्षल पटेल ने 45 रन बनाए। त्रिपुरा के एमबी मूरा सिंह ने पांच विकेट झटके। त्रिपुरा की दूसरी पारी में नौ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। उसकी ओर से सौरभ दास ने सर्वाधिक 10 रन बनाए। हरियाणा की ओर से हर्षल पटेल और आशीष हुड्डा ने पांच-पांच विकेट झटके।

उत्तर प्रदेश व कर्नाटक में बढ़त लेने की होड़: कर्नाटक के तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन (6/60) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मेजबान टीम ने उत्तर प्रदेश को रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-बी मैच में बुधवार को दूसरे दिन 281 रनों पर समेट दिया।

डीडीसीए की चयन समिति से हटाए गए अतुल वासन

नई दिल्ली : अतुल वासन को बुधवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह पूर्व बल्लेबाज बंटू सिंह को नियुक्त किया। डीडीसीए के लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) बाबर दुरेज अहमद ने समिति में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया था लेकिन संघ ने इसके बावजूद तीन सदस्यीय चयन पैनल को बदल दिया।

मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालने की कोशिश करूंगा।
– पीटर सिडल, तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया

लीप्जिग ने डोर्टमंड को बराबरी पर रोका

फुटबॉल डायरी ▶ बुंडिशलीगा में 3–3 की बराबरी पर खत्म हुआ शानदार मुकाबला

लीप्जिग के लिए पैट्रिक शिक ने किए दो गोल

बर्लिन, एएफपी : जर्मन फुटबॉल लीग बुंडिशलीगा में मंगलवार को एक बेहद रोचक मुकाबले में आरबी लीप्जिग ने बोरुसिया डोर्टमंड को 3-3 की बराबरी पर रोक दिया। इस मुकाबले में पैट्रिक शिक (78वें मिनट) के गोल की बदौलत शीर्ष पर काबिज लीप्जिग ने अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद बोरुसिया मोनचेंगलाडबाक पर तीन अंकों की बढ़त हासिल कर ली।

सिग्नल इडुना पार्क में बारिश के बीच खेले गए इस मुकाबले में लीप्जिग की ओर से टिमो वार्नर (47वें व 53वें मिनट) ने दो गोल किए जिसकी बदौलत उनकी टीम दो बार पिछड़ने के बावजूद डोर्टमंड को बराबरी पर रोकने में सफल रही। हालांकि पहले हाफ में डोर्टमंड की टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा। खेल के 23वें मिनट में जूलियन विगल ने डोर्टमंड को बढ़त दिलाई। इसके 11 मिनट बाद जूलियन ब्रांड्ट ने एक शानदार गोल के जरिये डोर्टमंड को दोहरी बढ़त दिलाई। हालांकि हाफ टाइम के बाद सात मिनट के अंदर ही वार्नर ने डोर्टमंड की गलती का फायदा उठाकर दो गोल करके लीप्जिग को 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा किया। वार्नर इस सत्र में कुल 18 गोल कर चुके हैं लेकिन इस सत्र में उनके लिए ये सबसे आसान गोल रहे। इसके बाद जैडन सांचो (55वें मिनट) ने गोल करके डोर्टमंड को एक बार बढ़त पर ला खड़ा किया। हालांकि निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पैट्रिक ने गोल करके लीप्जिग को बराबरी दिलाई।

गोल करने के बाद आरबी लीप्जिग के पैट्रिक शिक। एपी

विला ने लिवरपूल के लड़कों को सिखाया सबक

बर्मिंघम, एएफपी : लीग कप के क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल की सबसे युवा टीम को एस्टन विया ने सबक सिखाते हुए 5–0 से हरा दिया और जोनाथन कोड्जी के दो गोल की मदद से सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस मुकाबले में लिवरपूल के लिए पांच खिलाड़ियों ने पदार्पण किए और मैदान में उतरने वाले उसके खिलाड़ियों की औसत उम्र 19 साल रही। लिवरपूल के लड़कों का अनुभवहीन होना उसके लिए बड़ी हार का कारण बना।

फाइनल में पहुंचा फ्लेमिंगो

दोहा, एएफपी : ब्रूनो हेनरिक के एक गोल और दो असिस्ट की मदद से ब्राजीली क्लब फ्लेमिंगो ने एशियन चैंपियन अल हिलाल को 3–1 से हराकर क्लब विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में सालेम अल्दावसारी ने सउदी अरब के क्लब अल हिलाल को शुरुआती बढ़त दिलाई लेकिन हाफ टाइम के बाद फ्लेमिंगो शानदार वापसी की। 49वें मिनट में डि एरासकाएटा ने बराबरी दिलाई। इसके बाद ब्रूनो ने 78वें मिनट में फ्लेमिंगो को बढ़त दिलाई।

रिकी ने दिलाई आंध्र प्रदेश को दिल्ली पर बढ़त

रणजी ट्रॉफी

ओंगोले (आंध्र प्रदेश), प्रेट्र : रिकी भुई ने बुधवार को 164 गेंदों पर नाबाद 70 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से आंध्र प्रदेश ने दिल्ली के खिलाफ ग्रुप-ए के रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक छह विकेट पर 249 बनाए। उस समय गिरिनाथ रेड्डी नाबाद 11 रन बनाकर रिकी का साथ निभा रहे थे। पहले दिन एक विकेट लेने वाले दिल्ली के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (3/77) ने दूसरे दिन दो विकेट और झटके। दिल्ली की पारी 215 रन पर खत्म हुई थी।

आंध्र ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 16 रन से आगे की। उसके लिए रिकी के अलावा मनीष गोलामारु (42), कप्तान हनुमा विहारी (38) और करन शिंदे (48) ने उपयोगी पारी खेलीं। 111 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद रिकी और करन ने छठे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी की, जिसके चलते आंध्र की टीम पहली पारी के आधार पर 34 रन की बढ़त हासिल कर सकी। हालांकि, उसके चार विकेट बाकी हैं। आंध्र की पारी के दौरान दिल्ली के गेंदबाजों ने निराश किया। दिल्ली के लिए नवदीप के अलावा पवन सुयाल (2/44) और सिमरनजीत सिंह (1/69) भी विकेट लेने में सफल रहे।

बिहार पर हावी चंडीगढ़

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पुछल्ले बल्लेबाजों की मदद से चंडीगढ़ की टीम बिहार के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन 420 रन के स्कोर तक पहुंच सकी। निचलेक्रम में गुरइंदर सिंह (67), जसकरण सिंह (23) और श्रेष्ठ निर्मोही (22) की तिकड़ी ने 114 रन जोड़े, जिसकी बदौलत चंडीगढ़ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। जवाब में बिहार ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में एक विकेट पर छह रन बना लिए थे। क्रिकेट ग्राउंड सेक्टर–16 में खेला जा रहा यह मैच दूसरे दिन ओस के चलते डेढ़ घंटा देरी से शुरू हुआ। चंडीगढ़ ने पांच विकेट पर 274 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। अंकित कौशिक (117) अपने स्कोर में मात्र 11 रन जोड़कर आउट हुए। उन्हें विवेक कुमार (2/104) ने चलता किया। विवेक ने बिपुल शर्मा (65) को बोल्ड कर दिया, जिससे स्कोर सात विकेट पर 306 रन था। यहां से गुरइंदर और जसकरण ने 43 रनों की अहम साझेदारी निभाई। आशुतोष अमन (5/71) ने जसकरण को बोल्ड कर अपने पांच विकेट पूरे किए।

पंजाब के मंदीप व अनमोल चमके

जागरण संवाददाता, पटियाला : कप्तान मंदीप सिंह (नाबाद 65) और अनमोलप्रीत सिंह (54) के अर्धशतकों की बदौलत पंजाब ने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले के दूसरे दिन हैदराबाद के खिलाफ पहली पारी में चार विकेट पर 167 रन बनाए। इससे पहले मंगलवार को हैदराबाद ने पहली पारी में 242 रन बनाए थे। स्थानीय ध्रुव पांडव स्टेडियम में बुधवार को मौसम खराब होने के कारण मैच दो घंटे देर से शुरू हुआ। पंजाब के सनवीर सिंह और शुभमन गिल ने पारी का आगाज किया। मुहम्मद सिराज ने शुभमन (00) को सुमंत के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा। सनवीर (14) भी पांचवें ओवर की पहली गेंद पर युद्धवीर का शिकार बने। इसके बाद आए गुरकीरत मान भी पांच रन बनाकर सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। बाद में अनमोलप्रीत ने मंदीप के साथ मिलकर टीम को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। मंदीप 135 गेंदों में नौ चौके जड़कर मैदान पर डटे हुए हैं। अनमोलप्रीत ने 92 गेंदों में नौ चौकों की मदद से 54 रन बनाए और सिराज की गेंद पर सुमंत के हाथों लपके गए।

उत्तराखंड पर हार का खतरा मंडराया

नईदुनिया, रायपुर : अजय मंडल (209*) के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहले दोहरे शतक और अमनदीप खरे (166*) की रिकॉर्ड पारी के दम पर छत्तीसगढ़ ने उत्तराखंड पर पहली पारी में 342 रनों की विशाल बढ़त बना ली है और उसके चार विकेट बाकी हैं। रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक छत्तीसगढ़ ने छह विकेट खोकर 462 रन बनाए। इससे पहले उत्तराखंड की पहली पारी 120 रन पर खत्म हुई थी। इस तरह उत्तराखंड पर हार का खतरा मंडरा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ ने पहली पारी पांच विकेट पर 109 रनों से आगे बढ़ाई। अमनदीप ने 33 रन और मनोज सिंह ने 14 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। मनोज अपनी पारी में केवल चार रन और जोड़ सके और 18 रन बनाकर आउट हो गए। उत्तराखंड को यह सफलता प्रदीप चमोली ने दिलाई। इसके बाद सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे अजय मंडल और अमनदीप ने दूसरे दिन उत्तराखंड को कोई और सफलता हाथ नहीं लगने दी। अमनदीप ने अपनी पारी में 317 गेंद खेलीं व 20 चौके जड़े। अजय ने 263 गेंदों का सामना किया और 32 चौके एवं एक छक्का जड़ा।

पूर्व बल्लेबाज यूनिस खान ने पीसीबी का निमंत्रण ठुकराया

कराची, प्रेट्र : पूर्व कप्तान यूनिस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के गुरुवार से यहां श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के दौरान विशेष अतिथि बनने के आमंत्रण को ठुकरा दिया। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने कहा कि पीसीबी ने बोर्ड की घरेलू मैचों के दौरान पूर्व महान खिलाड़ियों को सम्मानित करने की नीति के अंतर्गत विशेष अतिथि के रूप में यूनिस को आमंत्रण भेजा था। लेकिन यूनिस ने इसे ठुकरा दिया और यह बात पीसीबी को अच्छी नहीं लगी। वसीम ने कहा, 'यह निराशाजनक है कि वह नहीं आ रहे। लेकिन यूनिस हमारे लिए महान खिलाड़ी हैं और यह उनका निजी फैसला है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।' यूनिस अपने दौर में राष्ट्रीय टीम को कई मैच जीतने में अपनी भूमिका निभाई थी।

पाकिस्तान में टी–20 सीरीज खेलने को तैयार बांग्लादेश

कराची, प्रेट्र : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इन्कार कर दिया है, लेकिन उसने देश में टी–20 सीरीज खेलने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मुख्य कार्यकारी वसीम खान ने बुधवार को कहा कि उन्होंने बीसीबी को कड़े शब्दों में पत्र लिखा है और टेस्ट नहीं खेलने के कारणों के बारे में बताने को कहा है। यह सीरीज जनवरी–फरवरी में खेली जानी थी। उन्होंने कहा कि बीसीबी ने हमें सूचित किया है कि वे तीन टी–20 मैच खेलना चाहते हैं।

टिकटों के लिए दो करोड़ 30 लाख आवेदन

ओलंपिक डायरी

▶ टिकटों की ताजा लॉटरी में जापान के स्थानीय लोगों में होड़

▶ आयोजकों ने बताया, उपलब्धता से करीब 20 गुना ज्यादा की है मांग

टोक्यो, एपी : टोक्यो में होने वाले 2020 ओलंपिक के टिकटों को हासिल करना बेहद मुश्किल काम होता जा रहा है। खासतौर से जापान में उसे हासिल करना बेहद टेढ़ा काम बन गया है। बुधवार को ओलंपिक के आयोजकों ने बताया कि उन्हें हालिया टिकट लॉटरी के लिए केवल जापानी निवासियों द्वारा दो करोड़ 30 लाख आवेदन मिले हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि इसके लिए केवल 10 लाख टिकट ही उपलब्ध हैं। ऐसे में आवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों को खाली हाथ रहना पड़ेगा।

ओलंपिक के टिकटों के लिए जापान में होड़ मची हुई है। आयोजकों ने बताया है कि इससे पहले लॉटरी के माध्यम से करीब 30 लाख 57 हजार टिकट जापान के स्थानीय निवासियों को दिए गए थे। यह पहली बार है जब टिकटों की मांग उपलब्धता से 20 गुना ज्यादा है। ओलंपिक टिकटों के लिए अगली लॉटरी अगले साल के शुरुआत में निकाली जाएगी जिसे जापान के अलावा गैर-जापानी आवेदकों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। ओलंपिक के सभी प्रतियोगिताओं के लिए करीब 70 लाख 80 हजार टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे जिसमें से कम से कम 70 फीसद टिकट जापानी निवासियों को दिए जाएंगे। उद्घाटन समारोह की टिकटें सबसे महंगी हैं जिनकी कीमत 300000 येन (करीब एक लाख 94 हजार रुपये) हैं जबकि समापन समारोह के टिकट की कीमत 220000 येन (करीब एक लाख 42 हजार रुपये) है।

टोक्यो में भारतीय मुक्केबाजों से दो स्वर्ण की उम्मीद : पंघाल

नई दिल्ली : विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में कम से कम दो स्वर्ण पदक आएंगे। मुक्केबाजी में अब तक भारत को केवल दो ही पदक मिले हैं। इनमें विजेंदर सिंह ने 2008 बीजिंग और मेरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में अपने–अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। पंघाल ने कहा कि हाल के समय में मुक्केबाजी में हमारे प्रदर्शन में सुधार हुआ है। हमने कई स्वर्ण पदक जीते हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या फिर विश्व चैंपियनशिप हो। हम कम से कम दो स्वर्ण पदक की उम्मीद के साथ टोक्यो ओलंपिक में जाएंगे।

विविध

डिफेंस एक्सपो के लिए 64 हजार पेड़ काटने के प्रस्ताव पर यूपी को नोटिस

नई दिल्ली, एएनआइ : लखनऊ में होने जा रहे डिफेंस एक्सपो के लिए 64 हजार पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी के किनारे डिफेंस एक्सपो के लिए 64 हजार पेड़ों को काटे जाने प्रस्ताव है। हालांकि, डिफेंस एक्सपो समाप्त होने के बाद गोमती के किनारे पेड़ लगाने का भी प्रस्ताव है। डिफेंस एक्सपो लखनऊ में 2020 में आयोजित किया जाना है। गोमती नदी के किनारे हनुमान सेतु से निशातगंज तक के क्षेत्र को रक्षा उपकरणों को प्रदर्शित करने के लिए खाली कराया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने रक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश एवं अन्य को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई जनवरी 2020 में होगी। याचिका दायर करने वली शीला बर्से ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसी नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है, 'इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाना न केवल वर्तमान, बल्कि भावी मानवीय पीढ़ी और इकोसिस्टम पर आश्रित सभी सजीवों के साथ अन्याय है।'

विजयवाड़ा में भवानी दीक्षा वीरामना महोत्सव शुरू...

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित कनक दुर्गा माता मंदिर में बुधवार से पांच दिवसीय भवानी दीक्षा वीरामना महोत्सव की शुरुआत हो गई। पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दीक्षा और धार्मिक अनुष्ठान के लिए दूर–दूर से कुछ इस तरह पहुंचे। दीक्षा समारोह में पांच दिन तक श्रद्धालु पूरी तरह सांसारिक सुखों का त्याग कर संयमित जीवन जीते हैं। भवानी दीक्षा समारोह यहां का बड़ा आयोजन है। इसमें छह लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। प्रेट्र

मुंबई में बच्चा समय पर नहीं सोया तो सौतेले पिता ने मार डाला

मुंबई, प्रेट्र : नवी मुंबई के पनवेल में एक व्यक्ति ने समय पर सोने से इन्कार करने पर आठ साल के सौतेले बेटे को मार डाला। यही नहीं, उसने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे के शव को ठिकाने भी लगा दिया। पुलिस ने मंगलवार की रात दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बुधवार को बताया, राकेश अंबाजी तांबडे (32) ऑटो रिक्शा चलाता है। वह अपनी पत्नी व सौतेले बेटे सूरज के साथ सड़क किनारे सोता था। सूरज जब भी समय पर नहीं सोता था तो तांबडे आपा खो बैठता था। रविवार की रात उसने सूरज का गला दबा दिया और अपने मित्र रमेश के साथ मिलकर उसके शव को बोरे में बंद कर उरण-पलसपे रोड पर फेंक दिया।

नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान तांबडे ने सूरज की हत्या की बात स्वीकार कर ली है। तांबडे ने कहा कि सूरज की हत्या उसने समय पर सोने से इन्कार करने के कारण की है। हालांकि, अभी भी इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा रहा। हत्या के पीछे की असली वजह जानने के लिए मामले की जांच की जा रही है।

आइआरसीटीसी के सिस्टम में रेड मिर्ची का तड़का

चंद्रशेखर, पटना

रेड मिर्ची का सॉफ्टवेयर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) के टिकट बुकिंग सिस्टम में सेंध लगाए बैठा है। सॉफ्टवेयर कंपनी ने आइआरसीटीसी की नींद दूभर कर दी है। बेंगलुरु की यह कंपनी देशभर की फर्जी ट्रेवल एजेंसियों को सॉफ्टवेयर देती है। इससे एजेंसी संचालक आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंधमारी कर आराम से आरक्षित तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं। मंगलवार को आरपीएफ टीम की छापेमारी में चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं।

गिरफ्तार ट्रेवल एजेंसी संचालक से मिली जानकारी पर आरपीएफ की टीम सॉफ्टवेयर कंपनी रेड मिर्ची की तह तक पहुंचने में जुट गई है। टीम बेंगलुरु भी जा सकती है। गिरफ्तार शांतनु से अधिक जानकारी के लिए टीम उसे जेल से रिमांड पर लेगी। आरपीएफ इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार ट्रेवल एजेंसी संचालक शांतनु से लंबी पूछताछ की गई है।

कैसे संपर्क करते हैं रेड मिर्ची के प्रतिनिधि : कोई भी नया ट्रेवल एजेंसी संचालक रेलवे के तत्काल टिकट की बुकिंग कैसे करे अथवा इससे संबंधित साइट पर जाते हैं और रोज-रोज टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो रेड मिर्ची के प्रतिनिधि उनसे पहले दूसरी फेक कंपनी के नाम से संबंध बनाते हैं। जब उन्हें अहसास हो जाता है कि वह व्यक्ति व्यवसाय करने आया है, तो उसके मेल पर रेड मिर्ची का विज्ञापन भेजा जाता है। किस तरह आसानी से आइआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाकर बुकिंग कर अधिक पैसे कमा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए पांच हजार रुपये लिए जाते हैं। इसके बाद संचालक के कंप्यूटर का नंबर मांगा जाता है। कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाइन ही इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है।

100 रुपये प्रति टिकट देते हैं संचालक : रेड मिर्ची सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ट्रेवल एजेंसी संचालक से टिकट बुक करने पर प्रति टिकट 100 रुपये लिए जाते हैं। शाम को हिसाब कर पेटीएम से भुगतान को कहा जाता है। भुगतान में विलंब होने पर खाते को बंद कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर ही नहीं वेबसाइट में सेंध लगाने की व्यवस्था रेड मिर्ची की ओर से ही दी जाती है। आइआरसीटीसी का आइडी नंबर भी रेड मिर्ची ही देती है।

बुकिंग के पहले ही भर लेते हैं यात्री का सारा विवरण

रेड मिर्ची सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ट्रेवल एजेंसी संचालक तत्काल टिकट अथवा 120 दिन पहले के ओपनिंग बुकिंग का सारा विवरण समय शुरू होने के पहले ही डाल लेते हैं। रेड मिर्ची सॉफ्टवेयर में इसके लिए विशेष व्यवस्था है। तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही पहले ही मिनट में तीन से चार टिकट एजेंसी संचालक निकाल लेते हैं। एक–एक टिकट में चार से छह नाम भरे रहते हैं।

व्यवस्था : जेएनयू छात्र घर से दे सकेंगे सेमेस्टर परीक्षाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास के नए नियमों के लागू होने और छात्रावास की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने वैकल्पिक माध्यमों से सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। इसके तहत वे घर से ही परीक्षा दे सकेंगे।

जेएनयू प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के कारण अन्य छात्र परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वैकल्पिक माध्यमों से सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। रजिस्ट्रार प्रो. प्रमोद कुमार ने कहा कि घर के असाइनमेंट, क्विज, टर्म पेपर, प्रजेंटेशन, सत्रात्मक परीक्षा (सीजनल एग्जाम) जैसे वैकल्पिक माध्यमों से सेमेस्टर परीक्षाओं के मूल्यांकन किए जाएंगे। सभी स्कूलों के डीन और केंद्रों के अध्यक्षों ने फैसला किया है कि छात्रों के लिए घर में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जो भी छात्र अपनी मर्जी से परीक्षाएं वैकल्पिक माध्यम के अनुसार देंगे, उन्हें परीक्षा में लिखने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के अकादमिक हितों की रक्षा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जेएनयू शिक्षक संघ ने बुधवार को विश्वविद्यालय के विजिटर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है। इसमें जेएनयू प्रशासन द्वारा ईमेल एवं वॉट्सएप के माध्यम से परीक्षाओं के जवाब छात्र देने के फैसले पर भी शिक्षक संघ ने सवाल उठाए हैं। साथ ही कुलपति प्रो. एम जगदीश कुमार पर अकादमिक गतिविधियों का सही तरह से संचालन नहीं करने का आरोप लगाया है।

सरकार के छह माह के कामकाज की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू के छह महीने के दौरान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मंत्रालय अपने विभिन्न फैसलों पर संक्षिप्त प्रस्तुति देंगे। इसमें मुख्य जोर कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र होगा।

सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार की नीतियों को लागू करने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों की ओर से हुई प्रगति की समीक्षा की है। बहरहाल, शनिवार को होने वाली बैठक का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि इसमें राज्यमंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत सरकार बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई और नवंबर में उसके छह महीने पूरे हुए हैं।

मेरठ में एलजी स्पोर्ट्स में बन रहे थे एसजी के नकली बल्ले, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ

ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की टीम ने मेडिकल थाना पुलिस के साथ प्रवेश विहार स्थित एलजी स्पोर्ट्स में छापा मारा। पुलिस ने यहां से एसजी कंपनी के 88 नकली बल्ले और बल्लों पर लगाने वाले हजारों स्टीकर बरामद किया। टीम ने फैक्ट्री स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। बीते दस साल से वहां एलजी की आड़ में एसजी के नकली बल्ले बनाकर सप्लाई किए जा रहे थे।

ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी टीम मेरठ में एक माह से लगातार सक्रिय है। टीम ने मंगलवार को टीपीनगर में छापेमारी के बाद बुधवार को प्रवेश विहार में एलजी स्पोर्ट्स कंपनी में पुलिस के साथ छापा मारा। फैक्ट्री में एलजी के साथ एसजी के नकली बल्ले बनाए जा रहे थे। पुलिस ने फैक्ट्री स्वामी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र ने बताया कि एलजी के बल्ले की बिक्री नहीं के बराबर है, जबकि एसजी के नकली बल्ले की मांग काफी ज्यादा है। मेरठ के अलावा अन्य राज्यों के बड़े शहरों में एसजी के बल्लों की मांग पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ी है।

इसलिए ज्यादातर एसजी का माल ही तैयार किया जाता है। महेंद्र ने पुलिस को बताया कि एसजी का माल आर्डर पर ही तैयार किया जाता है। महेंद्र ने बताया कि विभिन्न शहरों की कई बड़ी दुकानें उनके संपर्क में है, जहां हर सप्ताह बल्ले की सप्लाई की जाती है। एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि नकली बल्ले की धरपकड़ करने वाली कंपनी ने सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मांगी थी। मेडिकल थाने की पुलिस के साथ प्रवेश विहार में एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। वहां से नकली बल्ले और स्टीकर बरामद हुए हैं।

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ ठंडी सुबह में मध्यम कोहरा व कुहासा छाया रहेगा। आंशिक बादलों के साथ धूप खिली रहेगी। दिन शीतल रहेगा। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बादल छाये रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/22/व	अहमदाबाद	30/16/व
कोलकाता	23/13/आंबा	बड़ौदा	31/14/आंबा
चेन्नई	31/24/व	नागपुर	28/13/व
हैदराबाद	28/18/आंबा	इन्दौर	29/14/आंबा
बंगलूरू	26/15/आंबा	राँची	28/16/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/25/आंबा	पटना	27/14/आंबा
गुवाहाटी	23/15/आंबा	जमशेदपुर	30/17/आंबा
गंगटोक	07/-4/ आंबा	पुणे	31/21/आंबा

पुर्तगालियों से मुक्त कराया गोवा, दमन और दीव

1961 में आज ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़ा लिया था। चालीस घंटे तक चली लड़ाई के बाद पुर्तगाली सेना ने घुटने टेक दिए। पुर्तगाल के गवर्नर ने सरेंडर फॉर्म पर हस्ताक्षर कर गोवा छोड़ दिया था।

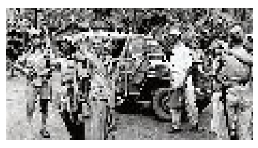

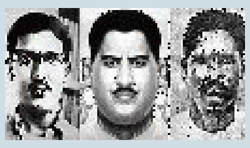

तीन भारतीय क्रांतिकारियों को दी गई फांसी

1927 में आज ही काकोरी कांड का दोषी पाते हुए अंग्रेजों ने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी दी। इस कांड में क्रांतिकारियों ने ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों का खजाना लूटा था।

प्रतिभा सिंह पाटिल को जन्मदिन मुबारक

स्वतंत्र भारत के इतिहास में देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का जन्म 1934 में आज ही महाराष्ट्र में हुआ था। 1962 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया और महाराष्ट्र की जलगांव सीट से विधायक बनीं। 1967 से 1985 तक मुक्तेनगर सीट से लगातार विधायक रहीं। 1985 में राज्यसभा सदस्य चुनी गईं। 1991 में लोकसभा की सदस्य बनीं। 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रहीं। 2007 से 2012 तक देश की राष्ट्रपति रहीं।

इधर-उधर की

...और चहेते पालतू की पहचान हुई मुश्किल

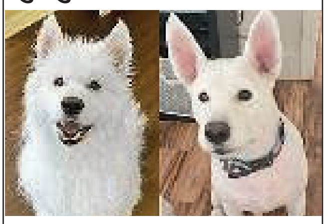

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका के फ्लोरिडा में एक ऐसा वाकया हुआ कि हर पालतू प्रेमी उसके ग्रूमिंग से पहले हजार बार सोचने पर विवश हो सकता है। फ्लोरिडा के कार्ली कोका के पास सात साल का एक कुत्ता है। जिसका उन्होंने प्यारा सा नाम नानुक रखा है। उन्होंने उसके बाल बड़े देखे तो छंटाई के लिए वे ग्रूमर के पास ले गईं। भीड़ होने के चलते उन्होंने कुत्ते को वहीं छोड़ दिया, लेकिन जब वे लौटकर आईं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लहराते बालों वाला उनका कुत्ता गंजा बन गया था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, तपाक से कहा कि ये मेरा कुत्ता नहीं है। ये दूसरी प्रजाति का लग रहा है। ग्रूमर ने भरोसा दिलाया कि आप चाहें तो इसे बुलाकर देख सकती हैं। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को जो भी सुन रहा है, बिना हंसे नहीं रुक पा रहा है।

सूर्य पर नए प्रकार का चुंबकीय विस्फोट खोजा

महत्वपूर्ण खोज ▶ नासा की सौर वेधशाला की तस्वीरों की मदद से मिली जानकारी

भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया पता

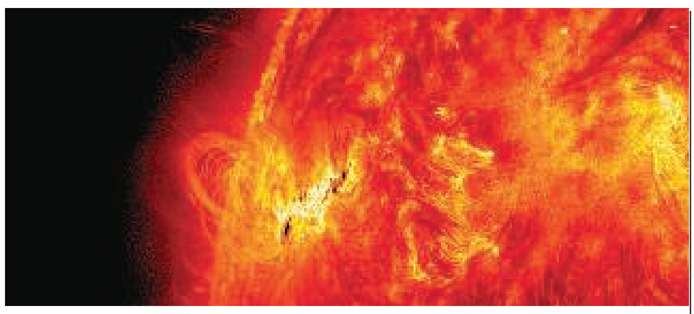

आइआइटी बीएचयू व भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने की खोज। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : धरती पर जीवन देने वाला तारा सूर्य कई अबूझ रहस्यों से भरा पड़ा है। जैसे-जैसे इसके रहस्यों से पर्दा उठ रहा है, इसे जानने में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार नासा की सौर वेधशाला से मिली तस्वीरों का प्रयोग करते हुए सूर्य से जुड़े एक बड़े रहस्य का पता लगाया है। उन्होंने सूर्य में एक नए तरह के चुंबकीय विस्फोट का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने सूर्य की ऊपरी सतह पर एक सौर उभार को देखा। यह सौर सतह की गतिविधियों के कारण बना एक लूप था जो सतह पर गिर रहा था। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि नीचे गिरते समय यह लूप चुंबकीय रेखाओं के संपर्क में आ गया और एक तरफ खिंचता चला गया। इस क्रम में एक चुंबकीय विस्फोट हुआ। इस तरह का चुंबकीय विस्फोट पहले नहीं देखा गया है। खोज करने वाली टीम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी और भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, बेंगलुरु के वैज्ञानिक शामिल रहे। चुंबकीय रेखाओं का यह स्रोत सूर्य की भूमध्यरेखा के चारों ओर स्थित रंग-बिरंगी सुराखों से निकलता है। वैज्ञानिकों ने सूर्य पर मौजूद कोरोनल छिद्रों के बारे में भी नई जानकारी हासिल की है। वैज्ञानिकों की मानें तो इन्हीं छिद्रों के जरिये आवेशित कणों का प्रवाह होता है। ये छिद्र अपेक्षाकृत ठंडे और कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं जिनसे होकर चुंबकीय रेखाएं अंतरिक्ष में पहुंचती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक, सौर हवा में कणों का विस्फोट तूफानी हवा के रूप में होता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अवलोकन एक दशक पुराने सिद्धांत की पुष्टि करता है तथा सूर्य के वातावरण के रहस्य को समझने में भी मदद कर सकता है। इससे अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर भविष्यवाणी की जा सकती है। आइआइटी बीएचयू के सौर वैज्ञानिक अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि यह अध्ययन अन्य प्रणालियों को समझने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है।

उम्मीद से कम समय में बने हैं मिल्की-वे के अधिकतर तारे

लंदन, प्रेट्र : खगोलविदों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप (वीएलटी) का उपयोग कर मिल्की वे के मध्य में एक तारे के विस्फोट की घटना का अवलोकन किया है और विश्लेषण में पाया है कि आकाशगंगा में अधिकांश तारों का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में हुआ होगा। स्पेन के अंडलूसिया के एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने अपनी आकाशगंगा के केंद्र में इस तारे के विस्फोट के गहरे सुबूत देखें हैं। 'नेचर एस्ट्रोनामी' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि हमारी आकाशगंगा के मध्यक्षेत्र के लगभग 80 फीसद तारे आठ से 13 .5 अरब वर्ष पूर्व के हैं। इस अध्ययन के सह लेखक फ्रांसिस्को नोगुआरेस-लारा ने बताया कि अब तक यह स्वीकार किया गया था तारों का बनना निरंतर जारी रहता है, जबकि यह सत्य नहीं है। शोधकर्ताओं ने बताया कि एक तारे को बनने के लिए लगभग छह अरब साल चाहिए होते हैं, लेकिन मिल्की -वे के तारों के बनने की गति बढ़ जाने से कई तारे एक अरब साल में ही बन गए।

वैज्ञानिक लेखों के प्रकाशन में भारत का स्थान दुनिया में तीसरा

स्पेक्ट्रम

▶ अमेरिका की सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट, चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर

वाशिंगटन, प्रेट्र : विज्ञान और अभियांत्रिकी (साइंस एंड इंजीनियरिंग) पर लेखों के प्रकाशन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2018 में भारत में 1.35 लाख से ज्यादा लेख प्रकाशित हुए। इस मामले में चीन शीर्ष पर जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है।

अमेरिकी सरकार की एजेंसी 'नेशनल साइंस फाउंडेशन' (एनएसएफ) के आंकड़ों के मुताबिक, 2018 में दुनियाभर में वैज्ञानिक लेखों के प्रकाशन की संख्या बढ़कर 25,55,959 हो गई जबकि 2008 में यह संख्या 17,55,850 थी। वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि 10 साल में औसतन चार प्रतिशत सालाना रही।

भारत में 2008 में विज्ञान और अभियांत्रिकी पर 48,998 लेख प्रकाशित हुए थे। जबकि 2018 में यह 10.73 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि के साथ बढ़कर 1,35,788 हो गए। दुनियाभर में विज्ञान और अभियांत्रिकी पर प्रकाशित कुल लेखों में भारत का हिस्सा अब 5.31 प्रतिशत हो गया है। वहीं, चीन में प्रकाशित लेखों की संख्या 2008 के 2,49,049 से बढ़कर 2018 में 5,28,263 हो गई है। चीन की औसत सालाना वृद्धि दर 7.81 फीसद रही। जबकि, अमेरिका में प्रकाशित लेखों की संख्या 0.71 फीसद की औसत सालाना वृद्धि दर के साथ 2008 के 3,93,979 के मुकाबले 2018 में 4,22,808 हो गई।

इस मामले में टॉप 10 देशों में जर्मनी (1,04,396), जापान (98,793), ब्रिटेन (97,681), रूस (81,579), इटली (71,240), दक्षिण कोरिया (66,376) और फ्रांस (66,352) शामिल हैं। अलग-अलग देशों में प्रकाशित लेखों का विशेषज्ञता क्षेत्र भी अलग-अलग रहा। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के देशों और जापान में स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में जबकि चीन और भारत में अभियांत्रिकी पर ज्यादा लेख प्रकाशित हुए।

शोध अनुसंधान

ग्रीन टी में दिखी टीबी के इलाज की नई उम्मीद

शोधकर्ताओं को ग्रीन टी में टीबी के इलाज की नई उम्मीद दिखी है। उन्होंने ग्रीन टी में ऐसा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाया है, जो इस बीमारी से मुकाबले में अहम हो सकता है। इस खोज से टीबी के उपचार के लिए नई दवाओं के विकास की राह खुल सकती है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने लैब में यह पाया कि एपिगैलोकेटेशिन गैलेट नामक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड किस तरह टीबी के कारक बैक्टीरिया की वृद्धि पर अंकुश लगा सकता है। प्रमुख शोधकर्ता गेरहार्ड ग्रुबर ने कहा, 'हमारी खोज ईजीसीजी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने में सक्षम है। इससे अब हम टीबी की नई दवा विकसित करने के लिए ग्रीन टी में पाए जाने वाले इस कंपाउंड की क्षमता को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।' -आइएएनएस

मोटापे से बदल सकता है रक्त जांच का नतीजा

यह पहले ही जाहिर हो चुका है कि मोटापे के चलते कई अन्य समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि बच्चों में मोटापा के कारण उनकी रक्त जांच का नतीजा भी बदल सकता है। चिकित्सकों के लिए रक्त जांच की सही व्याख्या करने में बच्चों का मोटापा बाधक बन सकता है। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष किशोर उम्र के करीब 1300 स्वस्थ बच्चों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला है। उन्होंने अध्ययन में नियमित रक्त जांच पर मोटापे के प्रभाव का पहला विस्तृत विश्लेषण किया। क्लीनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबोलिज्म जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में करीब 70 फीसद रक्त जांच को बच्चों के मोटापे के कारण प्रभावित पाया गया। बताया कि मोटापा रक्त में लिवर एंजाइम और लिपिड जैसे कई मार्कर्स के स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर देता है। -प्रेट्र

ज्यादा वसा सोचने की क्षमता पर भी डालता है असर

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने बताया कि कम मांसपेशियां और ज्यादा वसा लोगों के दिमाग पर भी असर डालता है। यह उम्र बढ़ने के साथ आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए 4,000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया। इसके बाद उनके पेट की वसा, ऊतकों की वसा और दुबली मांसपेशियों की जांच की गई। इसके बाद यह देखा गया कि किस तरह समय बीतने पर उनकी बुद्धिमत्ता में फर्क पड़ा। इसमें पाया गया कि 40 से 50 वर्ष के वे लोग जिनमें वसा उच्चस्तर पर मौजूद था, उनमें उम्र बढ़ने पर सोचने की क्षमता बिगड़ती गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि उम्र के आधे पड़ाव पर शरीर वसा को एकत्र करने लगता है, जिससे उनकी मांसपेशियां दुबली होने लगती हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि ज्यादा वसा बढ़ने के कारण दो प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाओं लिंफोसाइट और इसिनोफिल्स में परिवर्तन हो जाता है।

भोजन निगलने के दौरान होने वाली दिक्कत को दूर करेगी यह डिवाइस

स्टीकर जैसी है सेंसर लगी हुई नई डिवाइस। प्रतीकात्मक

▶ निगलने के लिए सिर और गले की 30 जोड़ी मांसपेशियों के सटीक समन्वय की आवश्यकता होती है

▶ अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया विकसित

वाशिंगटन, प्रेट्र : कुछ भी खाने पर निगलने में कठिनाई होना एक बड़ी बीमारी बनकर सामने आई है। दुनियाभर के लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। इससे निपटने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नई डिवाइस तैयार की है। इसका सफलता पूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। इस डिवाइस के माध्यम से इस बीमारी के उपचार को आसान और किफायती बनाया जा सकता है।

'साइंस एडवांसेज' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि कुछ भी निगलने के लिए सिर और गले की 30 जोड़ी मांसपेशियों के सटीक समन्वय की आवश्यकता होती है। किसी भी एक व्यवधान की वजह से निगलने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित टीम ने बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए वैसे तो कई डिवाइस हैं जो मंहगी हैं और घर नहीं ले जाई जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी पहुंच तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए शोधकर्ताओं ने नई सस्ती डिवाइस विकसित की है।

इस तरह बनाई नई डिवाइस : शोधकर्ताओं ने बताया कि यह एक तरह से स्टीकर जैसा होता है, जिसमें सेंसर लगे हुए हैं। जिसे गले पर चिपका दिया जाता है। सेंसर निगलने के दौरान मांसपेशियों में होने वाली गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर इकाई लगी रहती है। यह जानकारी इकट्ठा कर दूसरी डिवाइस में भेजते हैं जो आपके पास होती है, जिससे बाद में उसकी जानकारी से डॉक्टर को बीमारी समझने में बेहतर मदद मिलती है। इसके साथ ही यह डिवाइस भोजन निगलने के दौरान मांशपेशियों को मदद करती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह डिवाइस सस्ती है और एक डिवाइस को कम से कम दस बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

गंध बता सकता है रोबोटिक डॉग

जापान में ऐसा रोबोटिक डॉग हाना-चैन विकसित किया गया है जो गंध सूंघकर बता सकता है। इसकी नाक में एक खास तरह का सेंसर लगा हुआ है। इसकी मदद से यह हर प्रकार की गंध सूंघ सकता है। इससे अपराध को अंजाम देकर फरार होने वाले शातिर अपराधियों को ढूंढने में भी मदद मिल सकेगी। भविष्य में इन रोबोटिक डॉग को पुलिस के खोजी कुत्तों के स्क्वायड में शामिल किया जाएगा। राजधानी टोक्यो में आयोजित इंटरनेशनल रोबोट प्रदर्शनी में इसका प्रदर्शन किया गया। रायटर

3500 वर्ष पुराने शाही मकबरे मिले

ग्रीक के दक्षिण-पश्चिम शहर पाइलोस में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने करीब साढ़े तीन हजार साल पुरानी दो शाही क्रबों की खोज की है। यह दोनों मकबरे कांस्य युग के विशाल महल के करीब ही मिले हैं। मकबरों से गोल्डन सील रिंग, मिश्र के ताबीज और ओडिसी चित्र भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इन क्रबों में शाही परिवार के सदस्यों को दफनाया गया है। एपी

जर्मनी में क्रिसमस हाउस की सजावट

दुनियाभर में क्रिसमस के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। सेंट्रल जर्मनी के वाल्सचेबेन में मारियो लीच्ट के क्रिसमस हाउस को रंग-बिरंगी झालरों और फूल-पत्तियों से सजाया गया है। करीब आठ किलोमीटर के दायरे में एक लाख पैंतालीस हजार एलईडी बल्बों से रोशनी की गई है। क्रिसमस हाउस जर्मनी के मुख्य आकर्षक का केंद्र माने जाते हैं। देश-विदेश के हजारों पर्यटक लाइट्स का आनंद उठाने यहां आते हैं। एपी

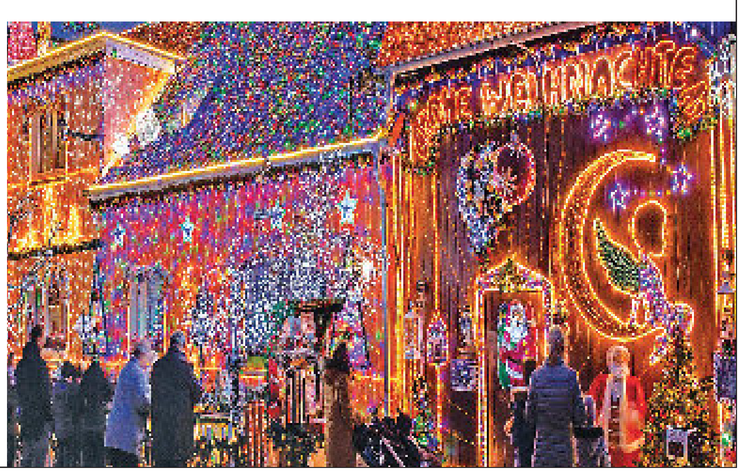

स्क्रीन शॉट

जन्मदिन की पार्टी में वरुण धवन से नाराज हो गई थीं श्रद्धा कपूर

वरुण धवन और श्रद्धा कपूर बचपन से एक-दूसरे के दोस्त हैं। फिल्म 'एबीसीडी 2' के बाद दोनों एक बार फिर फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में साथ काम कर रहे हैं। मुंबई में बुधवार को इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान वरुण ने बताया कि गणपति विसर्जन के मौके पर वह श्रद्धा के साथ कई बार डांस कर चुके हैं। इस मौके पर वरुण ने श्रद्धा के साथ बचपन की एक कहानी भी साझा की। वरुण के मुताबिक, श्रद्धा के सातवें जन्मदिन पर वह पहली बार श्रद्धा के घर गए थे। वरुण को अब भी याद है कि उस दिन श्रद्धा ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी और बच्चों के बीच हुई डांस प्रतियोगिता में वह अव्वल आए थे। उस समय श्रद्धा वरुण से इसलिए नाराज हो गई थीं, क्योंकि वरुण ने उनके साथ डांस नहीं किया था। वरुण ने बताया कि बचपन में अक्सर श्रद्धा उनके साथ ऐसी पार्टियों में डांस न करने पर नाराज हो जाया करती थीं। फिल्म के निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा कि श्रद्धा इस बात से भी नाराज हुई थीं कि उन्हें इस फिल्म में शुरू से नहीं लिया गया था। रेमो ने बताया कि कट्रीना की जगह श्रद्धा को फिल्म में शामिल करने के बाद स्क्रिप्ट में भी कुछ बदलाव करने पड़े। नागरिकता संशोधन बिल पर हो रहे विरोध के सवाल पर वरुण ने कहा कि खबरों में इस समय इस बिल को लेकर कई वर्जन चल रहे हैं। वह मुंबई में बैठकर किसी और जगह के बारे में नहीं बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के डांसर्स की प्रतियोगिता को दिखाती फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी' अगले वर्ष 24 जनवरी को रिलीज होगी।

शिवाजी महाराज के किरदार में सेट पर मिली इज्जत : शरद

अभिनेता शरद केलकर के लिए यह साल बहुत अच्छा साबित हुआ है। 'हाउसफुल 4' के बाद वह 'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। साथ ही वह अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' में भी नजर आएंगे। 'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' फिल्म में अपने किरदार को लेकर शरद बताते हैं कि इस किरदार की वजह से उन्हें सेट पर बहुत इज्जत मिली। शरद ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्हें वास्तविक किरदार निभाने का मौका मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजा जाता है। शरद ने कहा कि सेट पर पहुंचते ही वह किरदार में इतने रम जाते थे कि उनका हावभाव बिल्कुल बदल जाता था। उनका कहना है कि उन्हें अपनी तरफ से इस किरदार के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। री-टेक्स भी नहीं हुए। एक ही बार में शॉट ओके हो जाता था। शरद ने बताया कि उन्होंने पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मॉनिटर पर जाकर अपना काम नहीं देखा कि उन्होंने कैसा शॉट दिया है। शरद बताते हैं कि जैसे ही वह सेट पर पहुंचते थे, लोग अदब से किनारे हो जाते थे और उन्हें जाने के लिए जगह दे देते थे।

चुलबुल पांडे का किरदार जी रहा हूं : सलमान खान

सलमान खान फिलहाल अपनी फिल्म 'दबंग 3' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसके बाद उनकी फिल्म 'राधे' अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। दबंग की पहली दो फ्रेंचाइजी सफल होने की वजह से सलमान इस तीसरी फिल्म की सफलता के लिए भी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। तीनों फ्रेंचाइजी में सलमान दबंग पुलिस अधिकारी चुलबुल पांडे का किरदार निभाते आ रहे हैं।

सलमान कहते हैं, 'जब मैं स्क्रीन पर कोई रोल निभाता हूं तो उस किरदार का 25 फीसदी वापस घर ले जाता हूं। पिछले नौ सालों में दो सफल फ्रेंचाइजी करने के बाद मैं चुलबुल पांडे के किरदार को जी रहा हूं, जिसे लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है।' सलमान कहते हैं कि एक ही किरदार और फ्रेंचाइजी पर काम करना इतना आसान नहीं होता है। दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा होती हैं और यह जरूरी हो जाता है कि अगली फ्रेंचाइजी उस उम्मीद पर खरी उतरे। 'दबंग 3' के केस में हम निश्चिंत थे, क्योंकि यह पहले से टेस्ट की हुई थी और दर्शकों ने उसे स्वीकार किया था। यहां तक की दर्शकों को पहली दोनों फिल्में काफी पसंद आई थीं।

दादा राजकपूर की पसंदीदा थीं करिश्मा : करीना कपूर खान

बॉलीवुड की बहनों का जब भी जिक्र होता है, तो करीना कपूर और करिश्मा कपूर का नाम जरूर आता है। करिश्मा कपूर भले ही फिल्मों में इस वक्त बहुत ज्यादा सक्रिय न हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वह छाई रहती हैं। करीना और करिश्मा को अक्सर साथ देखा जा सकता है। बचपन की यादें साझा करते हुए करीना ने अपनी बड़ी बहन के बारे में एक बहुत ही प्यारी बात बताई। दरअसल, फिल्म 'गुड न्यूज' का प्रमोशन करने के लिए करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ 'द कपिल शर्मा' शो पर पहुंचे थे। करीना पहली बार कपिल के शो का हिस्सा बनी हैं। कपिल ने बातों-बातों में करीना से पूछा कि उनके दादा राजकपूर साहब आम के शौकीन थे। वह आम अपने कमरे में छिपा के रखते थे। क्या करीना को कभी उनके कमरे से उन आमों को लेकर खाने का मौका मिला है? जवाब में करीना ने कहा कि वे कोशिश करती थीं, लेकिन कभी मौका नहीं मिला।

उपलब्धि

पहली बार हड्डियों के अलावा किसी अन्य चीज से प्राप्त किया डीएनए, च्यूइंग गम को खाने वाले का लिंग और उसने आखिरी बार क्या खाया था यह भी पता लगाया

5700 साल पुराने च्यूइंग गम से निकला इंसान का डीएनए

भोजपत्र के पेड़ की चिपचिपी राल का इस्तेमाल च्युइंग गम के लिए होता था। प्रतीकात्मक

▶ दक्षिणी डेनमार्क के सिल्थोलम में पुरातात्विक खोदाई के दौरान यह 'च्यूइंग गम' पाया गया, इसकी जांच से कई बातें सामने आईं

लंदन, प्रेट्र : मानव विकास का क्रम जितना रहस्यमय है, उसको जानना उतना ही रोचक। दुनियाभर के वैज्ञानिक मानव विकास के संबंध में निरंतर नई जानकारियां एकत्र करने के लिए खोज व शोध कर रहे हैं। बहुत से रहस्यों से पर्दा उठ चुका है। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे तथ्य हैं, जिनसे दुनिया अनजान है। इसी कड़ी में शोधकर्ताओं को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शोधकर्ताओं ने प्राचीन 'च्यूइंग गम' के जरिये न केवल उसे चबाने वाले का लिंग पता किया, बल्कि उसने आखिरी बार क्या खाया था यह भी पता लगाया। दरअसल, शोधकर्ताओं ने 5,700 वर्ष पूर्व पाषाण काल की एक च्यूइंग गम मिली। उस पर मिले रोगाणुओं की जांच से पता लगाया गया कि उसे एक महिला ने चबाया था। यह पहली बार है, जब शोधकर्ताओं ने हड्डियों के नमूनों के अलावा किसी अन्य चीज से डीएन एकत्र किया है।

डेनमार्क में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को कुछ चिपचिपा पदार्थ मिला। जब उन्होंने उसकी जांच की तो उससे डीएनए एकत्र करने में सफल हुए। इस अध्ययन को नेचर कम्युनिकेशंस नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि दक्षिणी डेनमार्क के सिल्थोलम में पुरातात्विक खोदाई के दौरान यह 'च्यूइंग गम' पाया गया। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में कार्यरत और इस खोज के सह-लेखक हेंस श्रोएडर के मुताबिक, 'हड्डी के अलावा किसी अन्य चीज से पूर्ण प्राचीन मानव जीनोम प्राप्त करना आश्चर्यजनक है।'

शोधकर्ताओं का कहना है कि इस खोज से अनुमान लगाया जा सकता है कि भोजपत्र के पेड़ की चिपचिपी राल का इस्तेमाल उस दौर में शायद च्यूइंग गम जैसी किसी चीज के लिए होता था। इसके साथ ही यह भी पता लगाया गया है कि उस इंसान के मुंह में किस तरह के कीटाणु मौजूद थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक, वह एक महिला थी जिसके बाल काले, त्वचा काली और आंखें नीली थीं। जेनेटिक रूप से वह महिला यूरोप के शिकारी खानाबदोशों के बेहद करीब थी जो उस वक्त मध्य स्कैंडिनेविया में रहते थे।

रिपोर्ट के लेखकों में शामिल तेहिस जेनसेन ने बताया, 'सिल्थोल्म बिल्कुल अनोखा है। सब कुछ कीचड़ में लिपटा हुआ है। इसका मतलब है कि कार्बनिक अवशेषों का संरक्षण बहुत बढ़िया हुआ है। रिसर्चरों ने कुछ जीवों और पौधों के डीएनए के अंश भी खोज निकाले हैं। इनमें हेजेल नट (एक तरह का मेवा) और बत्तख भी शामिल हैं।